

भारतीय रिज़र्व बैंक

# बुलेटिन



जनवरी 2022

खंड 76 अंक 1

अध्यक्ष  
माइकल देबब्रत पात्र

संपादन समिति  
अजित आर. जोशी  
देबा प्रसाद रथ  
राजीव रंजन  
सितीकांत पट्टनाईक  
पल्लवी चव्हाण  
स्नेहल हेरवाडकर  
तुषार बर्मन दास  
पुलस्त्या बंदोपाध्याय

संपादक  
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2022

सर्वाधिकार सुरक्षित।  
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,  
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से  
<https://bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

# विषय-वस्तु

## भाषण

वित्तीय समावेश मौद्रिक नीति को मजबूती प्रदान करता है माइकल देब्रत पात्र	1
स्वामित्व और अभिशासन - डिजिटल नवाचारों के लिए ढांचे का निर्माण एम. राजेश्वर राव	7

## आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति	13
भारतीय कृषि: उपलब्धियां और चुनौतियां	43
भारत में उपभोक्ता विश्वास पर कोविड -19 महामारी का प्रभाव	61
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बदलती गतिशीलता	71

## वर्तमान सांख्यिकी

83

## हाल के प्रकाशन

130

## अनुपूरक

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2020-21 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट - दिसंबर 2021	
--	--



## भाषण

वित्तीय समावेश मौद्रिक नीति को मजबूती प्रदान करता है

माइकल देब्रत पात्र

स्वामित्व और अभिशासन - डिजिटल नवाचारों के

लिए ढांचे का निर्माण

एम. राजेश्वर राव



## वित्तीय समावेश मौद्रिक नीति को मजबूती प्रदान करता है\*

### माइकल देबब्रत पात्र

प्रो. एरोल डिस्जूजा, निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएमए); प्रो. उमाकांत दाश, निदेशक, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद (आईआरएमए); डॉ. सुप्रिया शर्मा, पार्टनर-इनसाइट्स, सेंटर फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईईई); बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के प्रतिनिधि; आईआईएमए के संकाय-सदस्य, छात्र और कर्मचारी; और दोस्तों, मैं, गाँवों के बदलाव हेतु वित्तीय समावेश की इस प्रशंसनीय पहल के लिए आप सभी की सराहना करता हूँ। अनुसंधान, मौजूदा और नए डेटा, और क्षेत्र प्रयोगों की मदद से वित्तीय समावेश की संपूर्ण मूल्य शृंखला और महिला सशक्तिकरण पर इसके प्रभाव की जांच की आवश्यकता व्यक्त कर इसने मानक को और ऊँचा उठा दिया। मैं निष्कर्षों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, विशेष रूप से - कौन से वित्तीय समावेश उत्पाद उपयोगी हैं, कहां और क्यों।

मैं इस परियोजना को शुरू करने का अवसर पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। अपने पेशे से प्रेरित होकर मैंने सोचा कि मैं अपने विचार साझा करूंगा कि वित्तीय समावेश मौद्रिक नीति को कैसे मजबूत बनाता है और इसके प्रभावी संचालन के लिए यह क्यों मायने रखता है।

बुनियादी वित्तीय सेवाओं के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली की उचित लागत पर सुविधा के अर्थ में वित्तीय समावेश अब 60 से अधिक देशों में नीतिगत उद्देश्य के रूप में मायने रखता है। यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के 2030 धारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और धारणीय विकास के लिए 2030 एजेंडा पर जी 20 की कार्य-

\* डॉ. माइकल देबब्रत पात्र, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया मुख्य भाषण, वित्तीय समावेश परियोजना के अंतर्गत 24 दिसंबर 2021 को भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा आयोजित, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (IIMA), ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद (IRMA) और सेंटर फॉर इनोवेशन, इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (CIIE) की एक संयुक्त पहल है। सीतिकांत पट्टनायक, बिनोद बी. भोई, स्नेहल एस. हेरवाडकर की मूल्यवान टिप्पणियों और विनीत कुमार श्रीवास्तव के संपादकीय सहयोग के लिए कृतज्ञतापूर्ण आभार।

योजना का केंद्रीय बिंदु भी है। कई प्रत्यक्ष विकासात्मक बदलाव का श्रेय वित्तीय समावेश को दिया जाता है, जैसे कि बचत का अधिक से अधिक जुटान, धन-विप्रेषण को सुविधाजनक बनाना, राजकोषीय आय को बढ़ावा देना और राजकोषीय हस्तांतरणों को सुप्रभावी बनाना। गुणात्मक विकास उत्प्रेरक या एक औजार की अपेक्षा, इसे व्यापक रूप से, समावेश को अपनाकर और गरीबी उन्मूलन, असमानता कम करने और महिला सशक्तिकरण जैसे अन्य विकास लक्ष्यों को संभव बनाकर, विकास की गुणवत्ता को बढ़ावा देने वाले साधन के रूप में देखा जाता है।

वित्तीय समावेश पर इस विकासात्मक बल को देखते हुए, वित्तीय समावेश और मौद्रिक नीति के बीच संबंध स्पष्टतः नया है। हाल ही में, हालांकि, मौद्रिक नीति के संचालन पर वित्तीय समावेश के प्रभावों और इसके माध्यम से जन-कल्याण में मौद्रिक नीति के योगदान के बारे में रुचि बढ़ रही है। इस रुचि को बढ़ावा देने के लिए शुरुआती स्थितियाँ हमेशा अस्तित्व में थीं। संयुक्त राष्ट्र का पूंजी विकास कोष या यूएनसीडीएफ, वित्तीय समावेश के कारक - जो स्थिर वित्तीय प्रणालियों में योगदान देते हैं - की रिपोर्ट करता है। वित्तीय रूप से शामिल आर्थिक कारक, प्रति-चक्र्रीय रूप से प्रभावित होने के बजाय, ब्याज दर चक्रों का सामना प्रचक्र्रीय रूप से करते हैं।

आज की अपनी टिप्पणी में, (ए) इस विषय पर अब तक अर्जित ज्ञान और अनुभवजन्य साक्ष्य को आत्मसात कर; और (बी) भारत के लिए प्रासंगिक सबक लेकर, मैं, वित्तीय समावेश और मौद्रिक नीति के बीच सहसंबंध को रेखांकित करना चाहता हूँ। यह महामारी के संदर्भ में भी प्रासंगिक है, जिसके दौरान जीवन और आजीविका के नुकसान ने आर्थिक रूप से वंचित और कमजोर परिवारों और व्यवसायों को सबसे अधिक प्रभावित किया। वित्तीय समावेश के अपने अनुभव से, आरबीआई ने महामारी का सामना करने के लिए जो योजना तैयार की वह समाज के पीड़ित वर्गों के लिए अपरंपरागत उपायों के रूप में पहुंची, और वित्त का प्रवाह बना रहा। विशेष रूप से जब व्यक्तिगत आय खत्म हो गई थी और भविष्य अत्यधिक अनिश्चित था, इन उपायों ने वित्तीय संस्थानों और बाजारों को कार्यशील बनाए रखा।

इस प्रयास में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सभी भारतीयों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की अपनी यात्रा में जिन पड़ावों को पार किया है, उनसे मैं उत्साहित हूँ - मैं, सितंबर 2021 में, एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेश सूचकांक (एफआई-इंडेक्स) के निर्माण और सार्वजनिक रिलीज का उल्लेख करता हूँ। यह सूचकांक 97 संकेतकों पर आधारित है, जो वित्तीय समावेश अवसंरचना की आपूर्ति अथवा 'पहुंच', 'उपयोग' या वित्तीय सेवाओं की मांग और 'गुणवत्ता' या वित्तीय साक्षरता और सुरक्षा में कमी के कारण पहुँच और उपयोग में असमानता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूचकांक 0 से 100 तक का मान लेता है और आरबीआई के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है- भारत के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश। 2021 तक, हमने वित्तीय अवसंरचना की पहुँच या आपूर्ति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए, आधे रास्ते को पार कर लिया है, और वित्तीय रूप से शामिल की जाने वाली मांग या उपयोग में अभी पीछे हैं। यह, वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई), 2019-24 और वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएफएसई) 2020-25 द्वारा स्थापित महत्वाकांक्षी एजेंडा के विज़न - वित्तीय साक्षर और सशक्त भारत - के लिए महत्वपूर्ण है।

एफआई-सूचकांक से जुड़े अन्य पूरक लाभ हैं। पहली बार, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और मात्रात्मक मीट्रिक के साथ वित्तीय समावेश के विस्तार के प्रयासों का पारदर्शी मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके अलावा, वित्तीय समावेश का एक मापनीय संकेतक, मौद्रिक नीति नियमों और प्रतिक्रिया कार्यों में शामिल किया जा सकता है ताकि उत्पादन और मुद्रास्फीति और उनकी अस्थिरता के साथ इसके संबंध की जांच की जा सके। पहली बार, नीतिगत दरों में बदलाव के आकार और समय-निर्धारण पर वित्तीय समावेश के प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है।

मौद्रिक नीति उत्पादन का उसकी क्षमता और मुद्रास्फीति का लक्ष्य से विचलन को न्यूनतम बनाकर जन-कल्याण को प्रभावी बनाती है। यद्यपि यह अनुभव में पाया गया है कि मौद्रिक नीति और वित्तीय समावेश के बीच दोतरफा संबंध है। यह स्पष्ट है कि वित्तीय समावेश मुद्रास्फीति और उत्पादन की अस्थिरता को कम करने में सक्षम है। मुश्किल समय में लोगों को वित्तीय बचत

को कम करने में सक्षम बनाकर और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खपत को सुचारू बनाकर प्राप्त इसे किया जाता है। इस प्रक्रिया में, यह लोगों को रुचि के प्रति संवेदनशील बनाता है। इसके अलावा, मुद्रास्फीति को लक्षित मौद्रिक नीति यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय समावेश के हाशिए पर रहने वाले भी आय के प्रतिकूल झटकों से सुरक्षित रहें, जो कीमतों में अनजाने में वृद्धि होने पर उन्हें प्रभावित करते हैं।

हालांकि, कुछ तकनीकी होने के बावजूद मेरी आगे की उक्ति इस गोष्ठी के चार केंद्रीय मुद्दों पर है: पहला, उचित मूल्य सूचकांक का चुनाव क्योंकि जनसंख्या उत्तरोत्तर आर्थिक रूप से समावेशी होती जाती है; दूसरा, उत्पादन और मुद्रास्फीति परिवर्तनशीलता पर वित्तीय समावेश का प्रभाव और उनके बीच संतुलन - जो मौद्रिक नीति संचालन की केंद्रीय दुविधा है; तीसरा, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के निर्णयों का संचरण; और चौथा, वित्तीय जागरूकता का प्रत्याशाओं और इस प्रकार मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता पर प्रभाव।

निष्कर्षतः वित्तीय समावेश, मुद्रास्फीति के प्रति सामाजिक अस्वीकृति, व्यापक आर्थिक स्थिरता के प्रति सामाजिक रुझान और लंबे और परिवर्तनशील अंतराल की भावना को बढ़ावा देता है जिसको ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति संचालित की जाती है। इससे, छोटी मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के लिए कम समय में समान लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव हो जाता है।

## II. मूल्य सूचकांक का चुनाव

जन-कल्याण को अधिकतम प्रभावी बनाने हेतु मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति के किस मापदंड को लक्षित करना चाहिए? ग्रामीण, कृषि-निर्भर क्षेत्रों में वित्तीय समावेश सबसे कम प्रतीत होता है जहां भोजन आय का मुख्य स्रोत है। दोहरे मॉडल के सिलसिले में हाल के काम से पता चलता है कि वित्तीय टकराव की स्थिति में - जैसा कि इस मामले में, आर्थिक रूप से असमावेशित या ऋण-बाधित उपभोक्ता के समांतर ऐसे लोग हैं जिनके पास औपचारिक वित्त तक पूर्ण पहुँच है - नम्य खाद्य कीमतों की, असमावेशित लोगों की वास्तविक मजदूरी और आय, इस प्रकार उनकी कुल मांग को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्याज दर में बदलाव इतना मायने नहीं रखता।



जब खाद्य कीमतों में वृद्धि होती है, तो आर्थिक रूप से असमावेशित लोगों द्वारा अर्जित अतिरिक्त आय को बचाया नहीं जाता है, बल्कि खपत में वृद्धि होती है, जिससे कुल मांग में वृद्धि होती है। इस तरह की स्थिति में, मौद्रिक नीति की क्षमता अपने स्थिरीकरण लक्ष्य को पाने में, कीमतों के उस मापदंड को लक्षित करने से बढ़ जाती है जिसमें खाद्य कीमतों को शामिल किया जाता है, बनिस्पत उसके जिसमें इसे छोड़ दिया जाता है, जैसे - मूल मुद्रास्फीति। इसलिए, वित्तीय समावेश का स्तर जितना नीचे तक होगा, मूल्य स्थिरता की संभवाना उतनी ही अधिक होगी, बशर्ते कि इसे हेडलाइन मुद्रास्फीति के संदर्भ में परिभाषित किया जाए, न कि मूल मुद्रास्फीति के किसी भी मापदंड के संदर्भ में, जो खाद्य और ईंधन को शामिल नहीं करता है।

भारत में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भोजन की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत है, जो दुनिया में कहीं भी सर्वाधिक हिस्सेदारियों में से एक है। इसके अलावा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक ग्रामीण सूचकांक और एक शहरी सूचकांक को जोड़ता है, जिसमें भोजन की हिस्सेदारी ग्रामीण सूचकांक में 54.2 प्रतिशत से भी अधिक है। शहरी सूचकांक में भी, 36.3 प्रतिशत की भोजन की हिस्सेदारी अंतर्देशीय परिप्रेक्ष्य में अधिक है। नतीजतन, समग्र मांग खाद्य कीमतों और कृषि उत्पादन के उतार-चढ़ाव से अत्यधिक प्रभावित होती है, न कि ब्याज दर में बदलाव से, जिसके प्रति शहरी सूचकांक संवेदनशील होता है। यह उल्लेखनीय है कि 2016 में मौद्रिक नीति ढांचे में मुद्रास्फीति को लक्ष्य करते हुए एक लचीली व्यवस्था की शुरुआत करने के लिए, मुद्रास्फीति लक्ष्य को मापने हेतु मूल मुद्रास्फीति के किसी भी मापदंड के बजाय हेडलाइन सीपीआई (सीपीआई) को मीट्रिक के रूप में चुना गया। मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत तक (अर्थात् अक्टूबर 2016 - मार्च 2020 के दौरान) नम्य मुद्रास्फीति को लक्षित करने की शुरुआत के बाद से हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति औसतन 3.9 प्रतिशत रही। कोविड-19 की पहली लहर, हेडलाइन मुद्रास्फीति ऊपरी सीमा से अधिक थी और 2020-21 में औसतन 6.2 प्रतिशत हो गई। प्रमुख सब्जी उत्पादक क्षेत्रों में खराब मौसम के कारण अल्पकालिक बढ़त को छोड़कर; बफर स्टॉक और आयात तक पहुंच बढ़ाने के लिए एवं उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए आपूर्ति में मजबूत हस्तक्षेप और करों को कम करने

से, हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी आई और वह पुनः लक्ष्य के अनुरूप बनी रही। इस पूरी अवधि में खाद्य मुद्रास्फीति अस्थिर रही है, जो उन वस्तुओं के उत्पादन पर आपूर्ति बाधाओं को दर्शाती है जिनके प्रति मुद्रास्फीति विशेष रूप से संवेदनशील होती है। यह 2016-20 की एफआईटी अवधि के दौरान औसतन 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में - महामारी की पहली लहर की ऊंचाई पर - 7.4 प्रतिशत हो गई, लेकिन नीतिगत हस्तक्षेपों ने इसे अप्रैल-नवंबर 2021 में 3.5 प्रतिशत तक सीमित करने में कामयाबी हासिल की है। नकदी और वस्तु दोनों के हस्तांतरण के माध्यम से महामारी के दौरान कृषि आय और खाद्य उपलब्धता को स्थिर रखना प्रमुख नीतिगत मिशन रहा है। संयोग से, वित्तीय समावेश में बढ़ोतरी हुई है, आरबीआई के वित्तीय समावेश सूचकांक का स्तर मार्च 2019 में 49.9 से बढ़कर मार्च 2020 में 53.1 और मार्च 2021 में 53.9 हो गया है।

घटनाएँ अभी जारी हैं और इनके विश्लेषण से ठोस निष्कर्ष निकालना जल्दबाज़ी हो सकती है, लेकिन भारत की मौद्रिक नीति वित्तीय रूप से समावेशी है और इस रणनीति का लाभ भविष्य में अधिकतम प्रभाव और जनहित के रूप में प्राप्त होगा।

### III. आउटपुट-मुद्रास्फीति परिवर्तनीयता को स्थिर रखना

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, मौद्रिक नीति को सौंपी गई जिम्मेदारी है - आउटपुट को उसकी क्षमता के करीब या उसके लक्ष्य के पास और मुद्रास्फीति को उसके लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखना। आर्थिक रूप से समावेशित उपभोक्ता आय की हानि की स्थिति में औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बचत (जमा) और ऋण लाभ के कारण कठिनाई का सामना करने में सक्षम होते हैं। दूसरी ओर, आर्थिक रूप से असमावेशित उपभोक्ता ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं और इसलिए वे उपभोग खर्च और आउटपुट में उच्च अस्थिरता के प्रति संवेदनशील होते हैं। आर्थिक रूप से समावेशित उपभोक्ताओं वाली सभी अर्थव्यवस्था कम खपत अस्थिरता के कारण कम उत्पादन अस्थिरता की उम्मीद रखेगी। आर्थिक रूप से असमावेशित उपभोक्ताओं वाली अर्थव्यवस्था में, मौद्रिक नीति को, उत्पादन को स्थिर बनाने के लिए अधिक बल देना पड़ता है। हालांकि, मोटे तौर पर, यह अस्थिर - मुद्रास्फीति है जो सभी उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है, चाहे वह सक्षम हो या कमजोर। इसलिए, कल्याणकारी

भूमिका में मुद्रास्फीति की अस्थिरता को न्यूनतम रखना मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। एक अर्थव्यवस्था में वित्तीय रूप से असमावेशित लोगों की हिस्सेदारी जितनी अधिक होगी, केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति स्थिरीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की कीमत पर उत्पादन स्थिरीकरण पर ध्यान देना होगा। जैसे-जैसे वित्तीय समावेश बढ़ता है, मौद्रिक नीति - मुद्रास्फीति को स्थिर करने और व्यापक जनहित - की अपनी क्षमता को बेहतर बना सकती है।

भारत में, मुद्रास्फीति को लक्ष्य करते हुए नम्य ढांचे की शुरुआत करते समय वित्तीय समावेश के मुद्दे और मौद्रिक नीति के असर को आकार देने में इसकी भूमिका को शुरु से ही मान्यता दी गई थी। तदनुसार, मौद्रिक नीति के लक्ष्यों के बीच मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता दी गई और आउटपुट दूसरा उद्देश्य था, जो कि +/- 2 प्रतिशत की सहन सीमा के साथ संख्यात्मक रूप से 4 प्रतिशत के संदर्भ में परिभाषित और प्राप्त किया गया। 2016 में संशोधित आरबीआई अधिनियम में उद्धृत - "मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।" - जैसा कि मैंने पहले बताया, यह काफी हद तक हासिल किया गया है। लेकिन महामारी के साथ असाधारण अनुभव के कारण, और आगे देखते हुए, मुद्रास्फीति अगले दो वर्षों में लक्ष्य तक पहुंचने की उम्मीद है, जैसा कि आरबीआई के मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अक्टूबर 2021 में बताया गया है।

इसके अलावा, इस बात के कुछ प्रमाण हैं कि वित्तीय समावेश ने उसी दिशा में काम किया है जिस तरह से मुद्रास्फीति और आउटपुट अंतराल के लिए भार के रूप में मौद्रिक नीति ढांचे में सुधारों ने किया है। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट, 2020-21 का अनुमान है कि 2000-11 की अवधि में मुद्रास्फीति का लक्ष्य से विचलन का गुणांक 0.41 था और साथ-साथ अपनी क्षमता से आउटपुट का विचलन गुणांक के रूप में 0.75 था। 2016-20 के दौरान, महामारी की पहली लहर तक मुद्रास्फीति लक्षित नम्य ढांचे की अवधि, मुद्रास्फीति अंतर पर भार बढ़कर 0.70 हो गया, जबकि आउटपुट अंतर पर भार 0.26 तक गिर गया, जो स्पष्ट रूप से आउटपुट की अपेक्षा मुद्रास्फीति स्थिरीकरण पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप उम्मीदों में स्थिरता आई,

विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा और मौद्रिक नीति ने विश्वसनीयता अर्जित की।

अनदेखा ही सही, बढ़ते वित्तीय समावेश का इस नेक परिणाम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह तर्क दिया गया है कि जैसे-जैसे वित्तीय समावेश बढ़ता है, आउटपुट अस्थिरता और मुद्रास्फीति अस्थिरता का अनुपात भी बढ़ना चाहिए, यदि केंद्रीय बैंक दोनों को ध्यान में रखता है और उनमें इष्टतम संतुलन स्थापित करने हेतु मौद्रिक नीति का उपयोग करता है। भारत में, यह अनुपात 2015 के मध्य में 0.6 से बढ़कर 2020-21 की अंतिम तिमाही में महामारी से ठीक पहले 1.3 हो गया है। महामारी की अवधि में, यह अनुपात 5 से ऊपर हो गया है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से अत्यधिक है जिसे अलग तरह से निपटना होगा। आगे देखते हुए, जैसे-जैसे भारत में वित्तीय समावेश और भी बढ़ता है, उत्पादन में उतार-चढ़ाव के स्रोत के रूप में खपत में उतार-चढ़ाव के कम होने की उम्मीद की जा सकती है, ताकि मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति की अस्थिरता को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर सबके लिए हितकारी हो सके।

#### IV. मौद्रिक नीति का संचरण

आधुनिक केंद्रीय बैंक ज्यादातर अर्थव्यवस्था के बाकी भागों को मौद्रिक नीति के रुख से अवगत कराने के लिए ब्याज दर का इस्तेमाल करते हैं। संक्षेप में कहें तो, नीतिगत दर में बदलाव अल्पकालिक मुद्रा बाजार दरों को तुरंत प्रभावित करते हैं, जिससे वे वित्तीय बाजारों की निरंतरता के माध्यम से लंबी अवधि की ब्याज दरों में संचरित होते हैं, जो व्यवसायों और घरों के खर्च संबंधी फैसलों को प्रभावित करते हैं और अंततः समग्र मांग को प्रभावित करते हैं। वित्तीय समावेश ब्याज दर आधारित मौद्रिक नीति प्रवाह के संचरण में दो तरह से सुधार करता है। सबसे पहले, आर्थिक रूप से असमावेशित लोग आम तौर पर 'घरेलु' बचत को प्राथमिकता देंगे और इसके लिए नकद पसंदीदा साधन है। जैसे-जैसे समावेश बढ़ता है, उनकी वरीयता नकद से ब्याज वाले बैंक जमा और अन्य वित्तीय संपत्तियों में स्थानांतरित होती जाती है। नतीजतन, अर्थव्यवस्था में वित्तीय बचत की ब्याज के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। लोगों के पोर्टफोलियो में मुद्रा की जगह ब्याज वाली जमाओं के कारण संरचनागत परिवर्तनों को

देखते हुए, शेष धन की ब्याज दर के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ जाती है। दूसरा, वित्तीय समावेश के कारण बैंक ऋण का विस्तार होता है, जो ब्याज-संवेदी और नीति दर में बदलाव से प्रभावित होता है। कुल मिलाकर, वित्तीय समावेश ब्याज दर आधारित मौद्रिक नीति की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे अधिकतर लोग ब्याज दर चक्रों के प्रति सचेत होने लगते हैं। बदले में, यह समुचित व्यवहार का संकेत देता है। इस संकेत के कुछ प्रमाण भी हैं कि जैसे-जैसे, ब्याज दर के प्रति जनता की संवेदनशीलता बढ़ती है, केंद्रीय बैंकों को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ब्याज दरों को कम करने की जरूरत होती है।

भारत में, मौद्रिक नीति प्रक्रिया में लोगों की बढ़ती भागीदारी के कारण ब्याज दर निर्धारण के प्रति दृष्टिकोण अधिक लोकतांत्रिक हुआ है। 1990 के दशक के दौरान आरबीआई ब्याज दरों के विनियमन से दूर हो गया था। इसके बाद निर्देश आधारित ऋण मूल्य निर्धारण मानदंड जारी हुए यथा- प्रमुख उधार दरें; आधार दर; निधि आधारित उधार दरों की सीमांत लागत। हमारा लक्ष्य पारदर्शिता, ग्राहक संरक्षण, जागरूकता और यथासंभव बाजार संगत होना है और इन सभी का उद्देश्य समावेश को बढ़ावा देना है। इन सभी व्यवस्थाओं में, नीतिगत दरों में बदलाव के संचरण के कारण जमा और उधार दोनों दरों में सुधार हुआ है। यह प्रक्रिया बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दरों के साथ पूर्ण हुई है जो पहले खुदरा ऋण और सूक्ष्म और छोटी इकाइयों को ऋण के लिए लागू हुई जिनके तहत संचरण पूर्ण हुआ है। स्पष्टतः वित्तीय समावेश पर बल देने से आरबीआई मौद्रिक नीति संचरण में अधिक सफल होगा।

## V. प्रत्याशाएँ और मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता

मौद्रिक नीति के संचालन के लिए प्रत्याशाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। भविष्य के बारे में लोगों की प्रत्याशाएँ आमतौर पर अतीत से निर्धारित होती हैं। उदाहरण के लिए, मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएँ भविष्य की कीमतों के बारे में बताती हैं क्योंकि लोग उन्हें रियर-व्यू मिरर में देखते हैं। केंद्रीय बैंकों के लिए, ऐसी प्रत्याशाएँ नीति निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट हैं क्योंकि यदि समान प्रत्याशा वाले लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो वे वास्तविक नतीजों में परिणत हो सकती हैं। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक यह आकलन कर सकते हैं कि प्रत्याशाएँ हैं या नहीं,

जिसका उनकी विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। इसलिए, प्रत्याशाओं को क्या संचालित करता है - यह एक ऐसा प्रश्न है जो लोग और उनकी सेवा करने वाले केंद्रीय बैंक, दोनों के लिए मूल्यवान है। यह देखा गया है कि वित्तीय साक्षरता लोगों को अधिक प्रासंगिक जानकारी चुनने और उसका बेहतर उपयोग करने का अधिकार देती है। भविष्य की मुद्रास्फीति का नजदीकी आकलन वित्तीय निजी निर्णयों के विकल्पों को सुझाने में मदद करता है, जिसमें बैंक खाता खोलना, बैंक ऋण लेना या मजदूरी के लिए सौदेबाजी भी शामिल हैं।

भारत ने हाल ही में समाज के उपेक्षित और वंचित वर्गों तक पहुंचने के लिए वित्तीय समावेश के अपने अभियान को आगे बढ़ाया है। जे ए एम - जन धन योजना; आधार; मोबाइल का त्रिकोण - इस संबंध में बदलाव का साधन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित है और इसे जमाराशि के दृष्टिकोण से व्यापक रूप से पूर्ण समावेशित माना जाता है। महामारी के दौरान, जे ए एम त्रिकोण का उपयोग लोगों की आजीविका बचाने और सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। नाबार्ड का स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, लाभार्थियों की संख्या और व्यापक व्यष्टि-ऋण के मामले में, दुनिया के सबसे बड़े माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम के रूप में उभरा है। आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता के लिए कई जन-संपर्क और जागरूकता अभियान चलाए हैं, जिनमें सबसे अधिक लोकप्रिय आरबीआई कहता है, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉंस सिस्टम (आईवीआरएस) है। इन उपायों ने सभी प्रकार के मीडिया को अपनाया है। जैसे-जैसे ये प्रयास तेज होते हैं, यह उम्मीद की जाती है कि एक सम्मिलित और जागरूक आबादी मौद्रिक नीति निर्माण और कार्यान्वयन में अधिक भाग लेगी, अधिक तर्कसंगत प्रत्याशाएँ विकसित करेगी और नीतिगत फायदों को वित्तीय प्रणाली में अधिक तेजी और प्रभावी ढंग से प्रसारित करने हेतु मध्यवर्ती वित्तीय संस्थानों को प्रेरित करेगी।

## VI. निष्कर्ष

मौद्रिक नीति प्राधिकरण आमतौर पर असमानता पर चर्चा से बचते हैं। वे समष्टिगत-स्थिरीकरण की भूमिका में दिखना पसंद करते हैं और वितरण संबंधी मुद्दों को राजकोषीय संस्थाओं के लिए छोड़ना पसंद करते हैं। फिर भी, वे स्पष्ट रूप से महसूस करते

हैं कि वित्तीय समावेश या औपचारिक वित्त तक पहुंच की समानता - बदलते लक्ष्य को मापने हेतु मीट्रिक के चुनाव में, उनकी भिन्नताओं के बीच संतुलन के विलम्ब में, और व्यापक अर्थव्यवस्था तक पहुंचने की मौद्रिक नीति की क्षमता के संदर्भ में - मौद्रिक नीति के संचालन को अपेक्षाकृत अधिक मौलिक रूप से प्रभावित करता है। यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बैंक वित्तीय समावेश के विस्तार के लिए नीतिगत अभियानों में अभिन्न रूप से शामिल हैं क्योंकि उन्हें उन अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक वित्तीय बनावट को ध्यान में रखना होता है जिनमें वे मौद्रिक नीति का संचालन करते हैं। जैसे-जैसे लोग वित्तीय रूप से समावेशित होते जाते हैं, वे अच्छे और बुरे दोनों समय से निपटने और भविष्य की मुद्रास्फीति का अधिक सटीक आकलन करने के लिए औपचारिक वित्त तक अपनी पहुंच का उपयोग कर पाते हैं। और इससे मौद्रिक नीति प्रभावित होती है - जैसा कि मैंने बताया है। इसलिए, केंद्रीय बैंक असमानता की परवाह करते हैं। आखिरकार, जन-कल्याण जोकि जनता की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध संस्थानों का उद्देश्य है - इस पर टिका है।

धन्यवाद !

### संदर्भ

Anarfo, E., Abor, J. Y., Osei, K. A., and Gyeke-dako, A. (2019). Monetary Policy and Financial Inclusion in

Sub-Sahara Africa: A Panel VAR Approach. *Journal of African Business* 20(4):549-572.

Mehrotra, A., and Yetman, J. (2015). Financial Inclusion - Issues for Central Banks. *BIS Quarterly Review*, March.

Morgan, P. J. and Pontines, V. (2014). Financial Stability and Financial Inclusion. *Asian Development Bank Institute (ADB) Working Paper No.488*. July.

Sahay, R., Cihak, M., N'Diaye, P., Barajas, A., Mitra, S., Kyobe, A., Mooi, Y. N., and Yousefi, S. R. (2015). Financial Inclusion: Can It Meet Multiple Macroeconomic Goals? *IMF Staff Discussion Note SDN/15/17*, September.

UN Capital Development Fund (UNCDF). Financial Inclusion and the SDGs. Available at <https://www.uncdf.org/financial-inclusion-and-the-sdgs>

World Bank (2018). Financial Inclusion Overview. October 2. Available at <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview#1>

Yetman, J. (2017). Adapting Monetary Policy to Increasing Financial Inclusion. Bank of Morocco – CEMLA-IFC Satellite Seminar at the ISI World Statistics Congress on "Financial Inclusion", Marrakech, Morocco, July 14.

## स्वामित्व और अभिशासन - डिजिटल नवाचारों के लिए ढांचे का निर्माण\*

एम. राजेश्वर राव

आज शाम मुझे मिंट के वार्षिक बैंकिंग कॉन्क्लेव में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। आयोजकों ने इस वर्ष के कॉन्क्लेव के लिए एक अत्यंत सामयिक और समकालीन विषय अर्थात्, **बैंकिंग का भविष्य: एक डिजिटल अवसर की यात्रा**, का चयन किया है। मुझे याद है कि इस कॉन्क्लेव के पिछले संस्करण के दौरान, गवर्नर शक्तिकांत दास ने पारंपरिक बैंकों और फिनटेक एवं बिगटेक के बीच डिजिटल व्यवधानों और सीमाओं की अस्पष्टता के बारे में बात की थी। आपके साथ जुड़ने वाले वक्ताओं के समूह को देखते हुए, मुझे यकीन है कि आप सभी ने सम्मेलन के दौरान कई उभरते मुद्दों पर एक अत्यंत ज्ञानवर्धक परिचर्चा किया है।

तकनीकी और डिजिटल नवाचारों ने वित्तीय सेवाओं के संवितरण में दक्षता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया है। वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और वित्तीय मध्यस्थता की लागत को कम करने में उनकी भूमिका सर्वविदित है। हालांकि, इस तरह के नवाचारों ने सभी हितधारकों के लिए नई चुनौतियों को भी जन्म दिया है। जहां ग्राहकों को गलत बिक्री, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के साथ-साथ पहचान की चोरी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं विनियामकों और पर्यवेक्षकों को ग्राहक सुरक्षा, नैतिक आचरण, नियामक मध्यस्थता और वित्तीय स्थिरता के बारे में चिंता संबंधी मुद्दों के साथ तेजी से जुड़ने की जरूरत है। बदले में, विनियमित संस्थाओं को प्रौद्योगिकी संचालित नवाचारों के माध्यम से हमेशा बदलती प्रतिस्पर्धा और कारोबारी व्यवधानों का सामना करने के लिए सतर्क रहने की जरूरत होती है, जिससे उन्हें अपनी व्यावसायिक योजनाओं को ठीक करने और कभी-कभी अपनी रणनीतियों को

फिर से उन्मुख करने एवं सहवर्ती जोखिमों का प्रबंधन करने की जरूरत होती है।

इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, मैंने सोचा कि मैं वित्तीय सेवाओं में कारोबारी आचरण और अभिशासन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ, जो नवाचार, परिवर्तन और कारोबारी व्यवधानों के समय में अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। मेरे विचार से ये प्रमुख नरम स्तंभ हैं जो किसी सफल वित्तीय संस्था के ढांचे का निर्माण करते हैं, और खासकर इस चुनौतीपूर्ण समय में। विशेष रूप से, अभिशासन संरचना अर्थात् बोर्ड और उसकी समितियों, स्वतंत्र निदेशकों और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में आश्वासन कार्यों से भूमिका और अपेक्षाओं पर विचार करने की जरूरत है।

इससे पहले कि मैं अभिशासन से संबंधित मुद्दों के बारे में बात करूँ, मैं निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और कॉर्पोरेट ढांचे के बारे में जो चिंता है उस पर संक्षेप में बात करना चाहूँगा, जो इन मुद्दों की जांच के लिए रिजर्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की सिफारिशों पर आधारित हैं। रिजर्व बैंक ने समूह द्वारा की गई 33 सिफारिशों में से 21 को स्वीकार कर लिया है और 26 नवंबर 2021 को इस निर्णय की घोषणा की थी। हालांकि, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां सिफारिशों पर व्यापक रूप से बहस हुई है और इसलिए और जांच की आवश्यकता है।

### भारत में निजी बैंकों का लाइसेंस और स्वामित्व

यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि एक गहरी, स्थिर और मजबूत वित्तीय प्रणाली आर्थिक विकास में योगदान करती है। लेकिन विकास के लिए सही मायने में समावेशी होना, औपचारिक वित्त की पहुंच को व्यापक और सघन करना एक पूर्वपेक्षा है। औपचारिक वित्त तक पहुंच निम्न आय समूहों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें उत्पादक उद्यमों और गतिविधियों के माध्यम से बचत, निवेश, ऋण प्राप्त करने और अपनी आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है। यह उन्हें भविष्य की आय के आघातों के खिलाफ बहुत जरूरी बीमा प्रदान करता है और उन्हें आपात स्थिति का प्रबंधन करने में मदद करता है। नब्बे के दशक की शुरुआत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की शुरुआत के बाद से रिजर्व बैंक द्वारा जारी निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए दिशानिर्देश उपरोक्त दर्शन द्वारा निर्देशित किए गए हैं। इसके

\* श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुंबई में मिंट वार्षिक सम्मेलन में 15 दिसंबर 2021 को दिया गया भाषण। श्री नवीन नांबियार और श्री प्रदीप कुमार द्वारा प्रदान किए गए इनपुट को कृतज्ञतापूर्वक अभिस्वीकृत किया गया है।

अलावा, उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए बैंकिंग प्रणाली में अधिक प्रतिस्पर्धा पैदा करने की अपेक्षा से विकल्पों को भी सूचित किया गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा अब तक लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के आठ सेट जारी किए गए हैं, जिनमें से चार सर्वव्यापी बैंकों के लिए हैं और चार अलग-अलग बैंकों से संबंधित हैं।

हाल ही में आईडब्ल्यूजी रिपोर्ट के बाद, सार्वजनिक चर्चा ज्यादातर बड़े औद्योगिक घरानों को बैंकिंग लाइसेंस देने की उनकी सिफारिश पर केंद्रित रही है। हालाँकि, इस मुद्दे पर थोड़ा ऐतिहासिक दृष्टिकोण मददगार होगा। वर्ष 1993 में जारी लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों में, बड़े कॉर्पोरेट/औद्योगिक घरानों द्वारा बैंक स्थापित करने पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं था; वर्ष 2001 के लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों ने बैंकों को एक बड़े कॉर्पोरेट/औद्योगिक घराने द्वारा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और अभिशासन पर वर्ष 2005 के दिशानिर्देशों के अनुसार, रिज़र्व बैंक के पूर्व मंजूरी से बड़े औद्योगिक घरानों को बैंक के 10 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 2013 में जारी लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के तहत, बैंकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण स्वामित्व वाली गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के माध्यम से स्थापित किया जाना था। इन दिशानिर्देशों के तहत व्यक्तियों को बैंकों को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर से बड़े कॉर्पोरेट/औद्योगिक घरानों के प्रमोटर होने पर कोई रोक नहीं थी। वर्ष 2016 के 'ऑन-टैप' दिशानिर्देशों ने बड़े औद्योगिक घरानों को परिभाषित किया और उन्हें बैंक को बढ़ावा देने से प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन साथ ही, उन्हें बैंक में 10 प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने की अनुमति दी गई। वर्ष 2014 और 2019 में जारी किए गए छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) के लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों ने सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी संस्थाओं और औद्योगिक घरानों को, उनके द्वारा प्रवर्तित एनबीएफसी सहित, ऐसे बैंक स्थापित करने के लिए स्पष्ट रूप से अपात्र बना दिया।

अतीत में इस विषय पर स्थापित कई समितियों के साथ-साथ आईडब्ल्यूजी ने भी स्वीकार किया है कि बड़े कॉर्पोरेट/औद्योगिक घराने पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं और उद्यमशीलता

और प्रबंधकीय प्रतिभा के अपने पूल को देखते हुए प्रबंधन विशेषज्ञता और रणनीतिक दिशा प्रदान कर सकते हैं। एक बड़े तकनीकी रूप से सुसज्जित सार्वभौमिक बैंक की स्थापना के लिए ज्यादा धन वाले योग्य और सक्षम प्रमोटरों को खोजने का मुद्दा भी है। हालांकि, साथ ही, आईडब्ल्यूजी सहित उन सभी द्वारा सामने आने वाले अनुवर्ती जोखिमों पर चिंता व्यक्त की गई थी। इनमें शामिल हैं - बैंक ग्राहकों की कीमत पर स्व-व्यवहार के माध्यम से और बैंक और उसके सहयोगियों के बीच लेन-देन में हितों का टकराव, ऋण देने के लिए सहयोगियों का पक्ष लेना और ऋण के आबंटन का निर्णय लेने में तटस्थता और स्वतंत्रता को कम करना और प्रतिद्वंद्वियों को ऋण प्रवाह को सीमित करना। संबद्ध उधार, समूह संरचनाओं के जटिल वेब, क्रॉसहोल्डिंग के साथ-साथ समूह में बड़ी संख्या में अविनियमित संस्थाओं की मौजूदगी से संबंधित मुद्दों के बारे में भी सावधानी बरती गई, क्योंकि ये आरबीआई के विनियामकीय और पर्यवेक्षी संसाधनों को बढ़ाएंगे। एक अन्य अक्सर उद्धृत तर्क भी बैंकिंग और उद्योग/व्यवसाय को अलग करने के सिद्धांतों की ओर इशारा करता है। जहां यह एक स्वीकृत तथ्य है कि वित्तीय अर्थव्यवस्था और वास्तविक अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सहजीवी हैं, वहीं खंडों का वास्तविक विलय वास्तव में प्रणालीगत जोखिमों को बढ़ा सकता है।

यह देखते हुए कि बैंकिंग सार्वजनिक धन से किया जाने वाला एक अत्यधिक लीवरेज्ड व्यवसाय है, उद्योग/व्यवसाय और बैंकिंग को अलग रखना समझ में आता है। इस पृथक्करण से जोखिमों से बचने की आशा है - जहां समूह इकाई में कहीं भी परेशानी के परिणामस्वरूप जमाकर्ताओं को जोखिम हो सकता है, जिसका असर जमा बीमा के दावों पर पड़ता है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर परस्पर जुड़ी वित्तीय प्रणालियों में व्यापक प्रभाव पड़ता है, जो वित्तीय स्थिरता के बारे में चिंता पैदा करता है। इन मुद्दों को आईडब्ल्यूजी द्वारा भी उठाया गया है और इसलिए, यह आवश्यक है कि हम बड़े औद्योगिक घरानों या ऐसे घरों के स्वामित्व वाली एनबीएफसी को कोई नया बैंक स्थापित करने की अनुमति देने से पहले संबंधित मामलों की बारीकी से जांच करें। निष्कर्ष के तौर पर, मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर जूरी ने अभी विचार नहीं किया है।

## शेयरधारिता और संरचना

बैंकों में स्वामित्व का विविधीकरण लंबे समय में वांछनीय माना जाता है क्योंकि केंद्रित शेयरधारिता उन्हें नैतिक खतरे की समस्या के लिए उजागर कर सकती है। इसलिए लंबे समय तक प्रमोटरों की होल्डिंग पर 15% की विनियामकीय सीमा निर्धारित की गई थी। साथ ही, कॉरपोरेट अभिशासन की चिंताओं के लिए केवल विविध स्वामित्व ही रामबाण नहीं है। वर्ष 2014 में पी.जे. नायक समिति (भारत में बैंक के बोर्ड के अभिशासन की समीक्षा करने के लिए समिति) द्वारा व्यक्त किए गए विचार यह थे कि यदि प्रमोटर निवेशक (निवेशकों) के लिए अधिकतम शेयरधारिता बहुत कम निर्धारित की जाती है, तो शेयरधारकों के बीच प्रोत्साहन के संरेखण के रूप में बैंक अधिक असुरक्षित हो सकते हैं और प्रबंधन कमजोर हो सकता है (तब प्रबंधन मुख्य रूप से शेयरधारकों के बजाय अपने स्वयं के हितों के बारे में चिंतित हो सकता है)। यह मुद्दा संकेंद्रित होल्डिंग से उत्पन्न जोखिमों की तुलना में अधिक चिंता का विषय हो सकता है। इसके अलावा, शेयरधारक, यदि बहुत छोटे हैं तो बैंक के मामलों से वंचित हो सकते हैं। इस दुविधा को स्वीकार करते हुए, आईडब्ल्यूजी ने सिफारिश की है कि लंबे समय में प्रमोटरों की होल्डिंग की सीमा को 26% (मौजूदा 15% से) तक बढ़ाया जाए। हम आईडब्ल्यूजी के विचारों से सहमत हैं जिन्होंने एक ओर स्वामित्व के संकेंद्रण और दूसरी ओर स्वामित्व के प्रसार से उत्पन्न चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। यहां तक कि गैर-प्रवर्तक होल्डिंग्स के लिए, एक तरफ नैसर्गिक व्यक्तियों और गैर-वित्तीय संस्थाओं के लिए निचली उप-सीमा (10 प्रतिशत) और पूर्ण रूप से विविधिकृत वित्तीय संस्थाओं (औद्योगिक घरानों से संबंधित वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर) के लिए थोड़ी अधिक (15 प्रतिशत) सीमा निर्धारित की गई है। वोटिंग अधिकारों पर 26% की वैधानिक सीमा से गुंजाइश निकालकर भी यह रुख पूंजी के संवर्द्धन के लिए अधिक लचीलेपन की अनुमति देता है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि रिजर्व बैंक ऐसे मामलों पर “उचित और उपायुक्त” अपेक्षाओं का उपयोग करके अपने निर्णय का प्रयोग कर सकता है जैसा कि विभिन्न वैश्विक क्षेत्रों में होता है।

जटिल समूह संरचनाओं और अपारदर्शी क्रॉस होल्डिंग्स से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने के परिप्रेक्ष्य से, एनओएफएचसी

को समूह में अन्य संस्थाओं के प्रभाव से बैंक को बचाने के लिए सबसे उपयुक्त संरचना में से एक माना गया है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, आरबीआई ने वर्ष 2013 से लाइसेंस प्राप्त बैंकों के लिए एनओएफएचसी संरचना अनिवार्य कर दी है। हालांकि, 2013 से पहले लाइसेंस प्राप्त बैंकों और समूह में अन्य संस्थाएं हैं, का एनओएफएचसी संरचना में अवस्थांतर एक और चुनौती है जिसमें विभिन्न जटिल मुद्दों के शामिल होने की वजह से इससे निपटने की आवश्यकता है। इन मुद्दों को भी सावधानीपूर्वक जांच करने की जरूरत है।

अंत में, आईडब्ल्यूजी की रिपोर्ट पर प्रतिक्रियाओं/टिप्पणियों की भारी संख्या ने हमें हितधारकों के व्यापक स्पेक्ट्रम से बहुत ही विविध विचार दिए। यह निजी बैंकों के स्वामित्व, नियंत्रण और कॉर्पोरेट संरचना के मुद्दों के महत्व और जटिलताओं की पुष्टि करता है। ठीक इन्हीं कारणों से, हमने निर्णय लिया है कि आईडब्ल्यूजी की कुछ सिफारिशों में व्यापक हितधारक परामर्श, वैधता सहित विभिन्न दृष्टिकोणों से गहन जांच की आवश्यकता है, और विभिन्न अन्य एजेंसियों और विनियामकों के साथ जुड़ कर काम करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है।

अब मैं वर्तमान परिवेश में महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करता हूँ - कॉरपोरेट अभिशासन।

## वित्तीय संस्थाओं में अभिशासन का महत्व

एक मजबूत, कुशल और सुदृढ़ वित्तीय मध्यस्थता संरचना अर्थव्यवस्था में वित्तीय संसाधनों के इष्टतम आबंटन की सुविधा प्रदान करती है। इसके लिए सभी हितधारकों, विशेषकर बैंकों के मामले में जमाकर्ताओं का विश्वास एक पूर्वापेक्षा है। जहां विधिक और विनियामकीय संरचनाएं इस विश्वास को बनाए रखने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करती हैं, वहीं विश्वास सुशासन और संस्थाओं एवं उनके पदाधिकारियों के नैतिक आचरण पर आधारित होना चाहिए। बैंकों को अच्छी तरह से विनियमित किया जाता है और उनकी गहन निगरानी की जाती है लेकिन वित्तीय संस्थाओं में जनता के विश्वास के किसी भी क्षरण को केवल विनियामकीय आदेश या पर्यवेक्षी कठोरता से नहीं रोका जा सकता है। इसलिए, अभिशासन के मुद्दों से उत्पन्न होने वाले ‘विफलता के जोखिम’ को कम करने के लिए, बैंकों से अपेक्षित

मानक हमेशा अन्य संस्थाओं की तुलना में अधिक होते हैं। वित्तीय मध्यस्थता का काम करने वाली अन्य विनियमित संस्थाओं पर भी यही सिद्धांत लागू होगा, यद्यपि यह अलग-अलग डिग्री में होगा।

सुदृढ़ कॉर्पोरेट अभिशासन सुनिश्चित करने के लिए, हमें दो प्रमुख चुनौतियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले, अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण रखने वाले प्रमुख शेयरधारक सभी हितधारकों के हित को उपयुक्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा, एक स्वयंसेवी प्रबंधन में अन्य हितधारकों के विविध, विसरित, या निष्क्रिय प्रकृति का लाभ उठाने के लिए विकृत प्रोत्साहन हो सकते हैं। जहां पहली चुनौती से निपटने के लिए स्वामित्व को नियंत्रण से अलग करना एक प्रमुख कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं दूसरी चुनौती का समाधान करने के लिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रबंधन द्वारा दिया जाने वाला प्रोत्साहन जमाकर्ताओं और अन्य हितधारकों के हित के साथ संरेखित हों।

घरेलू संदर्भ में, भारत की वित्तीय प्रणाली का बढ़ता आकार और जटिलता, प्रवर्तकों, प्रमुख शेयरधारक (ओं) और वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका अर्थात् बोर्ड की भूमिका की संवीक्षा को बढ़ाकर बैंकों में अभिशासन मानकों को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसके लिए, रिज़र्व बैंक ने जून 2020 में 'भारत में वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन' पर एक चर्चा पत्र जारी किया, इस चर्चा पत्र का उद्देश्य बैंकों में अभिशासन मानकों को बढ़ाना और मौजूदा विनियामकीय ढांचे को घरेलू संदर्भ के साथ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप संरेखित करना था। चर्चा पत्र में दिए गए सुझावों और इन सुझावों पर जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने इस वर्ष की शुरुआत में बोर्ड के अध्यक्ष और बैठकों, बोर्ड की कुछ समितियों की संरचना, निदेशकों की आयु, कार्यकाल और पारिश्रमिक, और पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति के संबंध में अनुदेश<sup>1</sup> जारी किए।

विनियमन की भाषा में, विवेकपूर्ण विनियमन और आचरण विनियमन का अर्थ आमतौर पर जाना जाने वाला जुड़वां चोटियों के रूप है। आरबीआई में, हम इन दो महत्वपूर्ण पहलुओं को

अभिशासन के नजरिए से देख रहे हैं, जिसमें विवेक के अलावा कारोबार के संचालन पर समान जोर दिया गया है, जो मुझे लगता है कि अब तक आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रबंधन के लिए अच्छा प्रदर्शन करना अपेक्षित है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे स्वीकार्य ग्राहक और बाजार आचरण एवं सर्वोत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं का पालन करके हासिल किया जाना चाहिए। इसकी गंभीरता दिखाने की चिंता होने या सीधे संवाद की आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई ने बोर्ड या बोर्ड/समिति के अध्यक्षों के साथ सीधे संपर्क के लिए कुछ शुरुआती कदम उठाए हैं।

### बोर्ड और उसकी समितियों की भूमिकाएं और उनसे अपेक्षाएं

बैंकों में सुशासन की संस्कृति को बढ़ावा देने की समग्र जिम्मेदारी उनके निदेशक मंडल की होती है। बोर्ड को "रुख शीर्ष पर<sup>2</sup>" निर्धारित करना चाहिए और एक सुदृढ़ अभिशासन, अनुपालन और जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने और बनाए रखने में प्रबंधन की भूमिका की निगरानी करनी चाहिए। यह जिम्मेदारी बोर्ड और उसके निदेशकों को दी गई है, भले ही उन्हें कोई भी नियुक्त करता है। बोर्ड से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि बैंक ईमानदारी के साथ पेशवरों द्वारा चलाया जा रहा है, सभी विनियामक और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, और उच्च पेशवर और नैतिक मानकों के अनुसार अपने कारोबार का संचालन करता है।

एक विश्वसनीय और रचनात्मक तरीके से प्रबंधन के साथ जुड़ने के लिए बोर्ड को गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए, यह अपेक्षित होगा।

- बोर्ड की समितियों के लिए विभिन्न समितियों को दिए गए अधिदेश के अनुरूप अपेक्षित विशेषज्ञ ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाले निदेशक हों।
- प्रबंधन प्रस्तावों की विश्वसनीय प्रत्यालोचना की संभावना को बढ़ाने के लिए बोर्ड और विभिन्न समितियों में अधिकांश स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

<sup>1</sup> <https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?id=12078&Mode=0>

<sup>2</sup> बीसीबीएस (<https://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf>)



- यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोर्ड की विशेष पर्यवेक्षी समितियों के लिए सूचना चैनल जोखिम लेने वालों के प्रभाव से स्वतंत्र हैं।

इन उपायों से बोर्ड और उसकी समितियों, विशेष रूप से प्रमुख समितियों, लेखापरीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के निर्णयों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। प्रमुख शेयरधारकों, अल्पसंख्यक शेयरधारकों और प्रबंधन के बीच जटिल परस्पर क्रिया के जवाब में बोर्ड द्वारा अक्सर एक बेहतर संतुलन बनाया जाता है। इसके माध्यम से चलाने की क्षमता एक प्रभावी बोर्ड को सामान्य बोर्ड से अलग करती है।

### स्वतंत्र निदेशकों की 'स्वतंत्रता'

स्वतंत्र निदेशकों को उन हितों को संतुलित करना जरूरी है जिनका बोर्ड में अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व हुआ हो, साथ ही, जिनका बोर्ड में प्रतिनिधित्व नहीं है या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। स्वतंत्र निदेशक जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्टता लाने में मदद करते हैं और हितधारकों के प्रति प्रबंधन की जवाबदेही भी बढ़ाते हैं। सबसे प्रभावी बोर्ड वे हैं जो 'मालिक और एजेंट' संबंध की चुनौतियों से निपट सकते हैं और सूचना विषमता पहली को हल कर सकते हैं। इस विषमता का स्तर बड़े और जटिल संस्थाओं में बढ़ने के लिए बाध्य है। इस चुनौती को हल करने के लिए, स्वतंत्र निदेशकों को यह पहचानने की जरूरत है कि वे वही हैं जिन्हें सूचना विषमता को दूर करना होगा। याद रखें, यह प्रबंधन ही है जो बोर्ड के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के तहत कार्य करता है। किसी बोर्ड की आवश्यकता क्यों होगी? बेशक, ऐसा होने के लिए, स्वतंत्र निदेशकों को स्वरूप और अर्थ में वास्तव में स्वतंत्र होने की जरूरत है।

### पारिश्रमिक प्रथाएं

पारिश्रमिक नीति बैंक के आंतरिक अभिशासन ढांचे का एक अभिन्न अंग है जो बोर्ड को अच्छे प्रदर्शन और स्वीकार्य जोखिम लेने वाले व्यवहार को पुरस्कृत करने में सक्षम बनाता है। यह बोर्ड के हाथों में (या बोर्ड के नामांकन और पारिश्रमिक समिति को

प्रत्यायोजन द्वारा) एक ठोस साधन भी देता है ताकि प्रमुख जोखिम लेने वालों के व्यवहार को स्वीकृत जोखिम-वहाँ क्षमता और रणनीतिक दिशा के साथ संरेखित किया जा सके। इस परिधि के भीतर, यह विभिन्न जोखिम लेने वालों की उद्यमशीलता की भावना है जो संस्था को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है।

जहां भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों की अपेक्षा है कि सीईओ, पूर्णकालिक निदेशकों, नियंत्रण कार्य कर्मचारियों और ठोस जोखिम लेने वालों (एमआरटी) के पारिश्रमिक को सभी प्रकार के जोखिमों के लिए समायोजित किया जाएगा और जोखिमों के समय-सीमा के प्रति संवेदनशील हो, वहीं हमें अक्सर संस्था के प्रदर्शन और एनआरसी/बोर्ड को अनुशंसित पारिश्रमिक के प्रस्तावों में गलत संरेखण देखने को मिलता है। मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए- आरबीआई जो आखिरी चीज करना चाहता है, वह व्यक्तिगत बैंक अधिकारियों के पारिश्रमिक का फैसला करना है, जो अनिवार्य रूप से बोर्ड / एनआरसी का कार्य है। लेकिन कभी-कभी ऐसी स्थितियां होती हैं जहां प्रस्ताव में इस तरह के मुआवजे की आंतरिक और बाहरी इक्विटी पर्याप्त रूप से उचित नहीं होती है। हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि विकृत प्रोत्साहनों से लापरवाह व्यवहार या उच्च जोखिम लेने का कारण हो सकता है जो एक अवधि में प्रकट हो सकता है। वैसी पारिश्रमिक प्रथाओं ने अत्यधिक जोखिम लेने को बढ़ावा दिया, जहां कर्मचारियों को अक्सर जोखिमों और इसके दीर्घावधिक परिणामों की पर्याप्त पहचान के बिना अल्पावधिक लाभ बढ़ाने के लिए पुरस्कृत किया जाता था जिसने 2008 में वैश्विक वित्तीय प्रणाली को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया था।

### निष्कर्ष विचार

कोविड ने हम सभी को अपने जीवन में हर चीज के प्रति एक नया नजरिया दिया है। महामारी की पहली लहर की शुरुआत में, हर कोई 'इम्युनिटी बूस्टर' के लिए हाथ-पांव मार रहा था, चाहे उसे किसी भी रूप में बेचा जा सके। कठिन समय के दौरान बैंकों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन वैसा ही है जो किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी डर के समय में प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा का विकास जटिल है और इसमें स्वस्थ और सकारात्मक प्रथाओं

का आजीवन अंतर्ग्रहण होता रहता है। मानव दीर्घायु की तरह, बैंकिंग कारोबार की स्थिरता स्वस्थ कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं से आती है।

जैसा कि हम सामूहिक रूप से वास्तविक क्षेत्रों में सकारात्मक प्रसार के साथ एक कुशल वित्तीय मध्यस्थता की आकांक्षा रखते हैं, हमें खुद को यह याद दिलाने की जरूरत है कि ये आकांक्षाएं तेजी से प्रतिस्पर्धी, विविध, परस्पर और बाजार संचालित पारिस्थितिकी तंत्र में स्थापित हैं। इस संदर्भ में जमाकर्ताओं और वित्तीय संसाधनों के विभिन्न प्रदाताओं जैसे अन्य हितधारकों का विश्वास हासिल करना और बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह वित्तीय संस्थाओं में अभिशासन, नियंत्रण और आश्वासन कार्यों द्वारा सर्वोत्तम रूप से सुनिश्चित किया जाता है। अभिशासन फ्रेमवर्क को नट और बोल्ट के एक जटिल जाल के रूप में चित्रित किया जा सकता है जिसमें पूंजी, आस्ति, जमा और निवेश के वित्तीय स्तंभ

होते हैं और बैंक की संरचना को सीधा रखते हैं। जैसे-जैसे हमलोग महामारी से उबरने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे-वैसे वित्तीय संस्थाओं को एक उज्ज्वल कल के लिए हमारे दृष्टिकोण को साकार करने हेतु संवृद्धि का समर्थन करने के लिए असाधारण मात्रा में वित्तीय संसाधनों की जरूरत होगी। इन संसाधनों को जुटाना किसी भी सुदृढ़ अभिशासन फ्रेमवर्क वाले वित्तीय मध्यस्थों के लिए बाधा नहीं होगा क्योंकि वे एक अभिशासन प्रीमियम का नियंत्रण कर सकते हैं। बदले में यह प्रीमियम शीर्ष पर नेतृत्व की अपेक्षाओं से प्रेरित होगा। आखिरकार, फर्क करने में कुछ ही समय लगता है।

आपको आगे आने वाले डिजिटल अवसरों के माध्यम से यात्रा करने के लिए तैयार होने के साथ-साथ अभिशासन को ठीक करने के लिए मेरी शुभकामनाएं!

धन्यवाद।

# आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारतीय कृषि: उपलब्धियां और चुनौतियां

भारत में उपभोक्ता विश्वास पर कोविड -19 महामारी का प्रभाव

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बदलती गतिशीलता



## अर्थव्यवस्था की स्थिति\*

नये साल की शुरुआत के साथ ही, दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत को भी ओमीक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण आर्थिक सुधार में बाधा का सामना करना पड़ा। फिर भी, उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास एवं बैंक ऋण में वृद्धि के कारण समग्र मांग की स्थिति सुदृढ़ है, जबकि आपूर्ति के मोर्चे पर, रबी की बुवाई पिछले साल के स्तर और सामान्य रकबे को पार कर गई है। विनिर्माण और विभिन्न सेवाओं में अभी विस्तार जारी है। ओमीक्रॉन की लहर चंद दिनों तक ही ठहरने की उम्मीद में निकट भविष्य के अनुमान सकारात्मक हैं।

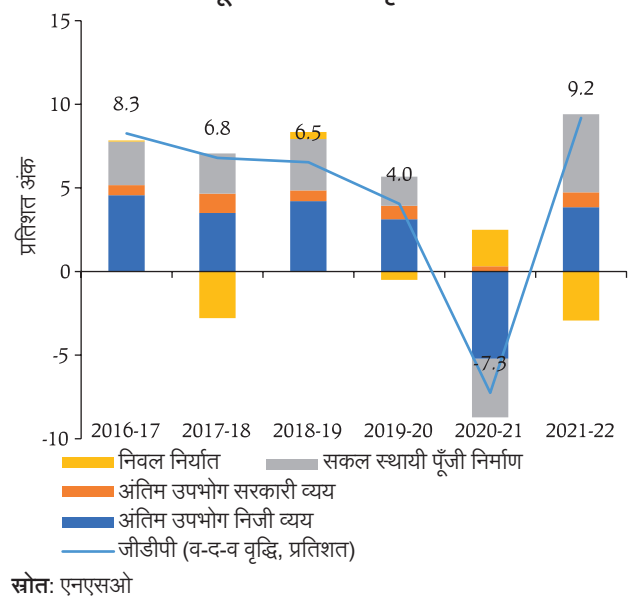
### भूमिका

नये साल में भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2021-22 में महामारी से पहले के अपने स्तर को पार कर लिया। जैसे-जैसे आर्थिक सुधार मजबूत हुआ निवेश, निर्यात और आयात अपने पूर्व-कोविड स्तरों से अधिक हो गए (चार्ट 1) और कुल मांग के सभी घटकों में विस्तार हुआ। सरकार के अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) में 2021-22 में तेजी आई, जिससे समग्र मांग को बल मिला। आपूर्ति में, कृषि क्षेत्र रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन के कारण सकारात्मक रहा। औद्योगिक और सेवा गतिविधि में अड़चन के बावजूद सुधार देखा गया, जबकि सेवाओं को अभी तक अपने 2019-20 के स्तर को प्राप्त करना बाकी है।

‘अर्थव्यवस्था की स्थिति’ आलेख के दिसंबर 2021 अंक के बाद से कुछ क्षेत्रों में धीमापन आया है। बाहरी मोर्चे पर, दिसंबर में भारत का मजबूत निर्यात प्रदर्शन भारतीय माल की लगातार मांग

\* यह आलेख कुणाल प्रियदर्शी, शशिधर एम. लोकरे, राजीव जैन, शाहबाज खान, विनीत कुमार श्रीवास्तव, अभिलाषा, प्रियंका सचदेवा, अभिनंदन बोराड, प्रशांत कुमार, दीपिका रावत, अक्षरा अवस्थी, ऋषभ कुमार, सत्यार्थ सिंह, रचित सोलंकी, सक्षम सूद, अवनीश कुमार, साक्षी अवस्थी, राधेश्याम वर्मा, आशीष थॉमस जॉर्ज, श्री देब प्रसाद रथ और श्री समीर रंजन बेहरा द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

चार्ट 1: सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि में भारत योगदान



को दर्शाता है, जबकि घरेलू मांग में सुधार के कारण आयात में भी वृद्धि हुई है। आने वाले दशकों में निर्यात वृद्धि को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मैकेनिकल उपकरण, ऑप्टिकल और सर्जिकल उपकरण जैसे उच्च तकनीकी उत्पादों की निर्माण-क्षमता महत्वपूर्ण साबित होगी।

महामारी के मद्देनजर रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए नीतिगत उपाय 2021-22 में अपनी पूर्व-घोषित समाप्ति तिथियों तक पहुंच गए। परिणामस्वरूप, जहाँ कुछ चलनिधि उपाय समाप्त हो गए हैं, ज़रूरतमंद क्षेत्रों को तय सहायता प्रदान करते हुए, अन्य विनियामक उपाय, जैसे - निवल स्थायी वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) के कार्यान्वयन का स्थगन, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा लाभांश के भुगतान पर रोक, और पूंजी संरक्षण बफर की अंतिम किश्त के कार्यान्वयन का स्थगन - को, विस्तारित चुकौती-अवधि और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों से बचने के लिए, फिर से संरेखित किया गया है।

बैंक ऋण वृद्धि खुदरा क्षेत्र में बढ़त के साथ एक क्रमिक सुधार का संकेत दे रही है, हालांकि कम रेटिंग वाले कॉरपोरेट्स में ऋण प्रवाह-संकुचन बना हुआ है। इस संबंध में, रिजर्व बैंक ने हाल ही

में, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर अपनी रिपोर्ट, 2020-21 जारी की। रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं:

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कुल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2020 अंत के 8.2 प्रतिशत से घटकर मार्च 2021 अंत में 7.3 प्रतिशत और आगे सितंबर 2021 के अंत में 6.9 प्रतिशत हो गया। प्रावधानीकरण व्याप्ति अनुपात (पीसीआर) सितंबर 2021 तक बढ़कर 68.1 फीसदी हो गया, जो मार्च 2020 में 66.2 था।
- जैसा कि आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) द्वारा दर्शाया गया है, स्थिर आय और व्यय में गिरावट की बदौलत, एससीबी की लाभप्रदता में मार्च 2020 के अंत में 0.2 प्रतिशत से मार्च 2021 के अंत में 0.7 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई जो सितंबर-2021 में बढ़कर 0.8 प्रतिशत हो गई।
- उच्च प्रतिधारित आय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूजीकरण और पीएसबी और निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) द्वारा बाजार से पूंजी जुटाने के सहयोग से, एससीबी का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2020 के अंत में 14.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 16.3 प्रतिशत और सितंबर 2021 के अंत में 16.6 प्रतिशत हो गया।
- कुल अग्रिमों में पुनर्गठित मानक अग्रिम (आरएसए) की हिस्सेदारी मार्च 2021 के अंत में बढ़कर 0.8 प्रतिशत हो गई, जो मार्च 2020 के अंत में 0.4 प्रतिशत थी। यह अगस्त 2020 में रिजर्व बैंक द्वारा घोषित मानक अग्रिमों के लिए एकबारगी पुनर्गठन योजना को दर्शाती है। साथ ही यह, खुदरा ऋण और एमएसएमई के लिए समाधान फ्रेमवर्क 2.0 के कारण सितंबर 2021 तक 1.8 प्रतिशत हो गई।

इस आलेख के बाकी हिस्सों को चार खंडों में बाँटा गया है। खंड II में हाल के वैश्विक आर्थिक गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन, खंड III में प्रस्तुत किया गया है। खंड IV में भारत की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा की गई है और अंतिम खंड में आलेख का समापन किया गया है।

## II. वैश्विक परिदृश्य










कोविड-19 के फिर से आने और नए वेरियंट के कारण लंबी अवधि की आर्थिक संभवनाओं को गंभीर जोखिम है। 10 जनवरी 2022 तक वैश्विक स्तर पर लगभग 306 मिलियन मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ओमीक्रॉन वेरियंट के उच्च प्रसार क्षमता के कारण, कई देशों ने फिर से लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंध और अन्य रोकथाम उपाय लागू कर दिए हैं। अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है क्योंकि प्रोत्साहन-प्रेरित कदम से उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी के साथ-साथ उत्पादन और आपूर्ति शृंखला में व्यवधान जारी है। इसके कारण मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण में तेजी आ रही है। आपूर्ति शृंखला में व्यवधान और पोत-परिवहन शुल्क में कुछ ढील दी जा रही है, हालांकि, महामारीजन्य मुद्रास्फीति में 2022 के उत्तरार्ध तक कमी आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, वैश्विक संवृद्धि की गति मंद हुई है।

विश्व बैंक ने 11 जनवरी 2022 को जारी अपनी नवीनतम वैश्विक आर्थिकी पूर्वक्षण (जीडपी) रिपोर्ट में पूर्वानुमान लगाया है कि कोविड-19 का लगातार उभार, नीतिगत मदद में न्यूनता और लगातार आपूर्ति बाधाओं के मद्देनजर वैश्विक सुधार में तेज गिरावट आएगी। अमेरिका और चीन के संवृद्धि पूर्वानुमानों को 2021 और 2022 (सारणी 1) दोनों के लिए विशेष रूप से संशोधित किया गया है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र मंदी उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए बाहरी मांग को नीचे ला देगी। विश्व बैंक को उम्मीद है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ (एई) 2023 तक उत्पादन में पूरी तरह से सुधार हासिल कर लेंगी, जबकि उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाएँ (ईएमई) अभी भी अपनी पूर्व-महामारी स्थिति से 4 प्रतिशत कम रहेगी।

ग्लोबल कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) दिसंबर 2021 में तीन महीने के निचले स्तर 54.3 पर समाप्त हुआ, हालांकि उसमें लगातार 18 महीनों तक विस्तार देखा गया। साथ ही, वैश्विक सेवाओं का पीएमआई भी दिसंबर में तीन महीने के निचले स्तर 54.6 पर आ गया, हालांकि इसने विनिर्माण - जो पिछले महीने के 54.2 (चार्ट 2) के स्तर पर स्थिर था - से

**सारणी 1: चुनिंदा उन्नत और उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि अनुमान**

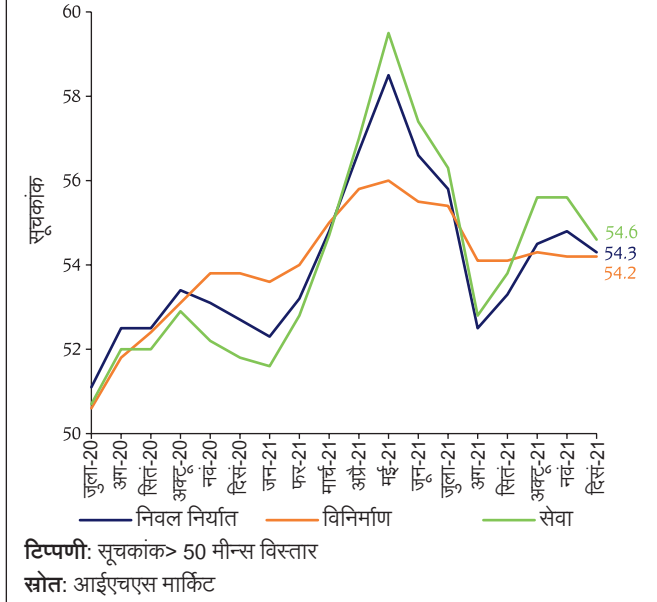
(प्रतिशत)

देश	2021		2022	
	जून 2021	जन 2022	जून 2021	जन 2022
 विश्व*	5.7	5.7	4.5	4.4
<b>उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ</b>				
 यूएस	6.8	5.6	4.2	3.7
 यूरो क्षेत्र	4.2	5.2	4.4	4.2
 जापान	2.9	1.7	2.6	2.9
<b>उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ</b>				
 ब्राजील	4.5	4.9	2.5	1.4
 रूस	3.2	4.3	3.2	2.4
 भारत#	<b>8.3</b>	<b>8.3</b>	<b>7.5</b>	<b>8.7</b>
 चीन	8.5	8.0	5.4	5.1
 दक्षिण अफ्रीका	3.5	4.6	2.1	2.1

\* : पीपीपी भारत # : राजकोषीय वर्ष पर आधारित भारत के आँकड़े

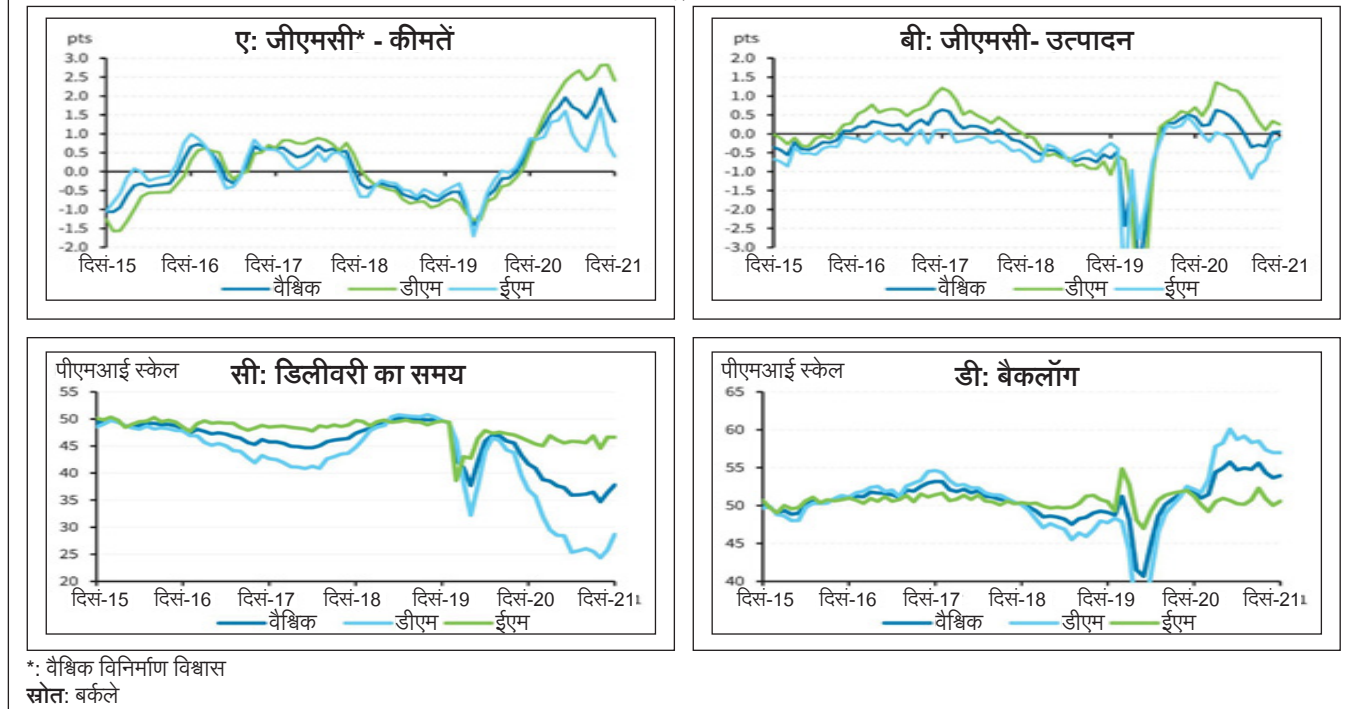
स्रोत: विश्व बैंक

**चार्ट 2: वैश्विक पीएमआई**

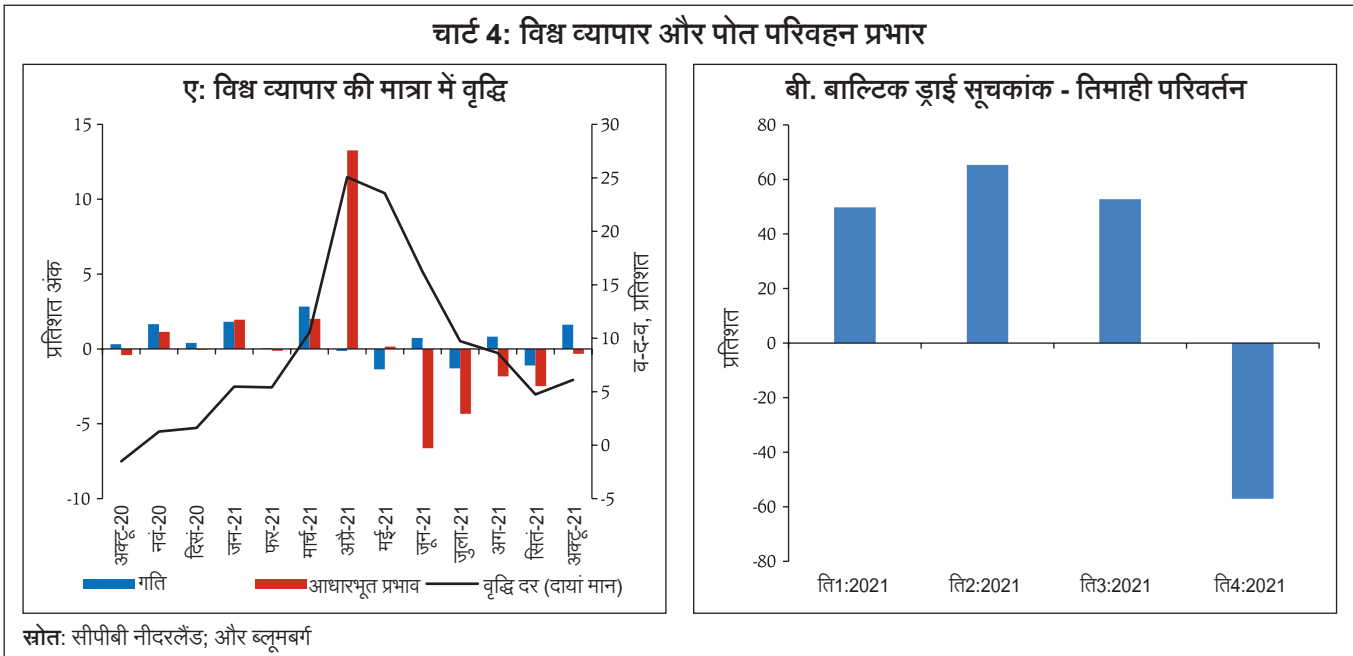


बेहतर प्रदर्शन जारी रखा। हालांकि मुद्रास्फीति और आपूर्ति शृंखला में दबाव बने रहे लेकिन इनमें कमी के संकेत हैं। निविष्टि लागत और उत्पादन कीमतों में आठ महीनों में सबसे कमजोर वृद्धि दर्ज की गई, जबकि विक्रेता का आपूर्ति-समय नौ महीनों में न्यूनतम था (चार्ट 3)। न्यूयॉर्क फेड का वैश्विक आपूर्ति शृंखला

**चार्ट 3: वैश्विक आपूर्ति शृंखला के कारक**



**चार्ट 4: विश्व व्यापार और पोत परिवहन प्रभार**



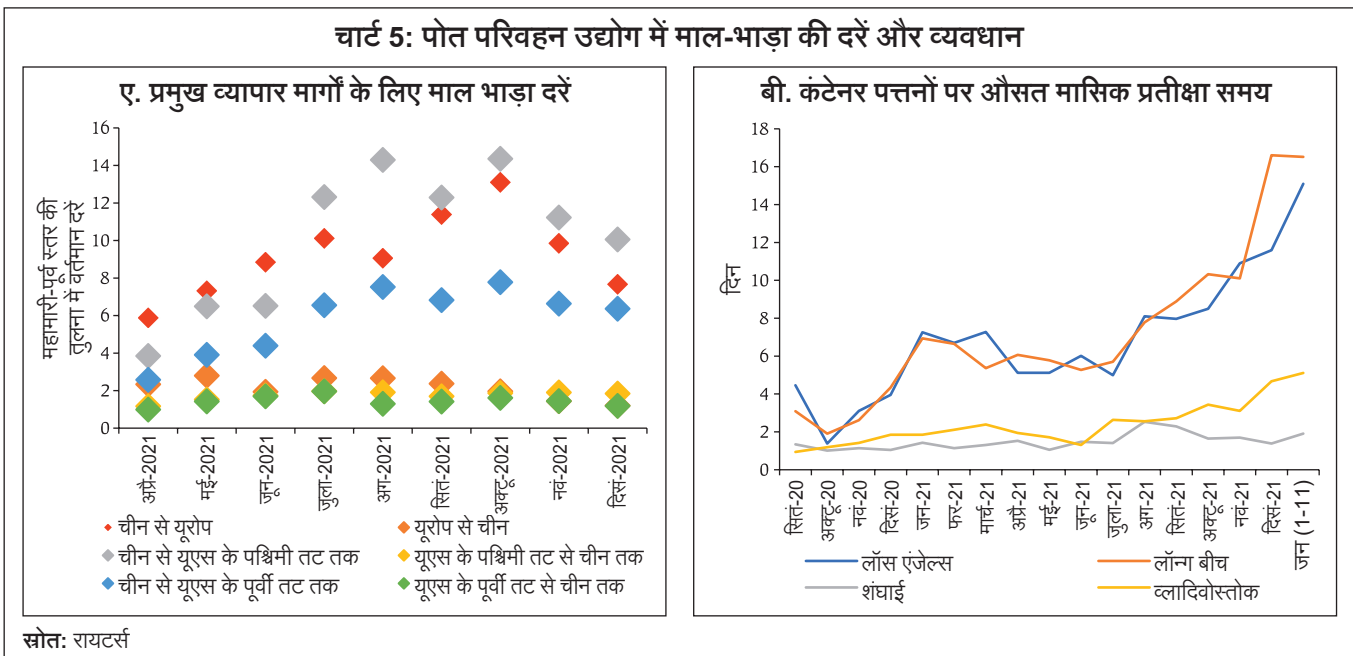
दबाव सूचकांक<sup>1</sup> चरम पर है और आगे चलकर मध्यम होना शुरू हो सकता है।

बाहरी मांग के मोर्चे पर, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष), लगातार पांच महीनों (चार्ट 4ए) की गिरावट के बाद अक्तूबर 2021 में बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गई। अक्तूबर की शुरुआत

में 13 साल के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद बाल्टिक ड्राई इंडेक्स भी 2021 की चौथी तिमाही में नरम हुआ (चार्ट 4बी)।

दिसंबर 2021 में सभी मार्गों की माल-भाड़ा दरों में भी कमी आई, लेकिन वे अभी भी अपने पूर्व-महामारी स्तर (चार्ट 5ए) से ऊपर हैं। हालांकि, ओमीक्रॉन के कारण आपूर्ति शृंखला व्यवधान

**चार्ट 5: पोत परिवहन उद्योग में माल-भाड़ा की दरें और व्यवधान**



<sup>1</sup> <https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2022/01/a-new-barometer-of-global-supply-chain-pressures/>



बढ़ गए हैं, जिससे टर्न-अराउंड समय और यूएस जाने वाले जहाजों का प्रतीक्षा समय बढ़ गया है (चार्ट 5बी)।

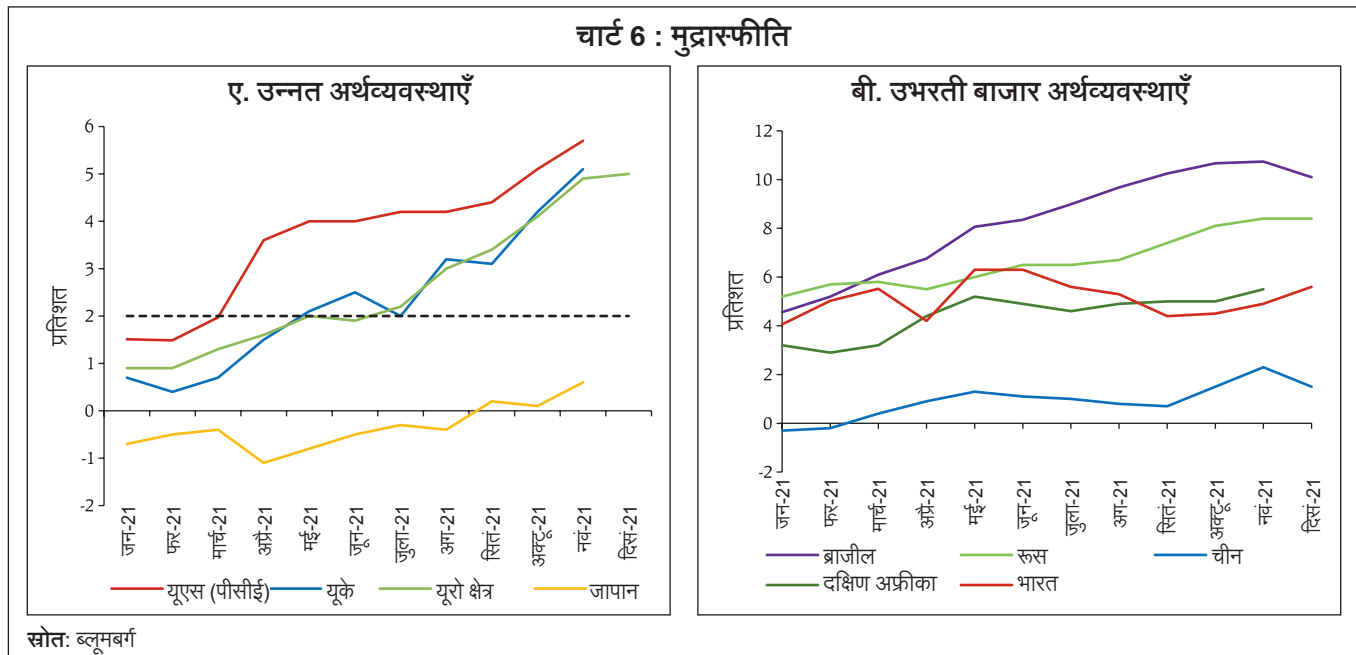
कई क्षेत्रों में मुद्रास्फीति कई दशकों के उच्च स्तर पर पहुंच गई (चार्ट 6)। अमेरिका में, व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मूल्य सूचकांक में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति नवंबर में 5.7 प्रतिशत - करीब 40 साल के उच्च स्तर - पर पहुंच गई, साथ ही मूल पीसीई मुद्रास्फीति भी 32 साल के उच्च स्तर - 4.7 प्रतिशत पर पहुंच गई। यूरो क्षेत्र की मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 5.0 प्रतिशत की नई ऊंचाई पर पहुंच गई। ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में, ब्राजील में दिसंबर 2021 में सीपीआई मुद्रास्फीति पिछले महीने के 18 साल के उच्च स्तर 10.7 प्रतिशत से घटकर 10.1 प्रतिशत हो गई। रूस में मुद्रास्फीति दिसंबर में 8.4 प्रतिशत पर स्थिर थी।

2021 में दुनिया भर में मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारक ऊर्जा, खाद्य और जिंस की कीमतों में तेज उछाल रहा है। विश्व बैंक के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में 2020 में 32.8 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2021 में 67.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 7ए)। प्राकृतिक गैस की कीमतों में 2021 में लगभग तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई - यूरोप में इसकी कीमतें दिसंबर में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं (चार्ट 7बी)। ब्लूमबर्ग क्मोडिटी प्राइस इंडेक्स में 2021 में

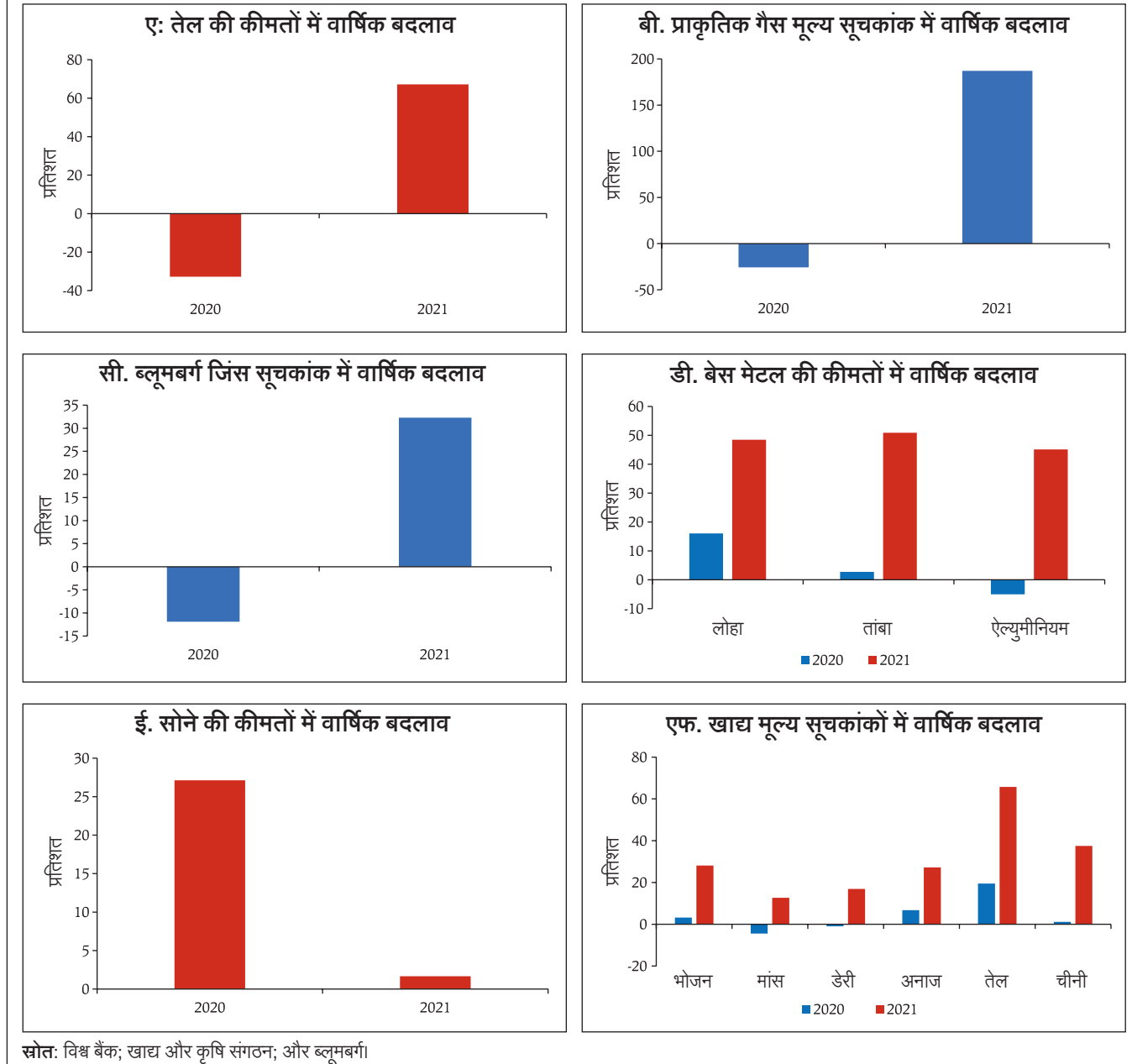
32.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके साथ - विनिर्माण में सुधार के कारण धातु की कीमतें बढ़ीं, 'हरी' धातुओं की अधिक मांग पैदा हुई और महामारी से संबंधित आपूर्ति व्यवधान भी बढ़े (चार्ट 7सी और 7डी)। दूसरी ओर, सोने की कीमतों में 2021 में केवल मामूली वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि पीली धातु की मांग कम हुई और डॉलर में मजबूती आई (चार्ट 7ई)। दिसंबर में मामूली कमी के बावजूद - मौसम संबंधी आपूर्ति में व्यवधान और चुनिंदा खाद्य पदार्थों के लिए चीन से उच्च आयात-मांग के कारण - खाद्य कीमतें 2021 में एक दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गईं (चार्ट 7एफ)।

वित्तीय बाजार वायरस के फैलाव और प्रमुख केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के कारण अस्थिर थे। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के शेयर बाजारों में तेजी बनी रही, जबकि उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं में कम संवृद्धि की संभावनाओं और संबंधित देश के अपने कारकों (चार्ट 8ए) के कारण शेयर बाजार कमजोर रहा। अमेरिकी ट्रेजरी बाजार में, उच्च मुद्रास्फीति और संवृद्धि परिणामों की प्रतिक्रिया में 10-वर्षीय प्रतिफल बेंचमार्क आम तौर पर 2021 के उत्तरार्ध में बढ़ा, लेकिन मौद्रिक नीति रुख में बदलाव के कारण 2 साल का प्रतिफल 2021 की चौथी तिमाही में ही कम होने लगा। परिणामतः प्रतिफल का फैलाव धीरे-धीरे कम होता गया (चार्ट 8बी)। सुरक्षित आश्रय मांग और फेडरल

चार्ट 6 : मुद्रास्फीति



चार्ट 7: जिंस और खाद्य वस्तुओं की कीमतें

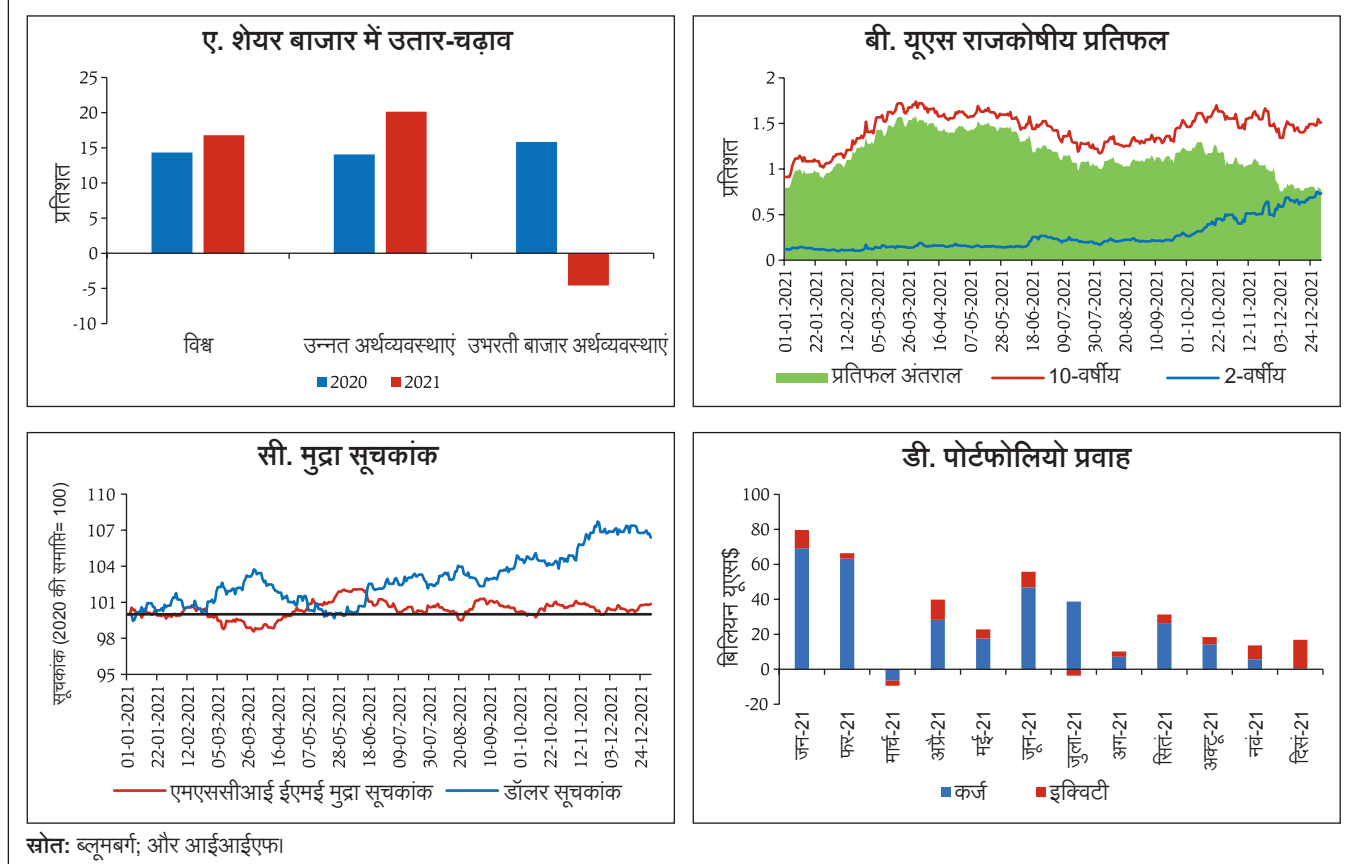


रिज़र्व की तीव्र सामान्यीकरण नीति (चार्ट 8सी) को देखते हुए अमेरिकी डॉलर 2021 के उत्तरार्द्ध में मजबूत हुआ। जैसे-जैसे जोखिम वहन क्षमता में कमी आई, 2021 के अंतिम महीनों में उभरते बाज़ार वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूंजी प्रवाह में भी कमी देखी गई, जिसमें ऋण प्रवाह में तेज गिरावट आई (चार्ट 8डी)। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने गौर किया है कि

वैश्विक संवृद्धि के प्रति उच्च जोखिम के माहौल में, फेड द्वारा दरों की तेज बढ़ोतरी से दुनिया भर की वित्तीय परिस्थितियाँ दबाव में आ सकती हैं। अमेरिकी मांग और व्यापार में संभावित मंदी से उभरते बाज़ार वाली अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी-बहिर्गमन और मुद्रा-मूल्यहास हो सकते हैं।

मौद्रिक नीति के मोर्चे पर, यूएस फेड ने अपनी दिसंबर की बैठक में मासिक टेपर की मात्रा को दोगुना करके अपने आस्ति

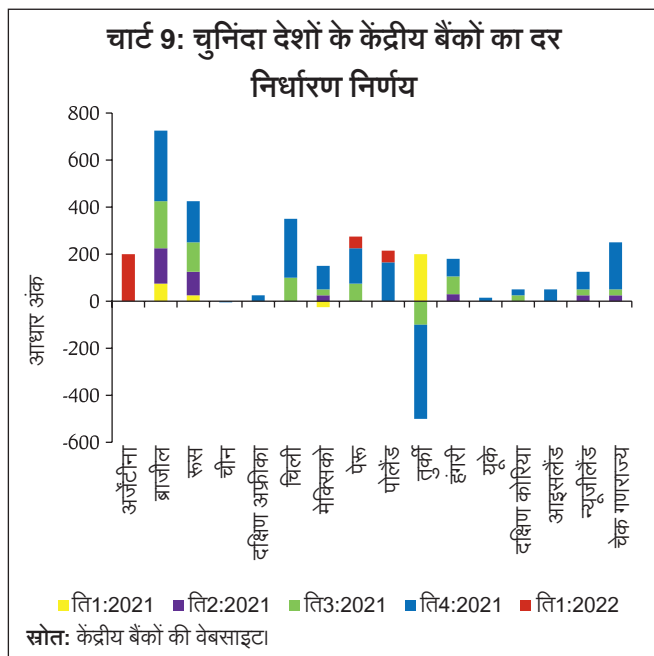
चार्ट 8: वित्तीय बाजार



खरीद कार्यक्रम में तीव्र मंदन का संकेत दिया। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 2022 की पहली तिमाही में महामारी आपातकालीन खरीद कार्यक्रम (पीईपीपी) के तहत आस्तित्व खरीद की धीमी गति और मार्च 2022 के अंत तक पीईपीपी को बंद करने की घोषणा की है। हालांकि, इसीबी 2022 की दूसरी तिमाही में संपत्ति खरीद कार्यक्रम (एपीपी) के तहत खरीद को दोगुना करेगा और धीरे-धीरे 2022 की चौथी तिमाही तक वास्तविक गति पर वापस आएगा। बैंक ऑफ जापान ने मार्च 2022 के अंत तक वाणिज्यिक पेपर और कॉरपोरेट बॉन्ड की अतिरिक्त खरीद को पूरा करने का भी संकेत दिया है और अप्रैल 2022 से, यह महामारी से पहले की खरीद की मात्रा में वापस आ जाएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड अपनी नीतिगत दर में 15 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि के साथ दर-बढ़ोतरी समूह में शामिल हो गया। रूस ने दिसंबर में दरों में सातवीं बार बढ़ोतरी की थी। पोलैंड 2022 में 4 जनवरी को 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी के साथ दरें बढ़ाने वाला पहला देश बन गया,

जो अक्टूबर 2021 में दरों में बढ़ोतरी के बाद से लगातार चौथी वृद्धि थी। पेरू, अर्जेंटीना और उरुग्वे अन्य केंद्रीय बैंक हैं जिन्होंने 2022 में अब तक (11 जनवरी तक) दरें बढ़ाई हैं। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) ने अपने 1 साल के लोन प्राइम रेट में 5 बीपीएस की कटौती की। अप्रैल 2020 के बाद से प्रमुख नीतिगत दर में यह पहली कटौती थी और इसके बाद दिसंबर में आवश्यक आरक्षित-निधि अनुपात में कमी की गई। तुर्की ने दिसंबर में लगातार चौथी बार कटौती की, जिससे सितंबर 2021 (चार्ट 9) के बाद से 500 बीपीएस की एकमुश्त कटौती हुई।

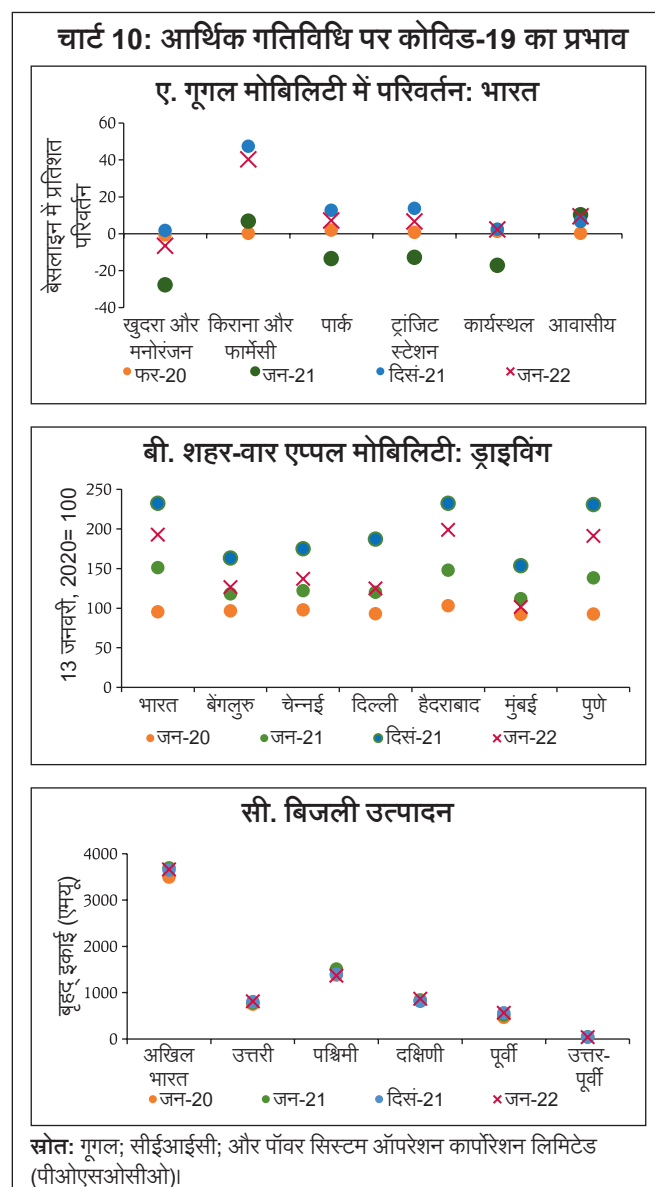
नये साल की शुरुआत में निकट भविष्य का वैश्विक दृष्टिकोण अस्पष्ट बना हुआ है। हालांकि, डेल्टा की तुलना में ओमीक्रॉन तेजी से बढ़ा लेकिन इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में तेजी से घटा है। इससे यह उम्मीद बँधी है कि ओमीक्रॉन पहली लहर की तुलना में अल्पकालिक सबित होगा।



बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को रोकना पहली प्राथमिकता होगी। हालांकि, ऐसा दृष्टिकोण भी व्यक्त किया जा रहा है कि विश्व-अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सबसे खराब दौर अभी आने वाला है। इसके कुछ कारक इस प्रकार हैं- पहला, वैश्विक खाद्य कीमतों का संयुक्त राष्ट्र सूचकांक एक दशक के उच्चतम स्तर के बाद, दिसंबर 2021 में 0.9 प्रतिशत फिसला। दूसरा, वैश्विक आपूर्ति शृंखला में गतिरोध कम हो रहा है और आगे जाकर और कम होने की उम्मीद है। तीसरा, धातु की कीमतें 2021 की दूसरी छमाही में स्थिर हो गई हैं और 2022 में घटने की संभावना है। विश्व बैंक को उम्मीद है कि मुद्रास्फीति, 2021 में बढ़ने के बाद, 2022 में भी पूर्व-महामारी के स्तर से ऊपर रहेगी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने 2021 के अंत तक मुद्रास्फीति के चरम पर पहुंचने और फिर उन स्तरों तक घटने - जो धीरे-धीरे बढ़ती श्रम लागत और दुनिया भर में घटती अतिरिक्त-उत्पादन क्षमता के अनुरूप हैं - का अनुमान लगाया था। ओईसीडी-अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 2021 की चौथी में 4.9 प्रतिशत से घटकर 2022 की चौथी तिमाही तक 3.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। चूंकि मुद्रास्फीति में कमी की उम्मीद केवल 2022 के उत्तरार्ध में ही है, इसलिए नीतिगत संतुलन जटिल होते जा रहे हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच रही है जबकि उत्पादन-अंतराल ऋणात्मक बना हुआ है।

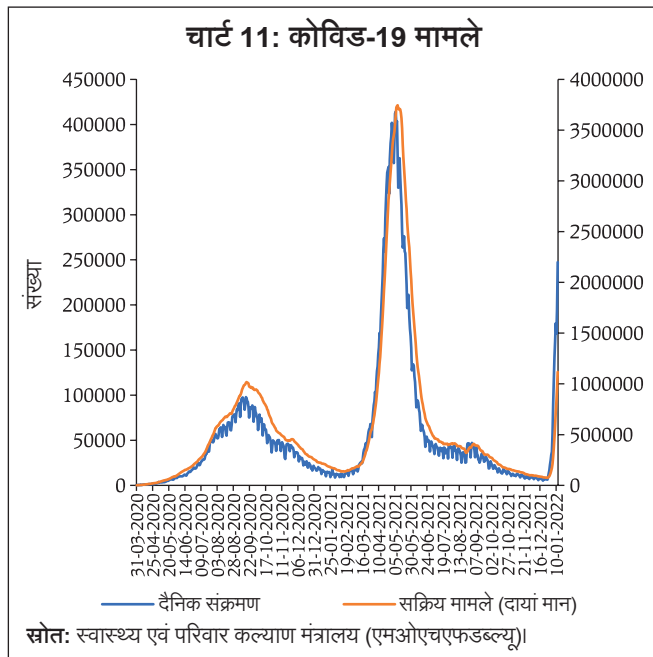
### III. घरेलू घटनाक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था में जारी सुधार को तीसरी लहर (विशेषकर ओमीक्रॉन प्रसार) के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। नतीजतन, गतिशीलता संकेतकों ने जनवरी में क्रमिक धीमापन प्रदर्शित किया। खुदरा और मनोरंजन गतिविधियों के लिए और कार्य-स्थलों के आस-पास गूगल गतिशीलता सूचकांक न्यूनतम संख्या से नीचे आ गए क्योंकि कार्यालयों ने तेजी से वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अपना ली (8 जनवरी, 2022 तक) (चार्ट 10ए)। ऐपल मोबिलिटी इंडेक्स सभी प्रमुख शहरों में

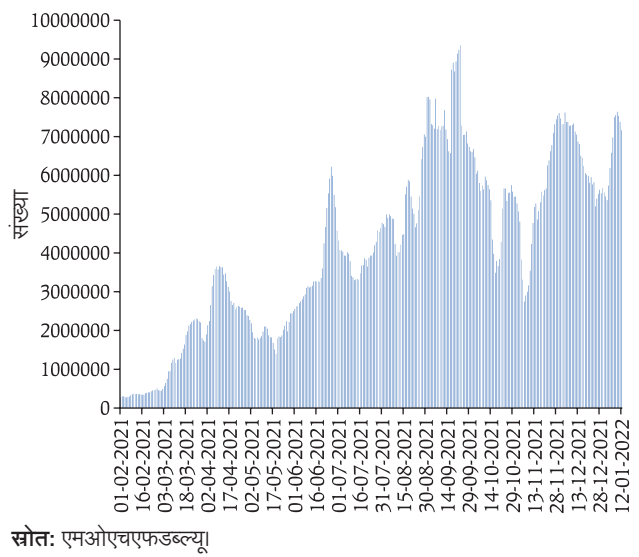


गिर गया, हालांकि यह अपने पूर्व-महामारी स्तर से ऊपर रहा (चार्ट 10बी)। जनवरी से अब तक बिजली उत्पादन में तेज हुआ है, जो महामारी से पहले के स्तर तक पहुंच गया है (चार्ट 10सी)।

13 जनवरी को दैनिक संक्रमण बढ़कर 2.71 लाख से अधिक हो गया, जो मई 2021 के मध्य के बाद से सबसे अधिक है, जिसमें सक्रिय मामलों की संख्या 15.5 लाख (चार्ट 11) थी। टीकाकरण के मोर्चे पर, भारत ने 13 जनवरी 2022 (चार्ट 12) तक 155.4 करोड़ टीका लगाकर सराहनीय प्रगति की है। 3 जनवरी 2022 से 15-18 वर्ष की आयु के किशोरों/किशोरियों के लिए टीकाकरण अभियान का विस्तार किया गया है, जिसमें उन्हें 3.15 करोड़ खुराक दी गई हैं। इसके अलावा, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए दो और टीकों को मंजूरी दी, जैसे - बायोलॉजिकल-ई का 'कॉर्बेवैक्स' और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का 'कोवोवैक्स', ताकि वैश्विक महामारी के विरुद्ध सशक्त हुआ जा सके।



**चार्ट 12: दैनिक टीकाकरण का 7-दिवसीय चल औसत**

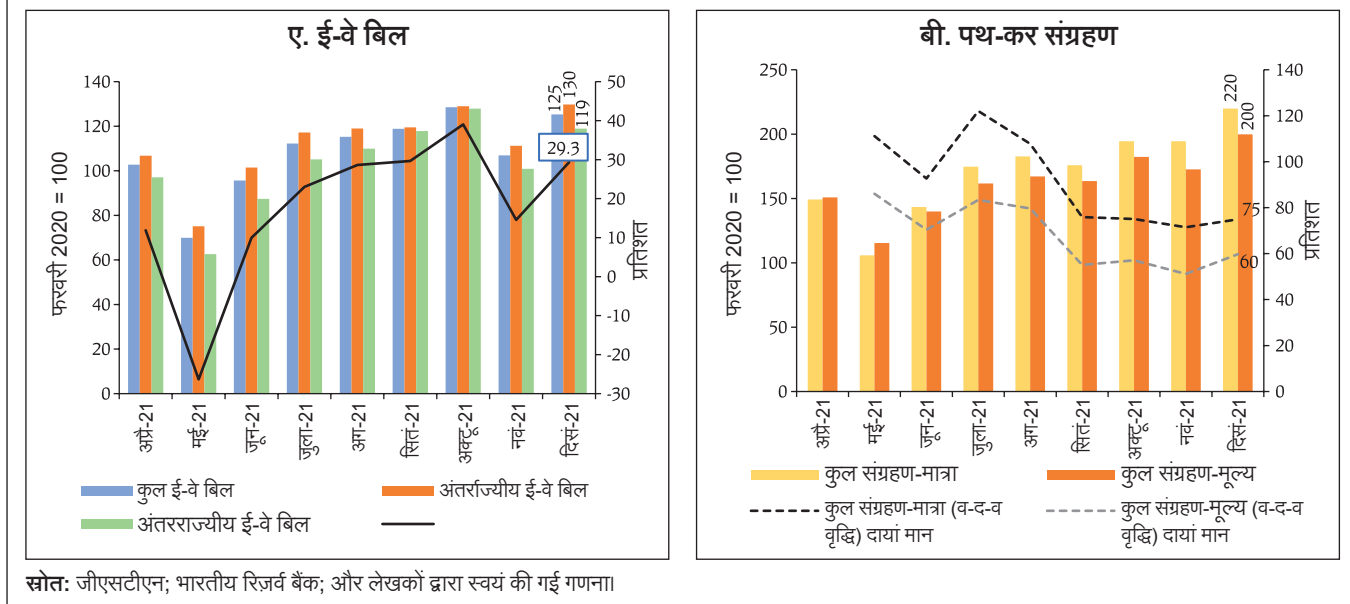


### कुल माँग

कुल माँग की स्थिति मजबूत बनी हुई है। ई-वे बिल निर्गम - माल दुलाई का एक संकेतक - दिसंबर में बढ़कर 7.2 करोड़ हो गया, जो इतिहास में दूसरी बार सर्वाधिक था (चार्ट 13ए)। यह जनवरी 2022 में माल और सेवा कर (जीएसटी) की अच्छी उगाही की संभावना का संकेत है। विनिर्माण और निर्माण में एक मजबूत बढ़त के कारण, राजमार्ग टोल उगाही में दिसंबर में माह-दर-माह 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 13बी)। दिसंबर में बिजली की खपत 4.5 फीसदी बढ़कर 110.3 बिलियन यूनिट हो गई।

दिसंबर 2021 में आवागमन में वृद्धि से ईंधन की खपत में वृद्धि हुई, पेट्रोल की खपत पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर गई। एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) और डीजल की खपत में भी क्रमिक सुधार हुआ है, हालांकि एटीएफ अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर (चार्ट 14ए) से नीचे है। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में जनवरी 2021 के बाद से धीमी वृद्धि के उलट, जनवरी की शुरुआत में कमी के संकेत दिखाई दिए।

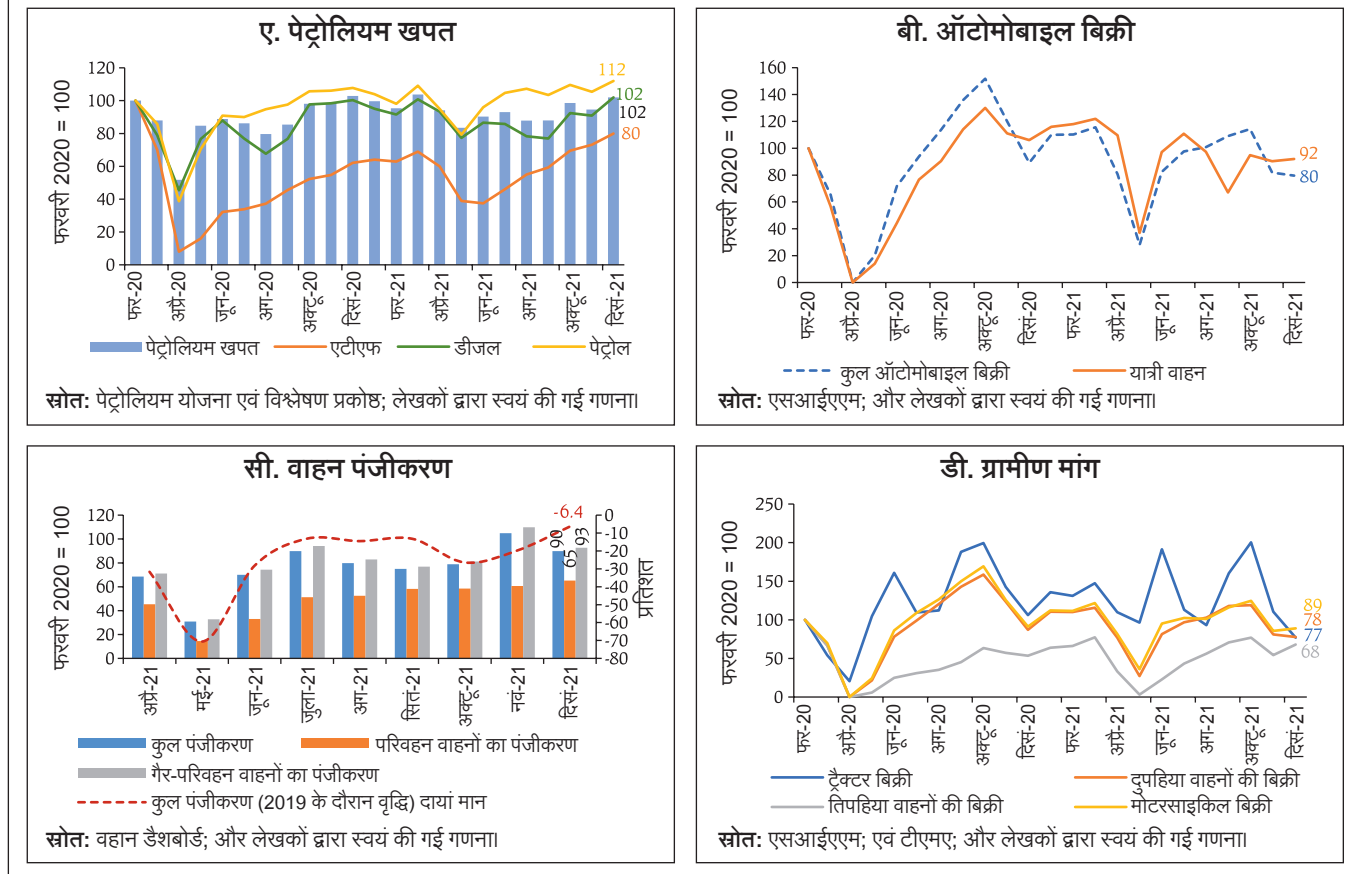
**चार्ट 13: ई-वे बिल और पथ-कर संग्रहण**



वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधानों (चार्ट 14बी) में मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर की कमी के कारण, दिसंबर 2021 में वाहन

पंजीकरण में व्यापक रूप से गिरावट आई थी। सर्वाधिक गिरावट दोपहिया वाहनों के पंजीकरण में हुई जिसमें 19.9 प्रतिशत की

**चार्ट 14: परिवहन क्षेत्र के संकेतक**



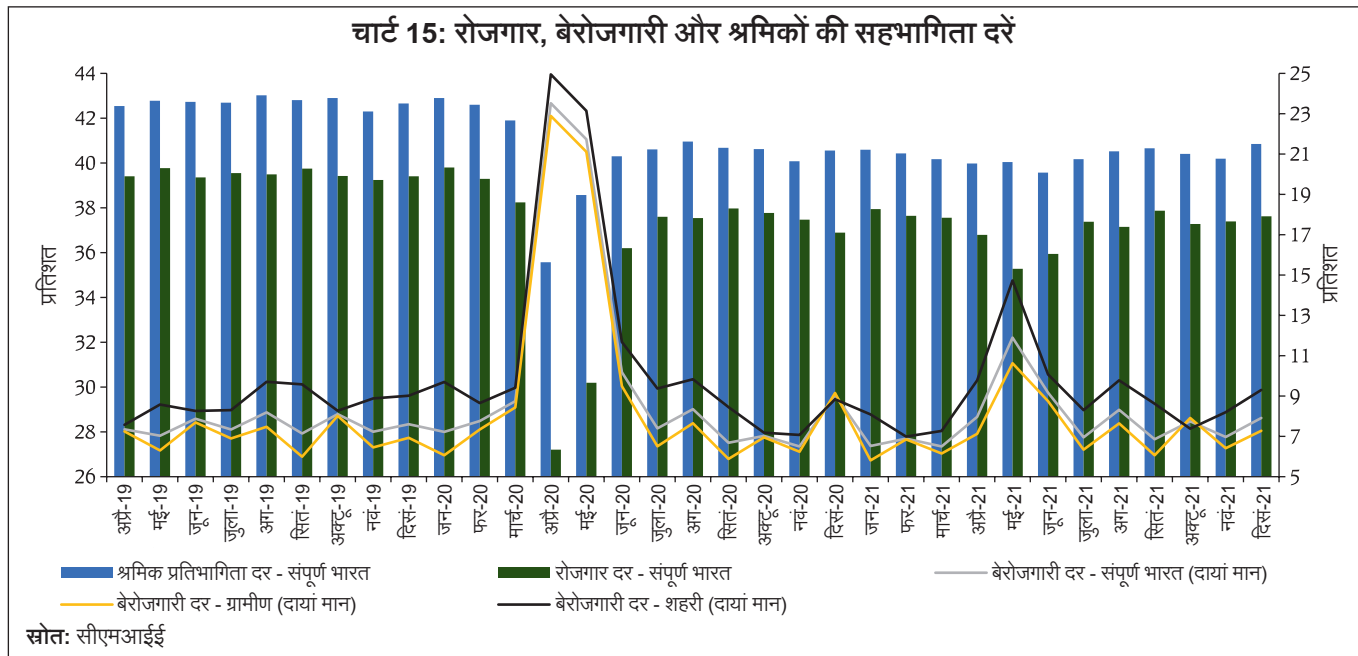
कमी देखी गई और इससे कुल पंजीकरण मात्रा में गिरावट आई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (एफएडीए) के अनुसार, उच्च स्वामित्व-लागत, सुस्त ग्रामीण रुझान और ओमीक्रॉन के हालिया खतरे के कारण दिसंबर 2021 में बिक्री घटी (चार्ट 14सी)। हालांकि, माल-भाड़ा दरों में वृद्धि के कारण वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में तेजी आई। ट्रैक्टर की बिक्री में 27.5 प्रतिशत की गिरावट, ग्रामीण मांग में गिरावट का संकेत है (चार्ट 14डी)।

उपभोक्ता का विश्वास लौटने के साथ ही, रेफनिटिव इपसॉस-प्राथमिक उपभोक्ता रुझान सूचकांक में एक महीने पहले की तुलना में दिसंबर में 2.6 प्रतिशत अंकों का सुधार हुआ। इससे व्यक्तिगत वित्त और निवेश के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई। वर्षात के दौरान समारोहों के लिए होटल बुकिंग में तेज वृद्धि हुई। कई स्थान और रिसॉर्ट पूरी तरह से भरे हुए थे<sup>2</sup> दिसंबर में तेजी से बढ़ते उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से पैकेटबंद खाद्य और अत्यावश्यक वस्तुओं की बिक्री के कारण थी<sup>3</sup> प्रधानमंत्री-किसान योजना की 10वीं किस्त के तहत ₹20,900 करोड़ निर्गत करने से ग्रामीण खपत बढ़ी। शीर्ष 7 शहरों

में, आवास की बिक्री में एक साल पहले की तुलना में 2021 में 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसका कारण दशकीय कम ब्याज दरें और बिल्डरों द्वारा आकर्षक छूट की पेशकश है<sup>4</sup>

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, दिसंबर में श्रम भागीदारी दर 40.9 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर 2020 के बाद सबसे अधिक है। रोजगार दर में भी 23 आधार अंकों का सुधार हुआ, हालांकि बेरोजगारी की दर एक महीने पहले के 7.0 प्रतिशत से दिसंबर में 7.9 प्रतिशत और खराब हो गई (चार्ट 15)। सीएमआईई द्वारा उद्योग-वार विश्लेषण इंगित करता है कि विनिर्माण, होटल, पर्यटन और शिक्षा में नौकरियां चली गईं, जबकि निर्माण, कृषि और खुदरा व्यापार में अधिक नौकरियां पैदा हुईं। सीएमआईई के रोजगार आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2021 में पहली बार नियोजित श्रमिकों की कुल संख्या 2019 के स्तर (पूर्व-महामारी) को पार कर गई (चार्ट 16)।

स्टाफ प्रदाता-टीमलीज के अनुसार, ई-कॉमर्स और संबद्ध क्षेत्रों द्वारा नियुक्तियों में 2021 में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है<sup>5</sup>

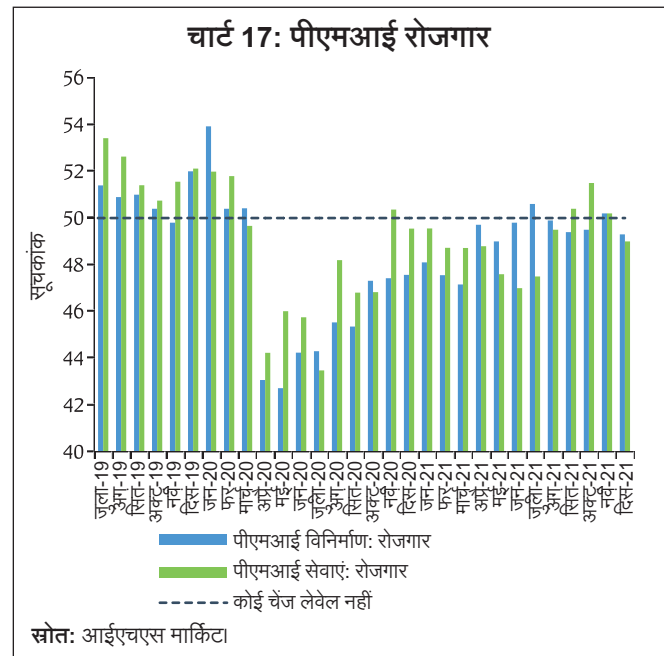
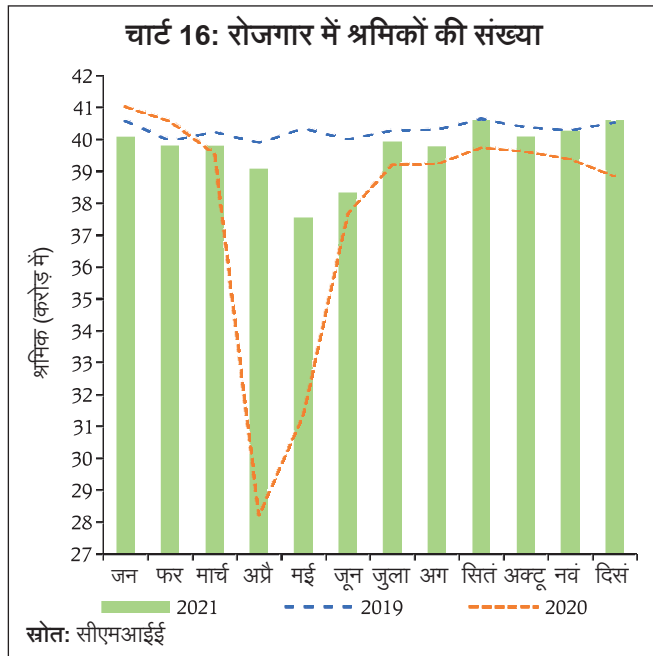


<sup>2</sup> <https://www.livemint.com/companies/news/new-year-s-eve-bookings-give-solid-boost-to-hospitality-biz-11641237663084.html>

<sup>3</sup> <https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/fmcg/packaged-foods-commodities-push-fmcg-sales-up-11/articleshow/88700894.cms>

<sup>4</sup> <https://www.thehindubusinessline.com/economy/housing-sales-in-india-rise-71-y-o-y-reach-90-of-pre-covid-levels/article38098621.ece>

<sup>5</sup> <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/e-commercehiring-surges-28-in-2021-teamlease/articleshow/88604278.cms>

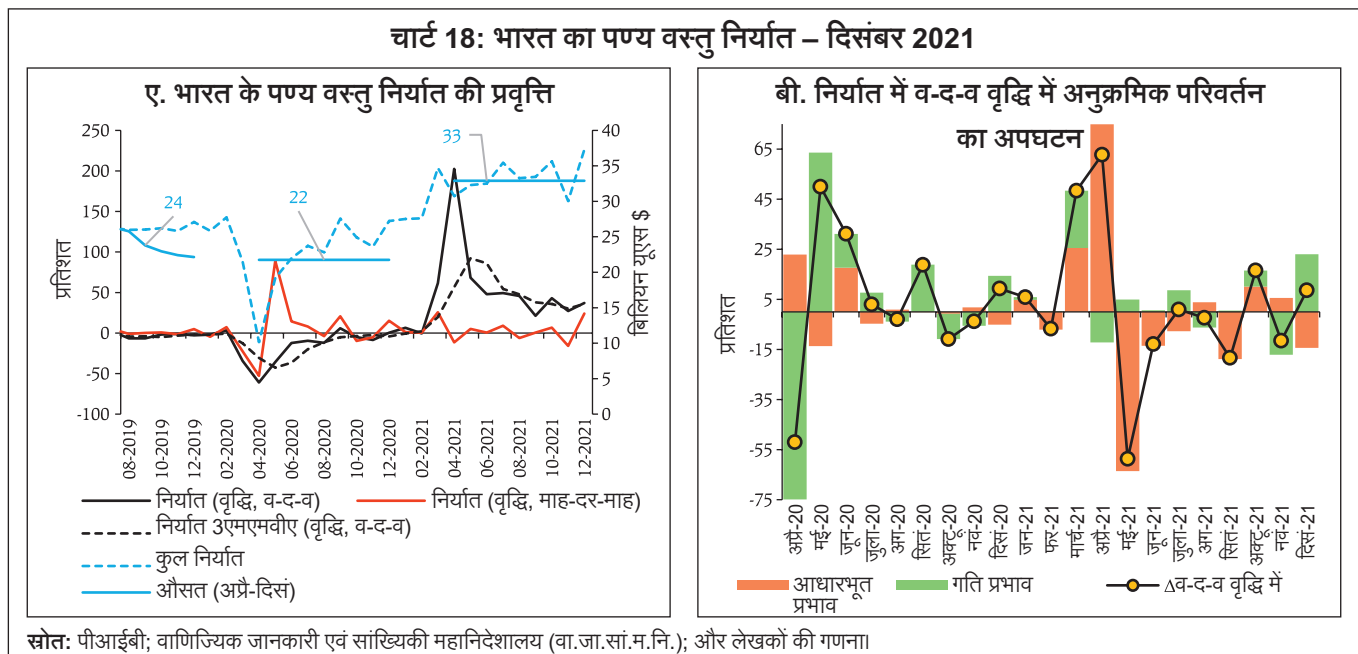


इसके विपरीत, क्रय प्रबंधकों के सूचकांक (पीएमआई) के रोजगार खंड ने दर्शाया कि विनिर्माण और सेवा, दोनों क्षेत्रों के तहत रोजगार दिसंबर 2021 में संकुचित हो गया (चार्ट 17)।

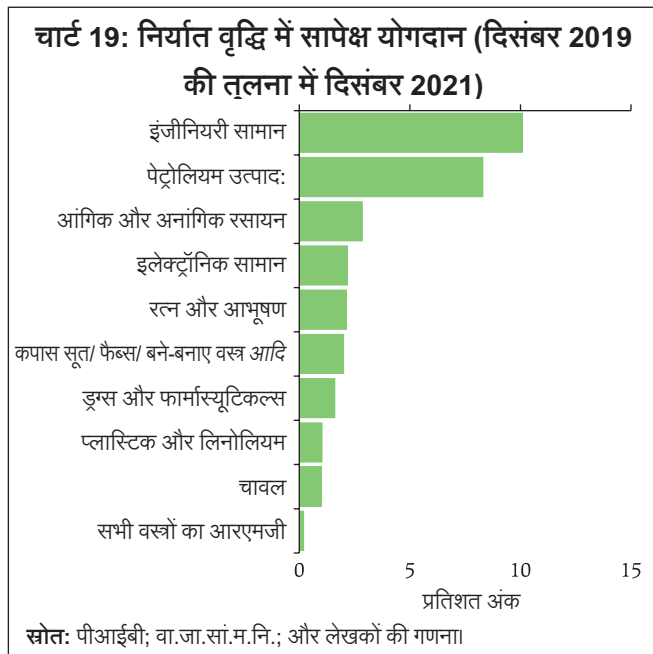
दिसंबर में 25.9 प्रतिशत का क्रमिक सुधार दर्ज करते हुए, भारत का पण्य वस्तु निर्यात 37.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया और 2021-22 के लिए

निर्धारित लक्ष्य का 75 प्रतिशत हासिल कर लिया (चार्ट 18ए और 18बी)।

निर्यात वृद्धि व्यापक-आधारित थी, जिसमें दस प्रमुख जिंस समूहों ने कुल निर्यात के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से के लिए अपने कोविड-पूर्व स्तर से ऊपर विस्तार दर्ज किया (चार्ट 19)। इंजीनियरी सामानों, पेट्रोलियम उत्पादों, रसायनों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के पोत-लदान के उच्च मूल्य से निर्यात





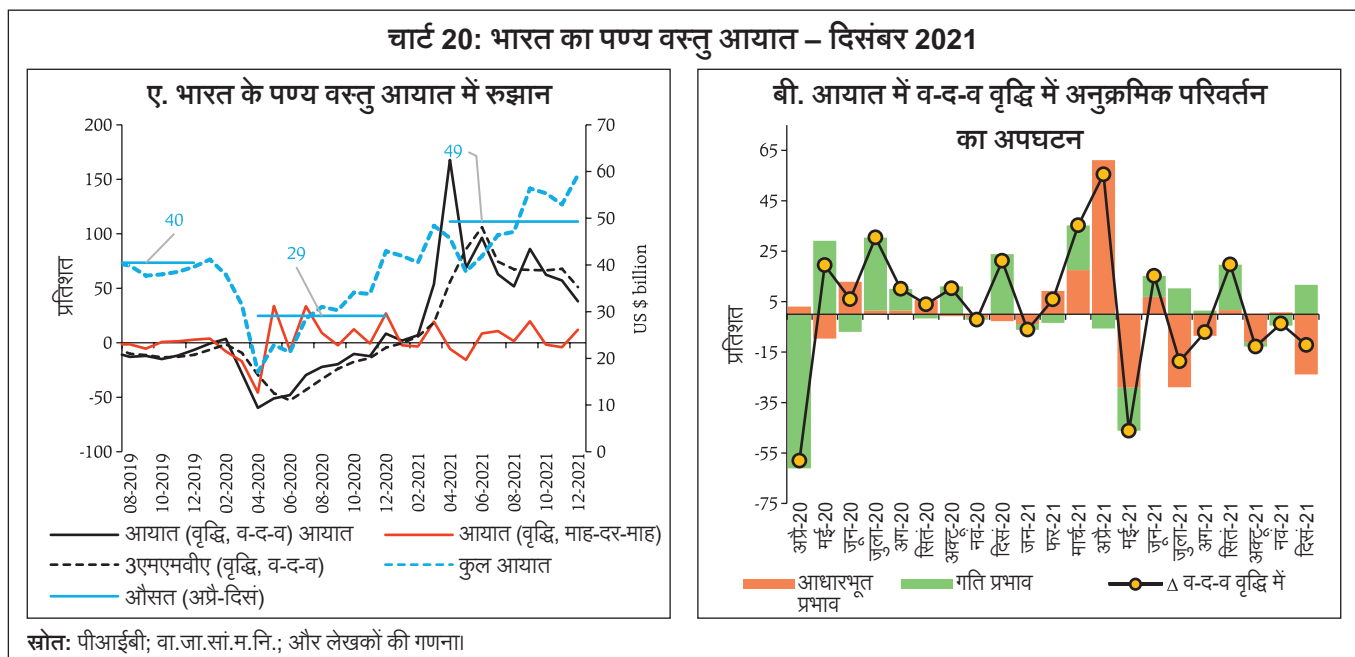


निष्पादन में सुधार आया। विशेष रूप से, वैश्विक धातु कीमतों में वृद्धि होने से इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 422.4 लाख कोविड-19 टीका खुराक के रिकॉर्ड निर्यात की सहायता से पूर्व-कोविड स्तर की तुलना में फार्मास्यूटिकल निर्यात में 23.5

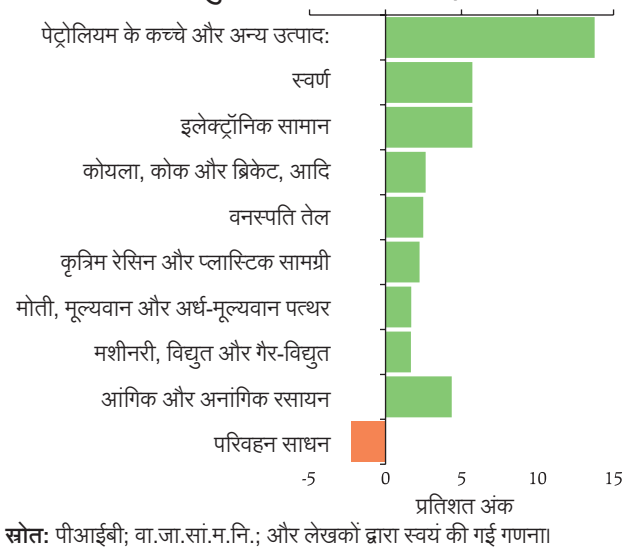
प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि निर्यात समूह का सबसे बड़ा घटक चावल है, जो महामारी-पूर्व के स्तर की तुलना में भी सुदृढ़ वृद्धि प्रदर्शित करता है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा 2022 में अनुमानित विश्व चावल व्यापार में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि भारत के चावल निर्यात के लिए अच्छी खबर है।

पण्य वस्तु आयात दिसंबर 2021 में अपने उच्चतम स्तर 59.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो लगातार चौथे महीने 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर बना रहा और घरेलू मांग की मजबूत अंतर्निहित संवेग को दर्शाता है (चार्ट 20ए और 20बी)।

सुदृढ़ आयात मांग पेट्रोलियम उत्पादों, सोने और इलेक्ट्रॉनिक सामानों से प्रेरित थी (चार्ट 21)। इसके अलावा, दस प्रमुख जिंस समूहों में से नौ 70 प्रतिशत से अधिक आयात के लिए उत्तरदायी थे और उन्होंने कोविड-पूर्व स्तर की तुलना में अधिक विस्तार दर्ज किया, जो व्यापक-आधारित मांग में वृद्धि को दर्शाता है। दिसंबर 2021 में 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सोने का आयात पूर्व-सीओवीआईडी अवधि की तुलना में 91.7 प्रतिशत बढ़ा। अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 720.3 टन के साथ भारत पहले ही पिछले पांच वर्षों की औसत वार्षिक आयात मात्रा का 88.1 प्रतिशत आयात कर चुका है।



**चार्ट 21: आयात वृद्धि में सापेक्ष योगदान (दिसंबर 2019 की तुलना में दिसंबर 2021)**

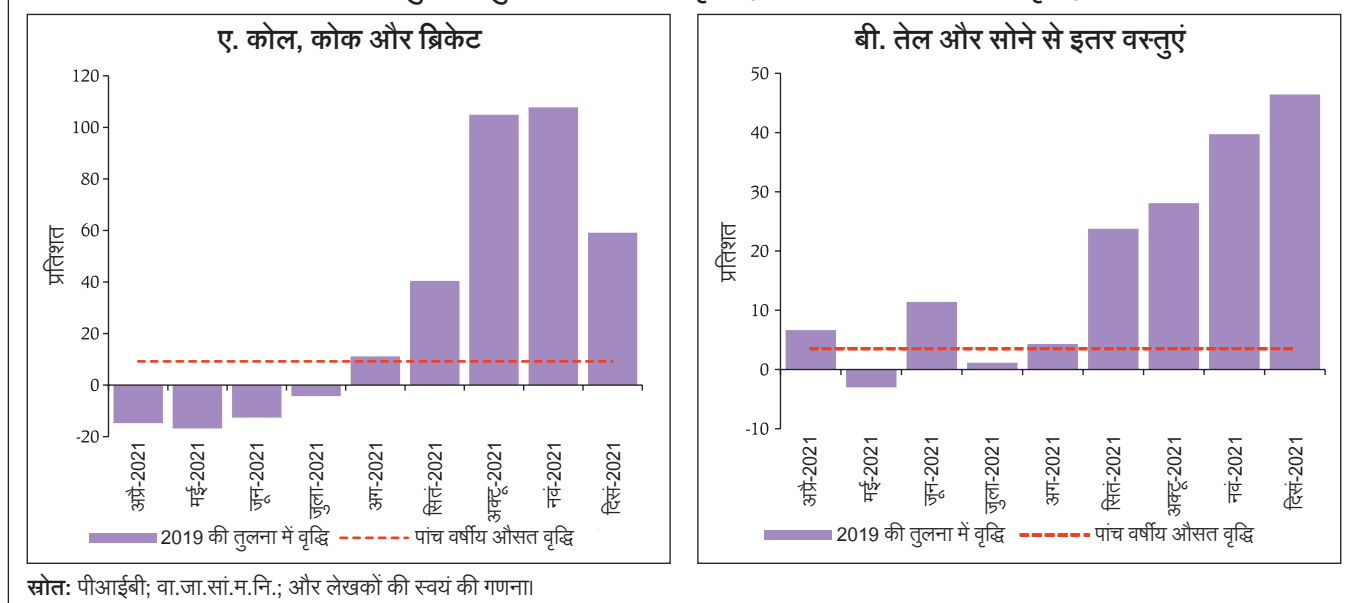


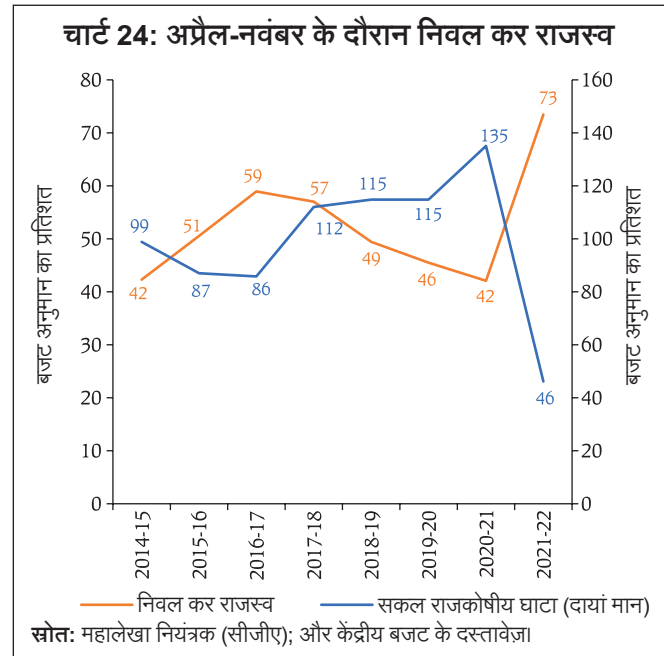
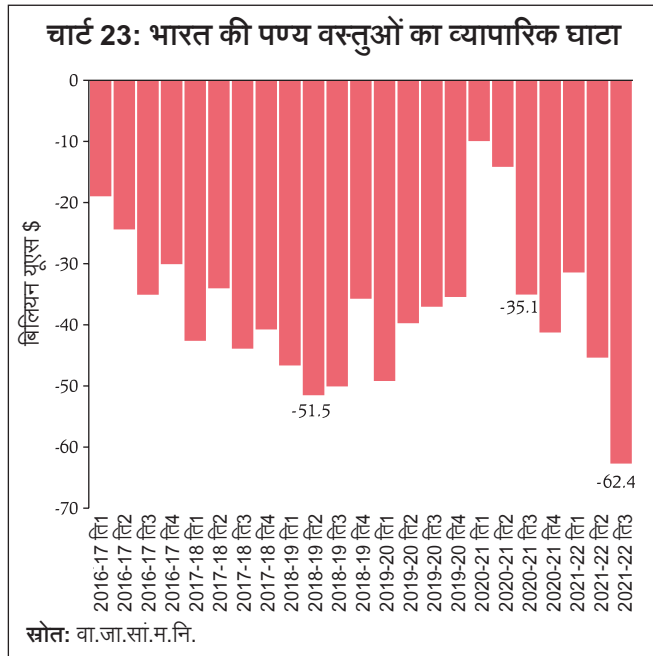
दिसंबर 2021 के दौरान कोयले, कोक और ब्रिकेट के आयात में क्रमिक गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 22ए)। समग्र रूप से तेल और सोने से इतर वस्तुओं के आयात में दिसंबर में लगातार सातवें महीने महामारी-पूर्व स्तर पर मजबूत वृद्धि बनी रही (चार्ट 22बी)।

नवंबर 2021 में 22.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च मासिक व्यापार घाटे के बाद, दिसंबर 2021 में व्यापार घाटा कम होकर 21.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तिमाही आधार पर, 2021-22 की तीसरी तिमाही के दौरान व्यापार घाटा 62.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। (चार्ट 23)।

केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति में सुधार जारी रहा, जिसमें निवल कर राजस्व, बजट अनुमान (बीई) के 73.5 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था और सकल राजकोषीय घाटे में अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान बजट अनुमान के 46.2 प्रतिशत तक की कमी आ गई, जिसकी तुलना में पहले पांच वर्षों का औसत क्रमशः 50.6 प्रतिशत और 112.5 प्रतिशत था (चार्ट 24)। व्यय के पहलू पर, पूंजीगत व्यय में 13.5 प्रतिशत का सुधार हुआ, जबकि राजस्व व्यय में 2020-21 की तुलना में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अपने बजटीय पूंजीगत व्यय के 68.3 प्रतिशत हिस्से का उपयोग करने से पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई। बजट अनुमान के प्रतिशत के अनुसार, हालांकि अप्रैल-नवंबर 2021-22 के दौरान राजस्व और पूंजीगत व्यय, दोनों प्रवृत्ति से कम हैं।

**चार्ट 22: प्रमुख वस्तुओं के आयात में वृद्धि (2019 के स्तर से अधिक वृद्धि)**

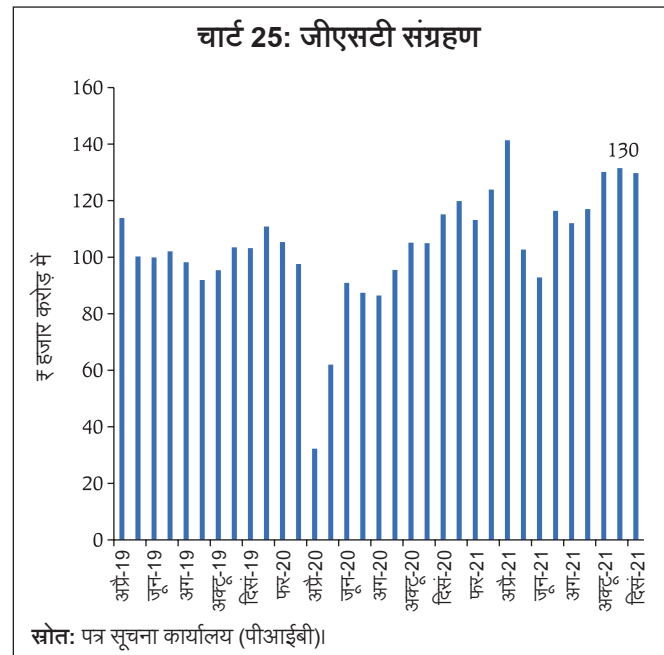




यदि 2021-22 के बजट अनुमान और अनुदान की दो अनुपूरक मांगों में निहित व्यय प्रस्तावों को स्वीकार किया जाता है, तो कुल मांग को बढ़ावा देते हुए ब्याज भुगतान घटाकर राजस्व व्यय और प्रमुख सब्सिडी (सरकार के अंतिम उपभोग व्यय का एक संकेतक) 2020-21 की तुलना में 29.0 प्रतिशत (2019-20 की तुलना में 70.3 प्रतिशत) तक बढ़ सकता है। बढ़े हुए व्यय की आंशिक रूप से कर संग्रह में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार को उच्चतर सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद से भी लाभ होगा, जो कि 2021-22 के बजट अनुमानों के लिए की गई ₹222.87 लाख करोड़ की पूर्वधारणा की तुलना में ₹232.15 लाख करोड़ है।

जीएसटी संग्रहण के अंतर्गत दिसंबर 2021 में 12.7 प्रतिशत की व-द-व वृद्धि दर्ज की (चार्ट 25)। 2021-22 की तीसरी तिमाही में ₹3.9 लाख करोड़ का तिमाही जीएसटी संग्रह हुआ, जो कि जीएसटी की शुरुआत के बाद से अभी तक का उच्चतम दर्ज संग्रह है। यह अनुपालन में सुधार के लिए विभिन्न नीतिगत और प्रशासनिक उपायों का परिणाम है और संभवतः जीएसटी व्यवस्था होने के अंतर्निहित लाभों को प्रदर्शित करेगा।

राज्य वित्त ने महामारी-पूर्व के स्तर से अधिक राजस्व प्राप्ति के साथ महत्वपूर्ण सुधार दर्शाया है। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान राज्यों की कर और कर-रहित प्राप्तियों में क्रमशः 29.2 प्रतिशत और 53.8 प्रतिशत की व-द-व वृद्धि दर्ज की गई। राज्यों के सभी प्रमुख कर शीर्षों ने 2019-20 के स्तर को पार कर लिया



है और अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान उच्च वृद्धि आयी है। विशेष रूप से, राज्यों के जीएसटी राजस्व और बिक्री कर संग्रह में क्रमशः 35.2 प्रतिशत और 37.3 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि देखी गई है। नवंबर 2021 तक राज्यों ने 2018-19 के बाद से पिछली प्रवृत्ति की तुलना में अपनी बजटीय राजस्व प्राप्तियों का अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा संग्रहित किया है (चार्ट 26ए)।

व्यय में अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान राज्यों के राजस्व व्यय में 12.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि महामारी-पूर्व वर्ष 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में 9.0 प्रतिशत अधिक है (चार्ट 26बी)। व्यय की गुणवत्ता में भी सुधार देखा गया है, जो अप्रैल-नवंबर 2021 में राज्यों के पूंजीगत व्यय में 67.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए परिलक्षित होता है (चार्ट 26सी)। पूंजीगत व्यय पर जोर एक स्थायी विकास पुनरुद्धार के लिए शुभ संकेत है। कुल मिलाकर, राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा अधिकांश

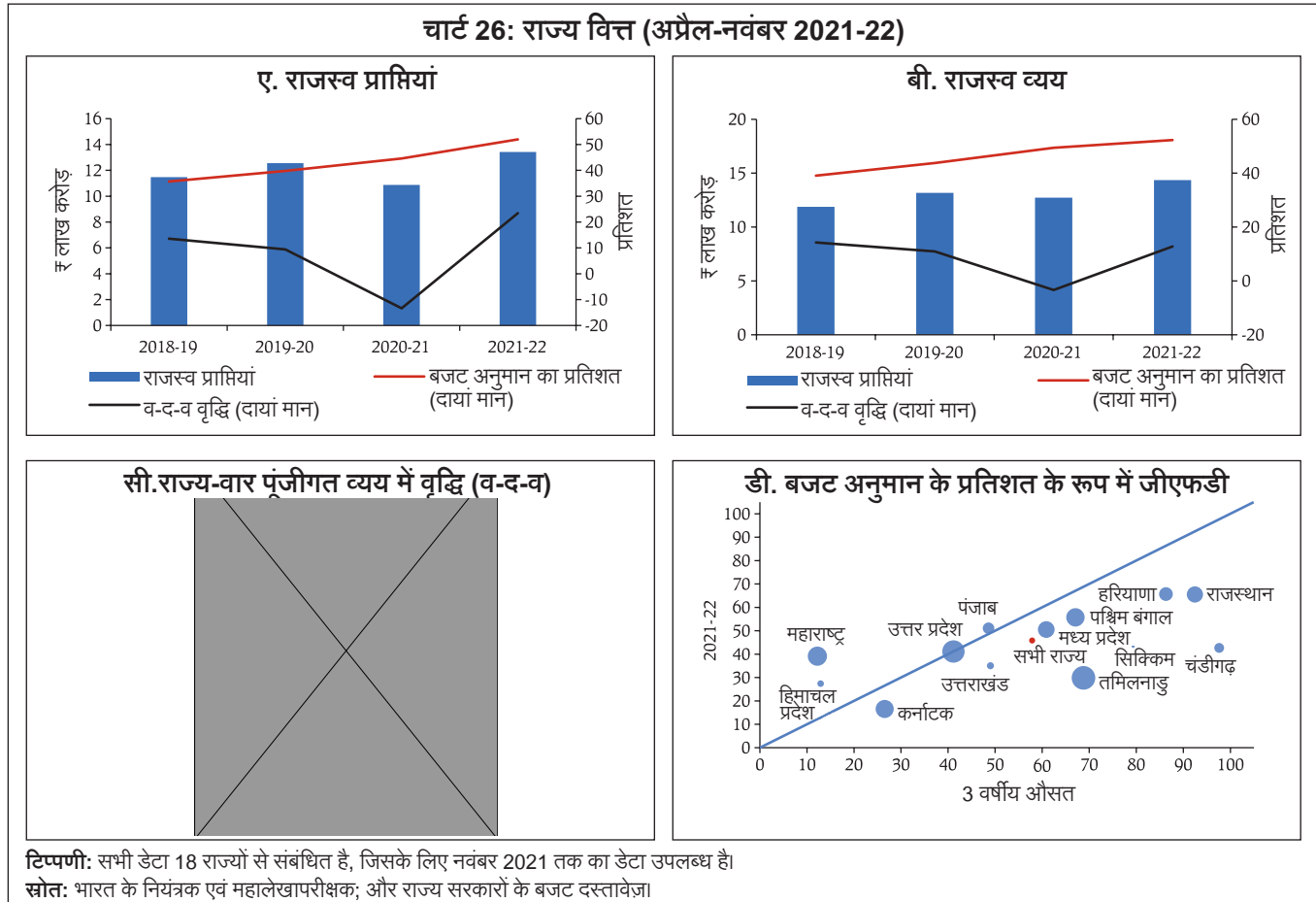
राज्यों के बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में तेजी से कम हुआ है, जो बेहतर वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है (चार्ट 26डी)।

### समग्र आपूर्ति

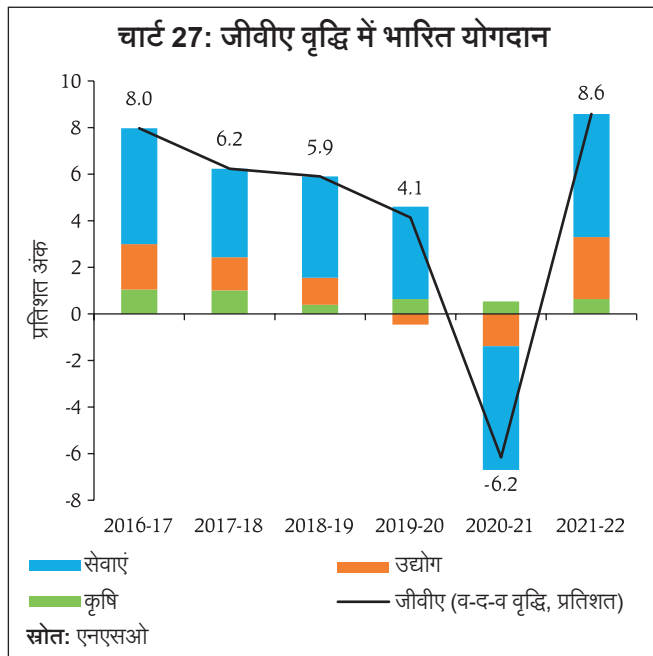
आपूर्ति पक्ष पर, मूल कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) द्वारा मापी गई कुल आपूर्ति 2021-22 में 8.6 प्रतिशत<sup>6</sup> की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले यह 6.2 प्रतिशत के संकुचन पर थी। कृषि में सुदृढ़ वृद्धि और साथ-साथ उद्योग में और सेवा क्षेत्र के कई घटकों में सुधार के साथ से जीवीए वृद्धि में तेजी आयी यद्यपि यह अनुकूल आधार पर थी (चार्ट 27)।

फिर से भरे हुए जलाशय स्तर (चार्ट 28ए) और स्थानिक और अस्थायी रूप से अच्छी तरह से वितरित उत्तर-पूर्व (एनई) मानसून वर्षा द्वारा समर्थित, अब तक 664.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को रबी बुवाई के तहत कवर किया गया है, जो पूरे मौसम के

चार्ट 26: राज्य वित्त (अप्रैल-नवंबर 2021-22)



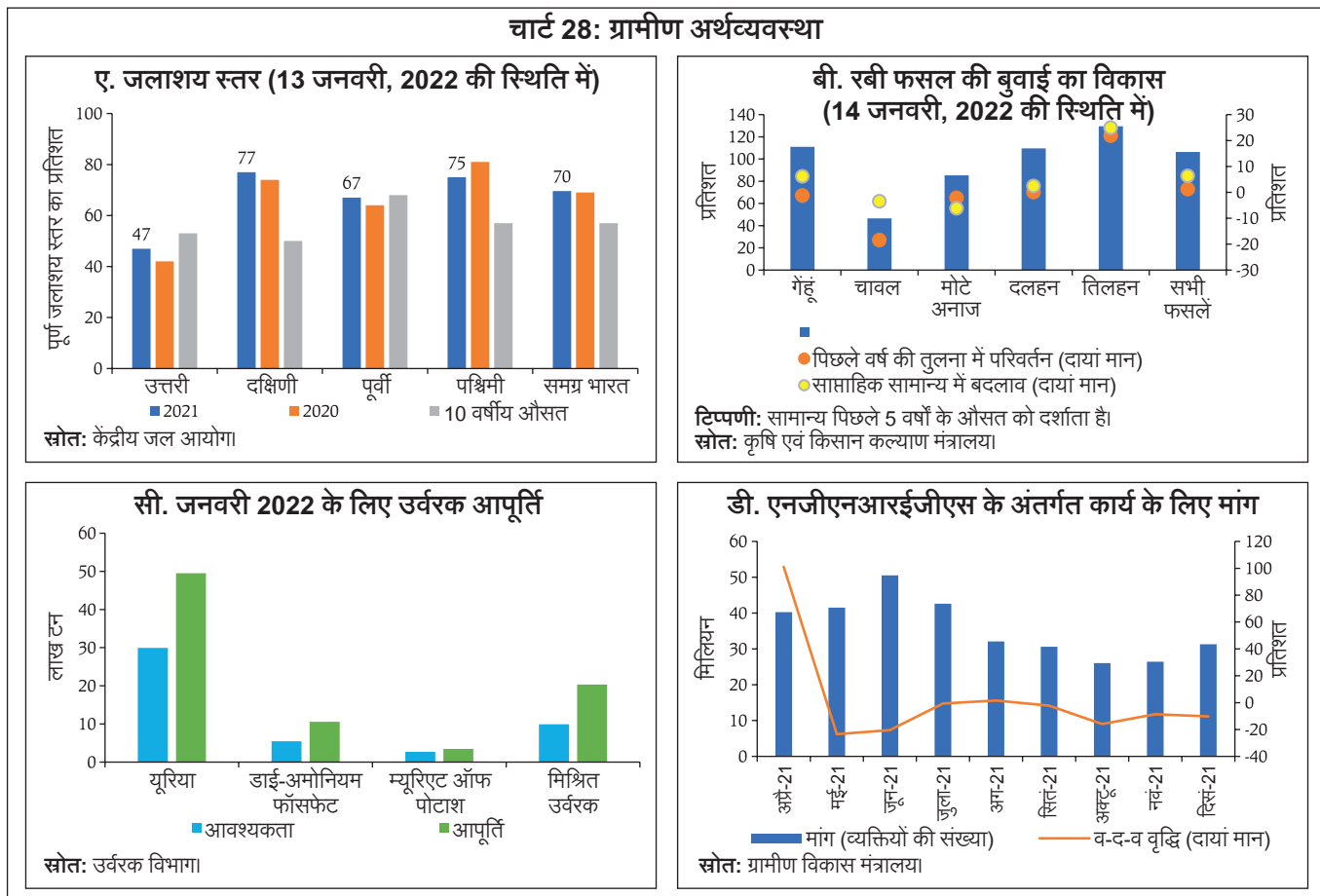
<sup>6</sup> यह एनएसओ द्वारा 7 जनवरी, 2022 को जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार है।



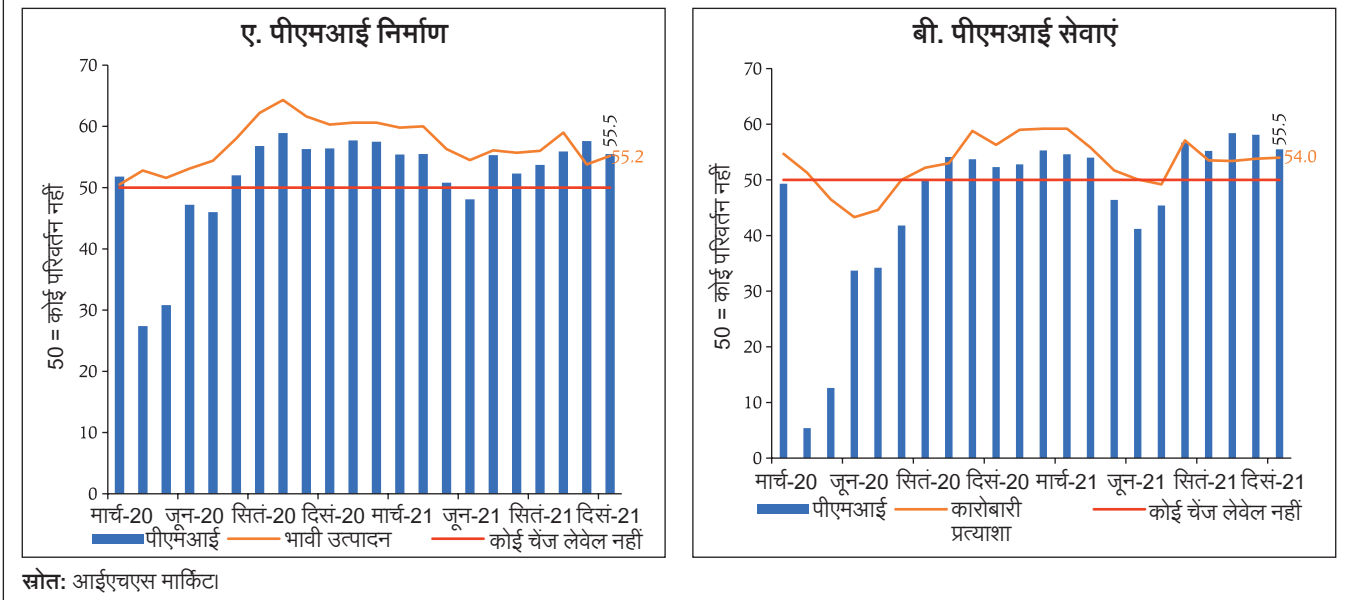
क्षेत्र से 46.9 प्रतिशत अधिक रहा, जो सरकार द्वारा मूल्य आश्वासन के रूप में दिए गए प्रोत्साहन को दर्शाता है (चार्ट 28बी)। 14 जनवरी 2022 तक, तिलहन के तहत बोए जाने वाले क्षेत्र में पिछले वर्ष (21.8 प्रतिशत) की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि गेहूं, चावल और मोटे अनाज के बुवाई क्षेत्रफल में कमी आयी। प्रमुख उर्वरकों की आपूर्ति के पिछले वर्ष के स्तर से कम रहने के बावजूद, (12 जनवरी, 2022 तक) मासिक उपलब्धता आवश्यक स्तरों की तुलना में अधिक थी (चार्ट 28सी)। ग्रामीण पशुभूमि में चल रही रबी की बुवाई से उत्पन्न रोजगार को दर्शाते हुए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम की मांग दिसंबर 2021 में लगातार चौथे महीने में घट गई (चार्ट 28डी)।

सामान्य रबी क्षेत्रफल का 106.3 प्रतिशत है। विशेष रूप से, सफेद सरसों और सरसों के तिलहन का क्षेत्रफल पूरे मौसम के सामान्य

12 जनवरी की स्थिति के अनुसार, चावल की 37.3 मिलियन टन (खरीफ विपणन मौसम 2021-22) संचयी खरीद पिछले वर्ष (36.3 मिलियन टन) के स्तर से अधिक थी। त्रैमासिक



**चार्ट 29: क्रय प्रबंधक सूचकांक**

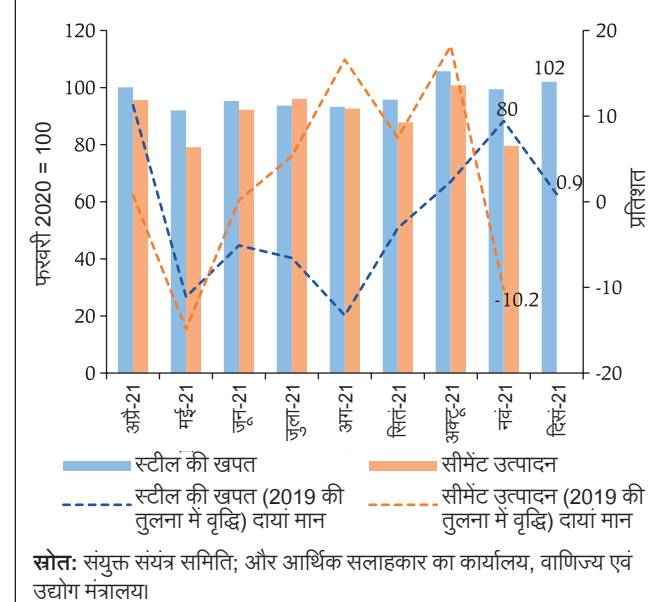


सुरक्षित भंडार मानदंडों (जनवरी-मार्च) के अनुसार, चावल और गेहूं दोनों के लिए पर्याप्त स्टॉक स्तर (क्रमशः 7.1 और 2.4 गुना) बना रहा। 20 दिसंबर, 2021 को मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने के लिए नीतिगत उपायों के रूप में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक साल की अवधि के लिए सभी पण्य बाजारों में धान (गैर-बासमती), गेहूं, चना, मूंग, सोयाबीन, सरसों के बीज और ताड़ के कच्चे तेल में डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर रोक लगा दी।

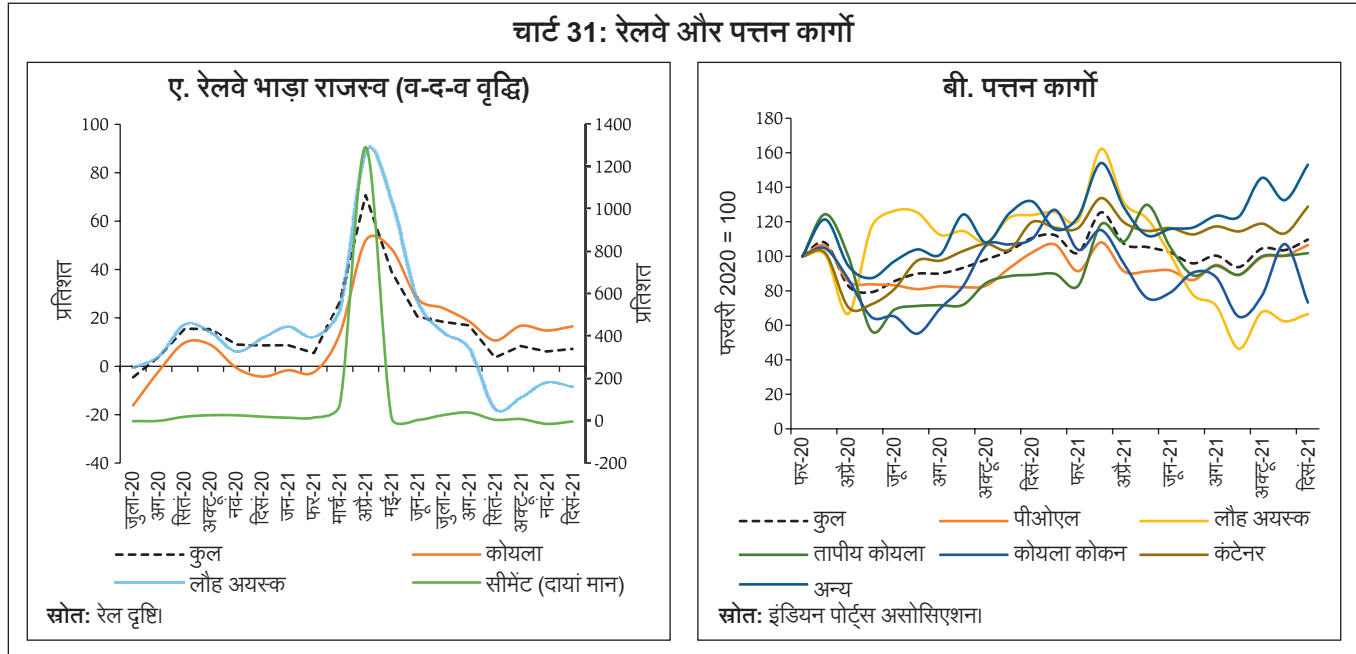
औद्योगिक क्षेत्र में, हेडलाइन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में विस्तार बना रहा और दिसंबर 2021 में 55.5 पर रहा। हालांकि, उत्पादन में गिरावट, खरीद के स्टॉक और नए ऑर्डर के कारण नवंबर में यह 57.6 के स्तर से कम हो गया। दिसंबर में भारत का कोयला उत्पादन बढ़कर 74.8 मिलियन टन हो गया, जो इसके महामारी-पूर्व के स्तर से 6.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। सेवा क्षेत्र का पीएमआई लगातार पांचवें महीने विस्तार दर्ज करते हुए दिसंबर में 55.5 रहा। सेवाओं के लिए कारोबारी प्रत्याशा सूचकांक (बीईआई) नवंबर 2021 में 53.8 से बढ़ कर दिसंबर 2021 में 54.0 हो गया (चार्ट 29)।

हालिया महीनों में निर्माण गतिविधि में कमी आयी है, जैसा कि इसके अनुकूल संकेतकों के निष्पादन से स्पष्ट है। दिसंबर में इस्पात की खपत में गिरावट जारी रही, हालांकि इसका मुख्य कारण ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कम मांग था। नवंबर 2021 में पिछले दस महीनों में पहली बार सीमेंट उत्पादन में कमी आयी है, जो मांग में कमी को दर्शाता है (चार्ट 30)।

**चार्ट 30: निर्माण क्षेत्र के संकेतक**



**चार्ट 31: रेलवे और पत्तन कार्गो**



सेवा क्षेत्र में, रेलवे माल यातायात दिसंबर में बढ़कर 7.2 प्रतिशत हो गया, जो पिछले महीने में 6.3 प्रतिशत थी (चार्ट 31ए)। जैसे ही पोत-परिवहन बाधाएं और कंटेनर की कमी विश्व स्तर पर कम हुई, दिसंबर 2021 में भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात क्रमिक रूप से बढ़ा। एक साल पहले, लौह अयस्क और कोकिंग कोल कार्गो में गिरावट के कारण कार्गो यातायात में 0.8 प्रतिशत की मामूली कमी आयी थी (चार्ट 31बी)।

विमानन क्षेत्र में यात्री और कार्गो यातायात, दोनों ने अगस्त 2021 के बाद से धीरे-धीरे सुधार का प्रदर्शन किया है, नवंबर 2021 में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कार्गो भाड़ा, दोनों सामान्य हो गए हैं। त्योहारी मौसम के दौरान यात्रा करने से यात्री यातायात में भी तेजी आयी। ओमीक्रॉन के हालिया खतरे के मद्देनजर, नए यात्रा दिशानिर्देश इस क्षेत्र के विकास में बाधा बन सकते हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में दैनिक घरेलू हवाई अड्डे पर यात्रियों

की संख्या<sup>7</sup>, औसतन 6.4 लाख प्रति दिन थी, जो दिसंबर में इसी सप्ताह की तुलना में 7.9 प्रतिशत कम है। अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों की संख्या में भी क्रमिक रूप से 7.2 प्रतिशत की गिरावट आयी है। कार्गो क्षेत्र ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कार्गो के लिए क्रमशः 23.7 और 21.6 प्रतिशत के दोहरे अंकों में संकुचन दर्ज किया, क्योंकि हवाई कंपनियों ने कोविड-19 संक्रमणों की बढ़ती संख्या के कारण उड़ानों को रद्द या पुनर्निर्धारित किया।

व्यापार, होटल, परिवहन संचार और जीएसटी ई-वे बिल के निष्पादन में सुधार हुआ (सारणी 2)। डिजिटलीकरण की तीव्र गति और फर्मों द्वारा उच्च विवेकगत व्यय द्वारा 2021-22 की तीसरी तिमाही में आईटी क्षेत्र का बेहतर निष्पादन हुआ था<sup>8</sup>

<sup>7</sup> इसमें प्रस्थान करने वाले और आने वाले, दोनों यात्री शामिल हैं।

<sup>8</sup> [https://www.business-standard.com/article/companies/infosys-to-hcl-tech-it-firms-to-see-strong-q3-despite-seasonal-quirks-122010400072\\_1.html](https://www.business-standard.com/article/companies/infosys-to-hcl-tech-it-firms-to-see-strong-q3-despite-seasonal-quirks-122010400072_1.html)

## सारणी 2: उच्च आवृत्ति वाले संकेतक- सेवा क्षेत्र

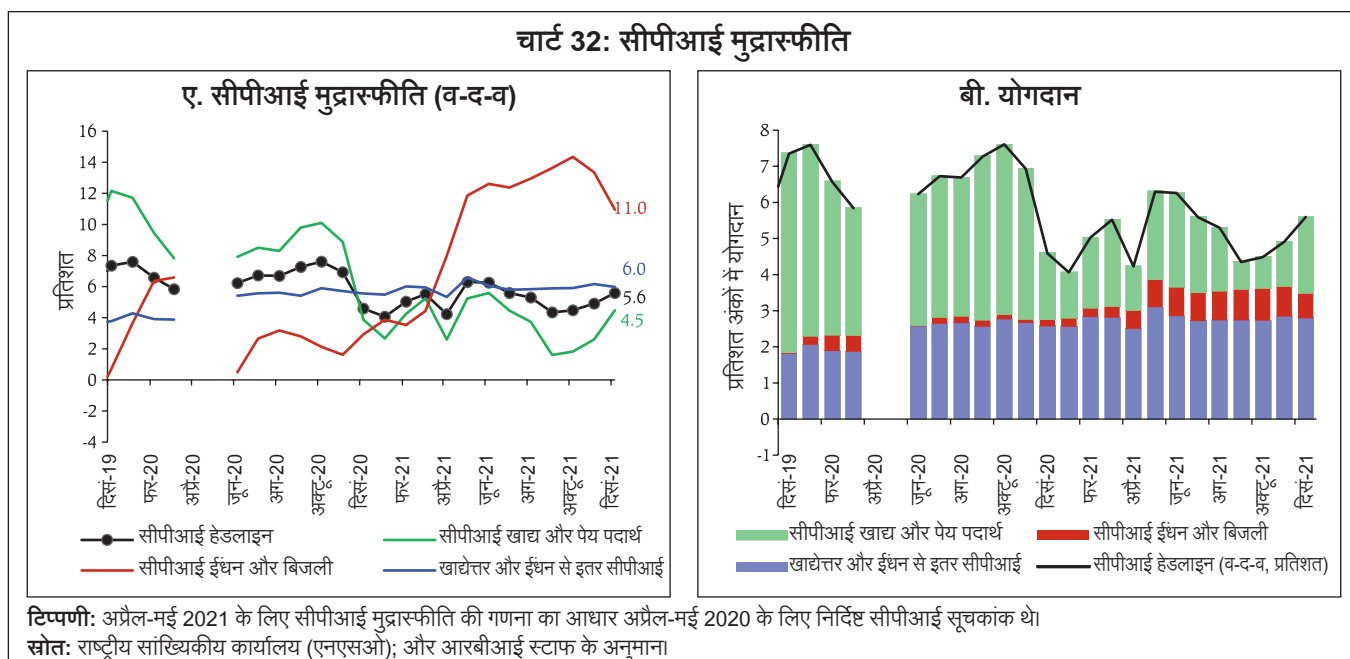
क्षेत्र	संकेतक	उच्च आवृत्ति वाले संकेतक- सेवा क्षेत्र वृद्धि (व-द-व, प्रतिशत)					2019 की तुलना में वृद्धि					
		अग-21	सितं-21	अक्तू-21	नव-21	दिसं-21	अग 21/ अग 19	सितं 21/ सितं 19	अक्तू 21/ अक्तू 19	नव 21/ नव 19	दिसं 21/ दिसं 19	
शहरी मांग	यात्री वाहनों की बिक्री	7.6	-41.2	-27.1	-18.6	-13.3	22.8	-25.6	-16.7	-14.8	-1.5	
	दुपहिया वाहनों की बिक्री	-14.6	-17.4	-24.9	-34.4	-10.8	-12.1	-7.7	-12.3	-25.5	-4.2	
ग्रामीण मांग	तिपहिया वाहनों की बिक्री	59.7	53.8	19.1	-6.6	25.1	-60.5	-56.0	-52.6	-59.7	-47.7	
	ट्रैक्टर की बिक्री	-17.0	-14.8	0.4	-22.5	-27.5	45.0	9.3	8.2	17.2	3.8	
व्यापार, रेस्तरां, परिवहन, संचार	वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री	24.5		0.9			0.6			-0.3		
	रेलवे माल यातायात	16.9	3.6	8.4	6.1	7.2	21.5	19.7	25.1	15.6	16.5	
	पोट कार्गो यातायात	11.5	0.5	6.3	-0.2	-0.8	-0.1	-1.4	5.3	2.7	3.5	
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	35.7	10.1	6.7	-1.7		-13.1	-11.8	-10.0	-11.4		
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	25.8	18.1	23.8	11.7		-5.5	2.0	8.4	-5.0		
	घरेलू हवाई यात्री यातायात	132.6	76.5	68.7	65.5		-43.8	-38.4	-27.0	-17.6		
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	119.2	155.9	162.9	140.2		-77.5	-68.9	-61.0	-58.6		
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	33.3	18.3	14.5	5.9	11.6	28.6	29.6	39.0	14.5	29.3	
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतर्राज्यीय)	30.8	15.6	14.1	7.3	13.4	32.7	33.0	40.7	17.6	33.0	
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतरराज्यीय)	37.2	22.3	15.1	3.9	8.9	22.9	25.0	36.7	10.1	24.0	
	पर्यटकों का आगमन	329.9	278.8	337.0	255.0		-89.4	-85.8	-80.8	-76.9		
	निर्माण	इस्पात की खपत	-2.2	-3.2	-3.8	-7.7	-14.1	-13.3	-3.1	2.4	9.4	0.9
		सीमेंट उत्पादन	36.3	10.8	14.5	-3.2		16.6	7.5	18.3	-10.2	
पीएमआई सूचकांक	विनिर्माण	52.3	53.7	55.9	57.6	55.5						
	सेवाएं	56.7	55.2	58.4	58.1	55.5						

स्रोत: सीएमआईई; सीआईसी डेटा; आईएचएस मार्किट; एसआईएम; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और संयुक्त संघर्ष समिति।

## मुद्रास्फीति

दिसंबर 2021 के महीने के लिए हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) एक महीने पहले के 4.9 प्रतिशत से

बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गई (चार्ट 32ए)। लगभग एक प्रतिशत अंक के एक बड़े प्रतिकूल आधारभूत प्रभाव (एक वर्ष पहले कीमतों में माह-दर-माह परिवर्तन) के माध्यम से लगभग 35 आधार अंकों द्वारा





गति में एक स्वागत योग्य गिरावट (चालू महीने में कीमतों में महीने-दर-महीने परिवर्तन) की भरपाई की गई। जिसके परिणामस्वरूप नवंबर और दिसंबर के बीच हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 70 आधार अंकों की वृद्धि हुई। सीपीआई खाद्य समूह, विशेष रूप से सब्जियां, हेडलाइन सीपीआई गति में गिरावट का प्रमुख चालक था। इसे प्रतिकूल आधारभूत-प्रभावों का भी सामना करना पड़ा।

दिसंबर में खाद्य और पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गई जो कि नवंबर में 2.6 प्रतिशत थी, जिसका मुख्य कारण लगभग 2.7 प्रतिशत अंकों का प्रतिकूल आधारभूत प्रभाव था। अनाज, अंडे, दूध और तैयार खाद्यों की मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। दूसरी ओर मांस और मछली, तेल और वसा, फल, दालें, चीनी और मिष्ठान्न, मसाले और गैर-मादक पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति सामान्य हुई। दिसंबर में सब्जियों की कीमतों की अवस्फीति में काफी कमी आयी।

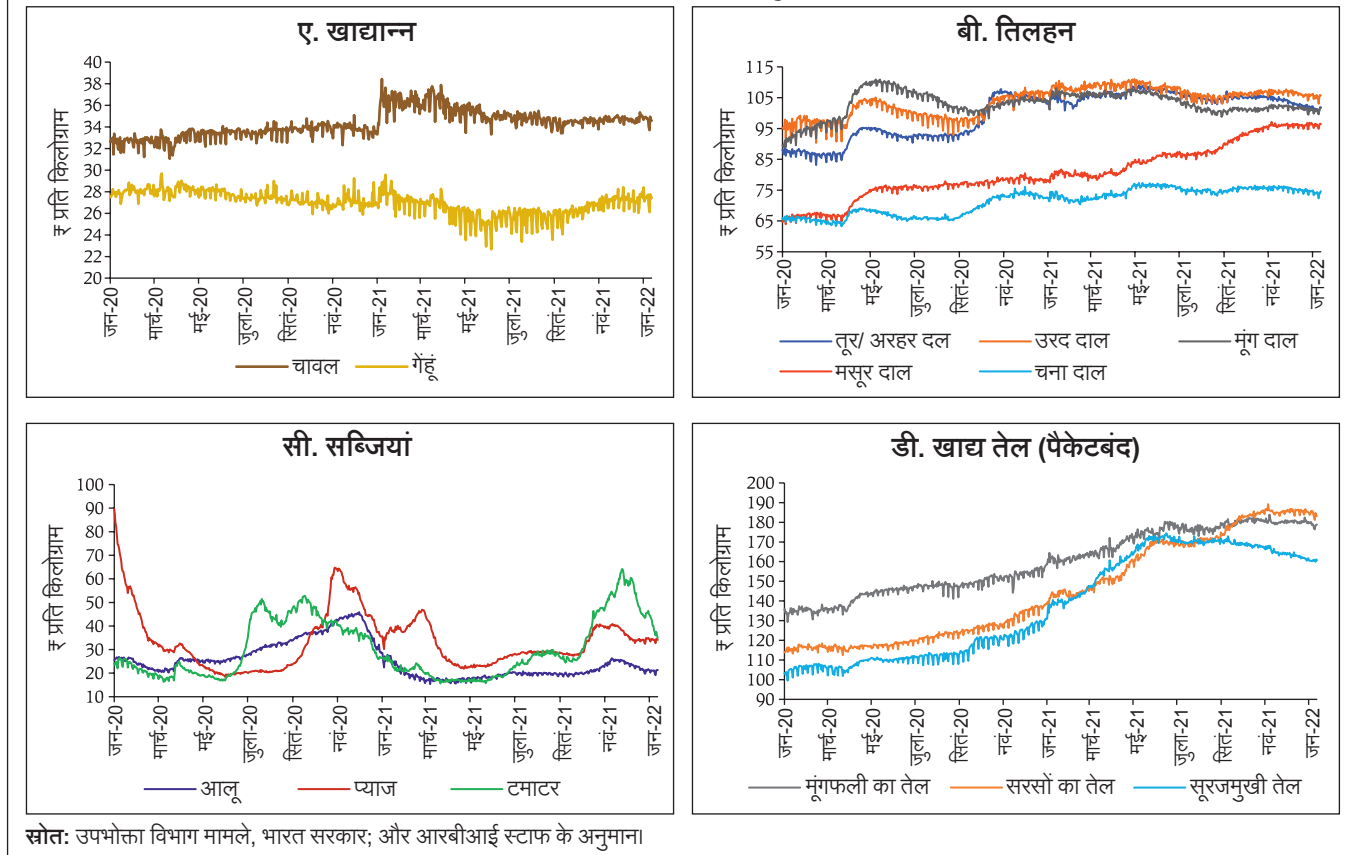
मुख्य रूप से एलपीजी, मिट्टी के तेल व जलाऊ लकड़ी और चिप के कारण ईंधन मुद्रास्फीति नवंबर में 13.3 प्रतिशत से

दिसंबर में 11.0 प्रतिशत हो गई। दिसंबर में बिजली की कीमतों में गिरावट जारी रही। सीपीआई ईंधन (सीपीआई समूह में 6.84 प्रतिशत का भार) ने दिसंबर में हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 13 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट 32बी)।

खाद्य और ईंधन से इतर सीपीआई मुद्रास्फीति या मूल मुद्रास्फीति दिसंबर में 6.0 प्रतिशत की वृद्धि पर बनी रही, हालांकि नवंबर 2021 में देखी गई 6.2 प्रतिशत की मुद्रास्फीति से कुछ कमी थी (चार्ट 32ए)। जबकि कपड़े और जूते, घरेलू सामान और सेवाओं, शिक्षा, और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव उप-समूहों में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, वहीं पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों, आवास, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार, और मनोरंजन और कौतुक में मुद्रास्फीति में कमी आयी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के जनवरी के लिए अब तक (1-12 जनवरी, 2022) के उच्च आवृत्ति डेटा प्रमुख खाद्य पदार्थों की कीमतों में व्यापक आधारित गिरावट का संकेत देते हैं। अनाज की

चार्ट 33: डीसीए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें



## सारणी 3: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें

मद	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		जन-21	दिसं-21	जन-22 ^	दिसं-21	जन-22
पेट्रोल	₹/लीटर	87.57	102.93	102.87	-2.5	-0.1
डीजल	₹/लीटर	78.97	90.51	90.51	-1.3	0.0
मिट्टी का तेल	₹/लीटर	23.21	38.68	38.68	-2.1	0.0
(सब्सिडी प्राप्त)						
एलपीजी (सब्सिडी के बिना)	₹/सिलेंडर	704.63	910.13	910.13	0.0	0.0

^: 1-12 जनवरी, 2022 की अवधि के लिए।

**टिप्पणी:** मिट्टी के तेल की कीमत के अलावा अन्य कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मिट्टी के तेल के लिए कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी-प्राप्त कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

**स्रोत:** आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं, जबकि दालों के साथ-साथ खाद्य तेलों की कीमतों में व्यापक आधार वाली गिरावट दर्ज की गई। आलू, प्याज और विशेष रूप से टमाटर की कीमतों में मौसमी कीमतों में सुधार देखा गया (चार्ट 33)।

चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य जनवरी में अब तक अपरिवर्तित रहे। जनवरी के पहले अर्धांश में एलपीजी और मिट्टी के तेल की कीमतें भी स्थिर रहीं (सारणी 3)।

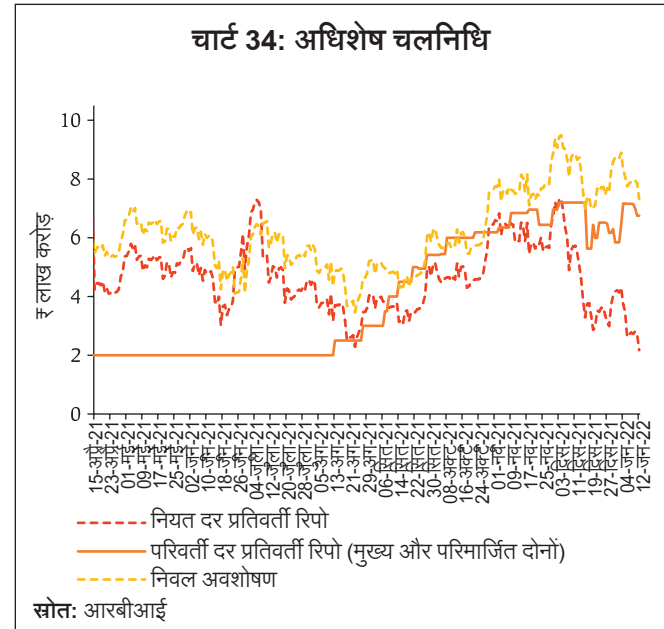
दिसंबर में निविष्टि लागत दबाव में कुछ कमी आयी, जैसा कि पीएमआई में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में परिलक्षित होता है। विनिर्माण और सेवाओं के बिक्री मूल्य में वृद्धि नहीं हुई।

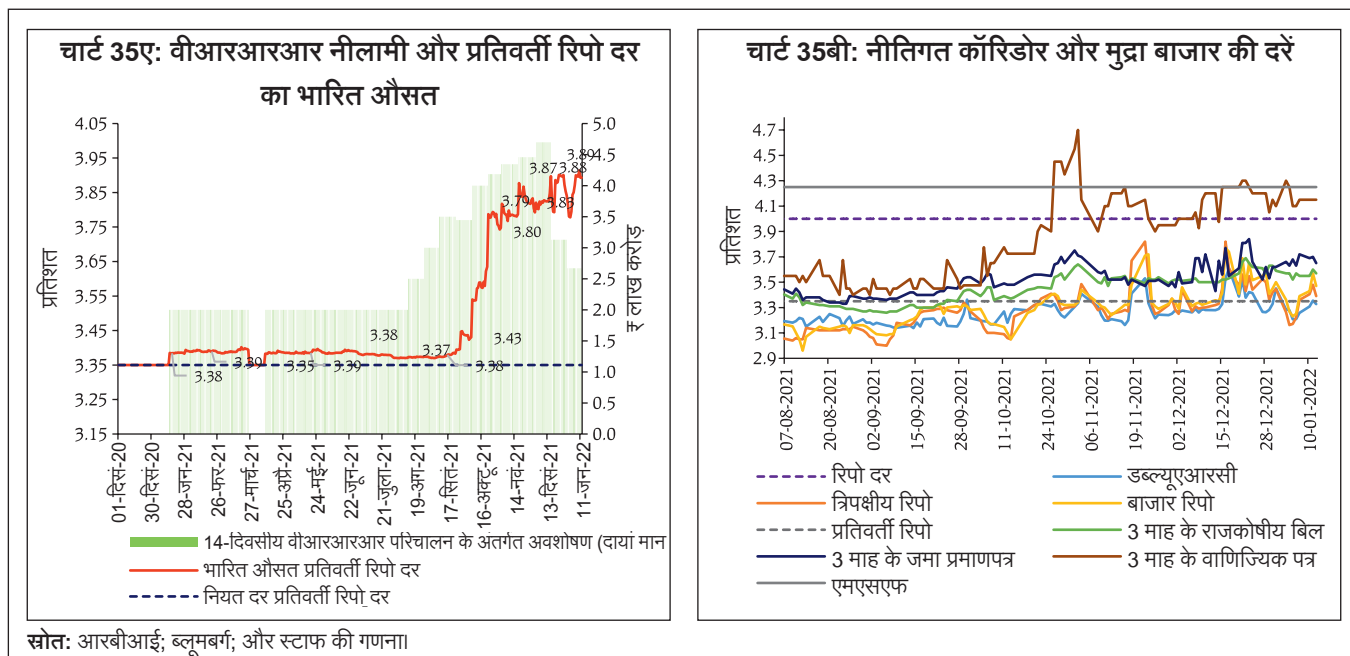
#### IV. वित्तीय स्थितियां

समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने और संक्रमणों में नए सिरे से वृद्धि के बीच समुत्थान बनाए रखते हुए, रिजर्व बैंक ने एमपीसी के समायोजनकारी नीतिगत रुख के अनुरूप पर्याप्त चलनिधि अधिशेष बनाए रखते हुए सक्रिय चलनिधि प्रबंधन किया। साथ ही, अधिशेष चलनिधि को नियत दर पर एक दिवसीय प्रतिवर्ती रिपो अवधि से लंबी परिपक्वता की परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रिपो (वीआरआरआर) नीलामियों में स्थानांतरित करके चलनिधि अधिशेष का पुनर्संतुलन जारी रखा

गया था। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, रिजर्व बैंक ने महीने की दूसरे अर्धांश में, यानी 17 दिसंबर और 31 दिसंबर को क्रमशः ₹6.5 लाख करोड़ और ₹7.5 लाख करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी आयोजित की। अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और शांतिपूर्ण तरीके से प्रणालीगत चलनिधि को व्यवस्थित करने के लिए 14-दिवसीय वीआरआरआर को लागू करते हुए, 3-7 दिनों की परिपक्वता के छह परिष्करण परिचालन और 28-दिन की परिपक्वता की एक लंबी अवधि के लिए वीआरआरआर आयोजित किए गए थे। जनवरी 2022 के पहले अर्धांश में अधिशेष चलनिधि के पुनर्संतुलन को जारी रखते हुए, रिजर्व बैंक ने ₹5.0 लाख करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए एक 14-दिवसीय वीआरआरआर और 3-7 दिनों की परिपक्वता के पांच परिष्करण परिचालन आयोजित किए। परिणामस्वरूप, जनवरी 2022 (13 जनवरी तक) के माध्यम से दिसंबर 2021 के दूसरे अर्धांश में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत दैनिक चलनिधि अवशोषण औसतन ₹8 लाख करोड़ था, जो पहले अर्धांश में ₹9.4 लाख करोड़ से कम था। साथ ही, नियत दर प्रतिवर्ती रिपो के माध्यम से अवशोषित चलनिधि भी नवंबर-मध्य से दिसंबर 2021-मध्य के दौरान ₹2.2 लाख करोड़ से कम होकर ₹1.5 लाख करोड़ हो गई (चार्ट 34)।

चार्ट 34: अधिशेष चलनिधि



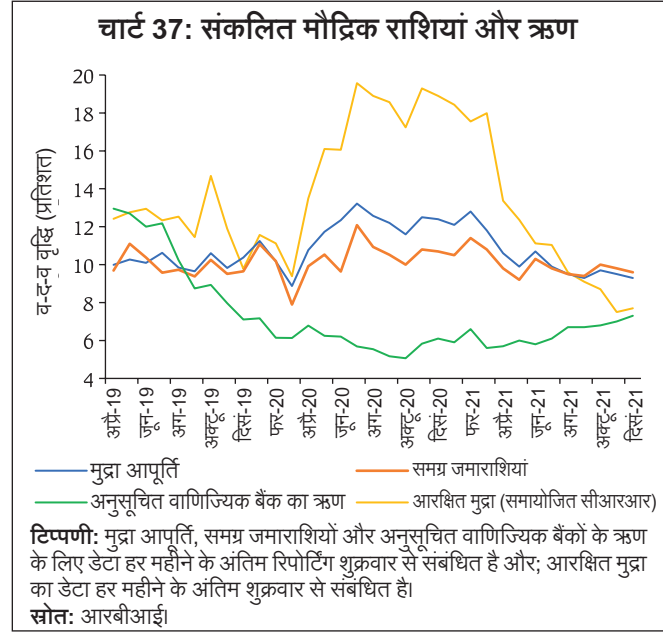
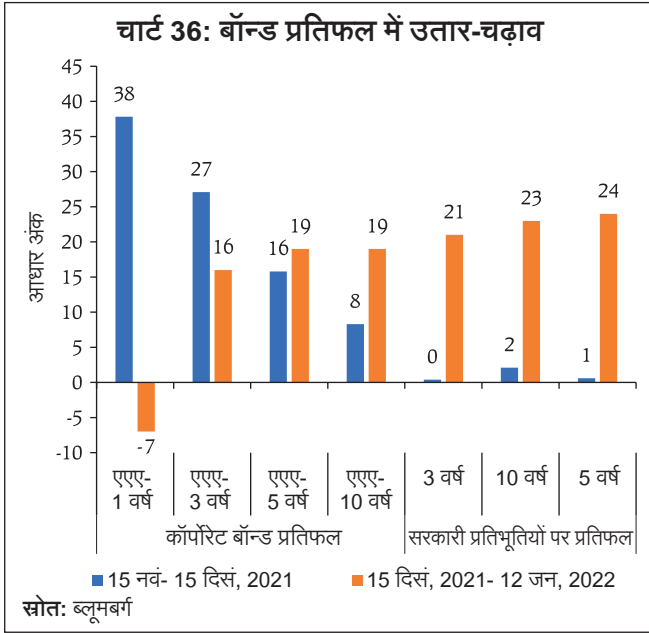


प्रभावी प्रतिवर्ती रिपो दर, रिपो दर के आस-पास आ गई (चार्ट 35ए)। वीआरआरआर नीलामियों में उच्च निर्दिष्ट सीमा से संकेत लेते हुए मुद्रा बाजार की दरों में वृद्धि हुई। 3-4 दिनों की परिपक्वता और अग्रिम कर भुगतान की वीआरआरआर नीलामियों की आवृत्ति में वृद्धि दिसंबर 2021 के दूसरे अर्धांश में मुद्रा बाजार के अंतिम क्षणों में भारत हुई। एक दिवसीय खंड में जबकि भारत औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर), प्रतिवर्ती रिपो दर के आस-पास बनी रही, वहीं जनवरी 2022 में कमी के पूर्वाग्रह के साथ संपार्श्विक खंड में बाजार रिपो और त्रिपक्षीय रिपो दिसंबर के मध्य से अधिक थे। मीयादी खंड में, 3 महीने की राजकोषीय बिल और जमा प्रमाण पत्र (सीडी) दरें प्रभावी प्रतिवर्ती रिपो दर के संयोजन के साथ विकसित हुईं; दिसंबर 2021 के दूसरे अर्धांश से 12 जनवरी, 2022 तक, उनके औसत स्प्रेड (प्रतिवर्ती रिपो दर की तुलना में) के साथ क्रमशः 24 और 31 आधार अंकों पर रही। दूसरी ओर, 3 महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी-एनबीएफसी) पर दरें तीव्र प्राथमिक बाजार गतिविधि को देखते हुए उच्च बनी रहीं (चार्ट 35बी)।

बॉन्ड प्रतिफल उच्चतर बना रहा, 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों (पुरानी) प्रतिफल लगभग दो साल के उच्च स्तर के आस-पास बनी रही और 14 जनवरी, 2022 को 6.58 प्रतिशत पर बंद हुई है। वैश्विक संकेत, जैसे, प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा (जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा अप्रत्याशित वृद्धि) समायोजनकारी रुख को समाप्त करने का संकेत, अमेरिकी राजकोषीय प्रतिफल में वृद्धि और कच्चे तेल की उच्च कीमतों ने रुख को प्रभावित किया और प्रतिफल के स्तर में वृद्धि की। घरेलू प्राथमिक खंड में, 24 दिसंबर, 2021, 7 और 14 जनवरी, 2022 को आयोजित साप्ताहिक नीलामी में प्राथमिक डीलरों (पीडी) पर न्यागमन के साथ उच्च प्रतिफल कट ऑफ हुआ। रिजर्व बैंक ने अस्थिर दर वाले बॉन्ड 2028 (जीओआई एफआरबी 2028) और 6.10 जीएस 2031 के लिए किसी भी बोली को स्वीकार नहीं किया और 31 दिसंबर, 2021 को साप्ताहिक नीलामी में 6.95 जीएस 2061 के लिए सभी बोलियों को स्वीकार किया। मंदी की प्रवृत्ति 31 दिसंबर, 2021 को आयोजित नीलामी के लिए उच्च हामीदारी शुल्क और जनवरी 2022 के पहले दो सप्ताहों में भी परिलक्षित हुई। सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में वृद्धि के संकेतों के आधार पर कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल में भी वृद्धि हुई (चार्ट 36)।

<sup>9</sup> प्रभावी प्रतिवर्ती रिपो दर, नियत दर प्रतिवर्ती रिपो दर का भारत औसत और परिष्करण परिचालन सहित सभी परिपक्वताओं के वीआरआरआर हैं, जिसमें भार, संबंधित प्रतिवर्ती रिपो की अवधि के तहत अवशोषित राशि है।

समग्र रूप से, मौद्रिक और ऋण स्थितियां रिजर्व बैंक के विकासोन्मुख समुत्थान को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुरूप



विकसित हुई हैं। नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की बहाली के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर, आरक्षित मुद्रा (आरएम) 31 दिसंबर, 2021 (एक साल पहले 19.1 प्रतिशत) की स्थिति में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई - प्रचलन में मुद्रा जो कि आरएम का सबसे बड़ा घटक है - उसमें 7.8 प्रतिशत (एक साल पहले 22.1 प्रतिशत) का विस्तार हुआ। दूसरी ओर, बैंकों द्वारा सुदृढ़ जमाराशि संग्रहण (10.3 प्रतिशत) के बल पर, मुद्रा आपूर्ति (एम 3) में 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति में 9.9 प्रतिशत (एक साल पहले 12.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण में वृद्धि, जो अप्रैल 2020 के बाद पहली बार नवंबर 2021 में 7 प्रतिशत के स्तर को पार कर गई, 31 दिसंबर, 2021 तक 9.2 प्रतिशत हो गई (एक वर्ष पहले 6.2 प्रतिशत) (चार्ट 37)।

मौद्रिक नीति के रुख पर अधिशेष चलनिधि और आगे के मार्गदर्शन से मौद्रिक संचारण की सुविधा जारी है। मार्च 2020 के बाद से, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निधि-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की एक वर्ष की औसत सीमांत लागत में संचयी रूप से 100 आधार अंकों की कमी आयी है। मार्च 2020 से दिसंबर 2021 तक औसत सावधि जमा दर में 154 आधार अंकों की गिरावट आयी है। निधि की कुल लागत में कमी ने बकाया रुपये के ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) में

संचारण को सक्षम किया है। मार्च 2020 से नवंबर 2021 के दौरान बकाया ऋणों पर डब्ल्यूएलआर के लिए रिपो दर में पूर्ण रूप से कटौती की गई है (सारणी 4)।

साथ ही, मार्च 2020 से शुरू होने वाली सभी अवधियों में जमाराशि की दरों में भी नरमी आयी है। एक वर्ष की परिपक्वता

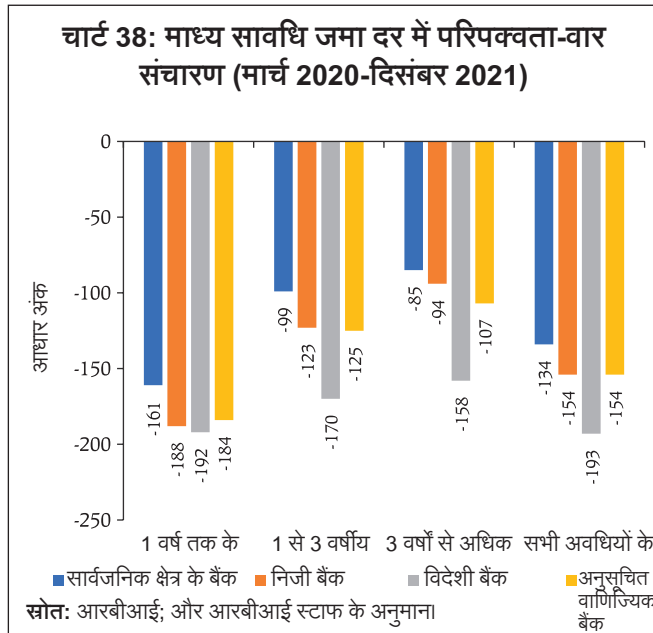
#### सारणी 4: रिपो दर से बैंकों की जमा और उधार दरों में संचारण

(आधार अंक में उतार-चढ़ाव)

अवधि	रिपो दर	सावधि जमा दरें		उधार दरें		
		टीडीआर माध्य (नई जमाराशियां)	डब्ल्यूएलएलटीडीआर (बकाया जमाराशियां)	1 वर्षीय एमसीएलआर माध्य	डब्ल्यूएलएलआर (बकाया रुपया ऋण)	डब्ल्यूएलएलआर (नये रुपया ऋण)
फर 2019 - सितं 2019	-110	-9	-7	-30	0	-43
अक्टू 2019 - दिसं 2021*	-140	-185	-180	-132	-133	-154
मार्च 2020 - दिसं 2021*	-115	-154	-141	-100	-114	-124
फर 2019 - दिसं 2021*	-250	-213	-187	-155	-133	-197

**टिप्पणी:** डब्ल्यूएलआर और डब्ल्यूएलएलटीडीआर पर नवीनतम डेटा नवंबर 2021 से संबंधित है।  
डब्ल्यूएलआर: भारित औसत उधार दर; डब्ल्यूएलएलटीडीआर: भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर;  
एमसीएलआर: निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत; टीडीआर: सावधि जमा दरा

स्रोत: आरबीआई

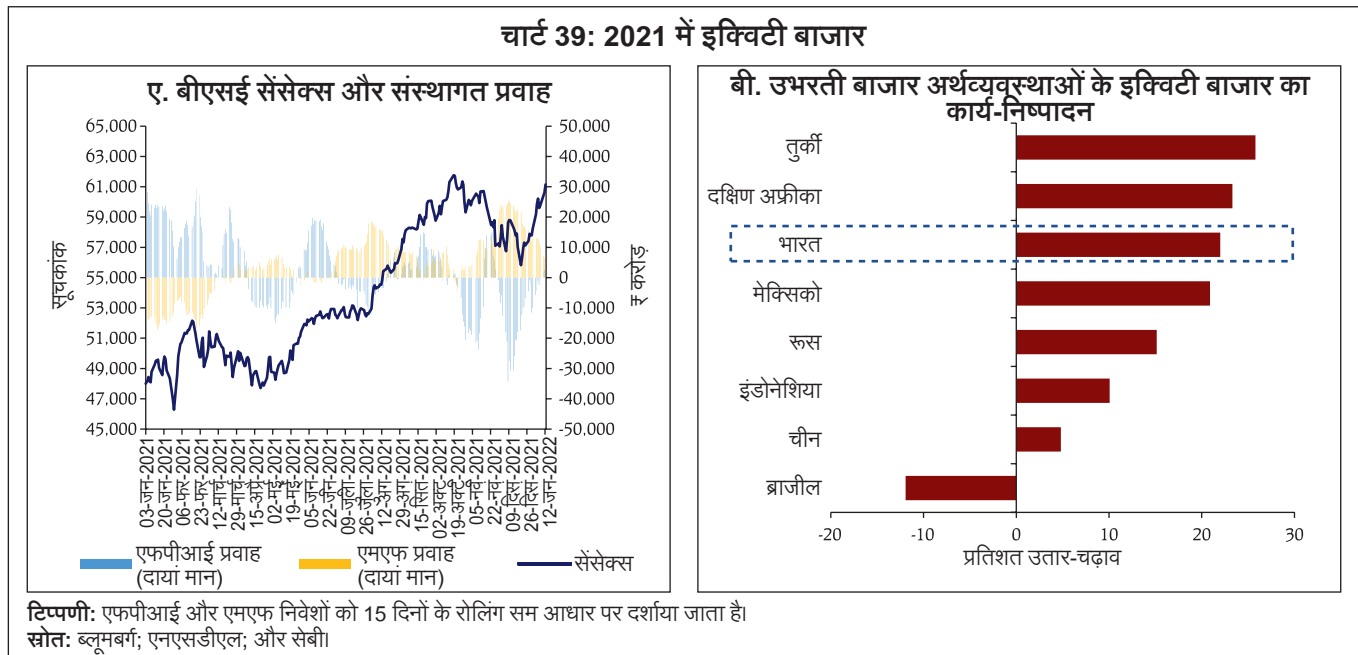


तक की लघु अवधि की जमा राशियों में 184 आधार अंकों की बड़ी गिरावट और 3 वर्षों से अधिक की परिपक्वता की लंबी अवधि की जमा राशियों पर जमा दरों के लिए अपेक्षाकृत कम प्रभाव अंतरण देखा जा सकता है। घरेलू बैंकों में, निजी बैंकों ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में मीयादी जमा दरों के लिए उच्च प्रभाव अंतरण प्रदर्शित करना जारी रखा है (चार्ट 38)। हाल के

महीनों में, कुछ प्रमुख बैंकों ने जमा राशियों पर ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे ऋण मांग में तेजी आने की उम्मीद है।

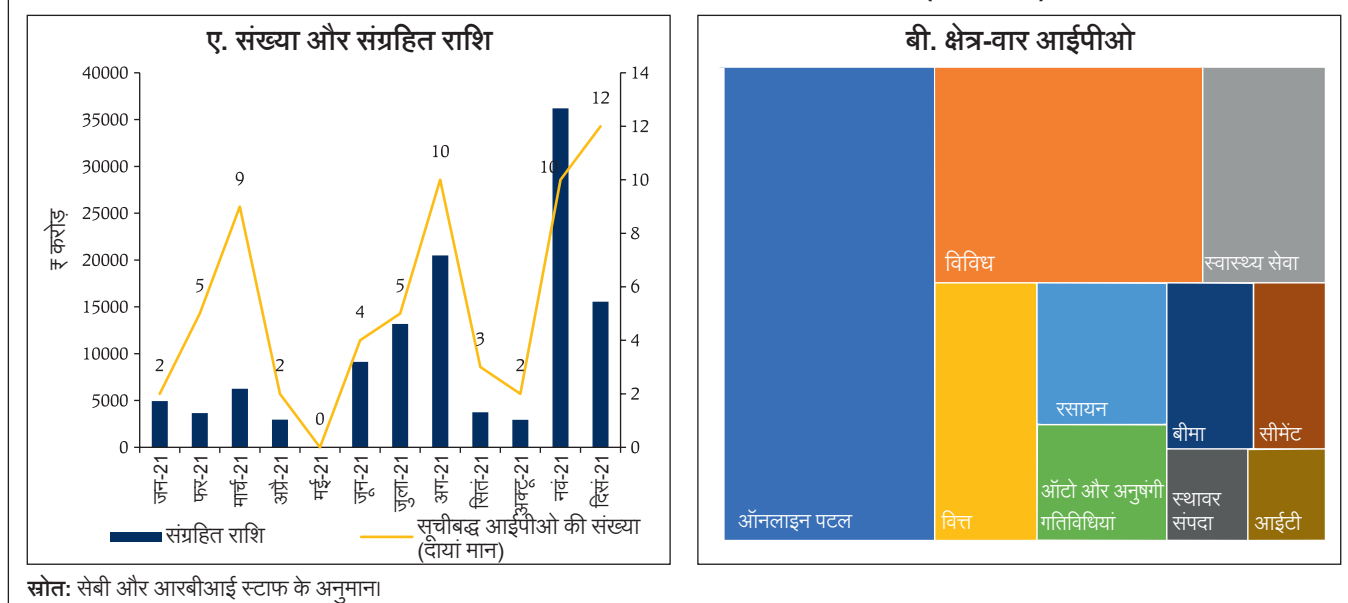
भारत सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 को अल्प बचत उपकरणों (एसएसआई) पर ब्याज दरों की समीक्षा की और उन्हें लगातार सातवीं तिमाही के लिए अपरिवर्तित रखा। 2021-22 की चतुर्थ तिमाही के लिए एसएसआई पर वर्तमान ब्याज दरें फॉर्मूला-आधारित दरों की तुलना में 42-168 आधार अंक अधिक हैं<sup>10</sup>

शुरुआत में नीतिगत दर और रुख में यथास्थिति की रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाले इक्विटी बाजार दिसंबर 2021 में अस्थिर हो गए, लेकिन बाद में ओमीक्रॉन संस्करण के प्रसार पर चिंताओं के कारण इसे उलटा लाभ हुआ (चार्ट 39ए)। ओमीक्रॉन वैरियंट के प्रसार की गंभीरता पर चिंताओं के साथ, बाजार ने सकारात्मक वैश्विक संकेतों से सीखते हुए अपने नुकसान की भरपाई की। कैलेंडर वर्ष के आधार पर, भारतीय इक्विटी (बीएसई सेंसेक्स) ने 22 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की, जो अधिकांश उभरते बाजार के प्रतिभागियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था (चार्ट 39बी)। बीएसई सेंसेक्स 2022 में 5.1 प्रतिशत बढ़कर 14 जनवरी, 2022 को 61,223 पर बंद हुआ।



<sup>10</sup> अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दरें भारत सरकार द्वारा प्रभावी और निर्धारित की जाती हैं। ये प्रभावी ब्याज दरें एक अंतराल के साथ सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार प्रतिफल से जुड़ी होती हैं और तुलनीय परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल के ऊपर 0-100 आधार अंकों से लेकर तिमाही आधार पर तय की जाती हैं।

**चार्ट 40: 2021 में मेनबोर्ड प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ)**



दिसंबर 2021 के दौरान, पारस्परिक निधियों (म्युचुअल फंड) ने ₹21,923 करोड़ की निवल खरीदारी दर्ज की, जबकि एफपीआई निवल विक्रेता बन गए और घरेलू इक्विटी बाजार में ₹13,150 करोड़ दिये।

दिसंबर में 12 कंपनियों के प्रमुख आईपीओ की सूचीबद्धता के साथ - 2021 में किसी भी महीने के लिए सबसे अधिक (चार्ट 40ए), आईपीओ बाजार में उत्साह बना रहा। इन कंपनियों द्वारा संसाधन जुटाने की राशि ₹15,553 करोड़ थी। वर्ष 2021 आईपीओ बाजार में उछाल का वर्ष साबित हुआ, जिसमें 64 कंपनियों की प्रमुख सूचीबद्धता ने 1.2 लाख करोड़ रुपये जुटाए, जबकि 14 कंपनियों की प्रमुख सूचीबद्धता ने 2020 में 26,312 करोड़ रुपये जुटाए थे। क्षेत्रवार देखें तो, 2021 में संसाधनों का बड़ा हिस्सा खाद्य वितरण, बीमा, ऑटो और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र (चार्ट 40बी) में काम करने वाली नए युग के मंच आधारित कंपनियों द्वारा जुटाया गया था।

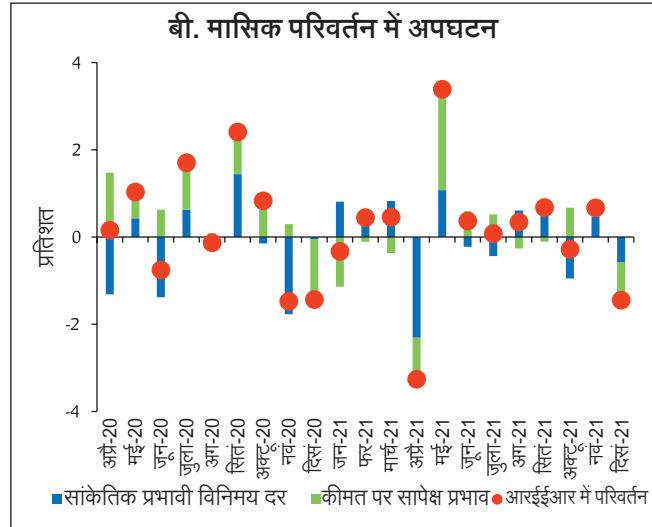
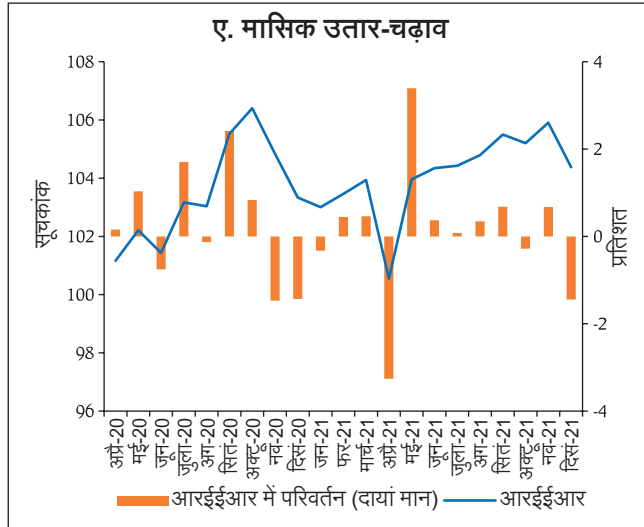
भारत के चालू खाते की शेष राशि में 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी का 0.9% और एक वर्ष पहले जीडीपी का 2.4% के अधिशेष की तुलना में 2021-22 की दूसरी तिमाही में जीडीपी का 1.3% घाटा दर्ज किया गया। बुनियादी विषयों में उतार-चढ़ाव के कारण, भारतीय रुपये (आईएनआर) में दिसंबर में अमेरिकी डॉलर

के मुकाबले 0.6% (माह-दर-माह) की गिरावट आई। यह 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक के संदर्भ में आईएनआर के उतार-चढ़ाव में भी प्रतिबिंबित हुआ, जो एक महीने पहले अपने स्तर (चार्ट 41) से 1.4 प्रतिशत कम हो गया था।

सितंबर 2021 के अंत तक भारत की निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति में मार्च 2021 के अंत में सुधार हुआ, जिसमें भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय आस्तियों में वृद्धि ने भारत में विदेशी स्वामित्व वाली आस्तियों में वृद्धि को पीछे छोड़ दिया। 2021-22 में विदेशी मुद्रा भंडार में एक मजबूत वृद्धि ने अन्य बातों के साथ-साथ, अल्पकालिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता आधार पर) के कवरेज को मार्च 2021 के अंत में 226.9 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2021 के अंत में 248.2 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है (सारणी 5)।

कोविड मामलों में अचानक वृद्धि और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा तेजी से नीतिगत सख्ती के पूर्वानुमानों के कारण विदेशी निवेशकों के बीच मंदी की भावनाओं को बढ़ावा मिला। दिसंबर 2021 के दौरान, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने घरेलू पूंजी बाजार के इक्विटी और ऋण दोनों क्षेत्रों में अपने जोखिम को कम कर दिया (चार्ट 42)। इससे आगे बढ़ते हुए, 2022 में आईपीओ के लिए एक मजबूत पाइपलाइन और वैश्विक

**चार्ट 41: 40 मुद्रा-समूह की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में मासिक संचलन (आधार वर्ष: 2015-16 = 100)**



**टिप्पणी:** दिसंबर 2021 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।  
**स्रोत:** आरबीआई

बॉन्ड सूचकांकों में सरकारी बॉन्ड के संभावित समावेश से एफपीआई अंतर्वाह को बढ़ाया जा सकता है।

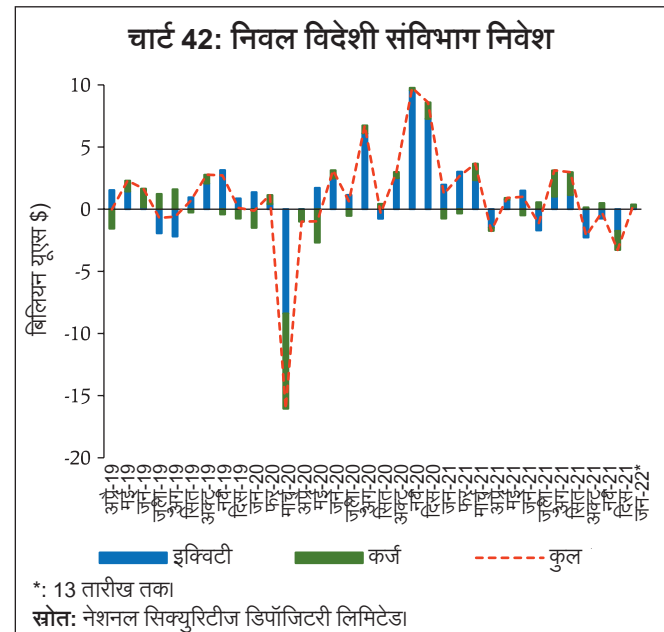
भारत को विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का निवल संवितरण (अंतर-कंपनी उधार सहित) एक वर्ष पहले 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल बहिर्वाह की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। नवंबर में उठाए गए ईसीबी के एक बड़े हिस्से का उपयोग नई परियोजनाओं

और पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए आगे उधार देने/पुनः-उधार देने के लिए किया गया था।

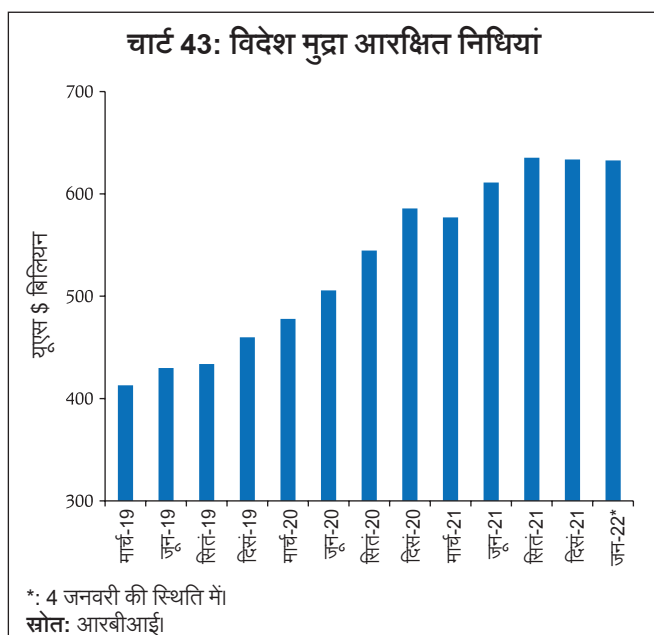
07 जनवरी, 2022 (चार्ट 43) को विदेशी मुद्रा भंडार 632.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2021-22 के लिए अनुमानित आयात के 13 महीनों के बराबर कवर प्रदान करता है।

सारणी 5: प्रमुख बाहरी भेद्यता संकेतक		
संकेतक	मार्च, 2021 की समाप्ति पर	सितंबर, 2021 की समाप्ति पर
1. बाह्य ऋण (बिलियन यूएस \$)	569.6	593.1
2. जीडीपी अनुपात के लिए बाह्य ऋण (%)	21.1	20.1
3. कुल ऋण अनुपात के लिए अल्पकालिक ऋण (आरएम)	44.6	43.2
4. कुल ऋण अनुपात के लिए आरक्षित निधियां (%)	101.3	107.1
5. अल्पकालिक ऋण (आरएम) अनुपात के लिए आरक्षित निधियां (%)	226.9	248.2
6. आयात का आरक्षित निधियों का कवर (महीनों में)	17.4	14.6
7. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी)# (बिलियन यूएस \$)	-351.1	-331.8
8. निवल आईआईपी/ जीडीपी अनुपात (%)#	-13.1	-11.6

आरएम: अवशिष्ट परिपक्वता।  
आईआईपी: अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति।  
#: ऋणात्मक संकेत भारत पर अनिवासियों के निवल दावों को इंगित करते हैं।  
**स्रोत:** आरबीआई।



\*: 13 तारीख तक।  
**स्रोत:** नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड।



### भुगतान प्रणाली

वर्ष 2021 में स्थिर वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) प्रदर्शित करते हुए थोक और खुदरा क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान लेनदेन की स्थिति दिसंबर में उत्साहजनक रही (सारणी 6)। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के तहत संसाधित लेनदेन मूल्य लगातार तीसरे महीने बढ़े, जबकि वॉल्यूम बढ़कर 1.92 करोड़ हो गया जो वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक का सर्वाधिक था। खुदरा मोर्चे पर, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), नेशनल ऑटोमेटेड

किलयरिंग हाउस (एनएसीएच) और भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से भुगतान ने एक महीने पहले अपने स्तर से दिसंबर में क्रमिक सुधार प्रदर्शित किया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ने एक और ऊँचाई हासिल की, जिसमें 456 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक लेनदेन हुआ, जिसका रिकॉर्ड मूल्य ₹8.26 लाख करोड़ था। गतिशीलता में उत्साहित गति को दर्शाते हुए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल उगाही (एनईटीसी) के माध्यम से लेनदेन के मात्रा और मूल्य अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। कुल मिलाकर, प्रमुख भुगतान चैनलों में दैनिक औसत लेनदेन का मूल्य पिछले महीने की तुलना में बढ़ा है।

भारत के डिजिटल भुगतान परितंत्र ने 2021 में अच्छा विस्तार दर्ज किया। आरटीजीएस की कुल मात्रा में 37 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि मूल्यों में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यूपीआई चैनल के माध्यम से लेनदेन, मात्रा और मूल्य दोनों दृष्टिकोण से दोगुने से अधिक हो गए हैं। अन्य प्रमुख खुदरा भुगतान तरीके, जैसे- एनईएफटी, आईएमपीएस, एनईटीसी और बीबीपीएस में भी वर्ष के दौरान मजबूत वृद्धि देखी गई।

3 जनवरी 2022 को, रिजर्व बैंक ने कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों, जैसे चैनलों के माध्यम से ऑफलाइन डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए रूपरेखा जारी की। इस तरह के भुगतान को, प्रति लेनदेन ₹200 के साथ सभी लेनदेन के लिए ₹2000 की कुल सीमा तक सीमित कर दिया गया है। इस कदम से सीमित इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी वाले दूरदराज

### सारणी 6: चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर

भुगतान प्रणाली	लेन-देन की मात्रा में वृद्धि (व-द-व, प्रतिशत)				(लेन-देन के मूल्य में वृद्धि (व-द-व, प्रतिशत))			
	नव-2020	नव-2021	दिस-2020	दिस-2021	नव-2020	नव-2021	दिस-2020	दिस-2021
आरटीजीएस	2.9	24.9	20.2	17.9	-8.0	37.5	3.3	21.7
एनईएफटी	24.6	24.1	31.6	22.3	27.9	4.3	31.7	6.5
यूपीआई	81.3	89.4	70.8	104.4	106.6	96.5	105.5	98.7
आईएमपीएस	48.7	21.5	38.7	24.5	36.3	31.9	38.6	35.6
एनएसीएच	2.5	15.7	28.0	-2.7	5.7	7.1	32.2	5.1
एनईटीसी	257.6	71.5	115.2	74.9	171.6	51.1	83.3	59.7
बीबीपीएस	78.7	148.6	86.2	137.0	78.1	175.3	97.9	165.2

स्रोत: आरबीआई



के क्षेत्रों में डिजिटल उपयोग बढ़ने और इससे डिजिटल वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है<sup>11</sup>

कार्ड-आधारित लेनदेन की सुरक्षा को बेहतर बनाने और ग्राहक की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने मर्चेट प्लेटफॉर्म पर ग्राहक-कार्ड की सूचनाएँ संगृहीत करने पर रोक लगा दी है और 31 दिसंबर 2021 से कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ) टोकन का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। उद्योग के पणधारियों के अभ्यावेदन के बाद, इन मानदंडों के अनुपालन की समय-सीमा 6 महीने - यानी 30 जून 2022 तक - बढ़ा दी गई है ताकि टोकन-आधारित कार्ड लेनदेन की ओर परिवर्तन आसान हो सके।<sup>12</sup> डिजिटल भुगतान तरीकों को प्रोत्साहित करने हेतु, सरकार ने रुपये डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई के माध्यम से किए गए व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) लेनदेन के मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के लिए ₹1,300 करोड़ की एक योजना शुरू की है।<sup>13</sup>

जनवरी 2022 के शुरुआती आंकड़ों (12 जनवरी तक) से डिजिटल भुगतान में वृद्धि के संकेत मिलते हैं, हालांकि संक्रमण में हालिया उछाल आगे चलकर चिंता का विषय बन सकता है। फिर भी, विभिन्न चेकआउट विकल्पों की उपलब्धता और बढ़ती डिजिटल जागरूकता को देखते हुए भुगतान उद्योग से लचीलापन अपेक्षित है। बाज़ार-अनुमानों के अनुसार डिजिटल भुगतान का मूल्य, वित्त वर्ष 2021 के यूएस \$ 300 बिलियन से वित्त वर्ष 2026 तक यूएस \$ 01 ट्रिलियन तक, तीन गुना बढ़ सकता है।<sup>14</sup>

## निष्कर्ष

उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास आशाजनक के होने और उच्च आवृत्ति संकेतकों में वृद्धि के कारण भारत में समग्र आर्थिक गतिविधि मजबूत बनी हुई है। टीकाकरण के मोर्चे पर भारत ने तेज प्रगति की है। ओमीक्रॉन वेरियंट पर, यूके और दक्षिण अफ्रीका के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि इस तरह के 66 से 80 प्रतिशत संक्रमण हल्के होते हैं, जिससे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता कम होती है।<sup>15</sup> इससे निकट अवधि की संभावनाएँ आशाजनक हैं और वित्तीय बाजार सकारात्मक हैं।

साथ ही, बैंक ऋण में धीमी लेकिन निरंतर वृद्धि से मौद्रिक और ऋण की स्थिति सुधर रही है। भारत के डिजिटल भुगतान परितंत्र में तीव्र विस्तार हो रहा है। इसके विपरीत, वैश्विक परिदृश्य काफी अनिश्चित हैं। उत्पादन, आपूर्ति शृंखला और परिवहन में व्यवधानों के कारण सभी भौगोलिक क्षेत्रों में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है। नतीजतन, देशों के मौद्रिक नीति के रुख में अंतराल व्यापक हो गया है। ऐसे संकेत हैं कि आपूर्ति शृंखला में व्यवधान और पोत-परिवहन लागत धीरे-धीरे कम हो रही हैं, हालांकि मुद्रास्फीति कम होने में अधिक समय लग सकता है। यह वैश्विक सुधार को तेज और व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का समय है।

<sup>11</sup> <https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12215&Mode=0>

<sup>12</sup> <https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12211&Mode=0>

<sup>13</sup> [https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/eGazette\\_Notification\\_Incentive%20Scheme\\_17thDec2021.pdf](https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/eGazette_Notification_Incentive%20Scheme_17thDec2021.pdf)

<sup>14</sup> <https://www.moneycontrol.com/news/business/companies/digital-payments-in-india-will-reach-1-trillion-by-fy26-estimates-clsa-7823371.html>

<sup>15</sup> एफटी, 10 जनवरी, 2022



## भारतीय कृषि: उपलब्धियां और चुनौतियां\*

कोविड-19 के दौरान, भारतीय कृषि ने उल्लेखनीय आघातसहनीयता प्रदर्शित की है। यह आलेख कोविड-19 के प्रकोप से पहले भी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है और यह आकलन करता है कि नई उभरती चुनौतियाँ अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ-साथ दूसरी हरित क्रांति की गारंटी देती हैं। देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले उत्पादन के मामले में सफलता के बावजूद, खाद्य मुद्रास्फीति और इसकी अस्थिरता एक चुनौती बनी हुई है, जिसके लिए इस आलेख के अनुभवजन्य निष्कर्षों के अनुसार उच्च सार्वजनिक निवेश, भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने जैसे आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

### भूमिका

उन्नीस सौ साठ के दशक की शुरुआत से खाद्य की कमी और आयात पर निर्भर राष्ट्र से आज जब भारत वैश्विक कृषि महाशक्ति बन गया है एक मूक क्रांति देखी है। भारत दूध, दाल, जूट और मसालों का दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है, और इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा मवेशी समूह (भैंस) है। यह चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना, चाय, मूंगफली, फल, सब्जियां और बकरी के मांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यद्यपि भारत के योजित सकल मूल्य (जीवीए) में कृषि का हिस्सा घट रहा है, लेकिन यह निरपेक्ष रूप से बढ़ रहा है और कुल हाउसहोल्ड के लगभग 49 प्रतिशत (पीएलएफएस, 2020) को रोजगार देता है। कृषि क्षेत्र कोविड-19 के झटके का सामना कर सका और 2020-21 में 3.6 प्रतिशत की औसत वास्तविक वृद्धि से ऊपर वृद्धि दर्ज की, यहां तक कि समग्र अर्थव्यवस्था (वास्तविक जीवीए) में 6.2 प्रतिशत की कमी आई। कोविड-19 की लगातार लहरों के बारे में चिंताओं को देखते हुए, कई देशों ने

\* यह आलेख भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के अत्री मुखर्जी, प्रियंका बजाज, ऋषभ कुमार और जोबिन सेबेस्टियन द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

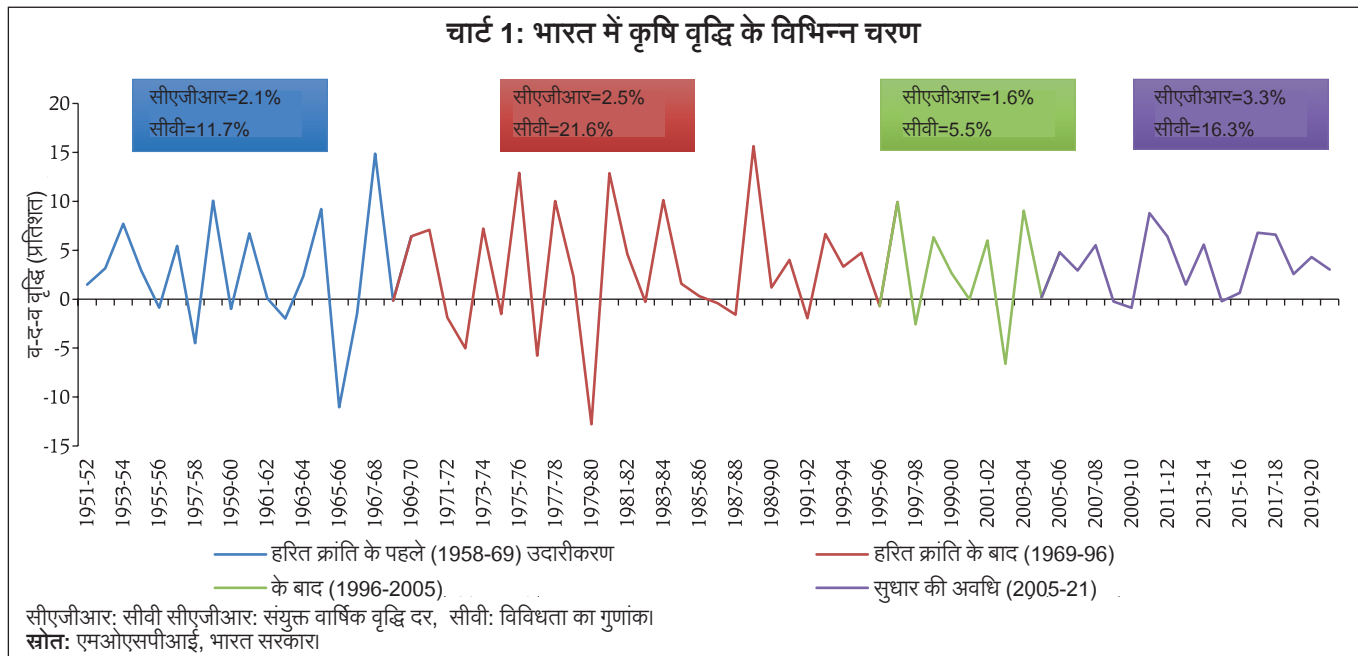
उच्च कीमतों पर प्राप्त खाद्यान्न का भंडार करना शुरू कर दिया है, जबकि भारत बफर मानदंडों के 2.8 गुना अनाज के सार्वजनिक स्टॉक के साथ सहज बना हुआ है (चंद्रशेखर और घोष, 2021), 2020-21 में कृषि निर्यात में 17.1 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि और 2020-21 और 2021-22 में विपणन अधिशेष की खरीद में बड़ी वृद्धि देखी गई।

इस तरह के लाभ के बावजूद, भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन की गड़बड़ी के अनुकूलन, खंडित भूमि जोत, कम कृषि उत्पादकता और उच्च खाद्य मूल्य अस्थिरता से जुड़े मुद्दों का सामना कर रही है, जो अगली पीढ़ी के सुधारों जैसे पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जलवायु प्रतिरोधी नई कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाने, भूमि समेकन के लिए बाजार के विकास और कटाई के बाद की प्रथाओं में सुधार की मांग करती है। इस पृष्ठभूमि में, यह आलेख इस प्रकार है: आलेख के खंड II में हाल की अवधि में कृषि क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। खंड III कृषि में वृद्धि के प्रमुख प्रवर्तकों का वर्णन करता है। वर्तमान बाधाओं और उभरती चुनौतियों में से कुछ पर खंड IV में चर्चा की गई है। खंड V में, खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति और इसकी अस्थिरता पर आपूर्ति पक्ष बाधाओं के प्रभाव का आनुभविक रूप से आकलन करने का प्रयास किया गया है। खंड VI आलेख का समापन करता है।

## II. प्रमुख उपलब्धियां

### II. 1 खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन

भारतीय कृषि ने 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद उत्पादन की वृद्धि में एक विशिष्ट कदम देखा, जो इनपुट और तकनीकी प्रगति के गहन उपयोग से प्रेरित था, जो सत्तर और अस्सी के दशक के दौरान कायम रहा (चार्ट 1)। 2000 के दशक की शुरुआत में कुछ गिरावट के बावजूद, पिछले दशक में उच्च कृषि ऋण, सार्वजनिक और निजी निवेश, गुणवत्ता वाले बीजों और उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि, सिंचाई के तहत रकबे के विस्तार और फसल की गहनता में वृद्धि के कारण खाद्यान्न के औसत उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (चंद और परप्पुरथु, 2012)। प्रमुख कृषि आदानों तक पहुंच में वृद्धि के अलावा, सरकार की मूल्य समर्थन नीति (न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा संचालित) ने भी अनाज और दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका

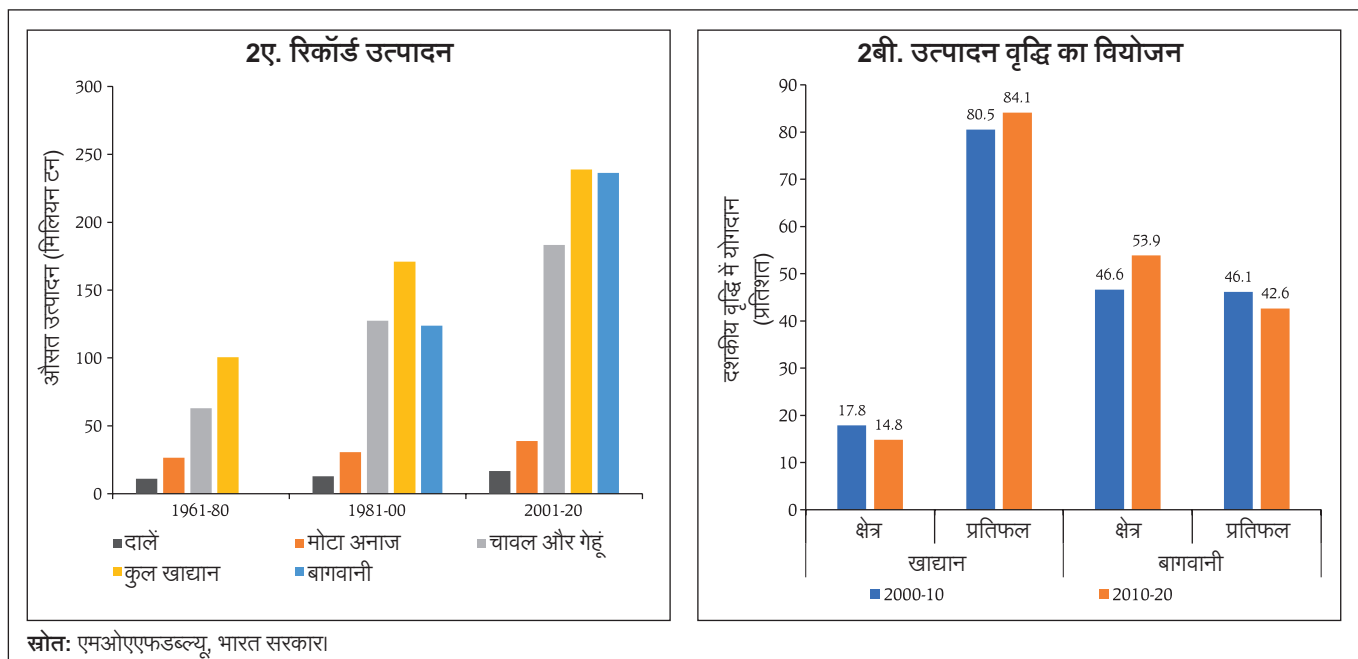


निभाई है जिसके परिणामस्वरूप 2016-17 से खाद्यान्न का लगातार रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।

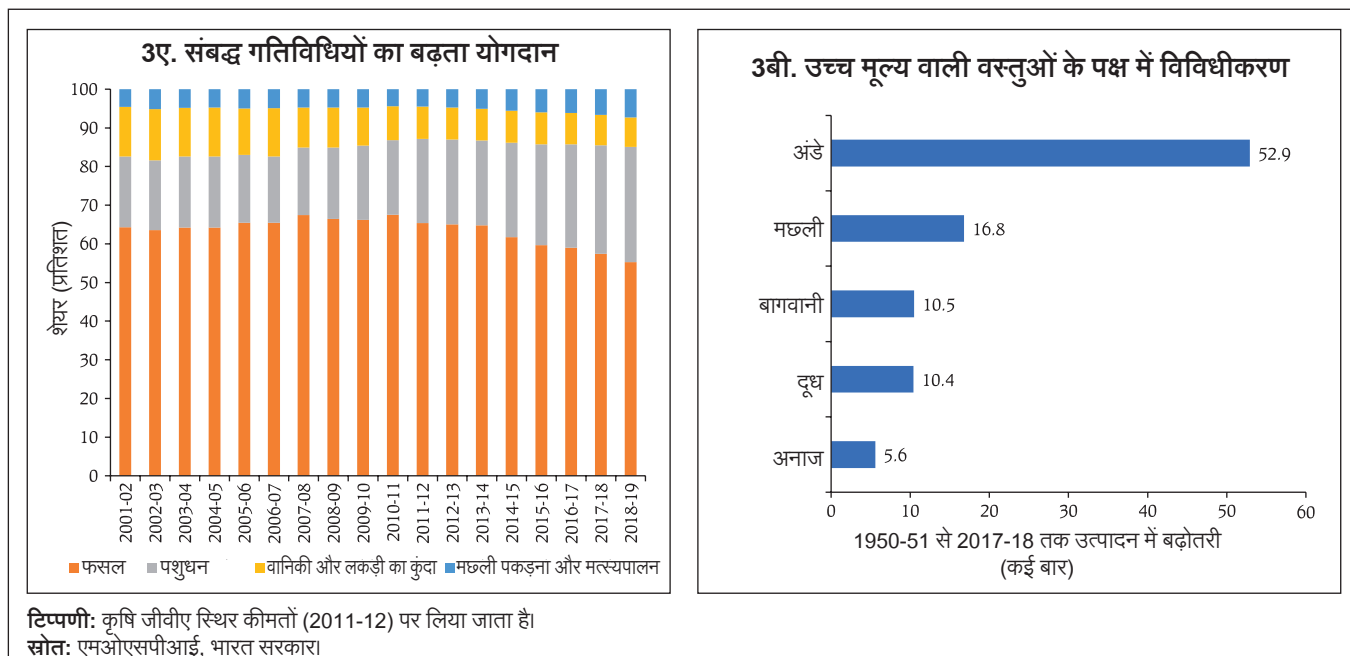
## II. 2 बागवानी फसल में विविधता

बागवानी उत्पादन ने 2012-13 से खाद्यान्न उत्पादन को पीछे छोड़ दिया है और वर्तमान में कृषि क्षेत्र में कुल फसल

उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा है (चार्ट 2ए)। बागवानी उत्पादन में वृद्धि लगभग समान रूप से खाद्यान्नों के मामले में उत्पादकता आधारित वृद्धि की तुलना में क्षेत्रफल और उत्पादकता<sup>1</sup> में वृद्धि से प्रेरित है (चार्ट 2बी)। हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न उत्पादन में प्रतिफल आधारित वृद्धि ने उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों की तरफ विविधिकरण को आसान बना दिया।



<sup>1</sup> कृषि क्षेत्र के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली हेजेल (1984) अपघटन विधि का उपयोग करके उत्पादन वृद्धि का अपघटन किया गया है।



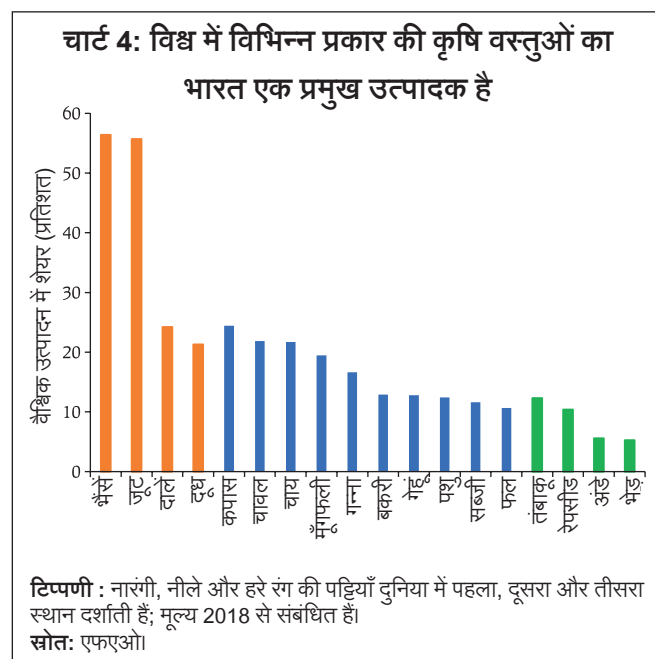
### II.3 संबद्ध गतिविधियों का बढ़ता महत्व

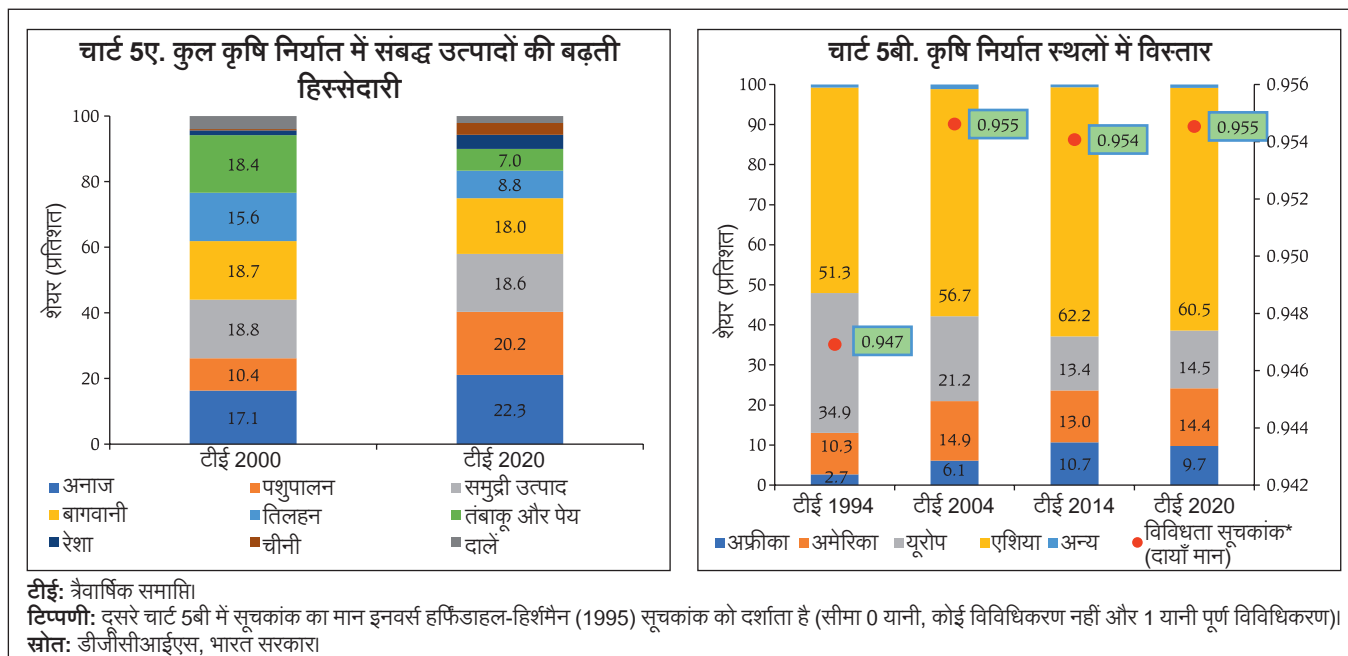
पशुपालन और मछली उत्पादन में मजबूत वृद्धि के कारण पिछले दशक में संबद्ध क्षेत्र ने लगातार महत्व प्राप्त किया है (चार्ट 3ए)। भारतीय पशुधन क्षेत्र ने पिछले दशक (2010-19) के दौरान 6.6 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हासिल की, जिसमें भारत दुनिया में दूध, अंडे और मांस के एक प्रमुख उत्पादक के रूप में उभरा (भारत सरकार, 2019) (चार्ट 3 बी)। परिचालन भूमि जोत के आकार में धीरे-धीरे गिरावट के साथ, पशुधन न केवल छोटे और सीमांत किसानों बल्कि भूमिहीन मजदूरों के लिए स्थिर आजीविका के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रहा है (अली, 2007)।

### II.4 कृषि व्यापार की बदलती गतिकी

जैसा कि भारत दुनिया में विभिन्न कृषि वस्तुओं के एक प्रमुख उत्पादक के रूप में उभरा है (चार्ट 4), कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादों के वैश्विक व्यापार में इसका हिस्सा 2000 में 1.1 प्रतिशत से दोगुना होकर 2018 में 2.2 प्रतिशत हो गया है (भारत सरकार, 2020)। कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने 2020-21 में भारत से कुल निर्यात में 14.2 प्रतिशत का योगदान दिया, इसमें अनाज, बागवानी फसलों, चीनी, पशुधन और समुद्री उत्पादों से लेकर कच्चे और संसाधित दोनों रूपों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं शामिल हैं। भारत के कृषि निर्यात बास्केट में अनाज का सबसे

अधिक हिस्सा (22.3 प्रतिशत) है, जो मुख्य रूप से विश्व बाजार में भारतीय चावल - दोनों बासमती और गैर-बासमती - की उच्च मांग से प्रेरित है। भारत के कृषि निर्यात में पशुपालन की हिस्सेदारी 2000 में 10.4 प्रतिशत से लगभग दोगुनी होकर 2020 में 20.2 प्रतिशत हो गई है, जो मुख्य रूप से भैंस के मांस के निर्यात से प्रेरित है। पिछले दो दशकों में समुद्री और बागवानी उत्पादों का





हिस्सा लगभग 18 प्रतिशत पर लगभग स्थिर रहा है (चार्ट 5ए)। दूसरी ओर, तिलहन और तंबाकू और पेय पदार्थों का निर्यात हिस्सा पिछले कुछ वर्षों में काफी कम हुआ है।

गंतव्य-वार, एशियाई और मध्य पूर्वी देश भारतीय कृषि निर्यात के प्रमुख खरीदार बने हुए हैं, जो आंशिक रूप से 2014 से भारत की एक्ट-ईस्ट नीति के प्रभाव को दर्शाते हैं (चार्ट 5 बी) [चक्रवर्ती और चक्रवर्ती, 2018]। दूसरी ओर, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों की पहुंच उनके उच्च सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) मानदंडों के कारण एक चुनौती बनी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कई कमोडिटी समूहों, विशेष रूप से फलों और सब्जियों के लिए उच्च इनकार या अस्वीकृति दर है। (गोयल एवं अन्य ..., 2017; आरती एवं अन्य..., 2012; और कुमार, 2016)।

### III. प्रमुख वृद्धि समर्थक

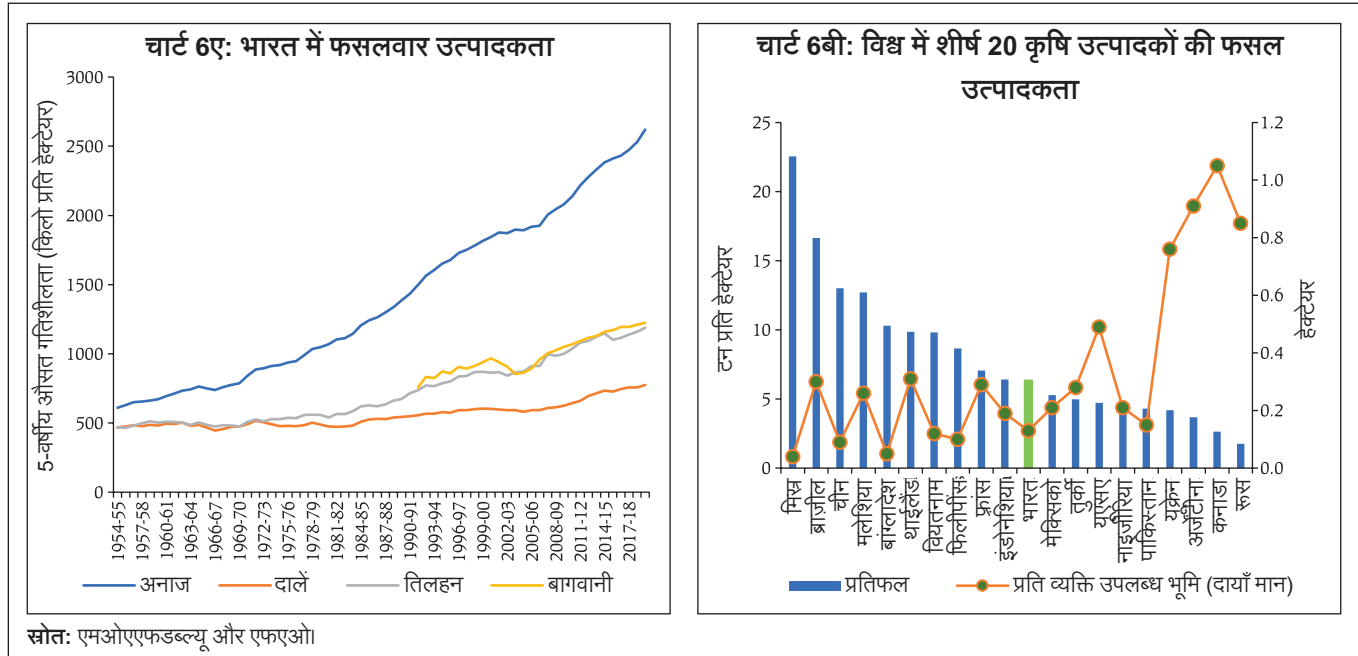
#### III. 1 उत्पादकता वृद्धि

मुख्य रूप से चावल और गेहूं द्वारा संचालित भारत में खाद्यान्न उत्पादकता बहुत तेज गति से बढ़ी है। कई अध्ययनों से पता चला है कि भारतीय कृषि ने उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत, सार्वजनिक अनुसंधान और उर्वरक प्रयोग में निवेश के

साथ उत्पादकता में पर्याप्त लाभ कमाया है (रोजग्रांट एंड इवनसन, 1992; ढोलकिया और ढोलकिया, 1993; इवनसन एवं अन्य..., 1999, फैन एवं अन्य..., 1999, चांद एवं अन्य..., 2012)। अनाज की तुलना में, दलहन, तिलहन, पोषक-अनाज और बागवानी फसलों के मामले में उत्पादकता वृद्धि सुस्त रही (चार्ट 6ए)। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय तुलना से पता चलता है कि भारत में फसल उत्पादकता कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की तुलना में बहुत कम है (चार्ट 6 बी)। भारत में फसल की पैदावार विकसित देशों में हासिल की गई उपज का लगभग 30 से 60 प्रतिशत ही रही है (फिक्की, 2017)।

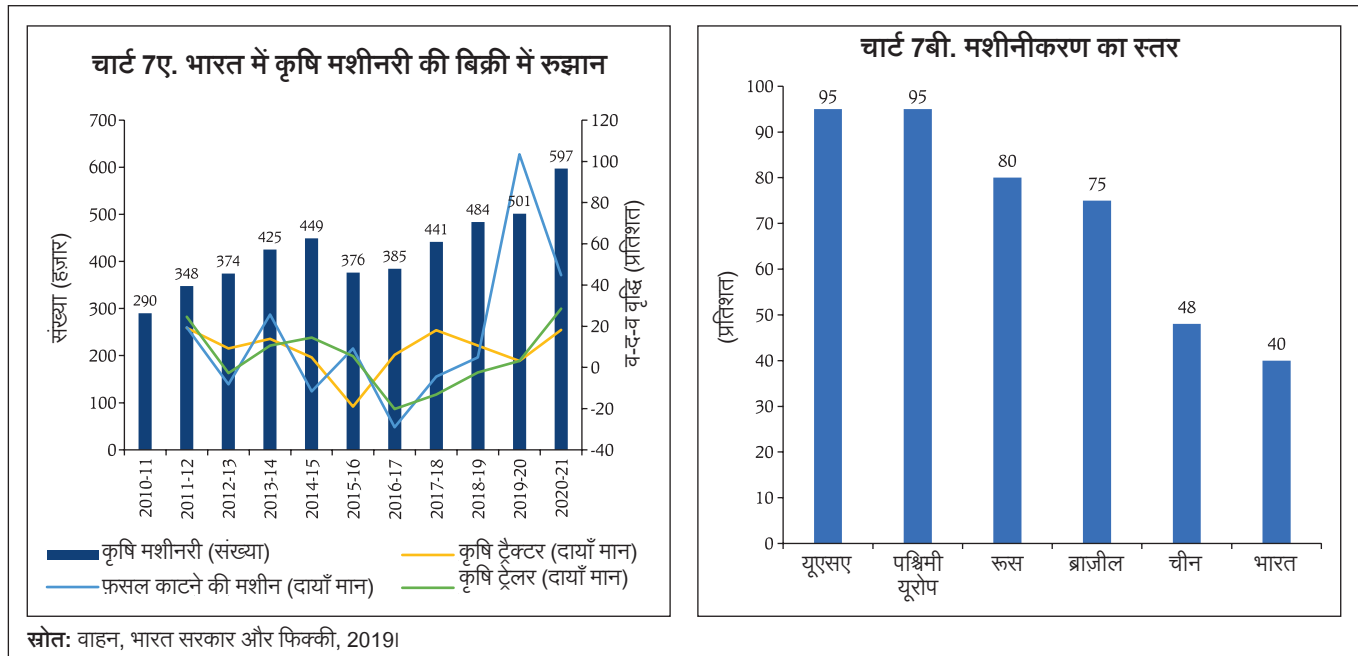
#### III. 2 कृषि यंत्रीकरण

कृषि यंत्रीकरण में कृषि उत्पादकता को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने और इनपुट लागत को 20 प्रतिशत तक कम करने की क्षमता है (नाबार्ड, 2018)। यंत्रीकृत खेती से कृषि कार्यों को पूरा करने में लगने वाला समय भी कम हो जाता है और कृषि श्रम से सहज रूप से जुड़े कठिन परिश्रम को कम कर देता है। भारत में कृषि यंत्रीकरण की सीमा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है और विभिन्न अनुमानों के अनुसार, भारत में कृषि यंत्रीकरण का वर्तमान स्तर 40-45 प्रतिशत है (फिक्की और पीडब्ल्यूसी, 2019; तिवारी एवं



अन्य.., 2019)। दूसरी ओर, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में ट्रैक्टरों का घनत्व काफी बढ़ गया है, पावर टिलर, रोटोवेटर और ट्रांसप्लांटर सहित अन्य कृषि उपकरणों का बाजार अभी भी सीमित और बहुत असंगठित है (कृषि उपकरण बाजार का 15 प्रतिशत) (चार्ट 7 ए) ( फिक्की, 2017)। अंतर्राष्ट्रीय तुलना से

पता चलता है कि भारत में कृषि यंत्रीकरण का स्तर अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और ब्रिक्स देशों की तुलना में बहुत कम है (चार्ट 7 बी)। छोटी और बिखरी हुई भूमि जोत बड़े पैमाने पर लाभ को कम करती है और इस प्रकार भारत में कृषि यंत्रीकरण के और विस्तार में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करती है।



### III.3 बढ़ती सिंचाई कवरेज

भारत में सिंचाई कवरेज में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है जिससे भारतीय कृषि को उच्च उत्पादकता और सूखे जैसे चरम मौसम के झटके की कम संवेदनशीलता के मामले में लाभ हुआ है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 126.7 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बनाई गई है, जो धीरे-धीरे 140 मिलियन हेक्टेयर की अंतिम मूल्यांकन सिंचाई क्षमता की ओर बढ़ रही है (सीडब्ल्यूसी, 2019)। पिछले कुछ वर्षों में लघु सिंचाई के योगदान में वृद्धि हुई है जो छोटे भूमिधारकों की बढ़ती समावेशिता को दर्शाता है (चार्ट 8ए)। 2015-16 के दौरान प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की शुरुआत के साथ, कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई) के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिर प्रगति के बावजूद, भारत में पूर्ण सिंचित क्षेत्र अभी भी 34.4 प्रतिशत तक सीमित है जो 38.6 प्रतिशत के पूर्ण असिंचित क्षेत्र से कम है (चार्ट 8ख)।

### IV. आगे की चुनौतियां

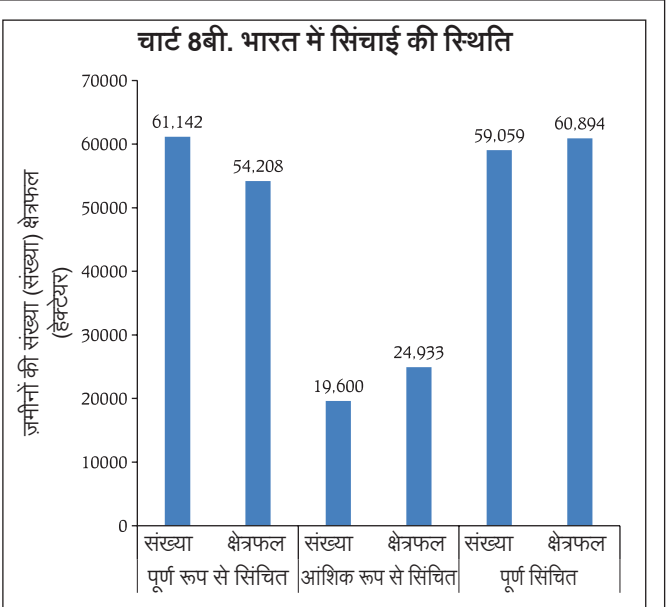
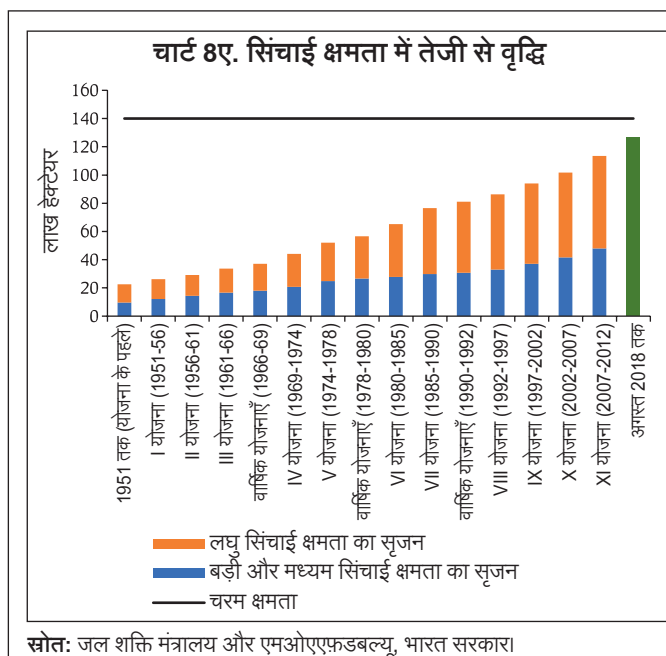
भारतीय कृषि ने पिछले दो दशकों के दौरान रिकॉर्ड उत्पादन, उच्च मूल्य वाले बागवानी में विविधीकरण, पशुधन और समुद्री उत्पादों और कृषि में वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को

दोगुना करने के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, यह क्षेत्र वर्तमान में कई मुद्दों से जूझ रहा है, विशेष रूप से स्थिरता, पोषण, नई कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाना और, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, खेती पर निर्भर आबादी का आय स्तर जिसके लिए भोजन, कृषि और कृषि नीतियों के दीर्घकालिक पुनर्रचना की आवश्यकता होती है। इस खंड में कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

### IV.1 जलवायु परिवर्तन

भारत में कृषि उत्पादकता पर जलवायु कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव जारी है। चरम मौसम की बढ़ती घटनाओं के साथ बढ़ते तापमान ने जलवायु परिवर्तन को भारतीय कृषि और उत्पादकता हानि के लिए एक बड़ा खतरा बना दिया है (आरबीआई, 2020)। मौसम-वार विश्लेषण से पता चलता है कि रबी मौसम (अक्टूबर से फरवरी) से संबंधित महीनों में वर्षा और तापमान में अधिकतम परिवर्तन दर्ज किए गए हैं। दीर्घकालिक सह-आंदोलनों से पता चलता है कि विभिन्न जलवायु चरों में परिवर्तन का रबी और खरीफ फसलों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है।

जबकि दोनों मौसमों में अधिकतम तापमान विसंगतियां संबंधित उपज के साथ एक महत्वपूर्ण नकारात्मक संबंध दर्शाती हैं, न्यूनतम तापमान विसंगतियों के लिए, सहसंबंध केवल रबी





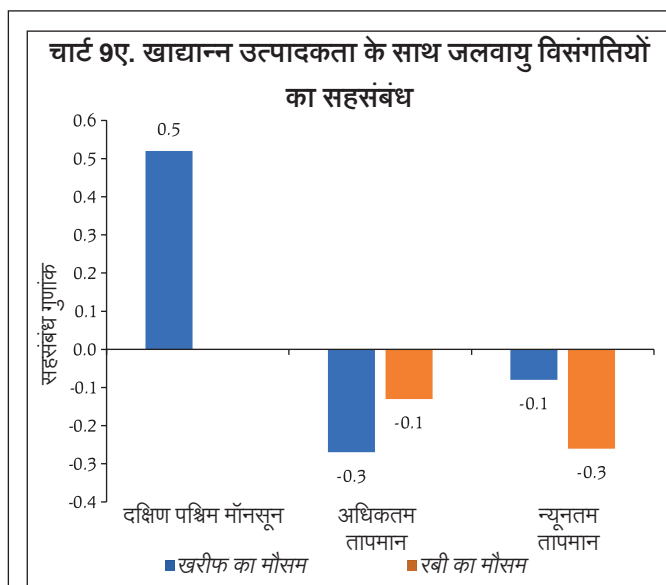
मौसम के मामले में नकारात्मक लेकिन सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण निकला (चार्ट 9ए)। कुल मिलाकर, प्रारंभिक निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि खरीफ मौसम के दौरान अधिकतम तापमान का प्रभाव अधिक प्रमुख होता है जबकि न्यूनतम तापमान की विसंगतियां रबी की फसल की पैदावार को अधिक प्रभावित करती हैं।

पौधों की जैविक वृद्धि में बाधा डालने के अलावा, जलवायु परिवर्तन के कारण कीटों की वृद्धि और रोगों के हमलों से फसल को भी नुकसान होता है। बेमौसम बारिश के साथ बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसम की स्थिति की बढ़ती घटनाएं भी खड़ी फसलों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती हैं। यह देखा गया है कि छोटे और सीमांत किसान इन प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं (प्रवीण और शर्मा, 2020)। ऐसे परिदृश्य में, कृषि आय को बचाने के लिए जलवायु जोखिम कम करने वाली नीतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। 2015-16 में शुरू की गई, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) - दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना - जलवायु संबंधी जोखिमों की एक विस्तृत श्रृंखला के कारण फसल क्षति को कवर करती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि की वृद्धि और स्थिरता दोनों को संतुलित करने के लिए एकीकृत और दीर्घकालिक जलवायु स्मार्ट नीति की आवश्यकता है। ऐसी नीति में स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से ग्राम

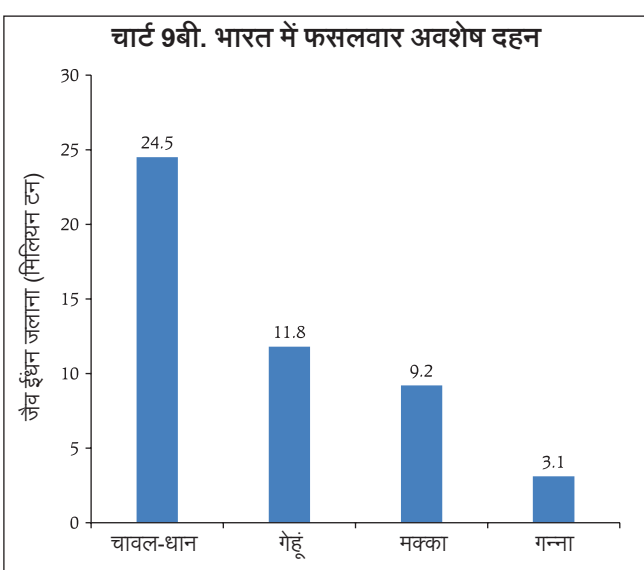
पंचायतों में जागरूकता और क्षमता निर्माण; महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जलवायु अभेद्य परियोजनाओं में तेजी लाना; दबाव सहने वाले काश्तकारों के विकास में गहन शोध; कृषि उत्पादन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना; और अधिक जलवायु प्रतिरोधी दालों और मोटे अनाज की ओर उपभोग टोकरी के विविधीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

### IV.2 कृषि अपशिष्ट प्रबंधन

कृषि अपशिष्ट प्रबंधन एक और बड़ी चुनौती है क्योंकि उत्तरी राज्यों में फसल अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा होता है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। अखिल भारतीय स्तर पर, फसलों के अवशेष जलाना 2018 के दौरान 48.6 मिलियन टन के आंकड़े तक पहुँच गया है, इसमें से 50 प्रतिशत का योगदान अकेले धान द्वारा किया गया (चार्ट 9बी)। उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल और रबी की बुवाई के बीच कम अंतराल के साथ-साथ अवशेष प्रबंधन में किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों - भौतिक (श्रम की अनुपलब्धता) और आर्थिक (हटाने में उच्च लागत) - छोटे और सीमांत किसानों को उसी जगह पर अवशेषों को जलाने के लिए प्रेरित करता है जिसके जलने से वायु प्रदूषण होता है। विशेषज्ञों



**टिप्पणी:** दक्षिण-पश्चिम मानसून की अवधि केवल खरीफ मौसम से संबंधित है।  
**स्रोत:** एमओएफडब्ल्यू; आईएमडी; और एफएओ।



द्वारा कई समाधान सुझाए गए हैं जैसे, ब्रिकेटिंग और कचरे को ईंधन के रूप में बदलना, विभिन्न औद्योगिक उपयोग और माइक्रोबियल डीकंपोजिंग सॉल्यूशन आदि का हालिया हस्तक्षेप, साथ ही स्वस्थानी अवशेष प्रबंधन के लिए बेहतर और प्रभावी मशीनीकरण शामिल है। हालांकि, स्थायी समाधानों को लागत प्रभावशीलता, सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कई हितधारकों की भागीदारी के साथ-साथ उपयुक्तता पर विचार करना चाहिए।

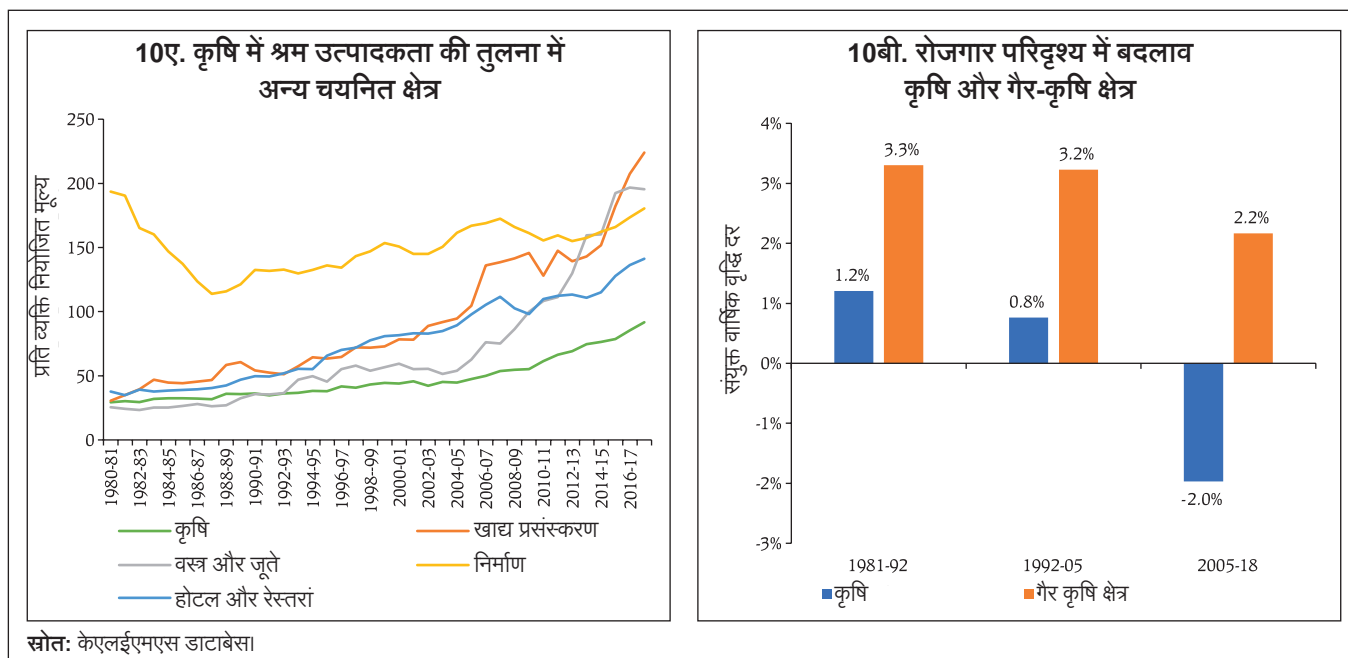
### IV.3 खंडित भूमि जोत

वर्षों से, भारत में कृषि जोत की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन खेती के तहत क्षेत्र में कमी आई है। नतीजतन, जोत के औसत आकार में काफी कमी आई है। देश में जोत का औसत आकार 2015-16 में घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गया है, जो 1970-71 में 2.28 हेक्टेयर था। सीमांत और छोटी जोत भारत में कुल जोत का 86 प्रतिशत है। इस तरह की खंडित भूमि अधिभोग संरचना किसानों के लिए नलकूपों, ड्रिप सिंचाई, भंडारण या थोक इनपुट में व्यावहारिक रूप से निवेश करना लगभग असंभव बना देती है। इस प्रकार उच्च दक्षता के लिए भूमि समेकन महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य

से, भारत में भूमि बाजार कमजोर है और विभिन्न बाधाएं जैसे भूमि अभिलेखों की खराब गुणवत्ता, जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं, भूमि अधिकारों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध, पट्टे, उप-पट्टे और किराये की व्यवस्था भूमि बाजार के विकास में बाधा डालती है (भट्टाचार्य, 2020)। देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि बाजार सुधारों के माध्यम से भूमि जोत के समेकन की आवश्यकता है।

### IV.4 प्रच्छन्न बेरोजगारी

जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में ग्रामीण आबादी 833 मिलियन है, जो कुल का लगभग 68 प्रतिशत है। जबकि कृषि क्षेत्र देश में कुल श्रम शक्ति का 49 प्रतिशत संलग्न करता है, कुल जीवीए में इसका योगदान केवल 17 प्रतिशत है जो कृषि पर भारतीय श्रम शक्ति की अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण छिपी या छिपी हुई बेरोजगारी है और इस प्रकार श्रम उत्पादकता कम है (एफएओ, 2020; जोशी 2005) (चार्ट 10ए)। अध्ययनों से पता चलता है कि कई किसानों [राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा सर्वेक्षण किए गए किसानों में से लगभग 40 प्रतिशत] ने उपयुक्त



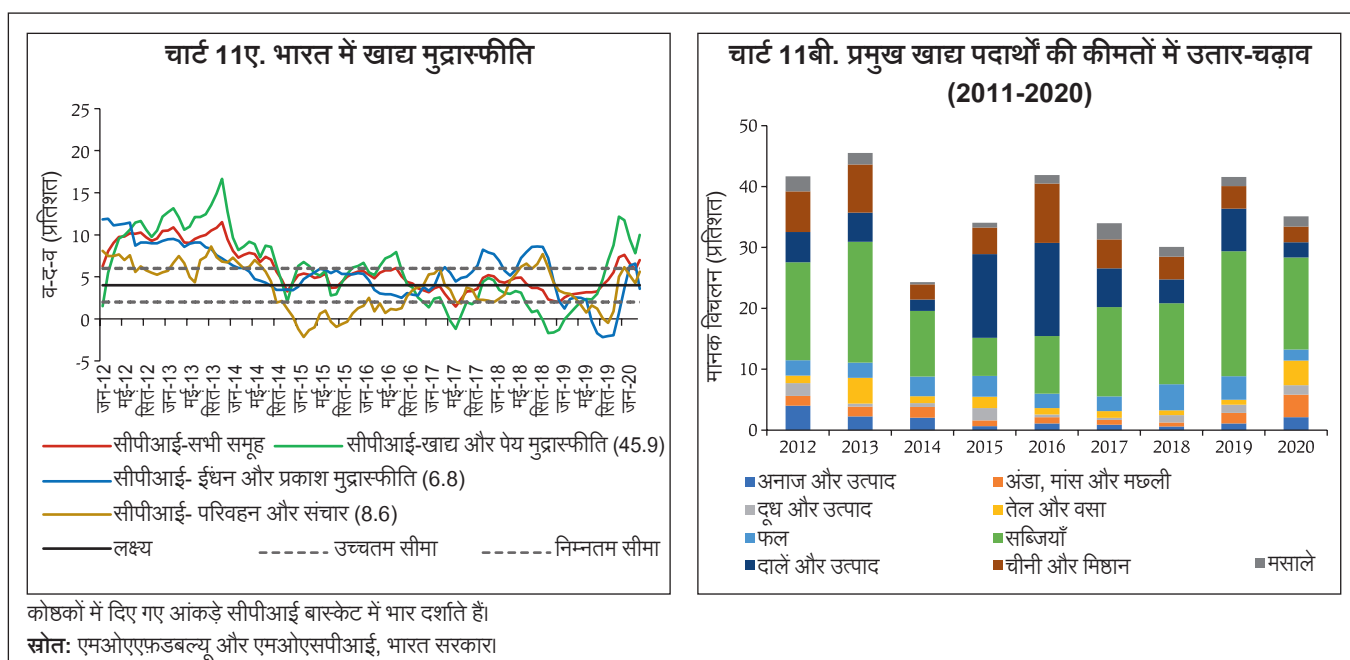
विकल्प मिलने पर खेती से बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की है (चांद, 2017; हिमांशु एवं अन्य., 2016 और चांद और श्रीवास्तव, 2014)। अतिरिक्त श्रम के कृषि से बाहर जाने से, प्रति व्यक्ति भूमि जोत का आकार बढ़ेगा और बदले में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि होगी। हालांकि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक बाधाओं जैसे कम कौशल और शिक्षा के स्तर, ग्रामीण निवासियों के स्थानीय नुकसान और गैर-कृषि क्षेत्रों की सीमित श्रम अवशोषण क्षमता के कारण, बदलाव बहुत धीमी गति से हो रहा है (चांद और श्रीवास्तव, 2014) (चार्ट 10 बी)।

#### IV.5 खाद्य मुद्रास्फीति और खाद्य कीमतों में अस्थिरता

चूंकि भारत में कृषि उत्पादन अभी भी वर्षा और इसके स्थानिक वितरण पर बहुत अधिक निर्भर है, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियाँ जैसे सूखा, बाढ़ और बेमौसम बारिश समग्र आपूर्ति और आपूर्ति श्रृंखला दोनों को बाधित करती हैं, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र में बड़ी अस्थिरता होती है। इसके अलावा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में अक्षमता - थोक / फार्म गेट कीमतों पर उच्च और अस्थिर खुदरा मूल्य बढ़ोतरी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के सीमित स्तर - भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को

प्रभावित करते हैं (भोई एवं अन्य., 2019; धन्या एवं अन्य., 2020)।

जबकि 2014-15 के बाद से खाद्य मुद्रास्फीति का समग्र स्तर कम हुआ है, खाद्यान्नों और बागवानी फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ-साथ कम वैश्विक खाद्य कीमतों द्वारा समर्थित, खाद्य मुद्रास्फीति में अस्थिरता उच्च बनी हुई है (चार्ट 11 ए)। हेडलाइन मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव में खाद्य और विशेष रूप से सब्जियों का योगदान गैर-खाद्य वस्तुओं की तुलना में काफी अधिक है, जो फसल की खराब होने वाली प्रकृति, लघु फसल चक्र, पर्याप्त भंडारण की कमी और फसल पूर्व और बाद की खराब प्रथाओं को दर्शाता है। (आरबीआई, 2020)। यहां तक कि गैर-नाशयोग्य जैसे दालों और अनाजों ने भी काफी अस्थिरता प्रदर्शित की है (चार्ट 11बी)। सामान्य तौर पर, भारत में कृषि उत्पादों की कीमतों ने एक मकड़जाल दर्शाते हैं, यानी आपूर्ति प्रतिक्रिया के आधार पर वैकल्पिक वर्षों में कीमतों का उच्च और निम्न होना। कटाई के बाद के नुकसान को कम करने, भंडारण के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास और खाद्य सुरक्षा मानकों के उन्नयन के मामले में आपूर्ति प्रबंधन की भूमिका इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का निवेश



फसल कटाई के बाद की कुशल प्रथाओं के लिए आवश्यक कृषि इनफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

#### IV.5.1 फसलोत्तर हानियों को कम करना

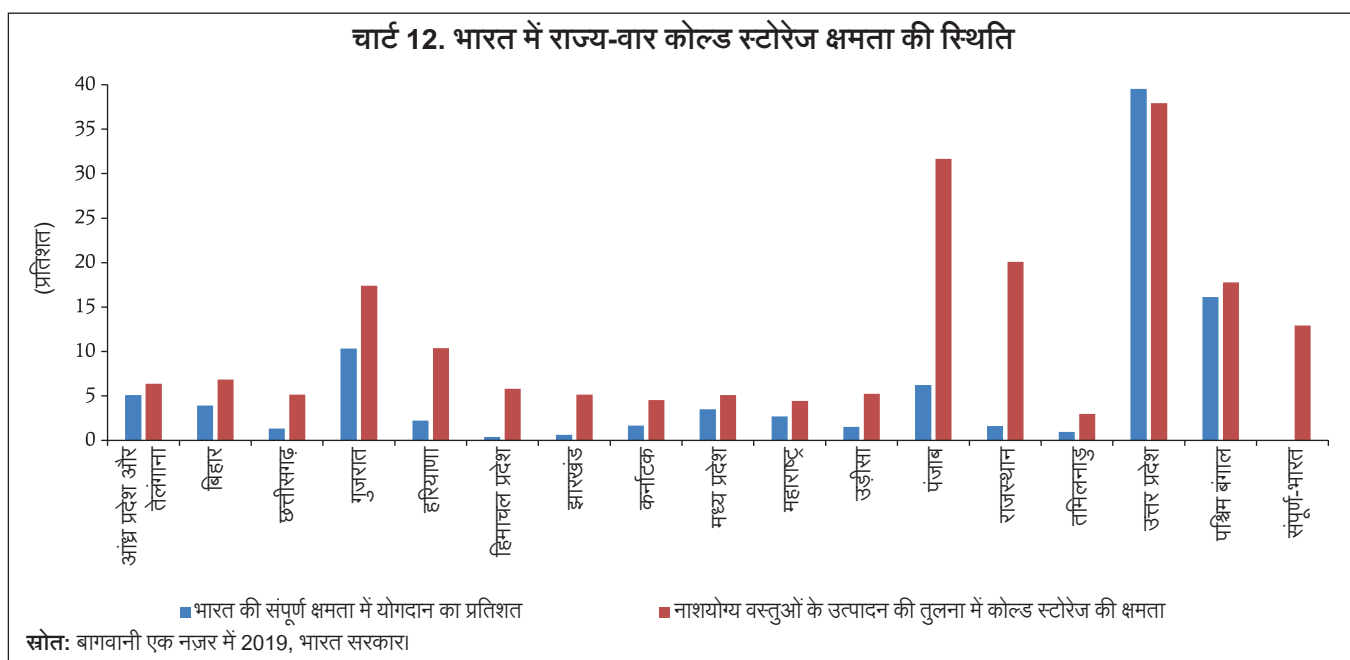
भारत में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के पीछे अकुशल फसलोत्तर प्रथाओं के कारण खाद्य उत्पादों की बर्बादी महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। खाद्य मूल्य श्रृंखला के सभी स्तरों पर बर्बादी होती है - किसानों के स्तर से लेकर ट्रांसपोर्टर्स, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के स्तर तक। बर्बादी कई स्रोतों जैसे फसल की क्षति, अनुचित कटाई तकनीक, खराब पैकेजिंग, भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी आदि के परिणामस्वरूप होती है। गैर-नाशयोग्य खाद्य पदार्थों की तुलना में फलों और सब्जियों जैसे खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए फसल के बाद के नुकसान काफी अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए, आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट-हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के एक अध्ययन में गैर-नाशयोग्य फसलों जैसे अनाज, दलहन और तिलहन में 4.6-9.9 प्रतिशत की सीमा में; जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों में 4.6-15.9 प्रतिशत की सीमा में कटाई के बाद की बर्बादी और 2.7 -6.7 प्रतिशत की सीमा में मांस; और

5.2-10.5 प्रतिशत की सीमा में मछली की बर्बादी का अनुमान लगाया गया है; (आईसीएआर-सिपेट, 2015)

कृषि अर्थशास्त्रियों ने माना है कि कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग और कोल्ड ट्रांसपोर्ट चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के माध्यम से बर्बादी को कम करके कृषि उपज, विशेष रूप से फलों और सब्जियों जैसी बागवानी फसलों की उपलब्धता बढ़ाने की जबरदस्त संभावना है। इसके अलावा, कटाई के बाद के प्रसंस्करण में सुधार से फसल के बाद के नुकसान को भी कम किया जा सकता है और खराब होने वाले उत्पादों के शेल्व जीवन को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से कटाई के बाद के नुकसान में कमी से खाद्य उपलब्धता में वृद्धि होगी और खाद्य कीमतों में अस्थिरता कम होगी जो उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के लिए फायदेमंद होगी।

#### IV.5.2 भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना

भारत में कोल्ड स्टोरेज सुविधा की वर्तमान उपलब्धता अत्यधिक विषम है क्योंकि देश की कुल क्षमता का लगभग 70 प्रतिशत चार राज्यों - उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और गुजरात तक सीमित है, जबकि बड़ी निर्यात क्षमता वाले महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं (चार्ट 12)। जबकि भारत में अधिकांश (68 प्रतिशत) कोल्ड स्टोरेज का



उपयोग आलू के भंडारण के लिए किया जाता है, केवल 30 प्रतिशत का उपयोग बहु-वस्तु भंडारण के लिए किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप क्षमता का सही उपयोग नहीं होता है (चक्रवर्ती, 2020)। इसके अलावा, केवल कोल्ड स्टोरेज क्षमता की उपलब्धता का सीमित लाभ है जब तक कि इसे संपूर्ण कोल्ड चेन के विकास के साथ एकीकृत नहीं किया जाता है, जिसमें प्री-कूलिंग, पैक-हाउस, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट से लेकर रेफ्रिजरेटेड मार्केटिंग डिस्प्ले तक के विभिन्न चरणों को शामिल किया जाता है, जब तक कि यह अंतिम उपभोक्ता तक नहीं पहुंच जाता। जबकि समग्र कोल्ड स्टोरेज क्षमता ने कुछ पकड़ दिखाई है, संबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता आवश्यकता से काफी कम है (सारणी 1)। अनियमित बिजली आपूर्ति, उच्च प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता, अपर्याप्त फार्म-गेट और मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल जनशक्ति की सीमित उपलब्धता, मानक प्रोटोकॉल की कमी और खराब होने वाली वस्तुओं की अक्षम हैंडलिंग वर्तमान में भारत में कोल्ड चेन विकास में कुछ प्रमुख बाधाएं हैं (यस बैंक, 2018)।

#### IV.5.3 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास

खाद्य प्रसंस्करण एक उभरता हुआ उद्योग है और भारत में प्रसंस्कृत खाद्य की मांग तेजी से शहरीकरण, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने और अधिक महिलाओं के कार्यबल में शामिल होने के साथ

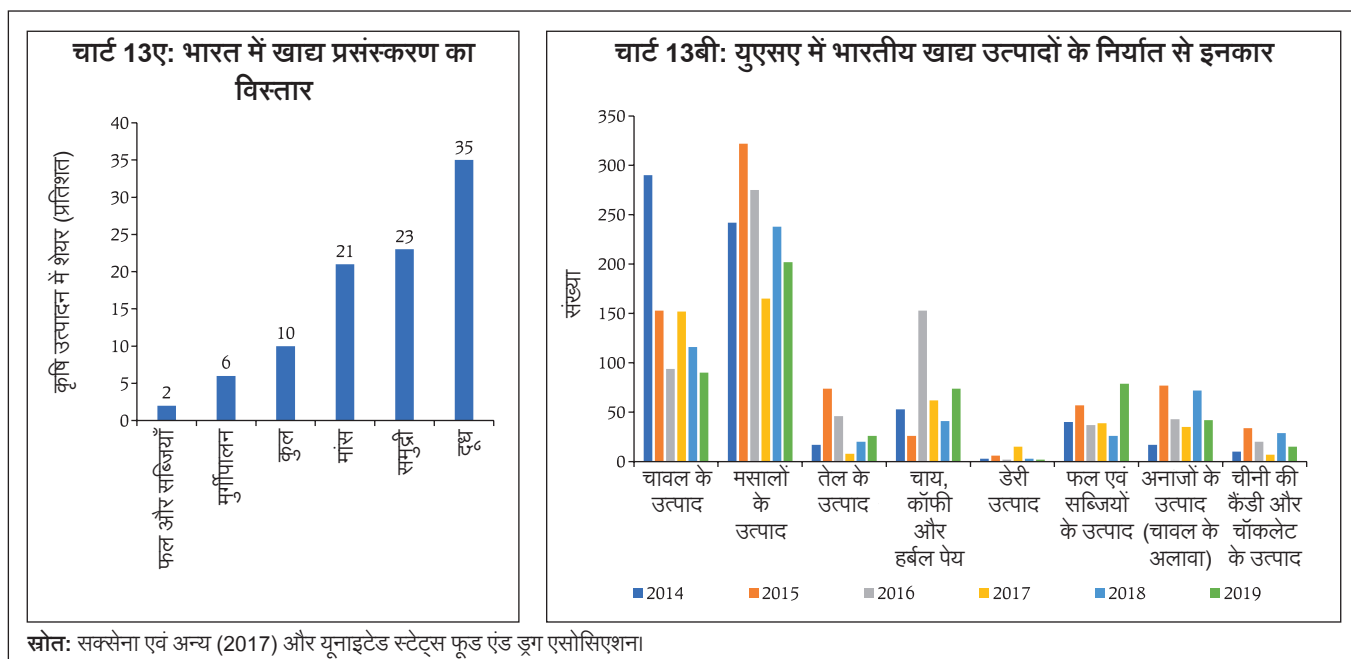
**सारणी 1: भारत में कोल्ड सप्लाय चैन इंफ्रास्ट्रक्चर (2015 एनसीसीडी रिपोर्ट)**

इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रकार	अखिल भारतीय आवश्यकता (1)	अखिल भारत में जो बनाया (2)	अंतराल (1-2)
पैक-हाउस (इकाइयाँ)	70,080	249	69,831
कोल्ड स्टोरेज (मिलियन टन)	35.1	36.7*	-
रीफर वाहन (इकाइयाँ)	61,826	9,000	52,826
पकने का कक्ष (इकाइयाँ)	9,131	812	8,319

\*: आंकड़ा मार्च 2019 तक है।

स्रोत: एनसीसीडी (2015): अखिल भारतीय कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता - स्थिति और अंतर का आकलन।

लगातार बढ़ने की संभावना है। विशाल विकास क्षमता होने के बावजूद, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वर्तमान में एक प्रारंभिक चरण में है - देश में उत्पादित कुल खाद्य का 10 प्रतिशत से भी कम के लिए जिम्मेदार है (चार्ट 13 ए)। अन्य उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में यह आंकड़ा बहुत कम है। उदाहरण के लिए, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के भीतर भी, थाईलैंड में कृषि उत्पादों के समग्र प्रसंस्करण का योगदान 30 प्रतिशत है; ब्राजील में 70 प्रतिशत; फिलीपींस में 78 प्रतिशत; और मलेशिया में 80 प्रतिशत (धन्या एवं अन्य., 2020)। एक और उल्लेखनीय पहलू यह है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वर्तमान में घरेलू रूप से उन्मुख है - प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन का केवल 12 प्रतिशत निर्यात किया जा रहा है। भारत



प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में अपना हिस्सा बढ़ाकर वैश्विक कृषि मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ सकता है।

#### IV.5.4 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का उन्नयन

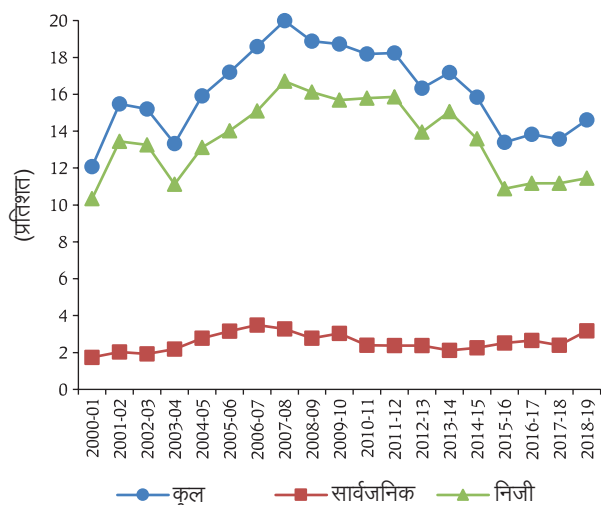
एशियाई और मध्य पूर्वी देश भारतीय कृषि निर्यात के लिए प्रमुख स्थान बने हुए हैं, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाजारों में प्रवेश उनके उच्च स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) मानदंडों के कारण एक चुनौती बना हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय उत्पादों के लिए इनकार या अस्वीकृति की संभावना अधिक रहती है (चार्ट 13बी)। मसाले और चावल आधारित उत्पादों (क्रमशः 37 और 23 प्रतिशत) को काफी अधिक नकारा जाता रहा है। इनकार या तो मिलावट या गलत ब्रांडिंग के आधार पर किया जाता है। अच्छी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना, उत्पादन और प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियों के साथ पिछड़ा एकीकरण, उचित पैकेजिंग और प्रमाणन सीमा अस्वीकृति को कम कर सकता है, एसपीएस मानदंडों का अनुपालन बढ़ा सकता है और उच्च आय वाले देशों में निर्यात पैठ को बढ़ावा दे सकता है। चूंकि फाइटोसैनिटरी मानक समय के साथ बदलते रहते हैं और आयातक देशों में अलग-अलग होते हैं, इसलिए संभावित निर्यातकों के बीच बदलते मानकों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक तंत्र तैयार किया जा सकता है जो उन्हें फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र प्राप्त करने में मदद करेगा।

#### IV. 5. 5 उच्च सार्वजनिक निवेश

पूंजी निर्माण कृषि में वृद्धि और विकास की कुंजी है। कृषि जीवीए के प्रतिशत के रूप में भारतीय कृषि में पूंजी निर्माण, हालांकि, हाल की अवधि में कम हुआ है (चार्ट 14 ए)। कृषि में पूंजी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा निजी क्षेत्र की तुलना में बहुत कम है। जबकि कृषि में सार्वजनिक निवेश मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, सिंचाई, अनुसंधान और विस्तार सेवाओं का गठन करता है, निजी निवेश – हाउसहोल्ड द्वारा प्रभावित - या तो प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए या संबद्ध गतिविधियों से किसानों के आय स्रोतों के पूरक के लिए किया जाता है (गोलाइट और लोकारे, 2008)।

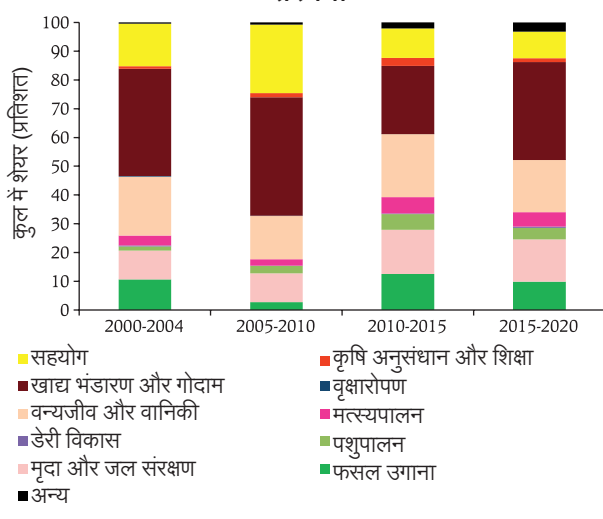
पिछले दो दशकों के दौरान सार्वजनिक निवेश बड़े पैमाने पर कृषि जीवीए के 1.7- 3.5 प्रतिशत के आसपास रहा। सार्वजनिक निवेश के भीतर, राज्य सरकारों का योगदान केंद्र सरकार की तुलना में काफी अधिक है, जिसमें लघु और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा है (80 प्रतिशत)। राज्य सरकार के निवेश के अन्य प्रमुख मदों में खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग, मिट्टी और जल संरक्षण, सहकारिता, फसल पालन, संबद्ध क्षेत्र आदि शामिल हैं (चार्ट 14 बी)। विश्व स्तर पर, भारत

चार्ट 14ए. कृषि-जीवीए के प्रतिशत के रूप में कृषि-जीसीएफ



स्रोत: राज्य वित्त (विभिन्न वर्ष) भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 14बी: कृषि और संबद्ध क्षेत्र में राज्य केपेक्स की संरचना



कृषि में सकल अचल पूंजी निर्माण के मामले में प्रमुख कृषि उत्पादक देशों से पीछे है (एफएओ, 2020)।

### V. अनुभवजन्य विश्लेषण और परिणाम

जबकि अधिकांश मौजूदा साहित्य लागत-प्रेरित (ग्रामीण मजदूरी, उत्पादन की लागत), मांग-जनित (बदलते खपत प्रारूप), वैश्विक (अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और ईंधन की कीमतें) और नीति संबंधी (मौद्रिक और राजकोषीय विस्तार, एमएसपी, खरीद) कारकों की गणना करता है जो भारत में खाद्य मुद्रास्फीति और अस्थिरता के प्रमुख चालकों के रूप में हैं (भट्टाचार्य और अन्य., 2017; शेखर एवं अन्य., 2017; अहमद और सिंगला, 2014; कोर्नहर और कालकुहल, 2013), हमने अनुभवजन्य रूप से भारत में औसत खुदरा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले विभिन्न आपूर्ति पक्ष चर जैसे कि निवेश, भंडारण अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण क्षमता, मानसून प्रदर्शन, ग्रामीण मजदूरी और सकल फसल क्षेत्र (जीसीए) और विशेष रूप से खराब होने वाले खाद्य पदार्थों पर ध्यान देने के साथ खाद्य कीमतों में अस्थिरता की भूमिका का आकलन करने का प्रयास किया है (फल और सब्जियां)।

अध्ययन में 2007-08 से 2018-19 तक की अवधि के लिए 16 प्रमुख कृषि राज्यों<sup>2</sup> के डेटा शामिल हैं, जिसमें उच्च औसत मुद्रास्फीति (2007-2013) और कम औसत मुद्रास्फीति (2014-2018) दोनों के वर्ष शामिल हैं। हमने साथ चार मॉडलों पर विचार किया है; (i) औसत खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति (ii) खाद्य मुद्रास्फीति में अस्थिरता; (iii) औसत खराब होने वाली वस्तुओं की मुद्रास्फीति; और (iv) खराब होने वाली वस्तुओं की मुद्रास्फीति में क्रमशः आश्रित चर के रूप में अस्थिरता। औसत खुदरा मुद्रास्फीति (मासिक व-द-व परिवर्तनों का वार्षिक औसत) और अस्थिरता (मासिक मुद्रास्फीति का मानक विचलन) को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) का उपयोग करके मापा गया है। विश्लेषण में विचार किए गए व्याख्यात्मक चर हैं - सार्वजनिक निवेश, कोल्ड स्टोरेज क्षमता, खाद्य प्रसंस्करण जीवीए, दक्षिण-पश्चिम मानसून का प्रदर्शन, सकल फसल क्षेत्र और ग्रामीण मजदूरी। मानसून को छोड़कर सभी व्याख्यात्मक चर

वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में लिए जाते हैं, जिसके लिए 1 के मान वाले डमी चर का उपयोग सामान्य मानसून वर्षों के लिए किया जाता है और 0 का उपयोग अन्यथा किया जाता है। यह उम्मीद की जाती है कि सार्वजनिक निवेश, कोल्ड स्टोरेज क्षमता, खाद्य प्रसंस्करण जीवीए, जीसीए के साथ-साथ सामान्य मानसून जैसे आपूर्ति पक्ष चर में उच्च वृद्धि का औसत खाद्य मुद्रास्फीति के साथ-साथ इसकी अस्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जबकि ग्रामीण मजदूरी में तेजी से वृद्धि होगी जिससे मुद्रास्फीति में एक लागत जनित वृद्धि देने की उम्मीद है। मुख्य चरों के सारांश आँकड़े अनुबंध सारणी 1 में दिए गए हैं। एक साथ किए गए ओएलएस<sup>3</sup> अनुमान के परिणाम सारणी 2 में दिए गए हैं।

अनुभवजन्य अभ्यास के परिणाम मोटे तौर पर केवल कुछ अपवादों के साथ अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। यह देखा जा सकता है कि सार्वजनिक निवेश में उच्च वृद्धि (मॉडल 2,3,4), कोल्ड स्टोरेज क्षमता (मॉडल 2,3,4), खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन (मॉडल 3,4), सकल फसल क्षेत्र (मॉडल 1,2, 3,4) और सामान्य मानसून (मॉडल 1,2,3) के औसत से खाद्य मुद्रास्फीति और भारत में इसकी अस्थिरता पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर, तेज वेतन वृद्धि मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा देती है (मॉडल 1,2,3)।

**सारणी 2: भारत में खाद्य कीमतों में खाद्य मुद्रास्फीति और अस्थिरता के आपूर्ति पक्ष निर्धारक**

	आश्रित चर			
	मॉडल 1	मॉडल 2	मॉडल 3	मॉडल 4
	औसत खाद्य मुद्रास्फीति	खाद्य मुद्रास्फीति में अस्थिरता	खराब होने वाली वस्तुओं में औसत मुद्रास्फीति	खराब होने वाली वस्तुओं में मुद्रास्फीति में अस्थिरता
स्थिर	3.32***	2.49***	2.78***	12.32***
सार्वजनिक निवेश	0.01***	-0.004***	-0.01***	-0.02***
कोल्ड स्टोरेज की क्षमता	0.03***	-0.001**	-0.03***	-0.01**
जीवीए खाद्य प्रसंस्करण	-	-	-0.03***	-0.005***
सकल फसली क्षेत्र	-0.01***	-0.004***	-0.02***	-0.01***
मानसून_डमी	-1.14***	-0.26***	-0.62***	0.10
वेतन	0.42***	0.04***	0.56***	-0.001
समायोजित आर-वर्ग	0.38	0.11	0.22	0.05
एफ-आँकड़े	376.02	80.65	147.29	25.86
प्रसंभाव्य (एफ-आँकड़े)	0.00	0.00	0.00	0.00

<sup>2</sup> आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

<sup>3</sup> हाँसमैन टेस्ट और रिडंडेंट फिक्स्ड इफेक्ट टेस्ट (संभावना अनुपात) के परिणाम बताते हैं कि यादृच्छिक/निश्चित प्रभाव मॉडल की तुलना में इकट्ठे किए गए ओएलएस डेटा सेट के लिए अधिक उपयुक्त हैं।

## VI. निष्कर्ष और आगे का रास्ता

भारतीय कृषि ने विभिन्न खाद्यान्नों, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ नई ऊंचाइयों को छुआ, कोविड अवधि के दौरान आघातसहनीयता प्रदर्शित किया और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। हालांकि, इस क्षेत्र को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके शमन के लिए एक समग्र नीतिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भारत में फसल उत्पादकता विभिन्न कारकों के कारण अन्य उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है, जैसे, खंडित भूमि जोत, कम कृषि मशीनीकरण और कृषि में कम सार्वजनिक और निजी निवेश। दूसरा, चावल, गेहूं और गन्ने जैसी फसलों के वर्तमान अति-उत्पादन ने भूजल स्तर में तेजी से कमी, मिट्टी की गिरावट और बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण के कारण भारत में वर्तमान कृषि प्रथाओं की पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में सवाल खड़े कर दिया है। तीसरा, कई वस्तुओं में अधिशेष उत्पादन के बावजूद, खाद्य मुद्रास्फीति और कीमतों में अस्थिरता उच्च बनी हुई है जिससे उपभोक्ताओं को असुविधा होती है और किसानों के लिए कम और उतार-चढ़ाव वाली आय होती है। इस पेपर में किए गए अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि कम सार्वजनिक निवेश, अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज क्षमता और नवजात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे आपूर्ति पक्ष की बाधाएं भारत में खाद्य कीमतों में अस्थिरता के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कृषि-जल-ऊर्जा गठजोड़ पर केंद्रित दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता होगी, जिससे कृषि को अधिक जलवायु प्रतिरोधी और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बनाया जा सके। जैव प्रौद्योगिकी और प्रजनन का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल, रोग प्रतिरोधी, जलवायु-सुदृढ़, अधिक पौष्टिक और विविध फसल किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण होगा। डिजिटल प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवाओं का व्यापक उपयोग किसानों के बीच सूचना साझा करने और जागरूकता पैदा करने में सहायक होगा। फसल कटाई के बाद के बेहतर प्रबंधन और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन के माध्यम से सहकारी आंदोलन में सुधार से खाद्य कीमतों और किसानों की आय में उतार-चढ़ाव को रोका जा सकता है और भारतीय कृषि की वास्तविक क्षमता का दोहन करने में मदद मिल सकती है।

## संदर्भ

- Arathi, L. R., Kumar, S., Negi, D. S., & Singh, D. R. (2012). Prevailing standards and dimensions governing Sanitary and Phyto-Sanitary compliance in Indian black pepper supply chain. *Agricultural Economics Research Review*, 25(1), 69-78.
- Ahmed, M., & Singla, N. (2014). An analysis of major determinants of food inflation in India. *Indian Journal of Economics and Development*, 10(3), 275-282.
- Ali, J. (2007). Livestock sector development and implications for rural poverty alleviation in India. *Livestock Research for Rural Development*, 1-14.
- Bhattacharya, R. (2017). Effectiveness of monetary policy in stabilising food inflation: Evidence from advanced and emerging economies. *National Institute of Public Finance and Policy*. New Delhi.
- Bhattacharjee, S. (2020). Current Land Issues in India: Puzzles and Possible Solutions. Institute of South Asian Studies -Insights (630), National University of Singapore.
- Bhoi, B.B., Kundu, S., Kishore, V., & Suganthi, D. (2019, October) Supply Chain Dynamics and Food Inflation in India. *RBI Bulletin*, pp. 95-111.
- Central Water Commission (CWC). (2019). Yearbook of Water Statistics. Government of India.
- Chakraborty, D., & Chakraborty, A. (2018). India's Act East Policy: Walking the Talk. *MPRA Paper 88034*, University Library of Munich, Germany.
- Chakraborty, M. (2020). Cold Storage in India: Challenges and Prospects. *Agriculture and food: E-newsletter*, pp. 458-460
- Chand, R. (2017). Presidential Address: Doubling Farmers' Income: Strategy and Prospects. *Indian Journal of Agricultural Economics*, 71(1), 1-23.
- Chand, R., & Parappurathu, S. (2012). Temporal and Spatial Variations in Agricultural Growth and Its Determinants. *Economic and Political Weekly*, 55-64.
- Chand, R., & Srivastava, S. K. (2014). Changes in the rural labour market and their implications for agriculture. *Economic and Political Weekly*, 47-54.



- Chand, R., Kumar, P., & Kumar, S. (2012). Total Factor Productivity and Returns to Public Investment on Agricultural Research in India. *Agricultural Economics Research Review*, 25(2), 181-194.
- Chandrasekhar, C.P. & Ghosh, J. (2021, May 31). The Centre's niggardly allocation of free food grain. *The Hindu Business Line*. <https://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/c-p-chandrasekhar/the-centres-niggardly-allocation-of-free-foodgrain/article34691962.ece>
- Dhanya, V., Shukla, A. K., & Kumar, R. (2020, March). Food Processing Industry in India: Challenges and potential. *RBI Bulletin*, pp. 27-41.
- Dholakia, R. H., & Dholakia, B. H. (1993). Growth of Total Factor Productivity in Indian Agriculture. *Indian Economic Review*, 25-40.
- Evenson, R. E., Pray, C., & Rosegrant, M. W. (1998). *Agricultural research and productivity growth in India* (Vol. 109). International Food Policy Research Institute.
- Fan, S., Hazell, P. B., & Thorat, S. (1999). *Linkages between government spending, growth, and poverty in rural India* (Vol. 110). International Food Policy Research Institute.
- FAO (2020). World Food and Agriculture - Statistical Yearbook 2020. Rome
- FICCI, & PwC. (2019). Farm mechanisation: Ensuring a sustainable rise in farm productivity and income.
- FICCI. (2017). Mechanisation - Key to higher productivity to double farmers' income.
- GoI. (2019). *Agricultural Statistics at a glance*. Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare, Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
- GoI. (2020). Foreign Trade Statistics. Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, <http://www.dgciskol.gov.in/>
- Golait, R., & Lokare, S. M. (2008). *Capital Adequacy in Indian Agriculture: A Reponse*. Reserve Bank of India.
- Goyal, T. M., Mukherjee, A., & Kapoor, A. (2017). India's exports of food products: Food safety related issues and way forward.
- Hazell, P. B. (1984). Sources of increased instability in Indian and US cereal production. *American Journal of Agricultural Economics*, 66(3), 302-311.
- Himanshu, H., Jha, P., & Rodgers, G. (2016). *The changing village in India: Insights from longitudinal research*. Oxford University Press.
- Jha SN, Vishwakarma RK, Ahmad T, Rai A and Dixit AK (2015). Report on assessment of quantitative harvest and post-harvest losses of major crops and commodities in India. ICAR-All India Coordinated Research Project on Post-Harvest Technology, ICAR-CIPHET, P.O.-PAU, Ludhiana-141004.
- Kornher, L & Kalkhul, M. (2013) Food price volatility in developing countries and its determinants. *Quarterly Journal of International Agriculture* 52(4):277-308.
- Kumar, C. N. (2016). *Sensitivity of India's Agri-food Exports to the European Union: An Institutional Perspective*. Institute for Social and Economic Change.
- National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). (2018). Sectoral paper on farm mechanisation. Mumbai: Farm Sector Policy Department, NABARD Head Office.
- Periodic Labour Force Survey (PLFS). (2020). Annual Report. Government of India.
- Praveen, B., & Sharma, P. (2020). Climate change and its impact on Indian agriculture: An econometric analysis. *Journal of Public Affairs*, e1972.
- Reserve Bank of India (2020). Annual Report, 2019-20.
- Reserve Bank of India (2021). The Report on Currency and Finance, 2020-21.

Rosegrant, M. W., & Evenson, R. E. (1992). Agricultural productivity and sources of growth in South Asia. *American Journal of Agricultural Economics*, 74(3), 757-761.

Saxena, R., Singh, N. P., Balaji, S. J., Ahuja, U., Kumar, R., & Joshi, D. (2017). Doubling Farmers' Income in India by 2022–23: Sources of Growth and Approaches. *Agricultural Economics Research Review*, 30(2), 265-277.

Sekhar, C. S. C., Roy, D., & Bhatt, Y. (2017). *Food inflation and food price volatility in India: Trends and determinants* (Vol. 1640). Intl Food Policy Res Inst.

Tiwari, P. S., Singh, K. K., Sahni, R. K., & Kumar, V. (2019). Farm mechanisation—trends and policy for its promotion in India. *Indian Journal of Agricultural Sciences*, 89(10), 1555-1562.

United States Food and Drug Association. (various years). Import Refusal Report.

**अनुबंध सारणी 1. आंकड़ों का सारांश**

चरों में वृद्धि	औसत खाद्य मुद्रास्फीति		खाद्य मुद्रास्फीति में अस्थिरता		खराब होने वाली वस्तुओं में औसत मुद्रास्फीति		खराब होने वाली वस्तुओं में मुद्रास्फीति में अस्थिरता		सार्वजनिक निवेश		कोल्ड स्टोरेज क्षमता		जीवीए खाद्य प्रसंस्करण		सकल फसली क्षेत्र		मानसून का सामान्य से विचलन		ग्रामीण वेतन		
	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन	
States																					
आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	13.2	3.4	3.2	1.4	8.4	6.9	8.7	9.0	4.9	28.6	8.7	6.4	13.8	41.9	-3.0	14.0	-1.9	17.0	13.4	6.7	
असम	10.3	2.6	2.3	1.2	7.0	3.9	8.4	12.1	27.3	65.6	6.8	4.8	10.8	39.8	0.6	1.8	-11.1	11.5	11.4	6.8	
छत्तीसगढ़	14.1	3.3	2.6	0.7	7.6	4.5	7.0	11.6	2.0	31.1	2.7	3.3	13.0	35.8	-0.3	2.8	-14.3	21.4	12.4	7.9	
गुजरात	12.3	4.8	3.6	1.6	7.4	5.6	7.5	10.1	7.1	35.6	11.6	4.6	17.8	51.1	0.8	6.1	10.5	33.7	10.2	6.9	
हिमाचल प्रदेश	11.9	2.8	2.4	0.8	7.0	4.2	7.2	6.8	12.1	46.7	29.3	46.5	16.9	44.6	0.0	2.0	-11.2	17.2	9.2	5.6	
हरियाणा	11.2	2.7	2.7	1.6	7.7	4.9	7.8	9.8	-120.4	448.2	7.9	4.8	25.8	56.2	0.7	1.5	-17.5	28.1	11.9	9.2	
जम्मू और कश्मीर	11.3	3.6	2.5	1.1	8.4	5.6	8.9	6.4	2.2	17.0	4.5	2.8	6.4	27.9	-0.2	3.6	1.4	15.0	14.2	7.8	
कर्नाटक	9.4	3.5	3.5	1.4	9.3	5.1	9.6	9.9	7.7	24.8	4.0	4.7	5.4	17.9	-0.4	2.6	-2.0	21.5	11.8	8.4	
मध्य प्रदेश	12.0	3.0	2.7	1.0	7.5	5.4	8.8	9.7	9.7	28.4	5.2	3.3	10.0	34.5	1.5	2.3	-5.1	20.4	12.3	4.9	
महाराष्ट्र	9.1	2.6	2.1	1.1	7.8	4.6	8.8	8.0	2.6	21.3	6.0	4.1	9.4	13.3	-0.8	4.5	0.3	17.7	11.8	7.6	
उड़ीसा	13.2	3.5	2.4	0.8	8.3	3.8	7.4	8.0	11.9	17.2	6.6	11.8	14.8	45.1	-4.7	11.6	0.9	12.7	10.7	5.3	
पंजाब	13.0	3.6	2.9	0.9	7.5	4.5	6.8	9.7	-0.4	34.9	6.4	7.2	9.3	36.9	0.0	0.4	-15.3	24.4	10.0	7.9	
राजस्थान	14.8	5.1	3.0	1.3	7.2	5.6	7.3	11.6	0.9	18.5	6.8	3.3	21.2	75.4	1.8	7.4	8.6	21.8	11.7	7.1	
तामिलनाडु	11.9	4.5	2.8	1.0	9.0	5.5	10.7	10.7	-2.1	17.6	4.2	3.4	9.7	14.8	-0.4	8.0	-2.5	15.7	13.7	9.3	
उत्तर प्रदेश	10.8	2.4	2.8	0.8	7.7	5.1	8.5	10.7	11.8	40.7	4.3	4.1	10.1	24.2	1.2	2.1	-22.4	16.8	12.2	5.9	
पश्चिम बंगाल	14.3	4.1	2.5	0.8	7.6	4.1	9.0	11.6	21.3	31.7	0.5	0.4	10.2	28.0	0.7	3.5	-8.5	17.2	12.0	7.0	

टिप्पणी: माध्य प्रतिशत वृद्धि में हैं।



## भारत में उपभोक्ता विश्वास पर कोविड -19 महामारी का प्रभाव\*

महामारी ने पूरे भारत में उपभोक्ता विश्वास को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जो कोविड-19 के नतीजों के सामने आते ही ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। सभी स्तर के घरों की भावना संक्रमण और घातक घटनाओं के प्रसार से प्रभावित थी। उपभोक्ताओं की भावनाओं पर उनकी अपनी वित्तीय स्थितियों के साथ-साथ सामान्य आर्थिक स्थिति पर स्थायी प्रभाव पड़ा - सामान्य आर्थिक स्थिति पर वित्तीय स्थितियों पूर्व द्वारा संचालित होने के साथ। महामारी से बुरी तरह प्रभावित शहरों में उपभोक्ताओं ने अन्य शहरों के उत्तरदाताओं की तुलना में अधिक नकारात्मक भावनाएं व्यक्त कीं। फिर भी, मौजूदा स्थिति की कम धारणा के बावजूद, आने वाले वर्ष के लिए उत्तरदाताओं की अपेक्षाओं ने महामारी के कम होने के बाद आर्थिक सुधार में विश्वास दिखाया।

### परिचय

कोविड -19 महामारी, जो 2020 की शुरुआत में शुरू हुई, एक बड़ा व्यवधान है जिसने वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल पैदा कर दी। महामारी के प्रकोप के साथ, दुनिया भर के देशों ने लोगों की आवाजाही और इकट्ठा होने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए, और कुछ ही हफ्तों में, मानवता का बड़ा हिस्सा अपने घरों की सीमा तक सीमित हो गया। इसका अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर गंभीर प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए, जबकि कुछ कम क्षमता के साथ काम कर रहे थे। न केवल मांग कम थी, बल्कि उपभोग व्यय में भी बदलाव आया, क्योंकि गैर-जरूरी खर्चों में बड़ी कमी देखी गई। इससे व्यवसायों की बिक्री और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में रोजगार और आय को महत्वपूर्ण आघात लगे हैं।

\* घरेलू सर्वेक्षण विभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग के आदित्य मिश्रा, रोशिन पॉल पी और तुषार बी दास द्वारा तैयार किया गया। आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

जैसा कि महामारी का प्रभाव अर्थव्यवस्था में बदल गया, सरकारों और दुनिया भर के अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों ने घरों और व्यवसायों के लिए राहत पैकेज शुरू किए। असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय बैंकों ने धन की लागत को कम करने के लिए ब्याज दरों में कटौती की, एक उदार रुख अपनाया, और कुछ नियामक सहनशीलता की शुरुआत की। सहायता और राहत उपायों के बावजूद, कई परिवार गिरती आय और नौकरी के नुकसान से गुजरे। महामारी की भविष्य की लहरों के बारे में अतिरिक्त अनिश्चितता महामारी की शुरुआत के बाद से अत्यधिक अस्थिर उपभोक्ता विश्वास में परिवर्तित हुई।

मौजूदा आर्थिक स्थिति के बारे में उपभोक्ताओं की धारणा और भविष्य के लिए उनकी उम्मीदें भी उनके खर्च, बचत और निवेश व्यवहार को प्रभावित करती हैं। आर्थिक विस्तार के दौरान, उपभोक्ता आमतौर पर अपनी आय के बारे में अधिक आश्वस्त होते हैं और अधिक खर्च कर सकते हैं। दूसरी ओर, जब अर्थव्यवस्था सिकुड़ती है, तो उपभोक्ता आमतौर पर अपने भविष्य के बारे में अधिक निराशावादी होते हैं और अपने खर्च पर अंकुश लगाकर अधिक बचत करने का प्रयास कर सकते हैं। इसका अर्थव्यवस्था पर चक्रीय प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, उपभोक्ता विश्वास एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है जो इस पहलू के बारे में एक विचार देता है। प्रमुख देश उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण करते हैं जो उपयुक्त नीतिगत उपायों को तैयार करने के लिए आर्थिक अनिश्चितता के समय पर और दूरदेशी उपायों को प्रदान करते हैं।

भारत में महामारी बहुत क्रूर रही है, विशेष रूप से अप्रैल-मई 2021 में दूसरी लहर के दौरान, जब दैनिक नए मामले अपने चरम पर प्रति दिन 4,00,000 तक पहुंच गए थे। इस संदर्भ में, भारतीय उपभोक्ताओं के उपभोक्ता विश्वास पर महामारी के प्रभाव का अध्ययन करना आवश्यक है। यह लेख मुख्य रूप से इस प्रभाव का विश्लेषण करता है, जैसा कि आरबीआई के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) <sup>1</sup> द्वारा अनुमान लगाया गया है। खंड II उपभोक्ता व्यवहार पर उपभोक्ता विश्वास के प्रभाव, संकट के

<sup>1</sup> सीसीएस की विस्तृत सर्वेक्षण पद्धति के लिए, कृपया कुमार एट अल., (2019) का अनुबंध ए देखें ([https://rbi.org.in/Scripts/BS\\_ViewBulletin.aspx?Id=18173](https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=18173))

दौरान उपभोक्ताओं के व्यवहार और प्रमुख क्षेत्रों में उपभोक्ता विश्वास पर इस विशिष्ट संकट के प्रभाव पर साहित्य की समीक्षा करता है। खंड III मई 2019 से उपभोक्ता विश्वास संकेतकों के प्रदर्शन की समीक्षा करता है। खंड IV का उद्देश्य, अनुभवजन्य रूप से, भारत में, शहरों और व्यवसाय समूहों में उपभोक्ता विश्वास संकेतकों पर महामारी के प्रभाव को दिखाना है। अंत में, खंड V का समापन कुछ प्रमुख बातों के साथ होता है।

## II. साहित्य की समीक्षा

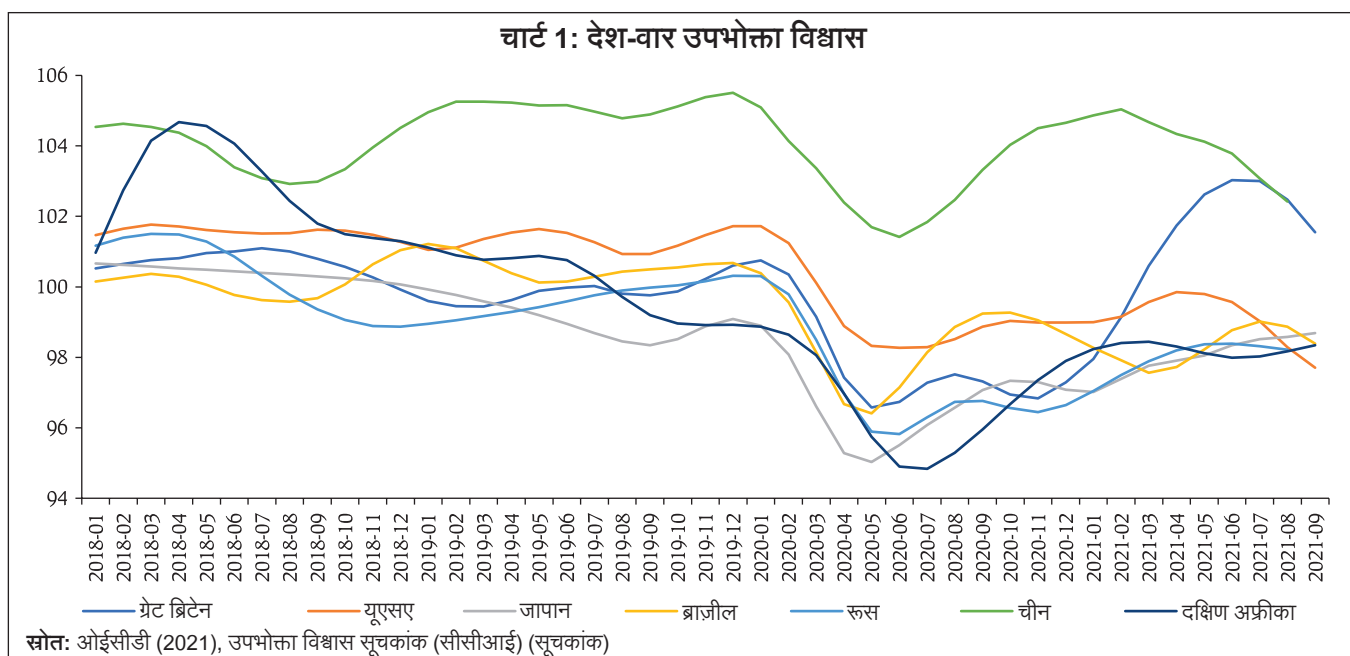
उपभोक्ता विश्वास संकेतकों और आर्थिक गतिविधि के बीच की कड़ी मंदी या अवसाद, या बड़े राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के दौरान संकट की अवधि के दौरान अधिक प्रासंगिक पाई जाती है। डीज और ब्रिंका (2013) ने दिखाया कि जब सर्वेक्षण संकेतक बड़े बदलाव प्रदर्शित करते हैं तो उपभोक्ता विश्वास उपभोग व्यय को बेहतर ढंग से बताता है। कैरोल एट अल.. (1994) ने दावा किया कि अमेरिका में मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स (एमसीएसआई) के पीछे घरेलू खर्च में बदलाव के लिए व्याख्यात्मक शक्ति है। बढ़ी हुई अनिश्चितता परिवारों को अपने खर्च में कटौती करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि आदत बनाने से खपत खर्च के समायोजन में देरी होती है। ओलिवियर एट अल .. (2021) ने पाया कि उच्च व्यापक आर्थिक अनिश्चितता परिवारों को बाद के

महीनों में गैर-टिकाऊ वस्तुओं और सेवाओं पर अपने खर्च को कम करने के लिए प्रेरित करती है, साथ ही साथ बड़ी टिकट वस्तुओं जैसे पैकेज हॉलिडे या लक्जरी सामान की कम खरीद के लिए प्रेरित करती है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पाया कि व्यापक आर्थिक अनिश्चितता घरेलू निर्णयों को प्रभावित कर सकती है और आर्थिक परिणामों पर बड़े नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

अध्ययनों में पाया गया है कि महामारी और परिणामी लॉकडाउन ने विभिन्न देशों में उपभोक्ता विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। यूरोपीय आयोग (2020) के एक तकनीकी पेपर में पाया गया कि कोविड -19 के प्रकोप और आगामी लॉकडाउन ने यूरो क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया और परिणामस्वरूप, मार्च और अप्रैल 2020 के दौरान उपभोक्ता विश्वास गिर गया। डीमांटे एट अल.. (2021) ने यह भी पाया कि कोविड -19 महामारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के उपभोक्ता विश्वास को प्रभावित किया।

## III. महामारी से पहले और उसके दौरान उपभोक्ता का विश्वास उपभोक्ता विश्वास सूचकांक

अधिकांश देशों में उपभोक्ता विश्वास पर महामारी का बड़ा प्रभाव पड़ा। चार्ट 1 सात प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, जैसे संयुक्त

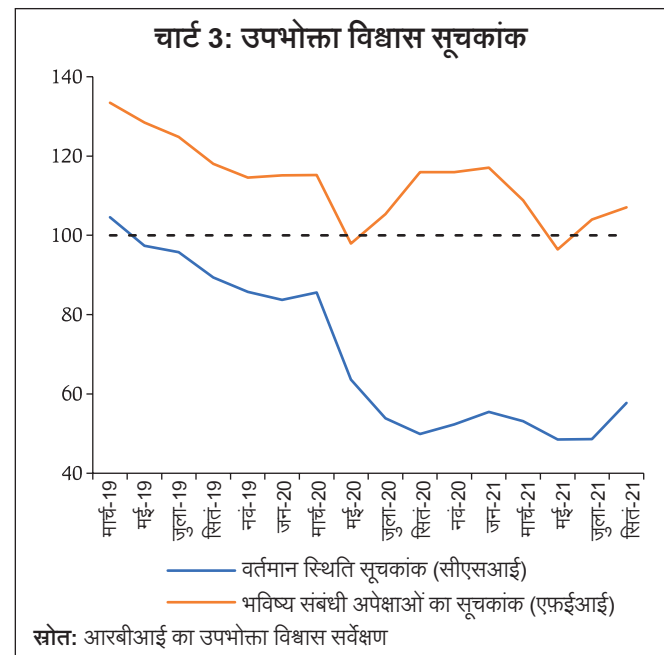
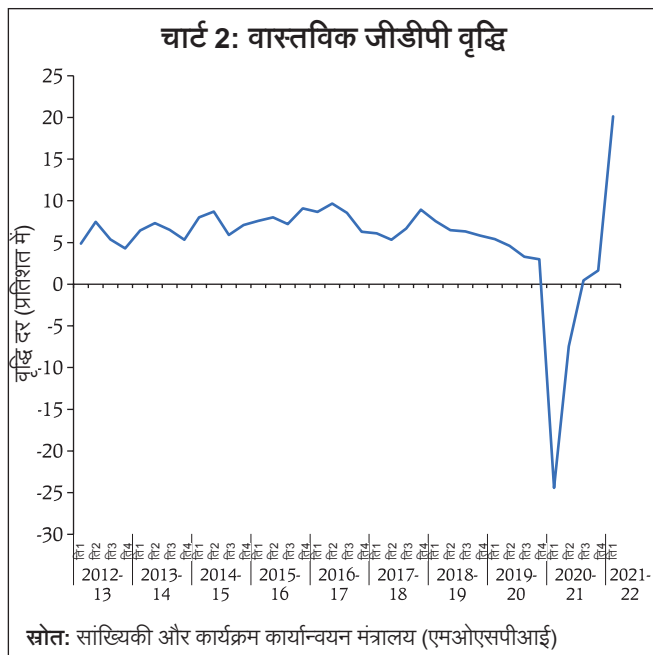


राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के लिए उपभोक्ता विश्वास सूचकांक दिखाता है। अधिकांश देशों ने विश्वास में एक बड़ी गिरावट देखी जब महामारी ने पहले उन्हें ही प्रभावित किया और फिर धीरे-धीरे बढ़ना शुरू कर दिया, हालांकि अधिकांश देशों में अभी तक पूर्व-महामारी के स्तर पर वापस आना बाकी है। टीकाकरण की बढ़ती दरों से रिकवरी में मदद मिल सकती है, लेकिन कोविड -19 के बार-बार होने वाले मुकाबलों से उपभोक्ताओं के विश्वास पर असर पड़ने की उम्मीद है, खासकर व्यापार और रोजगार की स्थिति के बारे में अनिश्चितता के साथ।

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, उपभोक्ता विश्वास और आर्थिक गतिविधि के बीच संबंध दोनों तरह से चलता है। इस प्रकार, देश में आर्थिक गतिविधि का स्तर, जैसा कि अर्थव्यवस्था की विकास दर से मापा जाता है, देश में उपभोक्ता विश्वास को प्रभावित करने की उम्मीद है। चार्ट 2 ति.1: 2012-13 के बाद से भारत के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर दिखाता है। डेटा से पता चलता है कि ति. 1: 2018-19 के बाद से, महामारी से पहले भी अर्थव्यवस्था धीमी हो रही थी, जो ति.1: 2020-21 में महामारी प्रेरित प्रतिबंधों के साथ संकुचन में बदल गई। तब से, अर्थव्यवस्था ठीक होने की राह पर है, विकास दर ति. 3: 2020-21 में सकारात्मक क्षेत्र में लौट रही है।

रिजर्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण में, उस अवधि के दौरान जब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही थी, 2019 (चार्ट 3) के दौरान अधिकांश सर्वेक्षण दौरों के लिए वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई) निराशावादी क्षेत्र में था। 2020 की शुरुआत में कोविड -19 महामारी के प्रकोप ने आत्मविश्वास के स्तर पर एक और नकारात्मक प्रभाव डाला, मई 2020 में इसे 63.7 तक कमजोर कर दिया। तब से, मई 2021 दूसरी लहर की शुरुआत के साथ यह गिरावट के पथ पर है और सर्वेक्षण के 48.5 के सर्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि, दूसरी लहर के धीरे-धीरे कम होने के साथ, वर्तमान स्थितियों में कुछ वृद्धि देखी गई, हालांकि वे अभी भी अत्यधिक नकारात्मक बने हुए हैं।

इसके विपरीत, उत्तरदाता भविष्य के बारे में तुलनात्मक रूप से आशावादी थे, क्योंकि भविष्य की उम्मीदों का सूचकांक (एफईआई) ज्यादातर सकारात्मक क्षेत्र (100 से ऊपर) में था। एफईआई मई 2020 तक सीएसआई के साथ आगे बढ़ रहा था, जब इसने देशव्यापी तालाबंदी के पहले चरण के दौरान पहली बार नकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन जुलाई 2020 से महामारी संबंधी प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील के साथ इसमें सुधार होना शुरू हो गया। हालांकि, अप्रैल 2021 में दूसरी लहर की शुरुआत और संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लगाए गए गंभीर प्रतिबंधों

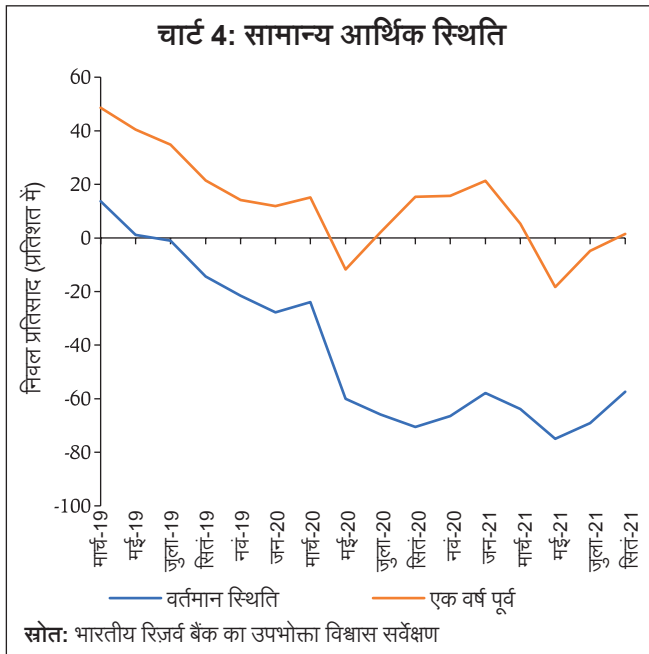


के साथ , महामारी के दौरान दूसरी बार भविष्य के लिए उम्मीदें फिर से निराशावादी क्षेत्र (100 से नीचे) में गिर गईं। जुलाई और सितंबर में उम्मीदों में धीरे-धीरे सुधार दिखाई दे रहा था, केसलोड में अचानक गिरावट और प्रतिबंधों में ढील के साथ, लेकिन कम आधार के बावजूद, मौजूदा अवधि की तुलना में आने वाले वर्ष के लिए उम्मीदें अत्यधिक सकारात्मक नहीं रही हैं, यह दर्शाता है कि उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि महामारी के बाद के प्रभावों को निकट भविष्य के लिए लंबित किया जाएगा।

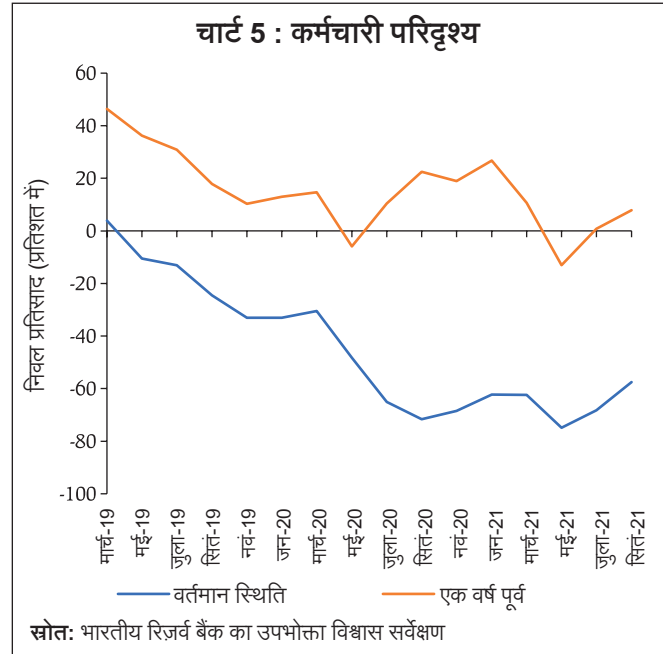
समग्र अर्थव्यवस्था के परिवारों के आकलन के बारे में पूछताछ करने के साथ-साथ सर्वेक्षण में उनकी अपनी आय और व्यय में परिवर्तन के बारे में उनकी धारणा भी दर्ज की गई है। निम्नलिखित हिस्से व्यक्तिगत सर्वेक्षण मानकों के लिए परिवारों के आकलन और अपेक्षाओं का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करते हैं, जो इस आधार पर अलग किया जाता है कि क्या वे समग्र अर्थव्यवस्था या परिवारों की अपनी परिस्थितियों से संबंधित हैं।

#### समग्र अर्थव्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं का दृष्टिकोण

उपभोक्ताओं ने महामारी के फैलने से पहले ही अर्थव्यवस्था में एक लंबी मंदी महसूस की (चार्ट 4)। अध्ययन अवधि के दौरान,



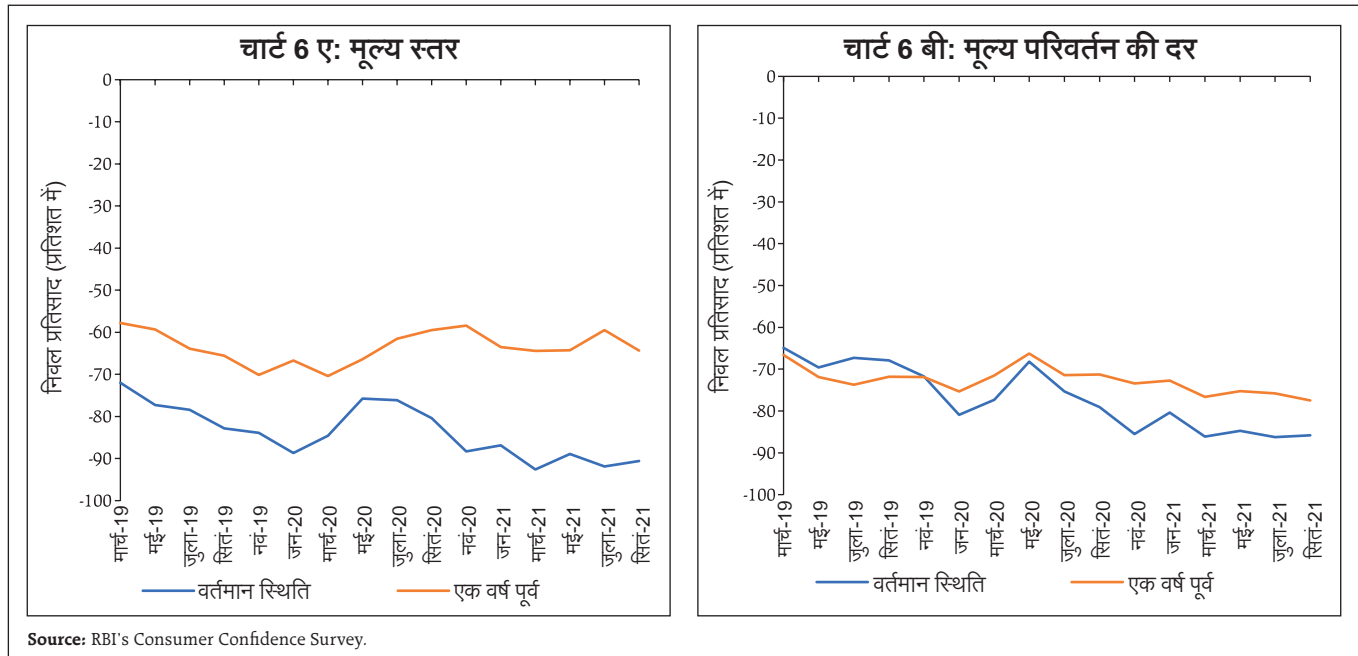
<sup>2</sup> सीसीएस के सितंबर 2021 के दौर के परिणामों की वेब रिलीज से जुड़ी एक्सेल फाइल में अलग-अलग मापदंडों और सूचकांकों के लिए परिणामों की विस्तृत समय श्रृंखला प्राप्त की जा सकती है। <https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=20648>



सामान्य आर्थिक स्थिति की धारणा पर शुद्ध प्रतिक्रिया में आंदोलन ने रोजगार परिदृश्य के लिए आंदोलन को प्रतिबिंबित किया। बिगड़ते रोजगार परिदृश्य (चार्ट 5) की धारणा के साथ संयोजन के रूप में, अधिकांश उपभोक्ताओं ने सामान्य आर्थिक स्थिति में साल-दर-साल बिगड़ने का अनुमान लगाया। मई 2021 दौर के लिए सर्वेक्षण फील्डवर्क कोविड -19 महामारी की क्रूर दूसरी लहर के साथ मेल खाता है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य आर्थिक परिदृश्य और रोजगार परिदृश्य के लिए भावनाएं होती हैं, जो दौर में अपने ऐतिहासिक चढ़ाव को दर्ज करती हैं। इसके अलावा, सर्वेक्षण के सभी दौरों में अधिकांश उत्तरदाताओं ने एक साल पहले की तुलना में उच्च कीमतों और मुद्रास्फीति की सूचना दी (चार्ट 6 ए और 6 बी)। उच्च कीमतों और बढ़ती मुद्रास्फीति की एक सामान्य धारणा ने रोजगार परिदृश्य और सामान्य अर्थव्यवस्था से पहले से ही चिंतित उपभोक्ताओं के लिए स्थिति को और बढ़ा दिया।

मार्च 2020 तक सामान्य आर्थिक स्थिति और रोजगार परिदृश्य के लिए उपभोक्ताओं की उम्मीदें आशावादी थीं, जिसके बाद मई 2020 में महामारी और सहवर्ती प्रतिबंधों के प्रकोप ने उन्हें निराशावादी बना दिया। हालांकि, उम्मीदें जुलाई 2020 से आगे अगले दौर से तुरंत सकारात्मक हो गईं। फिर भी, अप्रैल





2021 में दूसरी लहर की शुरुआत के साथ, समसामयिक अवधि के लिए निम्न आधार के बावजूद, उम्मीदों में तेज गिरावट देखी गई है, यह दर्शाता है कि उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि महामारी के बाद के प्रभाव होंगे।

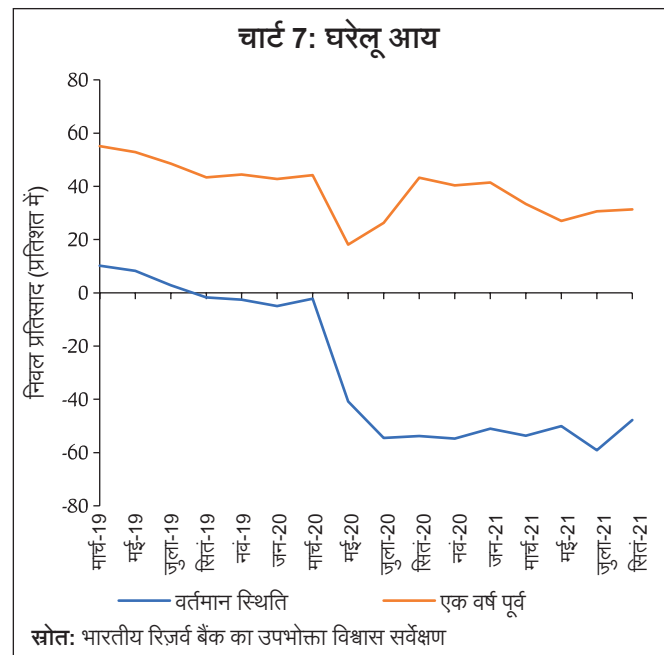
हालांकि उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि अल्पावधि में कीमतें अधिक होंगी, उच्च कीमतों और मुद्रास्फीति की उम्मीद करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात एक साल पहले की तुलना में उच्च कीमतों और मुद्रास्फीति की तुलना में बहुत कम है। महामारी की अवधि के दौरान यह अंतर व्यापक हो गया है, जो लॉकडाउन के दौरान कीमतों में झटके और सहवर्ती आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों की ओर इशारा करता है, जो धारणाओं को प्रभावित करता है, लेकिन उम्मीदें इस तरह के अल्पकालिक झटके से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहीं।

**उपभोक्ताओं की अपनी परिस्थितियों का आकलन**

समग्र अर्थव्यवस्था के आकलन के साथ-साथ, उपभोक्ताओं का विश्वास उनकी अपनी आय की स्थिति और उनके उपभोग व्यय के बारे में जो अनुभव करता है, उससे भी प्रभावित होता है। कम आय और परिवारों के लिए खर्च में संकुचन अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को खींचने की संभावना है, भले ही अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत

अच्छा कर रहे हों। दूसरी ओर, घरेलू क्षेत्र में उच्च मांग अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को बढ़ावा देती है।

परिवारों की आय संबंधी भावना मार्च 2020 तक बनी रही, हालांकि कुछ दौर में शुद्ध प्रतिक्रिया के नकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश करने के मामले थे। हालांकि, महामारी के प्रकोप के साथ, घरों की आय की स्थिति में भारी गिरावट आई, जिसमें उपभोक्ताओं के भारी बहुमत ने एक साल पहले (चार्ट 7) की तुलना में आय में

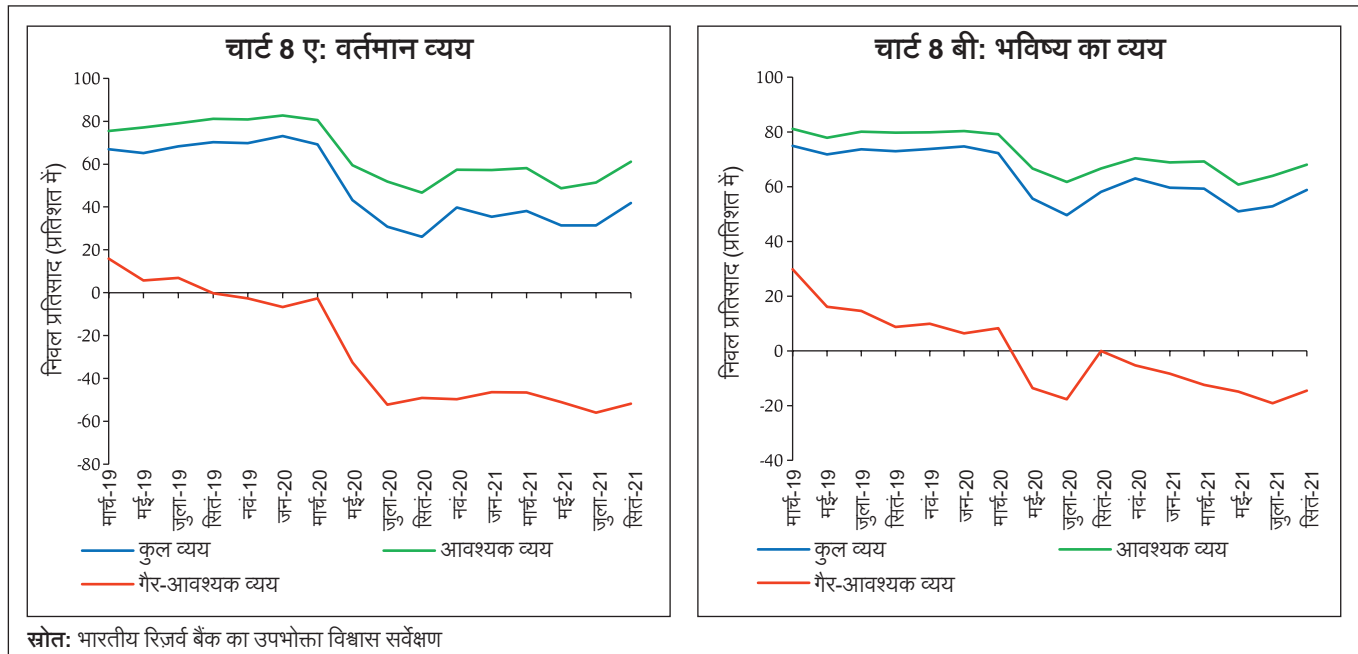


कमी दर्ज की। नतीजतन, मार्च से जुलाई 2020 के दौरान वर्तमान अवधि की घरेलू आय के लिए शुद्ध प्रतिक्रिया में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, एक ऐसी अवधि जिसके दौरान अधिकांश अर्थव्यवस्था बंद थी और सकल घरेलू उत्पाद में भारी संकुचन देखा गया। उत्तरदाता, हालांकि, अपनी भविष्य की आय में वृद्धि के बारे में आशावादी बने रहे। भविष्य की आय पर शुद्ध प्रतिक्रिया मई 2020 तक वर्तमान आय के साथ आई और 18.1 के निचले स्तर को छू गई, लेकिन तब से, सितंबर 2020 में पूर्व-कोविड -19 के स्तर में कमी की उम्मीदों के साथ अंतर चौड़ा हो गया है।

अन्य मानकों के गिरने के परिदृश्य में भी अपने उच्च स्तर को बनाए रखने के मामले में घरेलू खर्च का मानदंड परंपरागत रूप से सर्वेक्षण मानकों में सबसे अधिक आघात सहनीय रहा है। इसलिए, मौजूदा घरेलू खर्च के लिए शुद्ध प्रतिक्रिया में मार्च 2020 तक स्थिर 70-75 प्रतिशत के स्तर से सितंबर 2020 में 25 प्रतिशत से अधिक की तेज गिरावट ने असामान्य संकट को दर्शाया है कि परिवारों ने खुद को महामारी के दौरान पाया। मार्च

2020 तक, भविष्य के समग्र खर्च की उम्मीदें पूर्ण स्तरों और दिशात्मक परिवर्तनों दोनों के संदर्भ में समान थीं, लेकिन तब से, अन्य सर्वेक्षण मापदंडों के समान, धारणाओं और अपेक्षाओं के बीच 15-20 प्रतिशत का अंतर देखा जाता है (चार्ट 8 ए और 8 बी)।

समग्र खर्च ज्यादातर आवश्यक वस्तुओं पर खर्च से संचालित होता है क्योंकि अध्ययन अवधि के दौरान दो मापदंडों के बीच सह-आंदोलन देखा गया है। जबकि वर्तमान समग्र खर्च और आवश्यक खर्च के लिए शुद्ध प्रतिक्रिया मार्च 2020 तक स्थिर थी, गैर-आवश्यक खर्च के लिए शुद्ध प्रतिक्रिया जुलाई 2018 से लगातार बिगड़ रही है और नवंबर 2019 में नकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। महामारी के प्रकोप का भारत पर और प्रभाव पड़ा। लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने गैर-आवश्यक वस्तुओं पर खर्च में कमी की सूचना दी। हालांकि उत्तरदाता गैर-आवश्यक वस्तुओं पर अपने भविष्य के खर्च के बारे में अधिक आशावादी थे, जुलाई 2018 से शुद्ध प्रतिक्रिया में लगातार गिरावट



आ रही है, और यहां तक कि महामारी की शुरुआत के बाद से नकारात्मक क्षेत्र में है।

#### IV. कोविड -19 का प्रभाव - एक अनुभवजन्य विश्लेषण

##### मापदंडों के बीच सामंजस्य - पूर्व-महामारी बनाम महामारी के दौरान

असंख्य सर्वेक्षण मापदंडों के बीच सामंजस्य के एक अध्ययन का उद्देश्य यह दिखाना है कि किसी विशेष पैरामीटर के बारे में प्रतिक्रिया देते समय कौन से अन्य पहलू उपभोक्ताओं के दिमाग पर भार डालते हैं। सारणी 1 अध्ययन अवधि (मई 2019 से सितंबर 2021) के लिए विभिन्न सर्वेक्षण मापदंडों के बीच सुसंगतता <sup>3</sup> प्रस्तुत करती है। मार्च 2020 तक के सर्वेक्षण दौरों को पूर्व-महामारी दौर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि बाद के सभी दौर, सितंबर 2021 तक, महामारी प्रभावित दौर के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। परिणामों से पता चलता है कि अधिकांश दौरों के लिए, सामान्य आर्थिक स्थिति की वर्तमान धारणा आम

तौर पर रोजगार परिदृश्य और कीमतों के साथ सबसे अधिक संरेखित होती है, जबकि सामान्य आर्थिक स्थिति और खर्च के बीच तालमेल मामूली होता है। हालांकि, महामारी के दौरान सामान्य आर्थिक स्थिति और रोजगार परिदृश्य के साथ घरेलू आय अधिक सुसंगत हो गई है, यह दर्शाता है कि इन दो मापदंडों के लिए अत्यधिक नकारात्मक धारणाओं के पीछे घरेलू आय कम होना एक प्रमुख कारक रहा है। इस प्रकार, रोजगार, कीमतें और हाल ही में, घरेलू आय, उपभोक्ताओं की सामान्य आर्थिक स्थिति की धारणा पर प्रमुख प्रभाव रहा है।

जैसा कि पिछले खंड में चर्चा की गई है, सर्वेक्षण के दौर में, समग्र खर्च ज्यादातर आवश्यक खर्च से प्रेरित होता है। समग्र व्यय के दो घटकों, अर्थात् आवश्यक और गैर-आवश्यक व्यय के लिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आवश्यक व्यय कीमतों से अधिक प्रभावित होना चाहिए, मांग में अपेक्षाकृत लचीला होना, जबकि गैर-आवश्यक व्यय, प्रकृति में अधिक विवेकाधीन होने के कारण, कीमतों के बजाय सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार और घरेलू आय से प्रेरित होगा। यह सुसंगत डेटा से भी प्रमाणित होता है, जहां आवश्यक खर्च कीमतों के साथ सबसे अधिक संरेखित होता है। महामारी के दौर में सामंजस्य का स्तर मामूली रूप से कम हुआ है, लेकिन 67 प्रतिशत से ऊपर बना हुआ है। दूसरी ओर, गैर-आवश्यक खर्च सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार और घरेलू आय के साथ अधिक संरेखित है, और महामारी के दौरान सुसंगतता का स्तर तेजी से बढ़ा है, जबकि कीमतें कमजोर रूप से संरेखित हैं।

एक साल आगे की उम्मीदों के लिए, हालांकि समग्र प्रवृत्ति ऊपर की चर्चा के समान है, पूर्व-महामारी और महामारी के दौर के बीच बहुत अंतर नहीं देखा जाता है। जैसा कि पिछले खंड में चर्चा की गई है, जबकि महामारी के दौरान कुछ दौर में उम्मीदें कम हो गई हैं, जब बीमारी की व्यापकता और प्रतिबंध सबसे अधिक थे, पूर्व-महामारी दौर की तुलना में परिवर्तन समकालीन धारणा की तुलना में बहुत कम था। सुसंगतता के निष्कर्ष इस तथ्य को

#### सारणी 1: सर्वेक्षण मापदंडों के बीच तालमेल

(उत्तरदाताओं का प्रतिशत)

सर्वेक्षण पैरामीटर		वर्तमान धारणा		भविष्य की उम्मीदें	
		महामारी से पहले के दौर*	महामारी के दौर <sup>^</sup>	महामारी से पहले के दौर	महामारी का दौर
सामान्य आर्थिक स्थिति (जीईएस)	रोजगार कीमतों	59.4	73.0	68.9	68.8
	आय	48.1	71.7	37.9	45.0
	खर्च	39.5	59.7	48.8	45.4
		30.1	25.3	46.1	38.1
रोजगार परिदृश्य	जीईएस आय	59.4	73.0	68.9	68.8
		40.2	59.3	48.7	47.6
आवश्यक खर्च	कीमतों	79.1	67.5	69.7	62.1
	जीईएस आय	30.6	21.2	48.1	39.6
		33.0	26.9	56.4	51.7
गैर-जरूरी खर्च	जीईएस आय	36.5	54.3	37.3	37.8
	आय	44.8	55.8	46.1	43.3
	रोजगार कीमतों	36.5	53.5	37.4	37.6
		33.7	15.1	38.7	30.6

\* मई 2019 से मार्च 2020 राउंड

<sup>^</sup> मई 2020 से सितंबर 2021 राउंड

<sup>3</sup> सुसंगतता गुणांक को सर्वेक्षण के एक विशिष्ट दौर में प्रतिक्रियाओं की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दो चर के लिए समान प्रतिक्रिया के योग के रूप में परिभाषित किया गया है।

और प्रमाणित करते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों की धारणा की तुलना में अपेक्षाएं महामारी से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुई हैं।

### महामारी के प्रसार और गंभीरता का प्रभाव

इसके अलावा, कोविड -19 संबंधित चर<sup>4</sup> के प्रभाव, अर्थात्, प्रत्येक राज्य में और अखिल भारतीय स्तर पर पुष्टि किए गए मामलों और मौतों की संख्या, शहरवार उपभोक्ता विश्वास पर पैनल रिग्रेशन का उपयोग करके अध्ययन किया गया था। नियंत्रित शहर स्तर के प्रभावों के साथ निम्नलिखित समीकरण का अनुमान सीएसआई, एफईआई और कोविड-19 संबंधित चर के बीच संबंध को देखने के लिए लगाया गया था, मई 2020 से सितंबर 2021 तक सीसीएस के आठ राउंड के डेटा का उपयोग करके और इसी महीने के कोविड -19 संबंधित चर के डेटा का उपयोग किया गया था।

$$Y_{ijt} = C_1 + \beta_1 * X_{ijt} + \varepsilon_{ijt} \quad \dots (3)$$

जहां,

$Y_{ijt}$ : उपभोक्ता विश्वास संकेतक, जैसे सीएसआई और एफईआई;

$X_{ijt}$ : कोविड -19 संबंधित चर पर मासिक डेटा जैसे राज्य में पुष्टि किए गए मामलों की संख्या, राज्य में मौतों की संख्या, भारत में पुष्टि किए गए मामलों की संख्या और भारत में मौतों की संख्या ;

और,  $j$ ,  $j^{\text{th}}$  शहर को दर्शाता है और  $t$  समय को दर्शाता है।

यह देखा गया कि सीएसआई और एफईआई ने राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर केसलोड और कोविड -19 से जुड़ी मौतों में वृद्धि के लिए एक नकारात्मक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया। इस प्रकार, जैसे-जैसे मामले और मौतें बढ़ती गईं, उपभोक्ता का विश्वास कम होता गया, जबकि महामारी की स्थिति में सुधार के कारण सापेक्षिक सुधार हुआ (सारणी 2)।

### शहरवार सूचकांकों पर प्रभाव

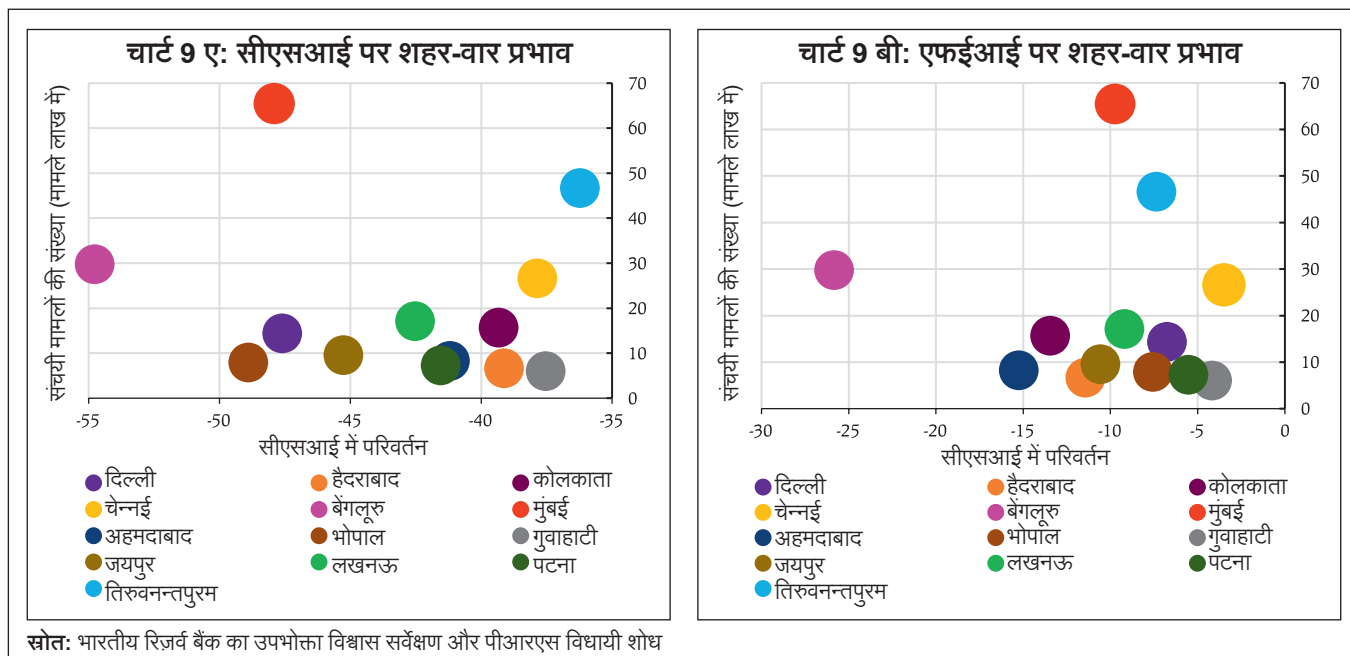
विभिन्न शहरों पर कोविड -19 के प्रभाव को देखने के लिए, महामारी (मई 2018 से मार्च 2020) से पहले और प्रकोप के बाद के सर्वेक्षण दौर के लिए औसत सीएसआई की तुलना की गई थी। इसकी तुलना सितंबर 2020 के अंत में राज्यवार कोविड मामलों की संचयी संख्या के साथ की गई थी। यह देखा गया कि बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में, जहां मामले बहुत अधिक थे, वहाँ अन्य शहरों की तुलना में कोविड -19 महामारी के प्रकोप में औसत सीएसआई में काफी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि तिरुवनंतपुरम में मामलों की संख्या अधिक थी, लेकिन इसने अन्य शहरों की तुलना में औसत सीएसआई में सबसे कम कमी दिखाई। छोटे शहरों में, भोपाल ने औसत सीएसआई (चार्ट 9ए) में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की। औसत सीएसआई और एफईआई मूल्यों से संकेत मिलता है कि सभी शहरों के लिए उम्मीदों की तुलना में मौजूदा अवधि के लिए महामारी का भावनाओं पर

### सारणी 2: उपभोक्ता भावना संकेतकों पर कोविड -19 के प्रभाव के पैनल प्रतिगमन मॉडल

चर	गुणक	Coefficient	पी मान	एडीजे आर <sup>2</sup>	टिप्पणियों की संख्या
वर्तमान स्थिति सूचकांक					
राज्य में पुष्टि किए गए मामलों की संख्या (मासिक)	60.3	-0.000019	0.00*	0.2	129
राज्य में मौतों की संख्या (मासिक)	60.2	-0.001305	0.00*	0.2	129
भारत में पुष्टि किए गए मामलों की संख्या (मासिक)	61.7	-0.00000172	0.00*	0.24	130
भारत में मौतों की संख्या (मासिक)	61.8	-0.000136	0.00*	0.26	130
भविष्य की उम्मीदों से संबन्धित सूचकांक					
राज्य में पुष्टि किए गए मामलों की संख्या (मासिक)	111.3036	-0.00000921	0.11	0.4	129
राज्य में मौतों की संख्या (मासिक)	111.5462	-0.000867	0.03**	0.41	129
भारत में पुष्टि किए गए मामलों की संख्या (मासिक)	112.6888	-0.0000012	0.01**	0.44	130
भारत में मौतों की संख्या (मासिक)	112.9365	-0.0000987	0.0*	0.45	130

\*1% के स्तर पर महत्वपूर्ण\* \*5% के स्तर पर महत्वपूर्ण

<sup>4</sup> डेटा स्रोत- पीआरएस विधायी अनुसंधान



अधिक प्रभाव पड़ा। बेंगलूरु, अहमदाबाद, कोलकाता और हैदराबाद (चार्ट 9बी) जैसे प्रमुख शहरों के लिए एफईआई में भिन्नता अधिक थी।

### विभिन्न व्यवसाय श्रेणियों पर प्रभाव

इसके अलावा, विभिन्न व्यवसाय श्रेणियों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का अध्ययन महामारी से पहले (मई 2018 से मार्च 2020) और कोविड-19 के प्रकोप के बाद यानी मार्च 2020 के बाद (तालिका 3) के सर्वेक्षण दौरों के लिए औसत सीएसआई और एफईआई की तुलना करके किया गया था। यह देखा गया कि महामारी का व्यवसाय श्रेणियों में प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनमें से

अधिकांश के लिए औसत सीएसआई महामारी के प्रकोप के बाद 40 प्रतिशत से अधिक बिगड़ गया है। विभिन्न व्यवसाय श्रेणियों में, डेटा से पता चलता है कि 'सेवानिवृत्त / पेंशनभोगी' महामारी से सबसे कम प्रभावित थे जैसा कि सीएसआई (-34.1 प्रतिशत) में गिरावट से दिखाया गया है। हालांकि, एफईआई विभिन्न व्यवसाय श्रेणियों के लिए केवल औसतन 11 प्रतिशत तक बिगड़ गया। 'सेवानिवृत्त/पेंशनभोगी' और 'स्व-नियोजित/व्यवसाय' अन्य व्यवसाय श्रेणियों की तुलना में आने वाले वर्ष के बारे में कम निराशावादी थे।

### V. निष्कर्ष

कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने भारत सहित दुनिया भर में उपभोक्ता विश्वास को बुरी तरह प्रभावित किया। विश्लेषण से पता चलता है कि मौजूदा स्थिति के बारे में उपभोक्ताओं की धारणा महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित होती है, जबकि भविष्य के बारे में उम्मीदें अपेक्षाकृत आशावादी रही हैं, बावजूद इसके कि लगातार दौर में गिरावट आई है। सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों के साथ-साथ चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम के साथ, उम्मीदें धारणाओं की तुलना में अपेक्षाकृत तेजी से ठीक हो गई हैं।

**सारणी 3: व्यवसाय श्रेणी के अनुसार उपभोक्ता के विश्वास पर प्रभाव**

व्यवसाय श्रेणियाँ	सीएसआई में % परिवर्तन	एफईआई में % परिवर्तन
कार्यरत	-41.9	-12.8
स्व - रोजगार / व्यापार	-44.2	-10.1
घर पर रहने वाली	-43.9	-11.6
दैनिक कार्यकर्ता	-41.9	-11.0
सेवानिवृत्त/पेंशनभोगी	-34.1	-8.5
बेरोजगार	-43.6	-12.5

सर्वेक्षण संकेतकों में, घरेलू आय महामारी प्रेरित प्रतिबंधों से सबसे अधिक प्रभावित हुई, जिससे इस अवधि के दौरान उपभोक्ता विश्वास कई निम्न स्तर पर पहुंच गया। सामान्य आर्थिक स्थिति और रोजगार के बारे में भी उपभोक्ताओं की धारणा पर कम आय का प्रभाव देखा जाता है। इसके अलावा, ये पैरामीटर उपभोक्ताओं द्वारा कम विवेकाधीन खर्च के प्रमुख चालक प्रतीत होते हैं। कुल खर्च को आवश्यक खर्च से बढ़ा दिया गया है, जो ज्यादातर कीमतों से प्रभावित होता है। सरकार द्वारा चल रहे सुधार उपायों में निरंतर गति से परिवारों के बीच रोजगार और आय की स्थिति में सुधार करने में मदद मिल सकती है, जिससे उपभोक्ता विश्वास में धीरे-धीरे सुधार होगा।

### संदर्भ

#### References

Dees, S. and Brinca, P. S. (2013), "Consumer confidence as a predictor of consumption spending: Evidence for the United States and the Euro area", *International Economics, Volume 134*, August 2013, Pages 1-14

Deimante Teresiene, Greta Keliuotyte-Staniuleniene, Yiyi Liao, Rasa Kanapickiene, Ruihui Pu, Siyan Hu and Xiao-Guang Yue (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Consumer and Business Confidence Indicators. *J. Risk Financial Manag.* 2021, 14, 159

Carroll, C., Fuhrer, G. & Wilcox, D. (1994). Does Consumer Sentiment Forecast Household Spending? If So, Why? *American Economic Review.* 84 (5):1397-1408

Olivier Coibion, Dimitris Georgarakos, Yuriy Gorodnichenko, Geoff Kenny, Michael Weber (2021) The effect of macroeconomic uncertainty on household spending. *Working Paper Series, European central bank*, May 2021

European Commission (2020). European Business Cycle Indicators, 2nd Quarter 2020, TECHNICAL PAPER 041 | JULY 2020

Kumar, N., Mishra, A. and Singh, D. P. (2019), "The Consumer Rules! Some Recent Survey-based Evidence", *RBI Bulletin* April 2019

## भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बदलती गतिशीलता\*

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की पूंजी आवश्यकताओं के वित्तपोषण का एक स्थिर साधन है और विकसित तथा उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं ने बाजार मूल्य पर एफडीआई पर सूचना आधार को बढ़ाने के लिए बड़े प्रयास किए हैं। भारत में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के समन्वित प्रत्यक्ष निवेश सर्वेक्षण (सीडीआईएस) के कार्यान्वयन और विदेशी संबद्ध व्यापार सांख्यिकी (एफएटीएस) के संकलन द्वारा इस संबंध में प्रमुख प्रगति हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के विश्लेषण के अनुभवजन्य परिणाम दर्शाते हैं कि व्यापार में खुलापन, आर्थिक विकास, बाजार का आकार, श्रम लागत और मेजबान देशों का खुला पूंजी खाता, एफडीआई अंतर्वाह के प्रमुख निर्धारक हैं।

### I. प्रस्तावना

विदेशी निवेश विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बचत-निवेश के अंतर को पाटकर पूंजी घाटे वाली अर्थव्यवस्था की निवेश आवश्यकताओं को पूरा करके आर्थिक विकास का समर्थन करता है। कई विदेशी निवेशक वित्तीय पूंजी के साथ नई तकनीक, सर्वोत्तम प्रथाएं और अभिशासन अपनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कौशल हस्तांतरण और उत्पादकता का लाभ प्राप्त होता है। हालांकि, नया व्यवसाय रोजगार का निर्माण कर सकता है, नई कंपनियों से अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण भी मेजबान देश में दक्षता बेहतर होती है।

देश के राष्ट्रीय वित्तीय खातों में एक घटक, विदेशी निवेश, इक्विटी और ऋण के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। यह प्राप्तकर्ता अर्थव्यवस्था में निवेशक के स्थायी प्रबंधन हित से जुड़ा है और इसलिए, एक अधिक स्थिर घटक है। जबकि विदेशी पोर्टफोलियो

\* यह लेख सुमित रॉय, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, जॉली रॉय और कमल गुप्ता, सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त विचार और राय लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे आरबीआई के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों। त्रुटियाँ, यदि कोई हों, लेखकों की हैं।

प्रवाह चालू खाता घाटे के वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण हैं, कई देश सामान्य और साथ ही चुनिंदा क्षेत्रों में एफडीआई पर ध्यान और प्रोत्साहन देते हैं।

यह लेख भारत के लिए पूंजी स्टॉक के आवक एफडीआई घटक पर ध्यान केंद्रित करता है जो 1990 में यूएस \$ 1.7 बिलियन से बढ़कर 2019 में यूएस \$ 427.0 बिलियन से अधिक हो गया है। हम विश्लेषण में उपयोग के लिए निरंतर आंकड़ों की उपलब्धता, मूल्यांकन संबंधित विषयों सहित इसकी सीमाओं और भागीदार देशों द्वारा सृजित आँकड़ों की तुलना पर भी चर्चा करते हैं। लेख का शेष भाग पांच खंडों में व्यवस्थित है। खंड II स्वतंत्रता के बाद से भारत में एफडीआई नीति के विकास का सारांश प्रस्तुत करता है। वैश्विक पूंजी प्रवाह के विकास और भारत के लिए आवक एफडीआई में प्रवृत्तियों की चर्चा खंड III में की गई है। सीडीआईएस पहल, एफडीआई सूचना आधार और भारतीय डेटा पर आधारित एफडीआई निवेश के मूल्यांकन के मुद्दे पर खंड IV में चर्चा की गई है। खंड V, पैनाल प्रतिगामी विश्लेषण का उपयोग करके प्रमुख देशों को ध्यान में रखते हुए, भारत में बाजार मूल्य पर उनके एफडीआई शेयरों के संदर्भ में आवक एफडीआई को प्रभावित करने वाले कारकों का अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। खंड VI में निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

### II. भारत में एफडीआई नीति का विकास – संक्षिप्त परिचय

1948 में, जब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भारत की अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं का पहला सर्वेक्षण किया गया था, तो देश में विदेशी निवेश का स्टॉक ₹256 करोड़ था, जो बड़े पैमाने पर यूके से आ रहा था और इसका बड़ा हिस्सा प्राकृतिक संसाधनों की खोज और व्यापार से संबन्धित था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद, भारत ने विकास योजना ढांचे में आयात के स्थान पर औद्योगीकरण की रणनीति शुरू की। मार्च-1950 तक, औद्योगीकरण की रणनीति ने मशीनरी निर्माण क्षेत्र सहित भारी उद्योगों में स्थानीय क्षमता के विकास के लिए धुरी का निर्माण किया। घरेलू प्रौद्योगिकी, कौशल, उद्यमिता के विस्तार संबंधी कठिनाइयों और 1957-58 के विदेशी मुद्रा संकट ने एफडीआई के प्रति सरकार के रवैये को और उदार बनाया। सरकार ने 1961 में उन उद्योगों की सूची जारी की जहां योजना लक्ष्यों के संबंध में

क्षमता में अंतराल को ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेश का स्वागत किया जाना था।

देश में एफडीआई स्टॉक 1948 में ₹256 करोड़ से दोगुना से अधिक होकर 1964 में ₹566 करोड़ हो गया और मार्च 1974 में बढ़कर ₹916 करोड़ हो गया (हुड्डा, 2011)। स्थानीय लाभों के निर्माण से एफडीआई स्टॉक में विनिर्माण की हिस्सेदारी में तेजी से वृद्धि हुई जो स्वतंत्रता के समय लगभग 20 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत से अधिक हो गई और इसमें उपभोक्ता, अर्धनिर्मित और पूंजीगत वस्तुएं शामिल थीं। 40 प्रतिशत तक विदेशी निवेश या विदेशी इक्विटी के सहयोग से जुड़े सभी मामलों से निपटने के लिए विदेशी निवेश बोर्ड का गठन 1968 में किया गया था और 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी स्वामित्व वाले मामलों की जांच के लिए एक कैबिनेट समिति का गठन किया गया था।

1985 तक, भारत को भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1991 में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाराशियों की निकासी, बैंकों से अल्पकालिक पूंजी के बहिर्वाह और निर्यात प्रदर्शन में गिरावट जैसे अनेक मुद्दों के कारण समस्या और गंभीर हो गई। बाद के समष्टि-आर्थिक स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया और जुलाई 1991 में एक नई औद्योगिक नीति (एनआईपी) की घोषणा की गई। एनआईपी और बाद के नीतिगत संशोधनों ने देश में विशेष रूप से एफडीआई पर लागू होने वाली औद्योगिक नीति व्यवस्था को उदार बनाया। इसमें रणनीतिक या पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों में औद्योगिक अनुमोदन प्रणाली को समाप्त करना, 34 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51 प्रतिशत एफडीआई की स्वतः स्वीकृति, अनिवार्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों को समाप्त करना, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की स्थापना आदि शामिल हैं। खनन, बैंकिंग, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण और प्रबंधन जैसे नए क्षेत्रों को विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों सहित निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया।

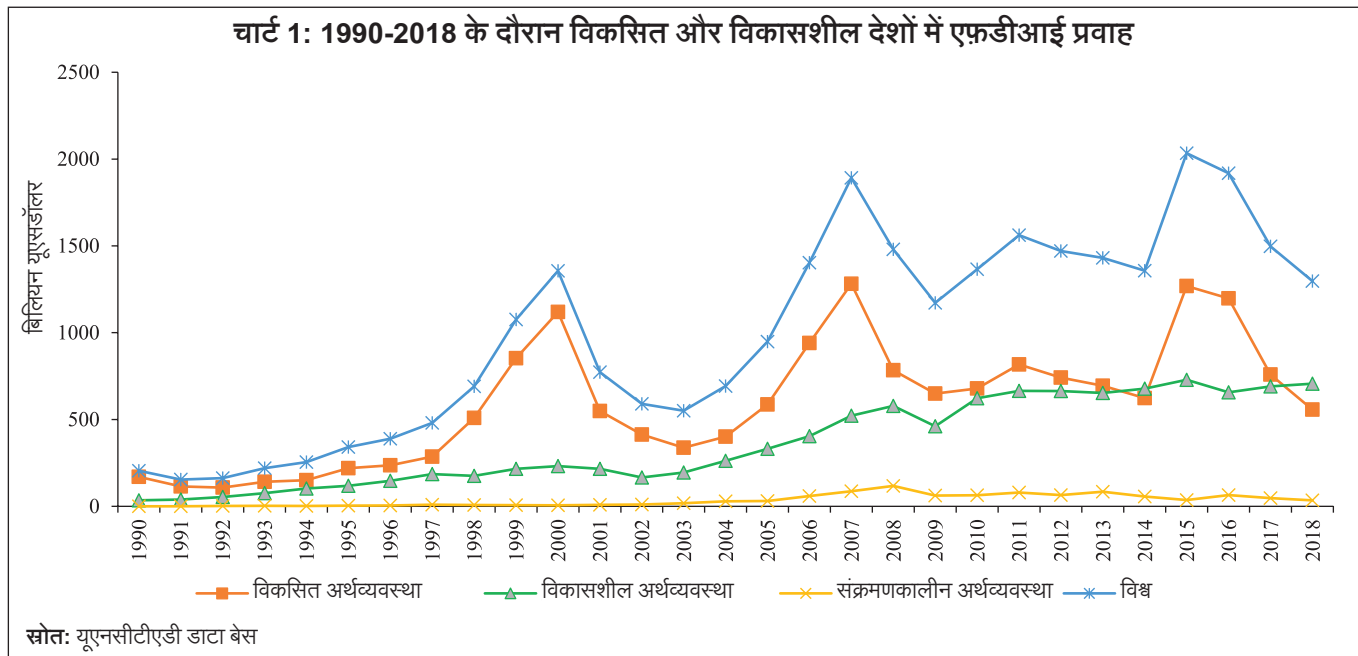
पिछले दशक के दौरान, भारत ने एफडीआई अंतर्वाह बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया और एक व्यापक एफडीआई उदारीकरण रणनीति को अपनाया। 2015 के दौरान, 15 प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में ढील दी गई, जिसमें कृषि, नागरिक उड्डयन,

निर्माण, रक्षा, विनिर्माण और खनन शामिल हैं। 2016 में, स्टार्ट-अप में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों के लिए निवेश व्यवस्था को उदार बनाने के लिए प्रत्यक्ष निवेश नियमों में और संशोधन किया गया। 2019 के दौरान, एकल-ब्रांड खुदरा कारोबार, विमान सेवा और ऊर्जा वितरण में विदेशी निवेश पर प्रतिबंधों में ढील दी गई। 2020 की शुरुआत में, घरेलू ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं के हितों की रक्षा के लिए ई-कॉमर्स के लिए एफडीआई नीति को उदार बनाया गया था।

### III. भारत के लिए वैश्विक पूंजी प्रवाह और आवक एफडीआई

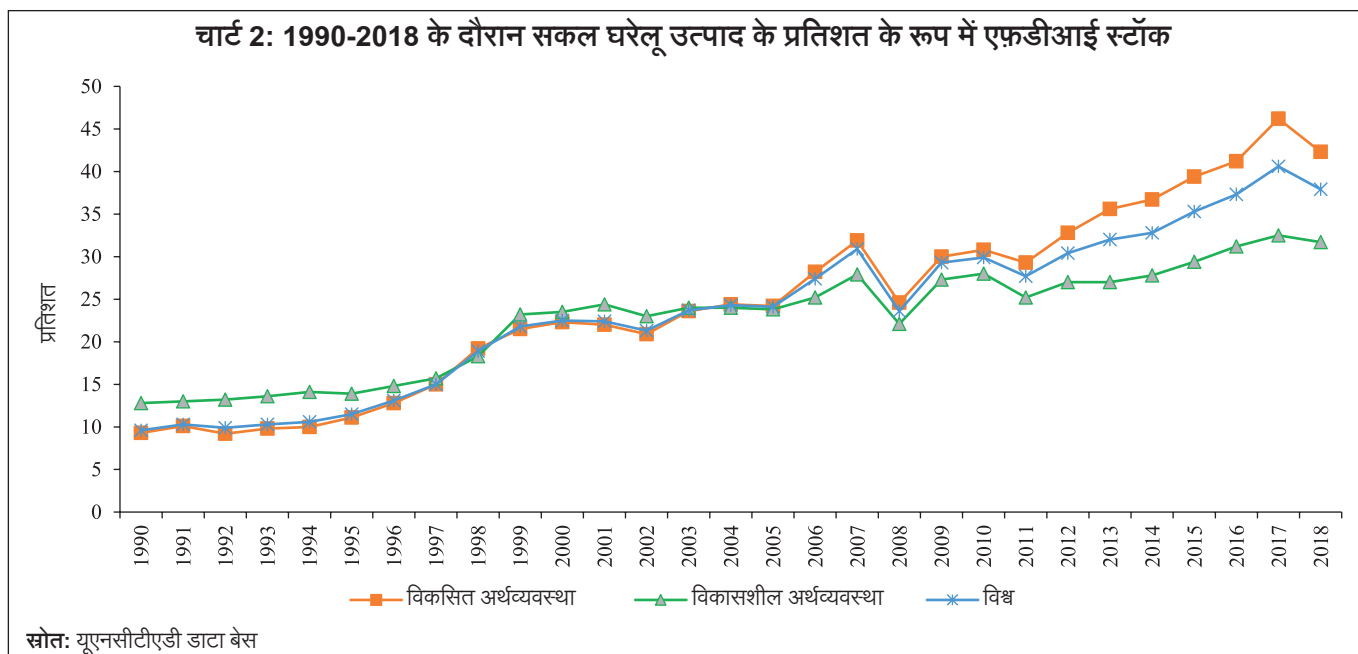
पिछले कुछ दशकों में वैश्विक व्यापार की तुलना में एफडीआई में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि, विकसित अर्थव्यवस्थाएं 1990 के बाद से प्रमुख केंद्रीय बैंकों से बड़े पैमाने पर नीति समर्थन के तहत सबसे अधिक वित्तीय रूप से एकीकृत रही हैं, इस बीच अधिक विकासशील देशों ने अपनी वित्तीय प्रणालियों और प्रत्यक्ष निवेश नीतियों को उदार बनाया है। इसके परिणामस्वरूप, एफडीआई अंतर्वाह 1997 की शुरुआत से 2007-2008 के वित्तीय संकट तक तेजी से बढ़ा। 2009 के दौरान, अंतर्वाह की एक लहर देखी गई, जिसके बाद 2010 से यूरोपीय ऋण संकट बिगड़ने के कारण एफडीआई प्रवाह में एक और उछाल आया। 2014 में, सीमा-पारीय विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) में 432 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 721 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, जिससे प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह का वैश्विक उछाल आया। हालांकि, 2017 से विकसित देशों और अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई अंतर्वाह में, मुख्य रूप से, संचित विदेशी आय पर कर देयताओं को हटाने के कारण, गिरावट जारी रही। विकासशील देशों में एफडीआई अंतर्वाह स्थिर रहा, जिससे वैश्विक एफडीआई में उनकी हिस्सेदारी 2017 में 46 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 54 प्रतिशत हो गई। हालांकि, 2017 के बाद से एफडीआई में मंदी के बावजूद, अमेरिका एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा, इसके बाद चीन, हांगकांग और सिंगापुर का स्थान रहा। विकासशील देशों और विकसित देशों (चार्ट 1 और 2) के लिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एफडीआई आवक स्टॉक पर्याप्त है। 2000-2018 की अवधि के दौरान विकासशील देशों में एफडीआई अंतर्वाह में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, उनका एफडीआई अंतर्वाह विकसित देशों की तुलना में अधिक रही और वैश्विक एफडीआई अंतर्वाह के आधे से अधिक हिस्से

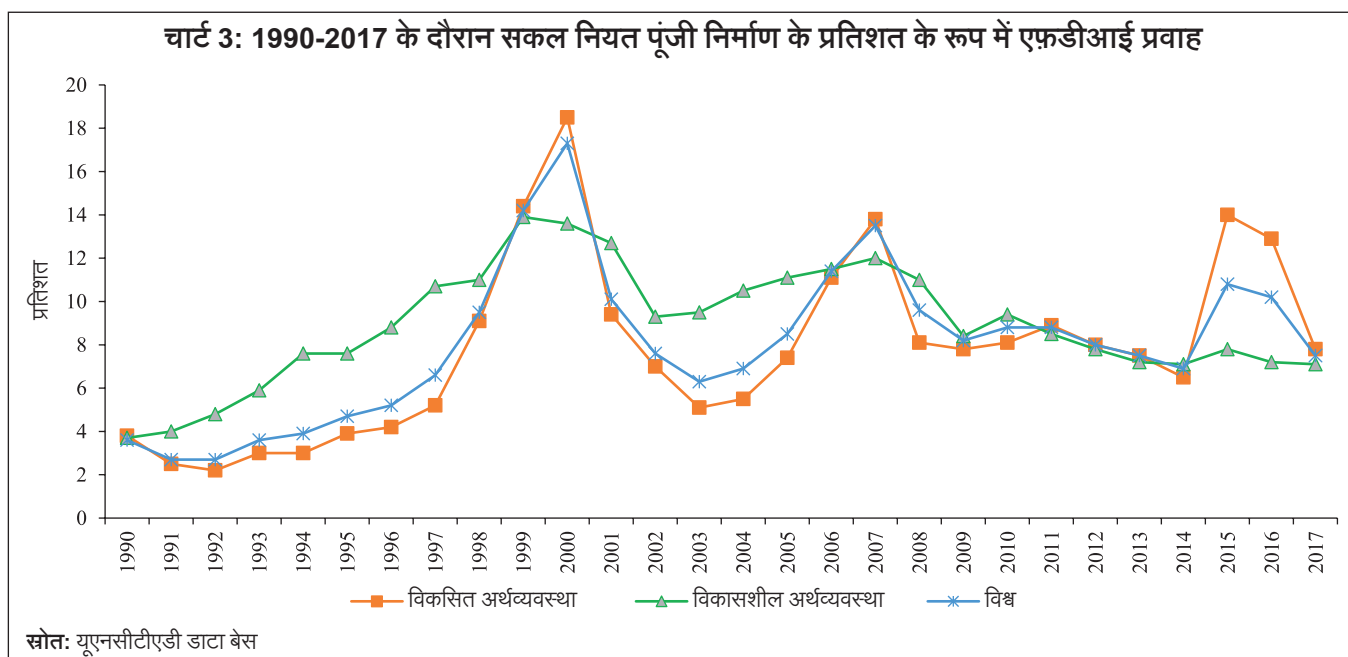




को हासिल किया। 1990-2018 के दौरान विकासशील देशों के आवक एफडीआई शेयरों का हिस्सा उनके सकल घरेलू उत्पाद का 24.6 प्रतिशत रहा, जबकि विकसित देशों में यह 22.7 प्रतिशत था। 1990-2017 के दौरान एफडीआई अंतर्वाह ने विकासशील देशों में सकल अचल आस्ति निर्माण के लगभग 9 प्रतिशत की औसत हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व किया, जबकि

विकसित देशों में यह 8 प्रतिशत था (चार्ट 3)। 2000 से 2018 तक आवक एफडीआई अंतर्वाह द्वारा मापित विकासशील देशों और विकसित देशों में शीर्ष दस स्थान वाले देश, एफडीआई (सारणी 1 और 2) के लिए विकासशील और विकसित देशों के आकर्षण के विभिन्न आयाम को दर्शाते हैं। विकासशील देशों में, संभवतः अन्य विकासशील देशों की तुलना में सस्ते ऑनशोर





मुद्रा बाजार लिखतों के कारण, चीन एफपीआई का सबसे अधिक प्राप्तकर्ता है, दूसरी ओर, अमेरिका अपने अभिनव और टिकाऊ पूंजी बाजार के कारण एफपीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा, जो दुनिया भर में पोर्टफोलियो निवेशकों को आकर्षित करता है।

20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी वृद्धि के साथ ही सरकार के नीतिगत रुख में भी उल्लेखनीय बदलाव आया। 1991 में, देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माहौल को उदार बनाने और मजबूत करने के लिए

नीतिगत उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की गई थी। परिणामस्वरूप, भारत में एफडीआई अंतर्वाह 1998-99 में 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2008 में संकट से ठीक पहले 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। वैश्विक वित्तीय संकट (2008) ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और दुनिया भर में एफडीआई अंतर्वाह को प्रभावित किया और भारत इससे अछूता नहीं रहा। भारत में एफडीआई अंतर्वाह 2013-14 तक कम रहा। 2013 में, सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 4 प्रतिशत तक धीमी हो गई, और चालू खाता घाटा सकल घरेलू

### सारणी 1: शीर्ष 10 एफडीआई - 2018 में विकासशील देशों की स्रोत अर्थव्यवस्थाएं और 2018 में एफपीआई प्रवाह

अर्थव्यवस्था	(बिलियन यूएस डॉलर और जीडीपी का प्रतिशत)				बिलियन यूएस \$	
	एफडीआई अंतर्वाह		जीडीपी का प्रतिशत		पोर्टफोलियो प्रवाह	
	2018	औसत वृद्धि (प्रतिशत) 2000-18	2018	सकल घरेलू उत्पाद में औसत हिस्सा (प्रतिशत) 2000-18	2018	औसत वृद्धि (प्रतिशत) 2000-18
चीन	139.0	10.6	1.7	3.2	60.7	1.2
चीन, हांगकांग एसएआर	115.7	48.4	26.8	29.4	-2.4	0.3
सिंगापुर	77.6	42.6	24.4	19.3	-3.7	-0.5
ब्राज़िल	61.2	25.1	4.1	3.3	-3.1	-0.2
केमैन टापू	57.4	26.4	N.A	N.A	N.A	N.A
ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड्स	44.2	11.1	N.A	N.A	N.A	N.A
भारत	42.3	35.7	1.6	1.6	-4.4	-0.2
मेक्सिको	31.6	11.8	3.2	2.8	2.4	-0.4
इंडोनेशिया	22.0	13.0	1.8	1.2	-3.7	-1.4
वियतनाम	15.5	24.7	6.3	5.5	N.A	N.A

स्रोत: अंकटाड डेटा बेस से एफडीआई अंतर्वाह; विश्व विकास संकेतक से पोर्टफोलियो अंतर्वाह और ओईसीडी से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एफडीआई अंतर्वाह।

**सारणी 2: शीर्ष 10 एफडीआई - 2018 में विकसित देशों की स्रोत अर्थव्यवस्थाएं और 2018 में एफपीआई**

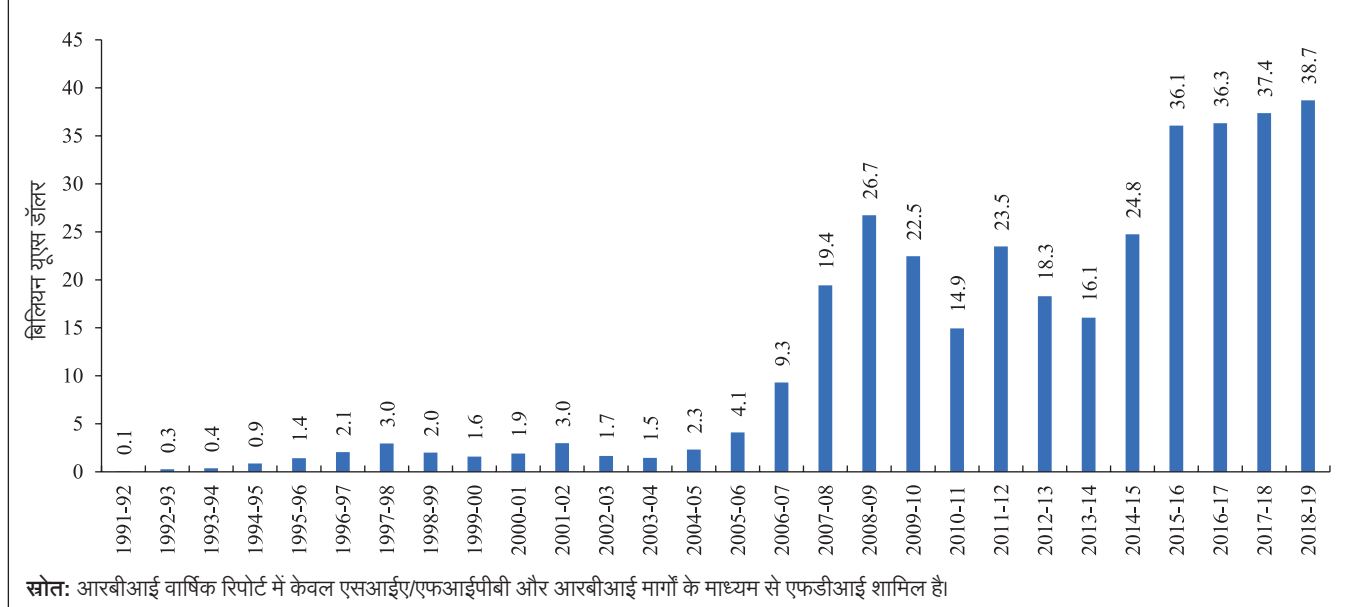
अर्थव्यवस्था	(बिलियन यूएस डॉलर और सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)				बिलियन यूएस \$	
	एफडीआई अंतर्वाह		जीडीपी का प्रतिशत		पोर्टफोलियो प्रवाह	
	2018	औसत वृद्धि (प्रतिशत) 2000-18	2018	सकल घरेलू उत्पाद में औसत हिस्सा (प्रतिशत) 2000-18	2018	औसत वृद्धि (प्रतिशत) 2000-18
संयुक्त राज्य अमरीका	251.8	14.2	1.3	1.8	142.4	0.7
नीदरलैंड	69.7	-7.0	7.2	25.2	-54.0	-0.3
यूनाइटेड किंगडम	64.5	25.8	2.8	4.6	5.6	0.5
ऑस्ट्रेलिया	60.4	78.6	4.3	3.5	-7.1	0.1
स्पेन	43.6	39.3	3.5	3.2	-15.6	0.6
कनाडा	39.6	6.2	2.7	3.3	20.1	-0.2
फ्रांस	60.4	-18.0	2.1	2.1	-20.7	0.4
जर्मनी	37.3	-11.5	4.3	2.1	-42.0	-0.6
इटली	25.7	-20.5	1.9	1.2	-5.4	-0.5
इजराइल	24.3	28.7	5.6	3.8	-8.3	-2.0

स्रोत: अंकटाड डेटा बेस से एफडीआई अंतर्वाह; विश्व विकास संकेतक से पोर्टफोलियो अंतर्वाह और ओईसीडी से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एफडीआई अंतर्वाह।

उत्पाद के लगभग 5 प्रतिशत के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। इन व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं ने भारत में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों की चिंता को बढ़ा दिया। उच्च मुद्रास्फीति और अन्य व्यापक आर्थिक समस्याओं के बीच, 2012-13 की तुलना में 2013-14 में, भारत में एफडीआई अंतर्वाह में गिरावट देखी गई। सितंबर 2014 के दौरान, भारत सरकार ने निवेश की सुविधा, नवाचार को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम निर्माण के लिए

‘मेक इन इंडिया’ पहल शुरू की। उक्त सुधार ने भारत में एक सकारात्मक विदेशी निवेश माहौल का निर्माण किया और मुख्य रूप से शीर्ष तीन उद्योग प्राप्तकर्ताओं जैसे ‘विनिर्माण’, ‘संचार’ और ‘वित्तीय सेवाओं’ में मजबूत निवेश के कारण एफडीआई अंतर्वाह में वृद्धि में मदद की। भारत में एफडीआई अंतर्वाह 2014-15 से 2018-19 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है (चार्ट 4)।

**चार्ट 4: 1991-92 से 2018-19 तक भारत में एफडीआई अंतर्वाह**



**सारणी 3: भारत में संचयी एफडीआई प्रवाह में हिस्सेदारी (2015-2019)**

देश	संचयी अंतर्वाह (%)
सिंगापुर	27.7
मॉरीशस	27.0
अमेरीका	7.5
नीदरलैंड	7.5
जापान	7.0
<b>कुल</b>	<b>76.7</b>

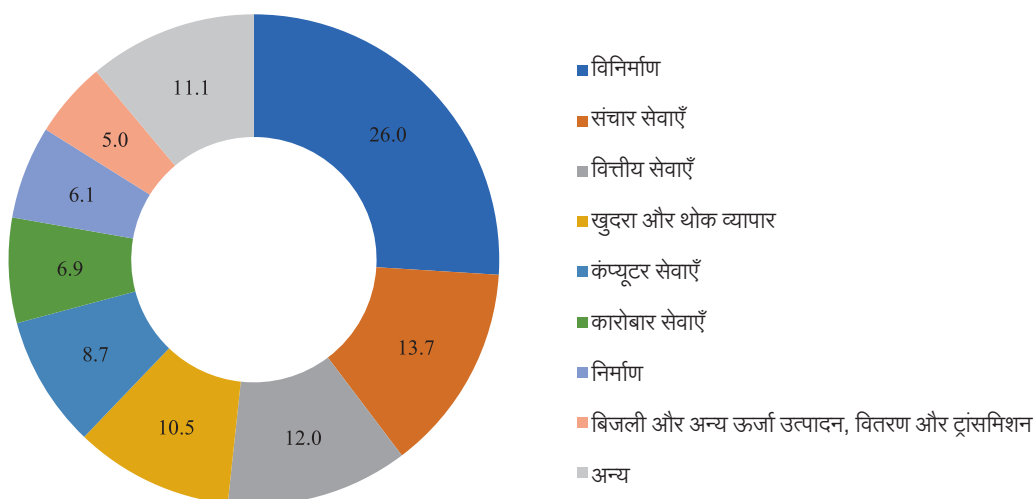
स्रोत: आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट (2018-19) में केवल एसआईए/एफआईपीबी और आरबीआई मार्गों के माध्यम से एफडीआई शामिल है।

2015 से 2019 के दौरान, भारत को 173.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संचयी एफडीआई अंतर्वाह प्राप्त हुआ और भारत में शीर्ष पांच निवेश करने वाले देशों की हिस्सेदारी 76.7 प्रतिशत रही। सिंगापुर और मॉरीशस ने मिलकर भारत में कुल विदेशी निवेश का आधे से अधिक हिस्सा हासिल किया, जिसमें कुल संचयी एफडीआई अंतर्वाह में 27.7 प्रतिशत का उच्चतम हिस्सा सिंगापुर का था (सारणी 3)। 2015-2019 के दौरान तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् 'विनिर्माण क्षेत्र', 'संचार सेवा' और 'वित्तीय सेवा' ने समग्र रूप से 89.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एफडीआई अंतर्वाह में 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी प्राप्त की (चार्ट 5)।

#### IV. एफडीआई सूचना आधार और सीडीआईएस

भारत की विदेशी देयताओं और आस्तियों (FLA) की पहली जनगणना 1948 में की गई थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक अधिनियम, 1944 के तहत जानकारी एकत्र की गई थी। बाद की अवधि में आंकड़े अलग-अलग समय-अंतराल पर संकलित किये गए थे। 1997 से, रिपोर्टिंग वार्षिक थी, लेकिन 2010 तक भागीदारी अनिवार्य नहीं थी। 2010-11 से, उन भारतीय कंपनियों के लिए रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई, जिन्होंने एफडीआई प्राप्त किया है और/या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) किया है। इसने भारत को 2010 के बाद से आईएमएफ के सीडीआईएस में भाग लेने में सक्षम बनाया। आईएमएफ द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित प्रत्यक्ष निवेश करने वाले देशों के आधार पर वर्गीकृत बाजार मूल्यों पर भारत के सीडीआईएस आंकड़े (आवक और जावक प्रत्यक्ष निवेश दोनों) अब शोधकर्ताओं और विश्लेषकों के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। एफडीआई कंपनियों ने 2012-13 से रिजर्व बैंक की वार्षिक एफएलए जनगणना के हिस्से के रूप में एफडीआई और/या ओडीआई डेटा पर विस्तृत डेटा प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। विदेशी संबद्ध व्यापार सांख्यिकी (एफएटीएस) अर्थात् निर्यात, आयात, घरेलू बिक्री और विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियों की खरीद की जानकारी भी एक साथ एकत्र की जाती है।

**चार्ट 5: 2015-19 के दौरान क्षेत्रवार संचयी एफडीआई अंतर्वाह (प्रतिशत में)**



स्रोत: आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट में केवल एसआईए/एफआईपीबी और आरबीआई मार्गों के माध्यम से एफडीआई शामिल है।

भारतीय प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों (2018-19) की एफएलए पर जनगणना से पता चलता है कि कुल एफडीआई स्टॉक का लगभग 95 प्रतिशत (मार्च 2019 में बाजार मूल्य पर 32,92,902 करोड़ रुपये) इक्विटी में था। समग्र स्तर पर, रेस्पोंडिंग कंपनियों के अंकित मूल्य पर कुल इक्विटी में एफडीआई हिस्सेदारी 81 प्रतिशत से अधिक थी; क्योंकि प्रत्यक्ष निवेश की सूचना देने वाली कंपनियों में से लगभग तीन-चौथाई कंपनियां विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियां थीं। बढ़ते वैश्वीकरण के साथ, भारतीय कंपनियां अधिक बहिर्गामी हो रही हैं और स्थायी हित के साथ विदेशी निवेश कर रही हैं। मार्च 2018 और 2019 दोनों में भारत के प्रत्यक्ष अंतर्वाही निवेश का अनुपात लगभग 18 प्रतिशत होने का अनुमान है। अंतर्वाही प्रत्यक्ष निवेश की सूचना देने वाली कंपनियों में से 96 प्रतिशत से अधिक गैर-सूचीबद्ध थीं और उन्होंने आईएमएफ द्वारा निर्धारित इक्विटी निवेश की स्व-निधि खाता मूल्य (ओएफबीवी) पद्धति का उपयोग करते हुए कंपनी के निवल मूल्य में निवासी इक्विटी होल्डिंग के हिस्से का अनुमान लगाया था।

एफएलए डेटाबेस में अंकित मूल्य के साथ-साथ बाजार मूल्य दोनों पर इक्विटी के स्टॉक को दर्शाया जाता है। मार्च 2019 के अंत तक, एफडीआई कंपनियों की कुल एफडीआई इक्विटी हिस्सेदारी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी अंकित मूल्य पर 46.2 प्रतिशत और बाजार मूल्य पर 53.3 प्रतिशत रही जो बाजार मूल्य के अनुपात में विभिन्न क्षेत्रों के इक्विटी के अंकित मूल्य के अनुपात में अंतर के कारण थी। (सारणी 4)।

मार्च 2019 में समग्र स्तर पर एफडीआई कंपनियों की इक्विटी के बाजार मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 5.1 था, लेकिन यह विभिन्न क्षेत्रों में 2.1 से 11.9 तक था। इसका कारण कॉरपोरेट लाभप्रदता, मध्यावधि की वृद्धि और संभावित वृद्धि सहित कई कारक हो सकते हैं। अंकित मूल्य और बाजार मूल्यांकन के बीच 0.9 का उच्च सहसंबंध बताता है कि विभिन्न क्षेत्रों के इक्विटी पर इन कारकों का प्रभाव है (सारणी 5)।

एफएलए जनगणना 2018-19 के अनुसार, अंतर्वाही एफडीआई की रिपोर्टिंग करने वाली कंपनियों में से लगभग 75 प्रतिशत एफडीआई सहायक कंपनियां ऐसी थीं, जिन्होंने अंतर्वाही एफएटी आंकड़ों की गतिविधि के अनुसार रिपोर्ट की है। एफडीआई

#### सारणी 4: एफडीआई कंपनियों की क्षेत्रवार इक्विटी भागीदारी: मार्च 2019

(₹ करोड़)

गतिविधि	कुल इक्विटी (निवासी और अनिवासी सहित)	एफडीआई इक्विटी हिस्सेदारी	
		अंकित मूल्य पर	बाजार मूल्य पर
1. कृषि से संबंधित, वृक्षारोपण और संबद्ध गतिविधियां	1,838	1,698	7,060
2. खनन	1,657	1,390	6,456
3. निर्माण	3,21,314	2,81,560	16,64,304
4. बिजली, गैस, भाप और एयर कंडीशनिंग आपूर्ति	47,545	27,136	59,016
5. जल आपूर्ति; सीवरेज, अपशिष्ट प्रबंधन और उपचारात्मक गतिविधियां	1,996	1,792	2,745
6. निर्माण	25,160	19,647	41,009
7. सूचना और संचार	58,874	45,448	5,41,385
8. अन्य सेवाएं	2,92,143	2,30,651	799,410
<b>कुल</b>	<b>7,50,527</b>	<b>6,09,322</b>	<b>31,21,385</b>

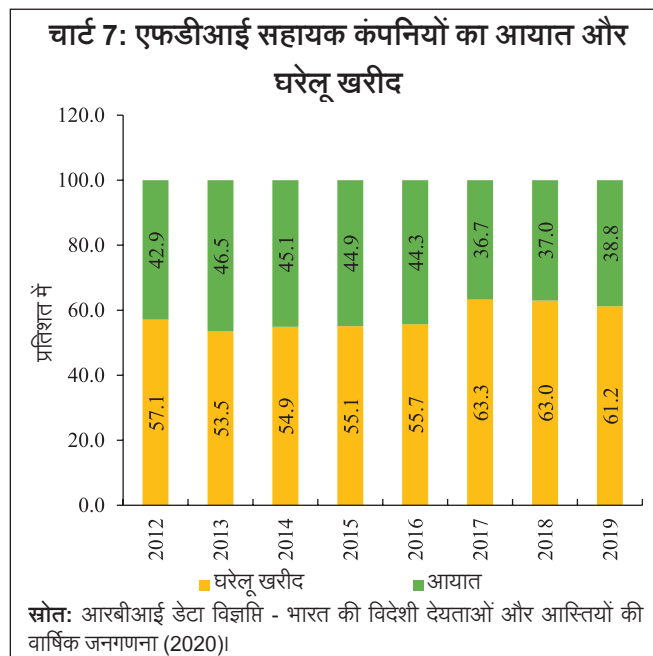
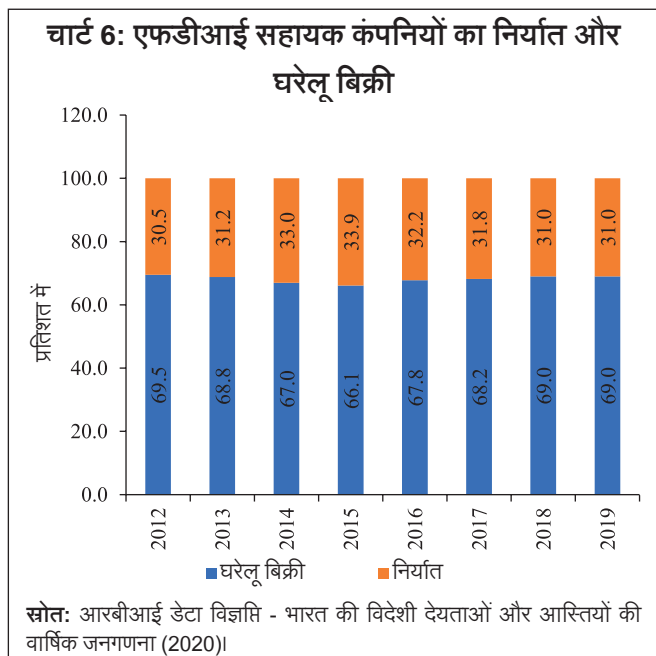
स्रोत: आरबीआई डेटा विज्ञप्ति - भारत की विदेशी देयताओं और आस्तियों की वार्षिक जनगणना (2020)।

सहायक कंपनियों के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से घरेलू बाजार में केंद्रित है। कुल बिक्री में एफडीआई सहायक कंपनियों के निर्यात की हिस्सेदारी 2012-2019 के दौरान औसतन 31.8 प्रतिशत रही (चार्ट 6)। 2018-19 के दौरान 'सूचना और संचार सेवाएं' प्रमुख निर्यात उन्मुख क्षेत्र रहा। विदेशी सहायक कंपनियां कच्चे माल, पुर्जों आदि की खरीद के लिए बड़े पैमाने पर भारतीय घरेलू बाजार पर निर्भर हैं (सारणी 6 और चार्ट 7)।

#### सारणी 5: इक्विटी अनुपात (अंकित मूल्य से बाजार मूल्य), सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि: क्षेत्र-वार

	बाजार मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात	औसत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि (2000-19)
1. कृषि से संबंधित, वृक्षारोपण और संबद्ध गतिविधियां	4.2	3.2
2. खनन	4.6	4.2
3. निर्माण	5.9	7.5
4. बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति	3.7	6.6
5. निर्माण	2.1	6.6
6. सूचना और संचार	11.9	18.3
7. अन्य सेवाएं	3.5	8.3
<b>कुल</b>	<b>5.1</b>	<b>7.0</b>

स्रोत: आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति (2020) और सीएसओ डेटा।



सीडीआईएस, आईएमएफ के नेतृत्व में सीमा पार निवेश में सूचना अंतराल को पाटने के लिए एक विश्वव्यापी सांख्यिकीय आंकड़ा संग्रहण के लिए एक प्रयास है। इसे समग्र रूप से और तत्काल समकक्ष अर्थव्यवस्था के आधार पर एफडीआई आंकड़े की उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सीडीआईएस में, कोई देश अपनी इच्छा से अपने

कैलेंडर-वर्ष के अंत में प्रत्यक्ष निवेश की स्थिति को तत्काल प्रतिपक्षों के आधार पर बाजार मूल्य पर इक्विटी और ऋण के बीच विभाजित करके रिपोर्ट करता है। बकाया विदेशी देयताओं और आस्तियों के बाजार मूल्यांकन में परिवर्तन किसी एक वर्ष के दौरान भुगतान संतुलन (बीओपी) प्रवाह से भिन्न होते हैं, क्योंकि बकाया विदेशी देयताओं और आस्तियों में मूल्यांकन परिवर्तन भी शामिल होते हैं।

**सारणी 6: बाजार मूल्य और कुल निर्यात पर कुल एफडीआई का गतिविधिवार हिस्सा: 2018-19**

क्र. सं.	गतिविधि	बाजार मूल्य पर कुल एफडीआई का हिस्सा (प्रतिशत)	कुल निर्यात का हिस्सा (प्रतिशत)
1	सूचना और संचार	16.7	45.5
2	वित्तीय और बीमा गतिविधियाँ	14.0	1.4
3	मोटर वाहन, ट्रैलर और अर्ध-ट्रैलर	6.9	7.2
4	अन्य सेवा गतिविधियाँ	5.2	10.7
5	खाद्य उत्पाद	4.7	0.8
6	रसायन और रासायनिक उत्पाद	4.0	1.6
7	मशीनरी और उपकरण एनईसी	3.6	3.4
8	फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय और रासायनिक उत्पाद	3.5	3.0
9	थोक और खुदरा व्यापार; मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत	3.2	7.6
10	अन्य	38.2	18.8
<b>कुल</b>		<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

स्रोत: आरबीआई डेटा विज्ञप्ति - भारत की विदेशी देयताओं और आस्तियों की वार्षिक जनगणना (2020)

चूंकि सीडीआईएस में भाग लेने वाले सभी देश भागीदार देश-वार प्रत्यक्ष निवेश (अंतर्वाही या बहिर्गामी या दोनों) की रिपोर्ट करते हैं, इसलिए शीर्ष नौ स्रोत देशों से, जो मार्च 2019 में एफएलए जनगणना परिणामों के अनुसार भारत में समग्र रूप से एफडीआई स्टॉक का 78.9 प्रतिशत हिस्सा है, अंतर्वाही प्रत्यक्ष निवेश की स्टॉक स्थिति को सत्यापित करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। मार्च 2019 में कुल एफडीआई स्टॉक में यूएसए की सबसे बड़ी हिस्सेदारी (17.8 प्रतिशत) थी (सारणी 7)। यह उल्लेखनीय है कि निवेश और निवेशित देशों द्वारा रिपोर्ट किए गए एफडीआई का स्टॉक विभिन्न कारणों से कई मामलों में भिन्न होता है और इसे केवल संदर्भ तिथि में केवल 3 महीने के अंतर के लिए जोड़ा नहीं जा सकता है। यह अंतर शामिल किए गए निवेशक/निवेशित फर्मों के आकलन पद्धति (जनगणना बनाम सर्वेक्षण), लेखांकन और मूल्यांकन की कठिनाइयों, रिपोर्टिंग त्रुटियों आदि के कारण भी हो सकता है।

**सारणी 7: बाजार मूल्य पर स्रोत देश-वार एफडीआई**

देश	भारत में एफडीआई (₹ करोड़)	
	एफएलए जनगणना परिणामों के अनुसार (मार्च '19)	सीडीआईएस में भागीदार देश द्वारा रिपोर्ट किया गया (दिसंबर '18)
अमेरीका	5,84,978	3,20,933
यूनाइटेड किंगडम	5,17,369	1,28,814
मॉरीशस	5,09,914	8,79,038
जापान	2,82,724	1,69,877
नीदरलैंड	2,50,491	1,76,888
जर्मनी	1,63,773	1,95,789
स्विट्जरलैंड	1,59,576	44,273
कोरिया गणराज्य	79,578	42,646
फ्रांस	48,135	44,199
उपरोक्त सभी देश	25,96,538	20,02,456
सिंगापुर	4,13,174	Not Reported
अन्य देश	2,83,190	All Not Reported
सभी देश	32,92,902	All Not Reported

स्रोत: आरबीआई डेटा रिलीज (2020) और आईएमएफ की वेबसाइट <http://cdsis.imf.org>

**V. एफडीआई अंतर्वाह को प्रभावित करने वाले कारकों का अनुभवजन्य विश्लेषण**

इस खंड में, हम प्रमुख साझेदार देशों में एफडीआई अंतर्वाह को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को निर्धारित करने के लिए भारत में एफडीआई स्टॉक का पर्याप्त हिस्सा रखने वाले एक पैनल के अभ्यास के परिणाम को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस आंकड़ा समूह में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं जैसे यूएसए, यूके, मॉरीशस, जापान, नीदरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कोरिया गणराज्य, फ्रांस और भारत के लिए 2009-10 से 2017-18 की अवधि के अवलोकन शामिल हैं। संपूर्ण आंकड़ा समूह विश्व बैंक, आईएमएफ, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) तथा विश्व बैंक डेटाबेस द्वारा प्रकाशित वैश्विक विकास वित्त से प्राप्त किया गया है।

एफडीआई प्रवाह को जीडीपी अनुपात में एफडीआई अंतर्वाह के रूप में मापा गया है और व्याख्यात्मक चर की सीमा रेंज में अवरोहित किया गया है। साहित्य समीक्षा के आधार पर एफडीआई प्रवाह को प्रभावित करने वाले कुछ चर ये हैं: बाजार का आकार (पीपीपी), व्यापार का खुलापन (ओपन), विनिमय दर (ईआर), श्रम भागीदारी दर (एलएबीओआर), सकल घरेलू उत्पाद के लिए कर राजस्व (टैक्स\_जीडीपी), समष्टि-आर्थिक स्थिरता (जीएफडी\_जीडीपी) और चयनित देशों का पूंजी खाता खुलापन सूचकांक (केए\_ओपन)। क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के संदर्भ में बाजार के आकार को जीडीपी अर्थात् क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के आधार

पर प्रति व्यक्ति जीडीपी के रूप में परिभाषित किया गया है। व्यापार के खुलेपन को वर्तमान प्राप्ति और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के भुगतान के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी देश में कम श्रम लागत और कर की दरों का एफडीआई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है (बरातकर, 2013)। यहां जिस चार पर विचार किया गया है, वह श्रम बल की भागीदारी की दर है, जिसे 15-64 आयु वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए श्रम की आपूर्ति में आर्थिक रूप से सक्रिय है। एफडीआई भी काफी हद तक विनिमय दर के उतार-चढ़ाव और मेजबान अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर पर निर्भर करेगा (सेविस और कैमुरान, 2007)। तदनुसार, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि (जीडीपी\_विकास) को भी स्वतंत्र चर माना गया है। प्राप्त परिणाम दर्शाते हैं कि एफडीआई पर वित्तीय खुलेपन (पूंजी नियंत्रण को आसान बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है) का प्रभाव वित्तीय बाजार के विकास की तुलना में कहीं अधिक प्रत्यक्ष है। वित्तीय खुलेपन में सुधार से मेजबान देश में एफडीआई में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। चिन और इतो (2006) में प्रस्तुत किए गए किसी देश की पूंजी खाते के खुलेपन के स्तर को मापने के लिए लाया गया चिन-इटो सूचकांक को एक स्वतंत्र चर के रूप में माना गया है। इंडेक्स (केए\_ओपन) का निर्माण कई ऐसे बाइनरी छद्म चर के आधार पर किया गया है, जो आईएमएफ की विनिमय व्यवस्था और विनिमय पंजीकरण (एआरईईआर) की वार्षिक रिपोर्ट में रिपोर्ट किए गए सीमा पार वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंधों के सारणीकरण को निर्धारित करता है। इस सूचकांक के उच्च मान का अर्थ है कि देश सीमा पार पूंजी लेनदेन के लिए उतना ही अधिक खुला है। केए\_ओपन इंडेक्स '1' का मान दर्शाता है कि देश सीमा पार वित्तीय लेनदेन पर पूरी तरह से खुला है और उच्च एफडीआई प्रवाह की उम्मीद है। केंद्र सरकार के वित्त और जीडीपी अनुपात के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के माध्यम से प्राप्त राजकोषीय स्थिरता को भी व्याख्यात्मक चर में से एक के रूप में लिया गया है। उक्त अध्ययन में पैनल निर्धारित प्रभाव <sup>1</sup> प्रतिगमन मॉडल पर विचार किया और समीकरण इस प्रकार है :

<sup>1</sup> निर्धारित-प्रभाव (एफई) मॉडल का उपयोग स्वतंत्र चर के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। एफई एक देश के भीतर अनुमानकर्ता और परिणाम चर के बीच संबंधों की पड़ताल करता है। यह माना जाता है कि एफई उन समय-अपरिवर्तनीय विशेषताओं के प्रभाव को हटा देता है, इसलिए हम परिणाम चर पर भविष्यवाणियों के निवल प्रभाव का आकलन कर सकते हैं।

$$Y_{it} = \beta_1 X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

जहाँ  $i = 1, 2, \dots, n$  और  $t = 1, 2, \dots, T$

$\alpha_i$ 's व्यक्तिगत अज्ञात अवरोधन हैं

$Y_{it}$  निर्भर चर (DV) है जहाँ  $i =$  देश और  $t =$  समय.

$X_{it}$  स्वतंत्र चर के वेक्टर का प्रतिनिधित्व करता है।

$\beta_1$  गुणांक है

$u_{it}$  एरर टर्म है

हॉसमैन परीक्षण से पता चलता है कि पैनल निर्धारित प्रभाव मॉडल उपयुक्त होगा और 2010 से 2018 की अवधि के लिए पैनल निर्धारित प्रभाव प्रतिगमन समीकरण 10 देशों (एन = 10) और 9 वर्षों (टी = 9) के लिए अनुमानित था।

अपेक्षाओं के अनुसार, पुल कारकों (चर) के गुणांक जैसे व्यापार खुलापन, विकास दर, श्रम भागीदारी दर और पूंजी खाता खुलेपन का सूचकांक (केए\_ओपन) सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया। इसी तरह, यह पाया गया कि पीपीपी के संदर्भ में मेजबान देशों के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर प्राप्त बाजार का आकार भी एफडीआई प्रवाह को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हालांकि, विनिमय दर, जीडीपी से जीएफडी अनुपात (जो राजकोषीय स्थिरता को दर्शाता है) और कर से जीडीपी अनुपात को सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन पाया गया, जबकि उनके संकेत पूर्व अपेक्षाओं के अनुसार थे। पैनल के परिणाम से पता चलता है कि उच्च स्तर का खुलापन, अर्थव्यवस्था का विकास, बड़ा

बाजार आकार, पर्याप्त श्रम भागीदारी प्रमुख कारक हैं जो मेजबान देश में एफडीआई प्रवाह को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा, देश के पूंजी खाते के खुलेपन का उच्च स्तर भी अधिक एफडीआई प्रवाह को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है (सारणी 8)।

## VI. निष्कर्ष

इस अवधि के दौरान, भारत के लिए एफडीआई सांख्यिकी पर कई सूचना आधार उपलब्ध हो गए हैं। विभिन्न देशों द्वारा आँकड़ों को संकलित करने में नियोजित वैश्विक अवधारणाएँ, सांख्यिकीय पद्धतियों को समझने में मदद करती हैं और परिणामी आँकड़ों का उपयोग विभिन्न देशों के बीच तुलना के लिए किया जा सकता है। बेशक, उदार निवेश योजना वाले देशों को विदेशी निवेश के आकलन में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत की एफएलए जनगणना, जो वैश्विक सीडीआईएस पहल का एक हिस्सा है, इस संबंध में एक बड़ा कदम है क्योंकि यह पूर्ण गणना के आधार पर भारत में एफडीआई के अंकित मूल्य के साथ-साथ बाजार मूल्य पर लगातार वार्षिक डेटा देता है।

एफएलए जनगणना के अनुसार और प्रमुख एफडीआई स्रोत देशों के लिए सीडीआईएस में भागीदार देश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष निवेश अनुमानों में अंतर संदर्भ तिथि, निवेशक/निवेशित फर्मों के कवरेज, आकलन पद्धति (जनगणना/सर्वेक्षण), लेखांकन और मूल्यांकन संबंधी कठिनाइयों में अंतर के कारण होता है। आईएमएफ, विश्व बैंक, ओईसीडी, यूएनसीटीएडी, यूरोपीय आयोग आदि जैसे वैश्विक सांख्यिकीय संगठन सीमा पार के आँकड़ों में ऐसी सांख्यिकीय विसंगतियों को दूर करने के लिए अवधारणाओं और विधियों के मानकीकरण किये जाने में शामिल हैं।

वैश्विक स्तर पर और क्षेत्रों/देशों में एफडीआई प्रवाह में हाल के रुझानों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत ने आम तौर पर उच्च एफडीआई प्रवाह रहा है और अपने मजबूत घरेलू आर्थिक प्रदर्शन और सतर्क पूंजी खाता उदारीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एफडीआई नीति का क्रमिक उदारीकरण के कारण अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए शीर्ष आकर्षक स्थानों में से एक बना हुआ है।

सारणी 8: पैनल निश्चित प्रभाव अनुमान के परिणाम

चर	गुणक	कक्षा त्रुटि	टी आँकड़ा	समस्या
सी*	154.505	42.762	3.613	0.0007
पीपीपी**	0.002	0.001	2.182	0.0336
ओपन *	0.935	0.246	3.798	0.0004
जीडीपी वृद्धि**	2.950	1.380	2.137	0.0373
श्रम*	2.816	0.956	2.946	0.0030
केए -ओपन *	3.613	1.084	3.334	0.0022
ईआर	-0.058	0.051	-1.145	0.2575
जीएफडी_जीडीपी	-0.728	1.046	-0.696	0.4893
टैक्स_जीडीपी	-0.247	0.767	-0.321	0.7491

आर<sup>2</sup> = 0.87 एड आर<sup>2</sup> = 0.82

डीडब्ल्यू स्टेटा = 1.7

\* 1% के स्तर पर महत्वपूर्ण \*\* 5% के स्तर पर महत्वपूर्ण।



विदेशी सहायक कंपनियों के लिए निवेश और संबंधित प्रदर्शन (एफएटी आंकड़े) के क्षेत्र-वार वितरण के दिलचस्प पहलुओं को संक्षेप में एफएलए जनगणना परिणामों के विश्लेषण द्वारा प्रस्तुत किया। विदेशी सहायक कंपनियों के लिए जहां खरीद में आयात की तीव्रता, बिक्री में निर्यात से अधिक रही, उनके व्यापार में विदेशी व्यापार एक बड़ा हिस्सा था।

भारत में एफडीआई स्टॉक की स्थिति के संदर्भ में प्रमुख देशों पर विचार करते हुए, आवक एफडीआई को प्रभावित करने वाले कारकों का एक अनुभवजन्य विश्लेषण दर्शाता है कि आवक एफडीआई व्यापार के खुलेपन, आर्थिक विकास की संभावनाओं, बाजार के आकार, श्रम लागत और मेजबान देशों के पूंजी खाते के खुलेपन से काफी प्रभावित है।

## References

1. Cevis, I., and Camuran, B. (2007), "The economic determinants of Foreign Direct Investment in developing countries and transition economies", *The Pakistan Development Review*, 46(3):285–299.
2. Chinn, Menzie D. and Hiro Ito (2006), "What Matters for Financial Development? Capital Controls, Institutions, and Interactions", *Journal of Development Economics*, Volume 81, Issue 1, Pages 163-192 (October).
3. Division of International Trade and Finance of the Department of Economic and Policy Research, Reserve Bank of India (2010-11), "Foreign Direct Investment Flows to India", [https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/FDIST\\_110412.pdf](https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/FDIST_110412.pdf).
4. Department for Promotion of Industry and Internal Trade, GoI, Press Note No. 1(2020 Series), "Review of Foreign Direct Investment (FDI) policy in Insurance Sector".
5. Department for Promotion of Industry and Internal Trade, GoI, Press Note No. 2(2020 Series) "Review of Foreign Direct Investment (FDI) policy on Civil Aviation: Review of Foreign Direct Investment (FDI) policy for curbing opportunistic takeovers/acquisitions of Indian companies due to the current COVID-19 pandemic".
6. International Monetary Fund (2008), "Balance of Payments and International Investment Position Manual", Sixth Edition (BPM6).
7. International Monetary Fund (1992), "Report on the Measurement of International Capital Flows", <https://www.elibrary.imf.org/view/books/071/05673-9781557753076-en/05673-9781557753076-en-book.xml>.
8. Ms. Sapna Hooda (2011), "A Study of FDI and Indian Economy, National Institute of Technology", Kurukshetra, Deemed University, Kurukshetra, Haryana, India, [https://nitkr.ac.in/nit\\_kuk/docs/Sapna\\_Hooda\\_Thesis\\_A\\_Study\\_of\\_FDI\\_and\\_Indian\\_Economy.pdf](https://nitkr.ac.in/nit_kuk/docs/Sapna_Hooda_Thesis_A_Study_of_FDI_and_Indian_Economy.pdf).
9. Nihal Bayraktar (2013), "Foreign Direct investment and Investment Climate", Pennsylvania State University-Harrisburg, USA.
10. Press Note No. 4(2019 Series), "Review of Foreign Direct Investment (FDI) policy on various sector".
11. Reserve Bank of India, "Annual Census of India's Foreign Liabilities and Assets", RBI Bulletin, [https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/PDFs/2AR\\_BUL10022014.pdf](https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/PDFs/2AR_BUL10022014.pdf) and [https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/PDFs/02AR\\_10041829F7F8EB034F4055ADE629893A9C0926.PDF](https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/PDFs/02AR_10041829F7F8EB034F4055ADE629893A9C0926.PDF).
12. Reserve Bank of India, Press Release (2020). "Finances of Foreign Direct Investment Companies 2018-19".
13. UNCTAD/WIR, "World Investment Report", [https://unctad.org/publications-search?f\[0\]=product%3A397](https://unctad.org/publications-search?f[0]=product%3A397).



# वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
मुद्रा और बैंकिंग  
मूल्य और उत्पादन  
सरकारी लेखा और खज़ाना बिल  
वित्तीय बाजार  
बाह्य क्षेत्र  
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ  
अवसरिक शृंखला



## विषय-वस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिदा आर्थिक संकेतक	85
	<b>भारतीय रिज़र्व बैंक</b>	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	86
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	87
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय/विक्रय	88
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	89
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	89
	<b>मुद्रा और बैंकिंग</b>	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	90
7	मुद्रा स्टॉक (एम <sub>3</sub> ) के स्रोत	91
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	92
9	कुल चलनिधि राशियां	92
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	93
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	93
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	94
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	94
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	95
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	96
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	97
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	98
	<b>मूल्य और उत्पादन</b>	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	99
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	99
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	99
21	थोक मूल्य सूचकांक	100
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	104
	<b>सरकारी खाते और खजाना बिल</b>	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	104
24	खजाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	105
25	खजाना बिलों की नीलामी	105
	<b>वित्तीय बाजार</b>	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	106
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	107
28	वाणिज्यिक पत्र	107
29	चुनिदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	107
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	108

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	<b>बाह्य क्षेत्र</b>	
31	विदेशी व्यापार	109
32	विदेशी मुद्रा भंडार	109
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	109
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	110
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	110
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	111
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- पंजीकरण	112
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरीकी डॉलर)	113
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	114
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	115
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	116
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	117
	<b>भुगतान और निपटान प्रणालियाँ</b>	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	118
	<b>अवसरिक श्रृंखला</b>	
44	लघु बचत	120
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	121
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	122
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	123
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	124
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	125

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।

– = शून्य/नगण्य

प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम      आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

## सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2020-21	2020-21		2021-22	
		ति1	ति2	ति1	ति2
	1	2	3	4	5
<b>1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)</b>					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	-6.2	-22.4	-7.3	18.8	8.5
1.1.1 कृषि	3.6	3.5	3.0	4.5	4.5
1.1.2 उद्योग	-6.4	-31.0	-1.6	40.4	6.7
1.1.3 सेवाएं	-8.4	-24.9	-11.0	16.1	9.9
1.1क अंतिम खपत व्यय	-7.3	-19.9	-13.4	13.8	8.6
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	-10.8	-46.6	-8.6	55.3	11.0
	2020-21	2020		2021	
		अक्टू.	नव.	अक्टू.	नव.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	-8.4	4.5	-1.6	4.0	-
<b>2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)</b>					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	11.4	11.1	10.7	10.0	8.9
2.1.2 ऋण	5.6	5.6	5.9	6.9	6.9
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	5.5	5.6	5.9	7.0	7.1
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	19.3	21.5	19.3	4.4	3.6
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	18.8	12.8	15.3	14.1	12.8
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	12.2	11.6	12.5	9.7	9.5
<b>3 अनुपात (%)</b>					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	3.50	3.00	3.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.2	3.8	3.8	4.9	4.8
3.4 ऋण-जमा अनुपात	72.4	72.0	72.2	70.0	71.0
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	37.4	2.0	11.0	20.8	37.3
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.5	31.0	30.5	29.4	29.0
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	46.8	85.4	73.6	27.0	17.7
<b>4 व्याज दरें (%)</b>					
4.1 नीति रिपो दर	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
4.2 रिवर्स रिपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
4.4 बैंक दर	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
4.5 आधार दर	7.40/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80	7.30/8.80	7.30/8.80
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	6.55/7.05	6.65/7.10	6.60/7.10	6.50/7.00	6.50/7.00
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50
4.8 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	3.25	3.19	3.10	3.28	3.35
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.32	3.20	2.93	3.56	3.53
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.47	3.36	3.26	3.83	3.83
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.83	3.45	3.39	4.04	4.13
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	6.34	5.91	5.84	6.43	6.33
<b>5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया</b>					
5.1 भा.रु.-अमरीकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	72.40	73.97	73.80	74.79	74.71
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	85.31	86.97	88.02	87.26	83.85
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमरीकी डॉलर					
1-माह (%)	6.80	3.24	3.36	4.17	3.69
3-माह (%)	5.64	3.46	3.52	4.39	3.80
6-माह (%)	5.47	3.89	4.23	4.75	4.71
<b>6 मुद्रास्फीति (%)</b>					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	6.18	7.6	6.9	4.5	4.9
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.03	5.9	5.3	4.5	4.8
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	1.29	1.3	2.3	12.5	14.2
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	1.71	4.3	3.8	5.2	10.3
6.3.2 ईंधन और पावर	-7.99	-11.1	-7.0	37.2	39.8
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	2.75	2.2	3.2	12.0	11.9
<b>7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)</b>					
7.1 आयात	-16.91	-10.3	-12.2	56.9	56.6
7.2 निर्यात	-6.88	-4.9	-8.3	43.0	27.2

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

## भारतीय रिज़र्व बैंक

## सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां\*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2020-21	2020	2021				
		दिसं	दिसं 3	दिसं 10	दिसं 17	दिसं 24	दिसं 31
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1 निर्गम विभाग</b>							
<b>1.1 देयताएं</b>							
1.1.1 संचलन में नोट	2831727	2751458	2956654	2973108	2970938	2968500	2959237
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	12	17	13	15	14	13
<b>1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां</b>	<b>2831738</b>	<b>2751470</b>	<b>2956672</b>	<b>2973121</b>	<b>2970954</b>	<b>2968513</b>	<b>2959250</b>
<b>1.2 आस्तियां</b>							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	106555	116647	112142	113765	115546	114565	113486
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2724437	2633880	2843876	2858724	2854792	2853359	2845196
1.2.3 रुपया सिक्का	746	942	654	632	616	589	567
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 बैंकिंग विभाग</b>							
<b>2.1 देयताएं</b>							
2.1.1 जमाराशियां	1504697	1460970	2035493	2036766	2032848	2023248	1991453
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	100	100	100	100	101	100
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	542693	457719	684594	645866	693730	649877	716432
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6529	5507	7541	7072	7819	6968	7631
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3204	2586	3705	3751	3570	3530	3416
2.1.1.7 अन्य बैंक	31820	27481	36666	37160	36186	36877	37349
2.1.1.8 अन्य	895440	962753	1236011	1259766	1202262	1238933	1180276
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	24868	4782	66833	83009	89139	86922	46206
2.1.2 अन्य देयताएं	1343670	1476078	1352182	1389760	1423006	1356333	1313545
<b>2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां</b>	<b>2848367</b>	<b>2937049</b>	<b>3387675</b>	<b>3426526</b>	<b>3455855</b>	<b>3379581</b>	<b>3304998</b>
<b>2.2 आस्तियां</b>							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	12	18	13	15	14	13
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1204135	1348295	1489239	1507032	1524661	1459742	1412900
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	1674	3946	7758	10531	13574	5188	6677
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	90275	77318	93941	93941	94213	98265	102489
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	26422	26133	20297	20297	20297	24696	24770
2.2.3.7 एक्विजि बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	6678	9241	77	77	77	77	77
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	24858	15826	50993	67039	76260	74040	46227
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1331671	1296115	1539742	1538852	1534678	1525792	1521572
2.2.6 अन्य आस्तियां	162643	160163	185611	188745	192080	191768	190274
2.2.6.1 सोना	146572	153378	176453	179370	182546	180997	179293

\*: डेटा अनंतिम है।



**सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन**

(करोड़ ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घावधि रिपो परिचालन&	लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन#	लघु वित्त बैंकों के लिए विशेष दीर्घावधि रिपो परिचालन	विशेष पुनः क्रय रिपो ₹	निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+11+12-2-4-7-8-13)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय					
दिसं. 1, 2021	-	278854	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-278554
दिसं. 2, 2021	-	250222	-	200022	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-449980
दिसं. 3, 2021	-	160485	-	434492	244	-	-	-	-	-	-	-	1449	-596182
दिसं. 4, 2021	-	12215	-	-	2110	-	-	-	-	-	-	-	-	-10105
दिसं. 5, 2021	-	35361	-	-	1475	-	-	-	-	-	-	-	-	-33886
दिसं. 6, 2021	-	8321	-	-	11442	-	-	-	-	-	-	-	-	3121
दिसं. 7, 2021	-	1328	-	-	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-1143
दिसं. 8, 2021	-	256290	-	-	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-255955
दिसं. 9, 2021	-	218794	-	200015	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-414709
दिसं. 10, 2021	-	251799	-	-	95	-	-	205	-	-	-	-	-	-251909
दिसं. 11, 2021	-	246428	-	-	12	-	-	50	-	-	-	-	-	-246466
दिसं. 12, 2021	-	243661	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-243536
दिसं. 13, 2021	-	3750	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-3688
दिसं. 14, 2021	-	4582	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-4572
दिसं. 15, 2021	-	250255	-	-	0	-	-	10	-	-	250	105	-	-249910
दिसं. 16, 2021	-	251559	-	200010	100	-	-	255	-	-	-	-	-	-451724
दिसं. 17, 2021	-	237185	-	-	9	-	-	290	-	-	-	-	-	-237466
दिसं. 18, 2021	-	97803	-	445742	1215	2500	-	625	-	-	-	-	-	-540455
दिसं. 19, 2021	-	46619	-	-	7201	-	-	-	-	-	-	-	-	-39418
दिसं. 20, 2021	-	15620	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-15552
दिसं. 21, 2021	-	1898	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-1873
दिसं. 22, 2021	-	113246	-	-	40	-4194	-	445	-	-	100	-	-	-117745
दिसं. 23, 2021	-	156814	-	148073	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-304887
दिसं. 24, 2021	-	177454	-	-	0	-	-	720	-	-	-	-	-	-178174
दिसं. 25, 2021	-	191837	-	-	0	-	-	135	-	-	-	-	-	-191972
दिसं. 26, 2021	-	196144	-	-	65	-	-	530	-	-	-	-	-	-196609
दिसं. 27, 2021	-	3450	-	-	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-3291
दिसं. 28, 2021	-	2458	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-2444
दिसं. 29, 2021	-	182093	-	-	73	-	-	685	-	-	305	-	-	-182400
दिसं. 30, 2021	-	186256	-	250016	646	-	-	295	-	-	-	-	-	-435921

**टिप्पणी:** # लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ), लक्षित दीर्घावधि रिपोपरिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) और मांग के अनुसार लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन। ऋणात्मक(-) चिन्ह बैंकों द्वारा लिए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है। & ऋणात्मक (-) चिन्ह बैंकों द्वारा किए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।  
 ₹ 07 मई 2021 की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2021-2022/177 के अनुसार। 18 जून 2021 से, 4 जून 2021 के प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2021-2022/323 के अनुसार डाटा में राशि शामिल है।

## सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय-विक्रय

## i) ओटीसी सेगमेंट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2020-21	2020	2021	
		नव.	अक्टू.	नव.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	68315	10261	-100	0
1.1 क्रय (+)	162479	14289	7755	8489
1.2 विक्रय (-)	94164	4028	7855	8489
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	510516	76326	156	1669
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	68315	68388	40330	40330
(करोड़ ₹)	510516	509189	305136	306805
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	72751	28344	49106	49106

## ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2020-21	2020	2021	
		नव.	अक्टू.	नव.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	12118	0	0	0
1.2 विक्रय (-)	12118	0	0	0
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	690	780	0	0

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)  
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	31 नवंबर 2021 की स्थिति		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	7475	6560	915
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	12494	2150	10344
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	47867	10020	37847
4. 1 वर्ष से अधिक	0	0	0
<b>कुल (1+2+3+4)</b>	<b>67836</b>	<b>18730</b>	<b>49106</b>

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति								
	2020-21	2020	2021					नव. 19	दिसं 31
			दिसं 18	जुला. 30	अग. 27	सितं. 24	अक्टू. 22		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1 सीमांत स्थायी सुविधा	182	1	254	2	152	461	7201	-	
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त									
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा									
3.1 सीमा	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	
3.2 बकाया	-	0	0	0	0	0	0	0	
4. अन्य									
4.1 सीमा	75000	75000	76000	76000	76000	76000	76000	76000	
4.2 बकाया	32387	34760	23296	23296	25396	21696	24196	24401	
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	32569	34761	23550	23298	25548	22157	31397	24401	

टिप्पणी: 1. अन्य को विशेष पुनर्वित्त सुविधा अर्थात एफिजम बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित्त सुविधा, अर्थात भारिबैंक अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिडबी/एनएचबी यू/एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

## मुद्रा और बैंकिंग

## सं. 6: मुद्रा भंडार की मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2020-21	2020	2021		
		नवं. 20	अक्टू. 22	नवं. 5	नवं. 19
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2751828	2673534	2825630	2879258	2878178
1.1 संचलन में नोट	2826851	2743952	2917700	2961581	2961030
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	26170	25798	26550	26698	26698
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	101935	96958	119363	109765	110293
2 जनता की जमाराशियां	2042471	1674841	2009808	2157661	2004853
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1995120	1632938	1962643	2109778	1956992
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	41904	47165	47882	47861
<b>3 एम<sub>1</sub> (1 + 2)</b>	<b>4794299</b>	<b>4348375</b>	<b>4835438</b>	<b>5036918</b>	<b>4883031</b>
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	170025	162724	170025	170025	170025
<b>5 एम<sub>2</sub> (3 + 4)</b>	<b>4964324</b>	<b>4511099</b>	<b>5005463</b>	<b>5206943</b>	<b>5053056</b>
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	14050278	13589564	14688688	14877780	14763615
<b>7 एम<sub>3</sub> (3 + 6)</b>	<b>18844578</b>	<b>17937939</b>	<b>19524126</b>	<b>19914699</b>	<b>19646646</b>
8 कुल डाकघर जमाराशियां	509544	481423	509544	509544	509544
<b>9 एम<sub>4</sub> (7 + 8)</b>	<b>19354122</b>	<b>18419362</b>	<b>20033670</b>	<b>20424243</b>	<b>20156190</b>

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम<sub>3</sub>) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020	2021		
		नव. 20	अक्टू. 22	नव. 5	नव. 19
	1	2	3	4	5
<b>1 सरकार को निवल बैंक ऋण</b>	<b>5850374</b>	<b>5691514</b>	<b>5977920</b>	<b>6170903</b>	<b>6075969</b>
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1099686	1023947	1043103	1186805	1193964
1.1.1 सरकार पर दावे	1337300	1293290	1561612	1551579	1555163
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1333917	1282559	1556811	1543944	1546532
1.1.1.2 राज्य सरकारें	3383	10731	4802	7635	8631
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमा राशियां	237615	269343	518509	364774	361199
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	237572	269301	518467	364731	361156
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	4750689	4667567	4934817	4984097	4882005
<b>2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण</b>	<b>11668466</b>	<b>11092385</b>	<b>11750103</b>	<b>11874147</b>	<b>11870213</b>
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	8709	12173	1980	2140	4634
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	11659757	11080212	11748123	11872007	11865579
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	10949509	10434880	11044619	11161089	11162194
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	694758	635516	685756	693114	684896
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	15490	9815	17747	17803	18489
<b>3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)</b>	<b>4578846</b>	<b>4546855</b>	<b>4973808</b>	<b>4944726</b>	<b>4929385</b>
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	4199400	4249125	4630458	4601376	4586034
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	4199637	4249368	4630698	4601617	4586275
3.1.2 विदेशी देयताएं	237	243	241	241	241
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	379446	297731	343350	343350	343350
<b>4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं</b>	<b>26913</b>	<b>26541</b>	<b>27293</b>	<b>27441</b>	<b>27441</b>
<b>5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं</b>	<b>3280021</b>	<b>3419355</b>	<b>3204998</b>	<b>3102519</b>	<b>3256362</b>
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1356660	1464944	1373122	1337602	1327908
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1923362	1954411	1831876	1764917	1928454
<b>एम<sub>3</sub> (1+2+3+4-5)</b>	<b>18844578</b>	<b>17937939</b>	<b>19524126</b>	<b>19914699</b>	<b>19646646</b>

## सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020		2021	
		नव. 20	अक्टू. 22	नव. 5	नव. 19
	1	2	3	4	5
<b>मौद्रिक समुच्चय</b>					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	4794299	4348376	4835438	5036918	4883031
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	11048277	10389165	11379886	11663328	11461488
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	18936051	18036372	19635690	20019852	19762150
<b>1 घटक</b>					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2751828	2673534	2825630	2879258	2878178
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	15892848	15056913	16505862	16835135	16575786
1.2.1 मांग जमाराशियां	1995121	1632938	1962643	2109778	1956992
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	13897727	13423976	14543219	14725356	14618794
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6253977	6040789	6544448	6626410	6578457
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	78702	66156	57773	55772	56026
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7643750	7383187	7998770	8098946	8040337
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	41904	47165	47882	47861
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	244025	264021	257033	257577	260325
<b>2 स्रोत</b>					
2.1 देशी ऋण	18518950	17737777	18725981	19050344	18950959
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	5850374	5691513	5977920	6170903	6075969
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1099686	1023947	1043103	1186805	1193964
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	4750689	4667566	4934817	4984097	4882005
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	12668575	12046264	12748060	12879441	12874990
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	34134	35419	23882	24116	26610
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	12634441	12010845	12724178	12855325	12848380
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	951313	919780	968828	974011	973791
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26541	27293	27441	27441
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4438202	4366249	4858484	4947109	4825536
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	4249125	4630458	4601376	4586034
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	238802	117124	228026	345733	239502
2.4 पूंजी खाता	2775245	2900745	3047506	3014428	2994318
2.5 अन्य मदें (निवल)	1272767	1193449	928561	990614	1047468

## सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2020-21	2020		2021	
		नव.	सित्त.	अक्टू.	नव.
	1	2	3	4	5
<b>1 एन एम<sub>3</sub></b>	<b>18936051</b>	<b>18036372</b>	<b>19499587</b>	<b>19635690</b>	<b>19762150</b>
2 डाकघर जमाराशियां	509544	481423	509544	509544	509544
<b>3 एल<sub>1</sub> (1 + 2)</b>	<b>19445595</b>	<b>18517795</b>	<b>20009131</b>	<b>20145234</b>	<b>20271694</b>
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	33179	34778	27371	26662	26861
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2645	2645	4244	3627	3631
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	25550	28600	18175	18175	18175
4.3 सावधि जमाराशियां	4984	3533	4952	4860	5054
<b>5 एल<sub>2</sub> (3 + 4)</b>	<b>19478774</b>	<b>18552573</b>	<b>20036502</b>	<b>20171895</b>	<b>20298555</b>
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	..	31905	..	..
<b>7 एल<sub>3</sub> (5 + 6)</b>	<b>19510679</b>	<b>..</b>	<b>20068407</b>	<b>..</b>	<b>..</b>

टिप्पणी : संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

## सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020		2021	
		नव. 20	अक्टू. 22	नव. 5	नव. 19
	1	2	3	4	5
<b>1 घटक</b>					
1.1 संचलन में मुद्रा	2853763	2770493	2944993	2989022	2988471
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	698867	504678	685574	718194	731562
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	651748	471488	638589	670135	683604
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	41904	47165	47882	47861
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	3599981	3317074	3677732	3755098	3767894
<b>2 स्रोत</b>					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	730328	506353	393104	463883	482327
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	1099686	1023947	1043103	1186805	1193964
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1096345	1013258	1038344	1179213	1185376
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खजाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1333174	1281765	1556230	1543423	1545839
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1333174	1281765	1556230	1543423	1545839
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	743	794	581	521	693
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	237572	269301	518467	364731	361156
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	3340	10689	4759	7592	8588
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-403492	-553013	-673881	-747038	-738247
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	-378066	-529767	-651979	-725063	-716272
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	34134	35419	23882	24116	26610
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	25426	23246	21902	21976	21976
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26541	27293	27441	27441
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	4249125	4630458	4601376	4586034
2.3.1 सोना	247723	267074	287854	288746	300065
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3951694	3982068	4342621	4312647	4285987
2.4 पूंजी खाता	1173033	1288399	1290235	1255885	1235252
2.5 अन्य मदें (निवल)	183626	176545	82887	81717	92656

## सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के अंतिम शुक्रवारों/शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया						
	2020-21	2020		2021			
		नव. 27	अक्टू. 29	नव. 5	नव. 12	नव. 19	नव. 26
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा							
(1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	3599981	3313212	3703451	3755098	3721940	3767894	3736107
<b>1 घटक</b>							
1.1 संचलन में मुद्रा	2853763	2770773	2945130	2989022	2993087	2988471	2983295
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	698867	497195	710775	718194	680965	731562	704368
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	45244	47546	47882	47888	47861	48443
<b>2 स्रोत</b>							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1099686	1036501	1108510	1186805	1243979	1193964	1177312
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-378066	-545484	-696020	-725063	-814367	-716272	-726053
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	8709	11175	2137	2140	2140	4634	2135
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	4246261	4635086	4601376	4591672	4586034	4597067
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26618	27441	27441	27441	27441	27539
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1356660	1461859	1373703	1337602	1328925	1327908	1341893

## सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवारों/ माह के रिपोर्टिंग शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020	2021		
		नव. 20	अक्टू. 22	नव. 5	नव. 19
	1	2	3	4	5
<b>1 घटक</b>					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	14960961	14204847	15567552	15894328	15634295
1.1.1 मांग जमाराशियां	1861193	1511516	1827341	1973121	1820862
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	13099768	12693331	13740211	13921208	13813433
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5894896	5711999	6183095	6264544	6216045
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	78702	66156	57773	55772	56026
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7204873	6981332	7557116	7656664	7597388
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	244025	264021	257033	257577	260325
<b>2 स्रोत</b>					
2.1 देशी ऋण	16378019	15782138	16650633	16822224	16720791
2.1.1 सरकार को ऋण	4461632	4423853	4637469	4685224	4582873
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11916387	11358285	12013164	12137000	12137918
2.1.2.1 बैंक ऋण	10949509	10434880	11044619	11161089	11162194
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	10888255	10345924	10980922	11084223	11079778
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	23633	11115	7491	9571	9273
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	894	1472	1189	1291	1622
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	942351	910818	959866	965048	964828
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	238802	117124	228026	345733	239502
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	454866	348921	442218	566399	456666
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	152552	165588	145469	152424	144821
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	63512	66208	68722	68242	72344
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	1010202	1087871	1397969	1493297	1498308
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	542693	471488	638589	670135	683604
2.3.2 उपलब्ध नकदी	90748	86616	107401	98099	98432
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-376761	-529767	-651979	-725063	-716272
2.4 पूंजी खाता	1578041	1588175	1733101	1734372	1734895
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	843995	930091	718942	774976	829084
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	593095	570368	501782	567279	536420
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	80681	62737	25116	40089	32065

## सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	26 मार्च 2021 की स्थिति	2020	2021		
		नव. 20	अक्टू. 22	नव. 5	नव. 19
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	4462526	4425325	4638658	4686515	4584495
2 वाणिज्यिक पत्र	82584	86031	74600	72255	67080
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	9840	11380	10137	9865	9713
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	64035	71284	69330	69559	70043
3.3 अन्य	5210	5416	5098	4981	5111
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	121008	122662	117204	116099	116952
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	308904	304812	327885	332683	332542
4.3 अन्य	149325	144171	147953	147290	148087
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	31142	35089	51553	53136	52548
5.2 वित्तीय संस्थाएं	167130	130912	156107	159180	162752



## सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुक्रवार की स्थिति									
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
	2020-21	2020		2021		2020-21	2020		2021	
		नव.	अक्टू.	नव.	अक्टू.		नव.	अक्टू.	नव.	
1	2	3	4	5	6	7	8			
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	209	209	211	211	133	133	135	135		
<b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>	<b>259530</b>	<b>263597</b>	<b>234060</b>	<b>240488</b>	<b>254589</b>	<b>258506</b>	<b>229549</b>	<b>235957</b>		
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	200585	208057	171935	180927	195866	203177	167740	176748		
1.2 बैंकों से उधार राशि	40886	38428	40905	37571	40880	38428	40905	37564		
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	18059	17112	21220	21989	17843	16901	20903	21645		
<b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>	<b>1645782</b>	<b>15790007</b>	<b>17168903</b>	<b>17097841</b>	<b>16014145</b>	<b>15360598</b>	<b>16728521</b>	<b>16654491</b>		
2.1 कुल जमाराशियां	15540152	14910668	16291396	16213300	15113512	14497351	15866061	15784717		
2.1.1 मांग	1899343	1607263	1946193	1881595	1861193	1571913	1905673	1840383		
2.1.2 मीयादी	13640809	13303405	14345203	14331705	13252320	12925438	13960388	13944334		
2.2 उधार	248271	273826	263983	267747	244025	269599	259657	263467		
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	669359	605513	613523	616794	656607	593647	602803	606307		
<b>3 रिजर्व बैंक से उधार</b>	<b>90275</b>	<b>77097</b>	<b>93597</b>	<b>93677</b>	<b>90275</b>	<b>77097</b>	<b>93597</b>	<b>93677</b>		
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2 अन्य	90275	77097	93597	93677	90275	77097	93597	93677		
<b>4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष</b>	<b>650745</b>	<b>570650</b>	<b>789961</b>	<b>777304</b>	<b>633440</b>	<b>555320</b>	<b>769600</b>	<b>757991</b>		
4.1 उपलब्ध नकदी	92793	95569	109142	103869	90748	93420	106286	101328		
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	557951	475081	680819	673435	542693	461900	663314	656663		
<b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>	<b>265729</b>	<b>265221</b>	<b>268619</b>	<b>269025</b>	<b>197541</b>	<b>205772</b>	<b>213942</b>	<b>213515</b>		
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	179430	181343	186549	185510	143294	147544	150786	151303		
5.1.1 चालू खाते में	16796	14432	19236	15272	14226	12122	16569	12961		
5.1.2 अन्य खातों में	162634	166911	167312	170239	129068	135422	134217	138342		
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	36716	28331	27608	27606	10654	7305	11960	9590		
5.3 बैंकों को अग्रिम	19908	21766	24329	24033	16764	21321	23949	23599		
5.4 अन्य आस्तियां	29675	33782	30133	31876	26829	29602	27247	29024		
<b>6 निवेश</b>	<b>4598924</b>	<b>4556799</b>	<b>4809010</b>	<b>4728213</b>	<b>4462526</b>	<b>4424629</b>	<b>4666403</b>	<b>4582167</b>		
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	4591896	4548980	4801635	4720339	4461632	4423189	4664994	4580669		
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7029	7819	7374	7873	894	1441	1409	1499		
<b>7 बैंक ऋण</b>	<b>11297014</b>	<b>10807692</b>	<b>11449603</b>	<b>11548622</b>	<b>10949509</b>	<b>10473053</b>	<b>11105758</b>	<b>11199938</b>		
7क खाद्यान्न ऋण	91653	123082	103289	121828	61254	92680	67471	86011		
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	11081668	10636795	11230982	11337537	10736491	10304077	10889136	10990885		
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	30896	23595	33176	31807	30531	23324	33161	31793		
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	128831	99543	131656	127812	127883	98638	130353	126685		
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	20762	17346	19901	18228	20394	17093	19711	17978		
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	34857	30414	33887	33239	34210	29922	33397	32597		

## सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 26, 2021	2020	2021		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		नव. 20	अक्टू. 22	नव. 19	2021-22	2021
	1	2	3	4	%	%
I. सकल बैंक ऋण (II+III)	10951561	10434880	11046293	11162247	1.9	7.0
II. खाद्यान्न ऋण	61254	88956	63697	82415	34.5	-7.4
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	10890307	10345924	10982596	11079831	1.7	7.1
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1271047	1217348	1344042	1344129	5.7	10.4
2. उद्योग	2895786	2760236	2854571	2865403	-1.0	3.8
2.1 सूक्ष्म और लघु <sup>1</sup>	383854	364491	404316	410646	7.0	12.7
2.2 मझौले	136054	123534	179905	183668	35.0	48.7
2.3 बड़े	2375878	2272211	2270350	2271089	-4.4	0.0
3. सेवाएं	2647362	2536455	2603938	2626577	-0.8	3.6
3.1 परिवहन परिचालक	133953	128097	131133	132364	-1.2	3.3
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	19183	17544	19455	18720	-2.4	6.7
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	48019	48905	48687	50282	4.7	2.8
3.4 शिपिंग	7188	5310	7203	7469	3.9	40.7
3.5 नौवहन	25643	25246	27095	26771	4.4	6.0
3.6 पेशेवर सेवाएं	105253	106404	100843	101363	-3.7	-4.7
3.7 व्यापार	590377	541651	595470	588738	-0.3	8.7
3.7.1 थोक व्यापार	309611	261567	307176	303758	-1.9	16.1
3.7.2 खुदरा व्यापार	280766	280084	288293	284979	1.5	1.7
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	264246	259296	253582	260262	-1.5	0.4
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) <sup>2</sup> जिसमें से	937949	874942	883614	920630	-1.8	5.2
3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	215189	181829	211107	220855	2.6	21.5
3.9.2 सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई)	78442	56097	84036	90751	15.7	61.8
3.10 अन्य सेवाएं <sup>3</sup>	515550	529059	536856	519979	0.9	-1.7
4. व्यक्तिगत ऋण	2845527	2675697	2955599	2985430	4.9	11.6
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	8810	8253	11628	12313	39.8	49.2
4.2 आवास	1458358	1380115	1485234	1490157	2.2	8.0
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	62975	57145	63734	64797	2.9	13.4
4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	4419	4483	4608	4714	6.7	5.2
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	116537	114307	123312	122111	4.8	6.8
4.6 शिक्षा	63968	65349	63601	63452	-0.8	-2.9
4.7 वाहन ऋण	267352	255456	272610	275249	3.0	7.7
4.8 सोने के आभूषण पर ऋण	60724	46221	65361	65630	8.1	42.0
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	802385	744369	865510	887007	10.5	19.2
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
5.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां <sup>4</sup>	1235082	1187677	1281929	1283063	3.9	8.0
5.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम <sup>5</sup>	1113243	1123739	1120901	1099438	-1.2	-2.2
5.3 मध्यम उद्यम <sup>6</sup>	207615	180413	223621	242069	16.6	34.2
5.4 आवास	468659	444436	445739	444762	-5.1	0.1
5.5 शिक्षा ऋण	48201	51424	47260	47039	-2.4	-8.5
5.6 नवीकरणीय ऊर्जा	1171	1171	1372	1244	6.2	6.2
5.7 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर	2352	1279	2336	2331	-0.9	82.2
5.8 निर्यात ऋण <sup>7</sup>	19028	14486	18931	16969	-10.8	17.1
5.9 अन्य	9169	10487	17063	17303	88.7	65.0
5.10 नेट पीएसएलसी- एसएफ/एमएफ सहित कमजोर वर्ग	813263	797782	865136	862276	6.0	8.1

टिप्पणी 1: डाटा अनंतिम हैं। सकल बैंक ऋण और गैर-खाद्य ऋण का डाटा धारा -42 रिटर्न पर आधारित है, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (एससीबी) शामिल किया गया है, जब कि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण डाटा क्षेत्र-वार पर और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कुल गैर खाद्य ऋण के लगभग 90 प्रतिशत के चुनिंदा बैंकों को समाविष्ट किया गया है। टिप्पणी 2: जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

1. सूक्ष्म और लघु में विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. अन्य सेवाओं के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के अंतर्गत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल है।
5. सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण और पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. मध्यम उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।
7. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत निर्यात ऋण विदेशी बैंकों से संबंधित हैं।

## सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	26 मार्च, 2021	2020	2021		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		नव. 20	अक्टू. 22	नव. 19		
	1	2	3	4	2021-22	2021
				%	%	
<b>1 उद्योग (2.1 से 2.19)</b>	2895786	2760236	2854571	2865403	-1.0	3.8
<b>1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)</b>	46052	43795	49758	51080	10.9	16.6
<b>1.2 खाद्य प्रसंस्करण</b>	153286	137304	144413	143214	-6.6	4.3
1.2.1 चीनी	25519	21215	17636	16763	-34.3	-21.0
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	18972	16917	17709	17251	-9.1	2.0
1.2.3 चाय	4273	4419	5061	4933	15.5	11.6
1.2.4 अन्य	104523	94752	104007	104267	-0.2	10.0
<b>1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू</b>	15966	14475	15136	15760	-1.3	8.9
<b>1.4 वस्त्र</b>	200487	186746	199359	200578	0.0	7.4
1.4.1 सूती वस्त्र	90546	84130	83975	85002	-6.1	1.0
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2724	2437	2734	2769	1.7	13.7
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	38861	34505	42009	41555	6.9	20.4
1.4.4 अन्य वस्त्र	68356	65674	70641	71252	4.2	8.5
<b>1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद</b>	10461	10660	10537	10330	-1.3	-3.1
<b>1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद</b>	13186	12678	13498	13363	1.3	5.4
<b>1.7 कागज और कागज से बने उत्पाद</b>	35466	34027	36839	36849	3.9	8.3
<b>1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आणविक इंधन</b>	66909	59028	67918	67963	1.6	15.1
<b>1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद</b>	192323	178236	185374	191240	-0.6	7.3
1.9.1 उर्वरक	32237	37567	27348	29327	-9.0	-21.9
1.9.2 औषधि और दवाइयाँ	51723	49379	51487	52133	0.8	5.6
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	45621	38439	40000	43178	-5.4	12.3
1.9.4 अन्य	62742	52852	66538	66602	6.2	26.0
<b>1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद</b>	54308	50667	61881	61748	13.7	21.9
<b>1.11 कांच और कांच के सामान</b>	6319	6681	5715	5714	-9.6	-14.5
<b>1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद</b>	54194	59665	46511	44765	-17.4	-25.0
<b>1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद</b>	328867	334280	280263	277870	-15.5	-16.9
1.13.1 लोहा और स्टील	232934	244987	187819	186191	-20.1	-24.0
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	95933	89292	92443	91678	-4.4	2.7
<b>1.14 सभी अभियांत्रिकी</b>	147545	138338	147637	149368	1.2	8.0
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	33871	29682	36495	36359	7.3	22.5
1.14.2 अन्य	113674	108656	111142	113009	-0.6	4.0
<b>1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर</b>	83188	85467	82822	84872	2.0	-0.7
<b>1.16 रत्न और आभूषण</b>	62983	67601	70162	70141	11.4	3.8
<b>1.17 निर्माण</b>	94565	99738	95759	95881	1.4	-3.9
<b>1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर</b>	1092217	1027515	1108932	1115313	2.1	8.5
1.18.1 पावर	567584	550835	582453	576805	1.6	4.7
1.18.2 दूरसंचार	112120	106146	111419	110269	-1.7	3.9
1.18.3 सड़क	237061	200344	243712	246836	4.1	23.2
1.18.4 हवाई अड्डा	7327	5804	7592	7570	3.3	30.4
1.18.5 बंदरगाह	7363	8996	7604	7546	2.5	-16.1
1.18.6 रेलवे	11260	12749	12677	13790	22.5	8.2
1.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	149502	142641	143475	152497	2.0	6.9
<b>1.19 अन्य उद्योग</b>	237464	213334	232056	229353	-3.4	7.5

टिप्पणी : जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

## सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति									
	2020-21	2020		2021					अक्टू. 22	अक्टू. 29
		अक्टू. 30	अग. 13	अग. 27	सितं. 10	सितं. 24	अक्टू. 08			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	33	33	33	33	33	33	33	
<b>1 कुल जमा राशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)</b>	<b>125859.6</b>	<b>127732.2</b>	<b>125488.9</b>	<b>125501.3</b>	<b>125705.2</b>	<b>125238.2</b>	<b>126845.4</b>	<b>127303.3</b>	<b>128013.9</b>	
2 मांग और मीयादी देयताएं										
<b>2.1 मांग देयताएं</b>	<b>23736.9</b>	<b>22996.2</b>	<b>27669.6</b>	<b>27501.5</b>	<b>30915.2</b>	<b>26961.0</b>	<b>25556.0</b>	<b>25393.8</b>	<b>25243.2</b>	
2.1.1 जमा राशियां										
2.1.1.1 अंतर-बैंक	4896.9	4028.2	5399.0	5419.8	5686.7	5734.8	5387.3	5285.9	5539.9	
2.1.1.2 अन्य	13,899.4	13799.5	15817.5	15695.3	15100.1	14619.8	14657.9	14799.4	14672.8	
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	0.0	1069.6	1069.6	999.6	999.7	749.8	279.9	80.0	
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	4940.6	5168.5	5383.4	5316.8	9128.8	5606.6	4761.0	5028.6	4950.5	
<b>2.2 मीयादी देयताएं</b>	<b>179957.5</b>	<b>172503.4</b>	<b>165604.8</b>	<b>166716.0</b>	<b>167660.1</b>	<b>168977.8</b>	<b>170167.9</b>	<b>171836.3</b>	<b>171867.5</b>	
2.2.1 जमा राशियां										
2.2.1.1 अंतर-बैंक	65333.7	56969.6	54146.9	55115.2	55191.0	56505.0	56018.2	57474.2	56659.6	
2.2.1.2 अन्य	111960.2	113932.7	109671.4	109806.0	110605.1	110618.4	112187.5	112503.9	113341.1	
2.2.2 बैंकों से उधार	630.0	629.9	908.0	908.0	911.0	911.0	985.1	910.1	927.5	
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	2033.7	971.3	878.5	886.8	953.0	943.3	977.1	948.0	939.3	
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	63559.8	56155.0	56575.4	56497.3	55045.9	54926.2	55750.0	57812.6	58096.5	
4.1 मांग	15691.8	13041.1	11558.3	11967.8	12202.9	12031.5	12308.4	12150.6	12222.9	
4.2 मीयादी	47868.0	43113.9	45017.1	44529.5	42843.0	42894.6	43441.6	45661.9	45873.6	
<b>5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष</b>	<b>8151.1</b>	<b>7243.4</b>	<b>9175.0</b>	<b>8711.2</b>	<b>13259.6</b>	<b>8940.2</b>	<b>9036.9</b>	<b>8911.0</b>	<b>9282.9</b>	
5.1 उपलब्ध नकदी	570.3	563.4	610.3	672.7	637.0	640.7	633.1	672.7	722.8	
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	7580.8	6680.0	8564.7	8038.4	12622.6	8299.5	8403.8	8238.2	8560.1	
<b>6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष</b>	<b>1148.1</b>	<b>983.8</b>	<b>1381.1</b>	<b>1310.9</b>	<b>1346.7</b>	<b>1223.7</b>	<b>1165.1</b>	<b>1217.3</b>	<b>1299.6</b>	
<b>7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश</b>	<b>64455.2</b>	<b>58774.4</b>	<b>68266.4</b>	<b>69149.6</b>	<b>69633.6</b>	<b>70603.5</b>	<b>70631.0</b>	<b>70288.0</b>	<b>71010.3</b>	
<b>8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा</b>	<b>28835.7</b>	<b>24890.4</b>	<b>19377.0</b>	<b>20512.8</b>	<b>18893.8</b>	<b>20170.1</b>	<b>19721.6</b>	<b>20940.3</b>	<b>20265.8</b>	
<b>9 बैंक ऋण (10.1+11)</b>	<b>114631.6</b>	<b>111449.1</b>	<b>108302.6</b>	<b>107334.4</b>	<b>107521.7</b>	<b>106670.5</b>	<b>107983.1</b>	<b>107964.4</b>	<b>107241.8</b>	
10 अग्रिम										
<b>10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट</b>	<b>114612.1</b>	<b>111430.3</b>	<b>108298.5</b>	<b>107314.7</b>	<b>107502.0</b>	<b>106650.9</b>	<b>107962.5</b>	<b>107943.9</b>	<b>107221.4</b>	
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	89429.1	82258.8	88700.2	88554.7	89065.7	88508.1	91408.2	94217.9	95223.9	
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	19.5	18.8	4.2	19.7	19.7	19.6	20.6	20.5	20.4	

# मूल्य और उत्पादन

## सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2020-21			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	नव. '20	अक्टू.'21	नव.'21(अ)	नव.'20	अक्टू.'21	नव.'21(अ)	नव.'20	अक्टू.'21	नव.'21(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1 खाद्य और पेय पदार्थ</b>	<b>156.7</b>	<b>161.1</b>	<b>158.3</b>	<b>164.5</b>	<b>165.5</b>	<b>167.5</b>	<b>167.0</b>	<b>171.5</b>	<b>173.5</b>	<b>165.4</b>	<b>167.7</b>	<b>169.7</b>
1.1 अनाज और उत्पाद	145.4	149.9	146.8	144.6	146.1	146.9	149.0	150.1	151.0	146.0	147.4	148.2
1.2 मांस और मछली	185.2	192.4	187.7	188.5	202.5	199.8	195.7	208.4	204.9	191.0	204.6	201.6
1.3 अंडा	160.3	164.8	162.0	173.4	170.1	171.5	178.3	173.0	175.4	175.3	171.2	173.0
1.4 दूध और उत्पाद	154.1	154.4	154.2	154.0	158.4	159.1	154.2	159.2	159.6	154.1	158.7	159.3
1.5 तेल और चर्बी	148.2	139.9	145.2	150.0	198.8	198.4	140.7	176.6	175.8	146.6	190.6	190.1
1.6 फल	146.9	153.4	149.9	145.9	152.6	153.2	149.7	159.3	160.4	147.7	155.7	156.6
1.7 सब्जी	174.2	196.2	181.7	225.2	170.4	183.7	240.9	214.4	229.2	230.5	185.3	199.1
1.8 दाल और उत्पाद	154.4	156.0	154.9	159.5	165.2	165.4	161.5	165.3	165.1	160.2	165.2	165.3
1.9 चीनी और उत्पाद	114.4	117.0	115.3	114.4	121.6	122.1	117.1	122.5	123.1	115.3	121.9	122.4
1.10 मसाले	161.9	160.4	161.4	163.5	170.6	170.8	161.9	166.8	167.3	163.0	169.3	169.6
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	149.8	141.3	146.3	153.4	168.8	169.1	143.3	155.4	156.0	149.2	163.2	163.6
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	163.2	165.5	164.3	163.6	173.6	174.2	166.1	175.9	176.8	164.8	174.7	175.4
<b>2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ</b>	<b>181.8</b>	<b>188.7</b>	<b>183.6</b>	<b>183.6</b>	<b>191.2</b>	<b>191.4</b>	<b>190.2</b>	<b>197.0</b>	<b>197.1</b>	<b>185.4</b>	<b>192.7</b>	<b>192.9</b>
<b>3 कपड़ा और जूते</b>	<b>155.6</b>	<b>149.7</b>	<b>153.3</b>	<b>156.3</b>	<b>168.3</b>	<b>169.8</b>	<b>149.6</b>	<b>158.3</b>	<b>159.7</b>	<b>153.6</b>	<b>164.3</b>	<b>165.8</b>
3.1 कपड़ा	156.4	152.0	154.7	157.0	168.9	170.4	151.9	160.8	162.3	155.0	165.7	167.2
3.2 जूते	151.1	137.2	145.3	151.6	164.8	166.0	136.7	144.4	145.4	145.4	156.3	157.4
<b>4 आवास</b>	-	<b>157.2</b>	<b>157.2</b>	-	-	-	<b>158.4</b>	<b>163.6</b>	<b>164.2</b>	<b>158.4</b>	<b>163.6</b>	<b>164.2</b>
<b>5 ईंधन और लाइट</b>	<b>149.1</b>	<b>140.9</b>	<b>146.0</b>	<b>148.7</b>	<b>165.5</b>	<b>165.3</b>	<b>137.9</b>	<b>162.2</b>	<b>161.7</b>	<b>144.6</b>	<b>164.2</b>	<b>163.9</b>
<b>6 विविध</b>	<b>153.9</b>	<b>146.1</b>	<b>150.2</b>	<b>155.2</b>	<b>164.7</b>	<b>165.2</b>	<b>146.9</b>	<b>157.0</b>	<b>157.3</b>	<b>151.2</b>	<b>161.0</b>	<b>161.4</b>
6.1 घरेलू सामान और सेवा	152.9	145.2	149.3	153.4	162.0	162.9	145.5	154.3	155.2	149.7	158.4	159.3
6.2 स्वास्थ्य	160.3	151.3	156.9	161.6	172.5	173.4	152.9	163.5	164.2	158.3	169.1	169.9
6.3 परिवहन और संचार	144.9	135.0	139.7	146.4	159.5	158.9	135.5	152.2	151.2	140.7	155.7	154.8
6.4 मनोरंजन	154.0	144.3	148.5	153.9	163.2	163.8	144.3	155.1	156.7	148.5	158.6	159.8
6.5 शिक्षा	162.5	156.2	158.9	162.9	169.0	169.3	156.9	160.3	160.8	159.4	163.9	164.3
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	153.7	155.8	154.5	156.6	161.1	162.4	157.9	160.3	161.8	157.1	160.8	162.2
<b>सामान्य सूचकांक (सभी समूह)</b>	<b>156.1</b>	<b>154.4</b>	<b>155.3</b>	<b>160.7</b>	<b>166.3</b>	<b>167.6</b>	<b>156.9</b>	<b>164.6</b>	<b>165.6</b>	<b>158.9</b>	<b>165.5</b>	<b>166.7</b>

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अनंतिम

## सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2020-21	2021		
				नव.	अक्टू.	नव.
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	-	119.9	124.9	125.7
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1034	1060	1081	1092
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	1040	1065	1090	1101

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

## सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2020-21	2020		2021	
		नव.	अक्टू.	नव.	अक्टू.
	1	2	3	4	
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	48723	50429	47219	48193	
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	59283	62256	62890	64667	

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।

**सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक**  
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
				नव.	सितं.	अक्टू. (अ)
	1	2	3	4	5	6
<b>1 सभी पण्य</b>	<b>100.000</b>	<b>123.4</b>	<b>125.1</b>	<b>137.4</b>	<b>139.1</b>	<b>142.9</b>
<b>1.1 प्राथमिक वस्तुएं</b>	<b>22.618</b>	<b>145.7</b>	<b>152.8</b>	<b>157.7</b>	<b>159.7</b>	<b>168.6</b>
<b>1.1.1 खाद्य वस्तुएं</b>	<b>15.256</b>	<b>160.7</b>	<b>170.1</b>	<b>164.1</b>	<b>168.6</b>	<b>178.4</b>
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	159.3	158.8	163.0	163.9	164.8
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	179.2	218.8	174.0	200.8	235.1
1.1.1.3 दूध	4.440	153.4	154.7	156.8	157.2	157.5
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	151.2	149.0	165.3	154.7	163.4
1.1.1.5 मसाले	0.529	149.5	156.5	161.7	155.1	161.6
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	162.0	165.7	163.9	164.8	166.1
<b>1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं</b>	<b>4.119</b>	<b>130.5</b>	<b>138.0</b>	<b>161.2</b>	<b>153.7</b>	<b>157.0</b>
1.1.2.1 फाइबर	0.839	119.8	120.3	147.6	156.0	164.2
1.1.2.2 तिलहन	1.115	161.7	162.0	235.0	199.7	202.3
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	109.0	114.0	119.8	119.8	120.7
1.1.2.4 फूल	0.204	210.0	310.4	211.2	217.9	228.7
<b>1.1.3 खनिज</b>	<b>0.833</b>	<b>164.9</b>	<b>157.4</b>	<b>190.3</b>	<b>179.6</b>	<b>190.3</b>
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	159.8	150.1	183.8	170.5	183.8
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	183.1	183.0	213.2	211.5	213.0
<b>1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस</b>	<b>2.410</b>	<b>70.4</b>	<b>67.5</b>	<b>100.4</b>	<b>106.2</b>	<b>119.2</b>
<b>1.2 ईंधन और बिजली</b>	<b>13.152</b>	<b>94.0</b>	<b>94.2</b>	<b>119.0</b>	<b>124.7</b>	<b>131.7</b>
<b>1.2.1 कोल</b>	<b>2.138</b>	<b>126.6</b>	<b>126.5</b>	<b>127.7</b>	<b>128.9</b>	<b>130.4</b>
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	141.8	141.9	143.4	143.4	143.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.3	119.0	119.8	119.8	119.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	130.9	131.1	138.1	166.0	200.5
<b>1.2.2 खनिज तेल</b>	<b>7.950</b>	<b>79.2</b>	<b>76.6</b>	<b>117.6</b>	<b>126.7</b>	<b>137.8</b>
<b>1.2.3 बिजली</b>	<b>3.064</b>	<b>109.6</b>	<b>117.4</b>	<b>116.7</b>	<b>116.7</b>	<b>116.7</b>
<b>1.3 विनिर्मित उत्पाद</b>	<b>64.231</b>	<b>121.5</b>	<b>121.6</b>	<b>134.0</b>	<b>134.9</b>	<b>136.1</b>
<b>1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>9.122</b>	<b>141.4</b>	<b>142.4</b>	<b>158.8</b>	<b>158.4</b>	<b>157.0</b>
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	137.2	137.2	142.7	142.4	142.4
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	139.0	135.8	141.5	144.3	144.9
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	120.2	122.4	122.2	122.1	121.9
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	143.5	148.1	188.6	186.4	182.4
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	146.9	144.9	149.0	149.0	147.9
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	143.5	142.3	145.8	145.8	147.3
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	115.9	111.4	129.2	130.2	135.1
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	138.1	138.5	144.5	145.3	147.2
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	118.4	118.4	126.5	127.4	125.7
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	128.0	128.5	128.8	129.8	130.1
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	132.3	133.5	138.4	139.0	133.4
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	166.5	172.2	168.7	168.5	170.3
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	147.0	147.5	156.5	155.4	154.8
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	132.2	131.8	135.3	135.4	135.3
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	142.9	140.4	155.1	154.6	154.3
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	170.5	171.6	208.1	207.4	198.6
<b>1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण</b>	<b>0.909</b>	<b>124.5</b>	<b>123.6</b>	<b>126.9</b>	<b>127.3</b>	<b>127.5</b>
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	120.2	119.6	123.4	123.7	124.0
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	126.5	125.9	130.2	131.3	131.4
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	129.4	127.8	129.5	129.4	129.4
<b>1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद</b>	<b>0.514</b>	<b>157.2</b>	<b>156.1</b>	<b>159.9</b>	<b>162.6</b>	<b>160.7</b>
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	157.2	156.1	159.9	162.6	160.7

**सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)**  
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
				नव.	सितं.	अक्टू. (अ)
<b>1.3.4 वस्त्र विनिर्माण</b>	<b>4.881</b>	<b>117.6</b>	<b>116.8</b>	<b>133.3</b>	<b>133.9</b>	<b>137.1</b>
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	106.6	105.5	125.0	126.2	130.8
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	131.7	130.9	146.2	146.3	147.7
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	115.2	115.0	124.7	123.6	126.8
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	132.3	132.5	138.3	138.0	139.8
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	155.6	157.6	167.5	169.6	170.5
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	116.3	114.8	126.5	126.8	127.9
<b>1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र</b>	<b>0.814</b>	<b>138.6</b>	<b>139.5</b>	<b>144.0</b>	<b>143.8</b>	<b>144.6</b>
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	138.1	138.3	143.6	142.9	143.3
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	139.8	142.8	145.0	146.4	147.9
<b>1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>0.535</b>	<b>117.9</b>	<b>117.9</b>	<b>118.7</b>	<b>118.9</b>	<b>118.7</b>
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	101.1	100.6	104.0	103.9	103.1
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	138.6	137.9	139.7	139.9	141.9
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	120.6	120.9	120.3	120.6	120.2
<b>1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद</b>	<b>0.772</b>	<b>134.6</b>	<b>134.7</b>	<b>140.7</b>	<b>142.3</b>	<b>142.6</b>
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	120.7	120.1	128.8	131.3	131.4
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	136.6	136.1	140.6	142.0	142.5
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	185.8	189.5	193.8	194.5	194.4
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	125.7	127.5	137.7	139.1	139.0
<b>1.3.8 कागज और कागज के उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>1.113</b>	<b>121.7</b>	<b>120.0</b>	<b>133.9</b>	<b>134.5</b>	<b>139.0</b>
1.3.8.1 लुगदी, कागज और कागज बोर्ड	0.493	124.1	121.3	138.5	138.7	143.8
1.3.8.2 लहरदार कागज और पेपर बोर्ड और कागज के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	122.2	123.3	135.1	136.4	137.9
1.3.8.3 कागज की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	117.4	114.8	125.1	125.7	132.4
<b>1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन</b>	<b>0.676</b>	<b>153.8</b>	<b>157.3</b>	<b>154.8</b>	<b>154.8</b>	<b>156.4</b>
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	153.8	157.3	154.8	154.8	156.4
<b>1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>6.465</b>	<b>118.2</b>	<b>118.2</b>	<b>131.1</b>	<b>133.0</b>	<b>135.6</b>
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	118.6	117.8	139.4	142.4	148.5
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	123.6	123.0	127.7	128.2	129.6
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	116.7	118.1	138.2	141.3	143.0
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकैमिकल उत्पाद	0.454	124.4	125.8	129.9	130.8	132.4
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	114.9	114.4	128.2	130.3	132.4
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	120.6	121.3	128.8	129.0	129.7
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	115.1	115.0	127.1	129.8	132.5
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	93.7	91.5	105.1	107.8	108.8
<b>1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>1.993</b>	<b>130.9</b>	<b>132.0</b>	<b>134.5</b>	<b>134.9</b>	<b>136.0</b>
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	130.9	132.0	134.5	134.9	136.0
<b>1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>2.299</b>	<b>111.3</b>	<b>112.0</b>	<b>123.9</b>	<b>126.0</b>	<b>127.0</b>
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.3	97.5	104.3	103.9	104.8
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	93.3	92.6	101.1	101.0	102.0
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	120.3	121.9	136.7	140.3	141.4
<b>1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>3.202</b>	<b>117.6</b>	<b>116.9</b>	<b>121.6</b>	<b>122.4</b>	<b>124.6</b>
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	127.2	126.4	136.9	135.5	136.5
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	109.5	110.2	111.2	114.9	116.2
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	109.3	113.3	110.8	111.1	117.5
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	109.5	108.0	111.7	111.6	112.2
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	120.9	119.1	124.5	125.8	128.7

**सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)**  
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
				नव.	सितं.	अक्टू. (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट,सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	125.3	126.0	128.6	128.0	129.3
1.3.13.7 पत्थरों को काटना,आकार देना और संवारना	0.234	121.1	120.9	122.6	122.5	123.3
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	78.9	81.3	88.0	88.0	89.2
<b>1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण</b>	<b>9.646</b>	<b>111.4</b>	<b>111.5</b>	<b>137.8</b>	<b>140.4</b>	<b>143.9</b>
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	109.2	108.4	147.2	151.6	162.6
1.3.14.2 मेटेलिक आयसन	0.653	113.3	113.6	145.2	151.2	150.4
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	99.8	100.0	116.8	118.9	119.4
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	112.0	112.8	133.5	137.8	140.0
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	117.2	118.2	156.3	159.2	163.4
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	108.3	107.7	129.8	134.8	133.6
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	108.7	106.3	138.7	139.2	147.8
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	127.9	126.7	154.3	155.5	159.7
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	112.3	113.5	138.1	140.0	141.3
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	109.1	109.5	119.2	119.2	118.5
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	145.7	145.4	157.8	157.2	160.2
<b>1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>3.155</b>	<b>115.9</b>	<b>115.9</b>	<b>130.6</b>	<b>130.9</b>	<b>131.6</b>
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	114.1	113.3	124.0	123.6	123.9
1.3.15.2 धातु से बने टैंक,जलाशय और डिब्बे	0.660	127.8	127.4	156.3	157.6	158.6
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरस को छोड़कर	0.145	98.9	96.9	96.9	96.9	97.5
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	96.7	98.0	117.8	118.6	120.1
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	102.9	104.1	108.3	108.7	109.7
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	125.0	125.7	136.4	136.5	137.0
<b>1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>2.009</b>	<b>109.8</b>	<b>108.6</b>	<b>112.7</b>	<b>112.7</b>	<b>113.6</b>
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	99.1	100.6	104.9	105.1	106.2
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	134.8	134.0	134.6	134.7	134.9
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	114.9	114.4	119.3	119.3	119.8
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	98.5	94.7	101.6	101.5	103.3
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	107.7	106.4	107.1	107.1	107.1
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	141.8	141.7	145.7	145.4	145.9
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	102.8	103.1	103.0	104.0	102.9
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	102.7	95.6	98.4	98.4	98.5
<b>1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण</b>	<b>2.930</b>	<b>113.6</b>	<b>113.2</b>	<b>122.0</b>	<b>122.3</b>	<b>121.9</b>
1.3.17.1 विद्युतमोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	113.2	112.0	119.3	119.8	117.7
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.1	117.8	121.9	122.3	123.7
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	98.1	99.5	102.1	100.4	102.4
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	115.9	116.1	140.1	140.6	141.8
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	111.1	111.2	114.0	114.1	114.6
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	119.7	119.2	128.7	129.1	129.4
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	109.5	109.9	113.0	113.0	113.2
<b>1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण</b>	<b>4.789</b>	<b>114.0</b>	<b>113.8</b>	<b>120.7</b>	<b>120.5</b>	<b>120.7</b>
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	106.3	104.4	121.2	120.6	120.5
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	119.4	120.2	120.8	120.8	121.7
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	111.6	111.5	114.6	114.9	116.0
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गैयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	111.8	110.4	119.0	117.5	118.7
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	80.2	83.7	75.3	75.0	73.1
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने-उतारने वाले उपकरण	0.285	113.4	113.5	119.6	123.3	119.9



**सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)**  
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
				नव.	सितं.	अक्टू. (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	128.7	127.7	135.9	131.6	132.9
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	121.6	121.6	129.0	129.3	129.7
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	108.4	108.2	115.5	116.0	116.0
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.7	75.6	77.9	78.1	78.7
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	128.0	131.7	131.6	133.0	132.6
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	121.9	123.3	124.6	124.8	124.0
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	128.7	128.4	135.5	134.7	134.6
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	65.2	65.5	66.5	66.6	66.3
<b>1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण</b>	<b>4.969</b>	<b>117.8</b>	<b>117.9</b>	<b>122.1</b>	<b>122.4</b>	<b>123.2</b>
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	119.4	120.1	122.2	122.4	123.2
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	116.1	115.5	122.1	122.5	123.1
<b>1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण</b>	<b>1.648</b>	<b>126.2</b>	<b>127.5</b>	<b>131.7</b>	<b>131.7</b>	<b>132.6</b>
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली -वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.9	158.9	158.9
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	105.0	104.8	104.3	104.5	104.5
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	124.7	126.5	131.0	131.1	132.2
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	130.3	128.7	137.3	137.3	137.9
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	128.5	127.7	135.0	136.0	136.6
<b>1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण</b>	<b>0.727</b>	<b>133.2</b>	<b>133.6</b>	<b>148.1</b>	<b>150.7</b>	<b>150.6</b>
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	133.2	133.6	148.1	150.7	150.6
<b>1.3.22 अन्य विनिर्माण</b>	<b>1.064</b>	<b>132.4</b>	<b>135.0</b>	<b>135.1</b>	<b>137.9</b>	<b>136.6</b>
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	130.5	133.3	133.0	136.0	134.6
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	173.7	170.2	189.2	190.5	192.6
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	132.0	131.8	138.6	141.1	142.1
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	142.4	141.5	151.0	149.9	151.6
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	167.4	168.5	172.9	172.9	172.9
<b>2 खाद्य सूचकांक</b>	<b>24.378</b>	<b>153.4</b>	<b>159.7</b>	<b>162.1</b>	<b>164.8</b>	<b>170.4</b>

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

## सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारांक	2019-20	2020-21	अप्रैल- अक्टूबर		अक्टूबर	
				2020-21	2021-22	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
<b>सामान्य सूचकांक</b>	100.00	129.0	118.1	105.8	127.0	129.6	133.7
<b>1 क्षेत्रवार वर्गीकरण</b>							
1.1 खनन	14.37	109.6	101.0	87.1	104.9	98.5	109.7
1.2 विनिर्माण	77.63	129.6	117.2	104.2	126.3	132.0	134.7
1.3 बिजली	7.99	158.4	157.6	155.7	173.4	162.2	167.3
<b>2 उपयोग आधारित वर्गीकरण</b>							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	127.0	118.1	108.7	124.8	117.9	128.5
2.2 पूंजीगत माल	8.22	93.3	75.9	62.1	84.0	91.3	90.3
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	137.7	124.7	109.4	138.9	140.7	143.7
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	136.6	124.7	108.5	142.3	144.1	151.8
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	119.0	101.2	85.0	109.2	133.8	125.6
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	145.3	142.1	134.4	144.1	148.7	149.5

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

## सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

## सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(करोड़ ₹)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल - नवंबर			
	2021-22 (बजट आकलन)	2021-22 (वास्तविक)	2020-21 (वास्तविक)	बजट आकलनों का प्रतिशत	
				2021-22	2020-21
	1	2	3	4	5
<b>1 राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>1788424</b>	<b>1358290</b>	<b>812710</b>	<b>75.9</b>	<b>40.2</b>
1.1 कर राजस्व (निवल)	1545396	1135264	688430	73.5	42.1
1.2 करेतर राजस्व	243028	223026	124280	91.8	32.3
<b>2 गैरेतर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां</b>	<b>188000</b>	<b>20703</b>	<b>18141</b>	<b>11.0</b>	<b>8.1</b>
2.1 ऋण की वसूली	13000	11339	11962	87.2	79.9
2.2 अन्य प्राप्तियां	175000	9364	6179	5.4	2.9
<b>3 कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) (1+2)</b>	<b>1976424</b>	<b>1378993</b>	<b>830851</b>	<b>69.8</b>	<b>37.0</b>
<b>4 राजस्व व्यय</b>	<b>2929000</b>	<b>1800977</b>	<b>1665200</b>	<b>61.5</b>	<b>63.3</b>
4.1 ब्याज भुगतान	809701	460323	383425	56.9	54.1
5 पूंजी व्यय	554236	273630	241158	49.4	58.5
<b>6 कुल व्यय (4+5)</b>	<b>3483236</b>	<b>2074607</b>	<b>1906358</b>	<b>59.6</b>	<b>62.7</b>
<b>7 राजस्व घाटा (4-1)</b>	<b>1140576</b>	<b>442687</b>	<b>852490</b>	<b>38.8</b>	<b>139.9</b>
<b>8 राजकोषीय घाटा (6-3)</b>	<b>1506812</b>	<b>695614</b>	<b>1075507</b>	<b>46.2</b>	<b>135.1</b>
<b>9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)</b>	<b>697111</b>	<b>235291</b>	<b>692082</b>	<b>33.8</b>	<b>785.3</b>

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

## सं. 24: खजाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	2020		2021				
		नव. 27	अक्टू. 22	अक्टू. 29	नव. 5	नव. 12	नव. 19	नव. 26
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 91-दिवसीय</b>								
1.1 बैंक	5676	2001	10507	11660	12406	10914	10304	11133
1.2 प्राथमिक व्यापारी	16740	12584	27651	31896	34137	31674	33660	31737
1.3 राज्य सरकारें	13347	71680	66865	68355	71138	76360	72060	86665
1.4 अन्य	52802	121644	102057	98459	95319	99341	98250	100079
<b>2 182-दिवसीय</b>								
2.1 बैंक	67473	126536	80391	81117	76159	73633	68696	63455
2.2 प्राथमिक व्यापारी	30966	38808	52650	55234	62765	54144	50747	47832
2.3 राज्य सरकारें	9436	4233	7717	7593	7593	7593	7593	8318
2.4 अन्य	31800	94013	97684	83272	68014	65366	61489	57109
<b>3 364-दिवसीय</b>								
3.1 बैंक	119024	140904	111412	114147	117948	116669	105248	110185
3.2 प्राथमिक व्यापारी	154197	120831	96903	94931	101864	101858	102088	107891
3.3 राज्य सरकारें	18510	16367	19263	19563	20223	20223	20223	19553
3.4 अन्य	174501	131253	91150	93755	85931	90626	104832	97489
<b>4 14-दिवसीय मध्यवर्ती</b>								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	220351	159713	157140	178049	120216	99122	122651	200002
4.4 अन्य	747	233	785	1098	1721	883	597	1026
<b>कुल खजाना बिल</b>								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिल को छोड़कर)#	694471	880853	764250	759982	753497	748402	735192	741446

# 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खजाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

## सं. 25: खजाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ		स्वीकृत बोलियाँ		कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)		
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या				कुल अंकित मूल्य	
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी					प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>91-दिवसीय खजाना बिल</b>										
<b>2021-22</b>										
अक्टू. 27	10000	113	32893	8831	52	9999	8831	18831	99.12	3.5610
नव. 2	10000	122	43959	9101	37	9999	9101	19100	99.10	3.6488
नव. 10	10000	123	51726	13201	19	9999	13201	23200	99.13	3.5390
नव. 17	10000	127	46169	4251	20	9999	4251	14250	99.13	3.5222
नव. 24	10000	124	36824	20951	44	9999	20951	30950	99.13	3.5300
<b>182-दिवसीय खजाना बिल</b>										
<b>2021-22</b>										
अक्टू. 27	3000	59	7159	0	37	3000	0	3000	98.13	3.8322
नव. 2	3000	66	12475	0	26	3000	0	3000	98.10	3.8780
नव. 10	3000	90	14854	0	11	3000	0	3000	98.13	3.8201
नव. 17	3000	104	14974	0	27	3000	0	3000	98.13	3.8192
नव. 24	3000	80	12590	700	26	3000	700	3700	98.13	3.8301
<b>364-दिवसीय खजाना बिल</b>										
<b>2021-22</b>										
अक्टू. 27	7000	143	22795	300	49	7000	300	7300	96.13	4.0390
नव. 2	7000	101	19630	660	49	7000	660	7660	96.08	4.0899
नव. 10	7000	124	20270	1	63	6999	1	7000	96.10	4.0694
नव. 17	7000	117	16395	0	72	7000	0	7000	96.07	4.1020
नव. 24	7000	129	18175	300	60	7000	300	7300	96.04	4.1299

## वित्तीय बाजार

## सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा		भारित औसत दरें
	उधार लेना/उधार देना		उधार लेना/उधार देना
	1		2
नवंबर	1, 2021	2.00-3.55	3.30
नवंबर	2, 2021	2.00-3.50	3.33
नवंबर	3, 2021	2.00-3.65	3.41
नवंबर	6, 2021	2.60-4.00	3.37
नवंबर	8, 2021	2.00-3.45	3.30
नवंबर	9, 2021	2.00-3.50	3.24
नवंबर	10, 2021	2.00-3.50	3.19
नवंबर	11, 2021	2.00-3.50	3.20
नवंबर	12, 2021	2.00-3.50	3.21
नवंबर	15, 2021	2.00-3.40	3.19
नवंबर	16, 2021	2.20-3.40	3.16
नवंबर	17, 2021	2.20-3.40	3.20
नवंबर	18, 2021	2.00-4.70	3.41
नवंबर	20, 2021	2.70-3.90	3.47
नवंबर	22, 2021	2.00-4.00	3.53
नवंबर	23, 2021	2.00-3.75	3.34
नवंबर	24, 2021	2.00-3.55	3.27
नवंबर	25, 2021	2.00-3.50	3.22
नवंबर	26, 2021	2.00-3.55	3.25
नवंबर	29, 2021	2.00-3.50	3.24
नवंबर	30, 2021	2.00-3.65	3.25
दिसंबर	1, 2021	2.00-3.50	3.27
दिसंबर	2, 2021	2.20-3.50	3.26
दिसंबर	3, 2021	2.00-3.60	3.28
दिसंबर	4, 2021	2.70-3.25	2.99
दिसंबर	6, 2021	2.00-3.45	3.26
दिसंबर	7, 2021	2.00-3.50	3.29
दिसंबर	8, 2021	2.00-3.55	3.26
दिसंबर	9, 2021	2.00-3.45	3.28
दिसंबर	10, 2021	2.00-3.45	3.28
दिसंबर	13, 2021	2.00-3.50	3.28
दिसंबर	14, 2021	2.00-3.45	3.29
दिसंबर	15, 2021	2.00-3.60	3.33

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

## सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2020	2021			
	नव. 20	सितं. 24	अक्टू. 8	अक्टू. 22	नव. 19
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	64068.52	60220.40	59201.66	57366.48	55596.33
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	791.91	3229.92	1684.57	410.21	2272.75
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.35-4.54	3.35-4.49	3.47-4.90	3.62-4.49	3.59-4.22

## सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2020	2021			
	नव. 30	अक्टू. 15	अक्टू. 31	नव. 15	नव. 30
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	373146.10	399720.05	379278.30	450890.70	388363.05
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	64386.20	55664.10	56178.95	172504.00	115234.25
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	2.79-8.80	3.38-8.47	3.32-12.71	3.38-10.44	3.38-12.76

## सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	2020	2021					
		नव. 27	अक्टू. 22	अक्टू. 29	नव. 5	नव. 12	नव. 19	नव. 26
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	17461	12157	16775	14570	13336	14985	11384	15488
2 नोटिस मुद्रा	2604	632	940	2904	6100	730	4943	912
3 मीयादी मुद्रा	757	687	390	373	285	410	214	358
4 त्रिपक्षीय रिपो	421118	411117	571157	774300	532245	678189	744194	652602
5 बाजार रिपो	337341	273258	322638	388328	335704	358178	424778	402681
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	2990	1208	3654	5351	1697	2510	3888	6203
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	57492	76434	92929	90250	74746	67253	73584
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	62490	70609	61211	56616	45603	51577	43374	51839
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5080	4965	3862	5087	5698	4495	6100	5137
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	4970	1555	3901	3487	5126	4212	1806	4211
10.2 182-दिवसीय	4870	7120	1694	2329	3912	3241	2406	2282
10.3 364-दिवसीय	4010	4704	2653	1685	2620	3866	3182	2083
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	1490							
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	82910	88953	73320	69203	62958	67392	56867	65552
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	-	4325	164	38	214	627	412	873

## सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2020-21		2020-21 (अप्रै-नवं.)		2021-22 (अप्रै-नवं.)*		नवं. 2020		नवं. 2021*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1 इक्विटी शेयर</b>	<b>74</b>	<b>102062</b>	<b>43</b>	<b>87738</b>	<b>94</b>	<b>111815</b>	<b>4</b>	<b>7070</b>	<b>17</b>	<b>57351</b>
1ए प्रीमियम	73	97648	43	84220	89	110383	4	6905	16	56994
1.1 पब्लिक	53	38004	28	27130	76	89180	3	6999	14	36296
1.1.1 प्रीमियम	53	34848	28	24377	75	88281	3	6837	14	36175
1.2 राइट्स	21	64059	15	60608	18	22635	1	71	3	21055
1.2.1 प्रीमियम	20	62800	15	59843	14	22101	1	68	2	20820
<b>2 अधिमान शेयर</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>3 बांड और डिबेंचर</b>	<b>16</b>	<b>5806</b>	<b>10</b>	<b>3871</b>	<b>20</b>	<b>9132</b>	<b>1</b>	<b>143</b>	<b>1</b>	<b>50</b>
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	16	5806	10	3871	20	9132	1	143	1	50
3.1.1 पब्लिक	16	5806	10	3871	20	9132	1	143	1	50
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>4 कुल (1+2+3)</b>	<b>90</b>	<b>107868</b>	<b>53</b>	<b>91609</b>	<b>114</b>	<b>120947</b>	<b>5</b>	<b>7213</b>	<b>18</b>	<b>57401</b>
4.1 पब्लिक	69	43809	38	31001	96	98312	4	7141	15	36346
4.2 राइट्स	21	64059	15	60608	18	22635	1	71	3	21055

**टिप्पणी:** 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कालम के आंकड़े कुल में नहीं जुड़ सकते।

**स्रोत :** भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)।

\* : आंकड़े अनंतिम हैं।

## बाह्य क्षेत्र

## सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2020-21	2020		2021			
			नव.	जुला.	अग.	सित.	अक्टू.	नव.
			1	2	3	4	5	6
1 निर्यात	करोड ₹	2159043	175307	264805	247711	248696	266964	223756
	मिलियन अमरीकी डॉलर	291808	23620	35531	33391	33807	35635	30036
1.1 तेल	करोड ₹	190896	11559	43617	34638	38214	39931	29494
	मिलियन अमरीकी डॉलर	25804	1557	5852	4669	5195	5330	3959
1.2 तेल से इतर	करोड ₹	1968147	163748	221189	213073	210481	227033	194262
	मिलियन अमरीकी डॉलर	266004	22063	29679	28722	28612	30305	26077
2 आयात	करोड ₹	2915958	250954	345085	336112	415501	400396	394420
	मिलियन अमरीकी डॉलर	394436	33812	46303	45307	56482	53447	52945
2.1 तेल	करोड ₹	611353	46868	93624	71805	125101	93947	109344
	मिलियन अमरीकी डॉलर	82684	6315	12562	9679	17006	12540	14678
2.2 तेल से इतर	करोड ₹	2304605	204086	251461	264307	290400	306449	285075
	मिलियन अमरीकी डॉलर	311752	27497	33741	35628	39476	40906	38267
3 व्यापार शेष	करोड ₹	-756914	-75647	-80280	-88401	-166805	-133432	-170664
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-102627	-10192	-10772	-11916	-22675	-17811	-22909
3.1 तेल	करोड ₹	-420457	-35310	-50007	-37167	-86886	-54016	-79850
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-56880	-4757	-6710	-5010	-11811	-7210	-10719
3.2 तेल से इतर	करोड ₹	-336458	-40338	-30273	-51234	-79919	-79416	-90813
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-45748	-5435	-4062	-6906	-10864	-10601	-12190

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

## सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2021						
		जन. 1	नव. 26	दिसं 3	दिसं 10	दिसं 17	दिसं 24	दिसं 31
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	करोड ₹	4276976	4776057	4776854	4815036	4835997	4765329	4707812
	मिलियन अमरीकी डॉलर	585324	637687	635905	635828	635667	635080	633614
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	3957808	4304119	4305743	4338196	4353228	4287220	4234327
	मिलियन अमरीकी डॉलर	541642	574664	573181	572860	572216	571369	569889
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	270554	290793	288595	293134	298092	295562	292779
	मिलियन अमरीकी डॉलर	37026	38825	38418	38709	39183	39390	39405
	मात्रा (मैट्रिक टन)	676.65	750.37	752.23	753.17	754.1	754.1	754.1
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1049	13657	13657	13657	13657	13657	13657
	करोड ₹	11035	142576	143677	144561	145226	143418	142017
	मिलियन अमरीकी डॉलर	1510	19036	19126	19089	19089	19114	19114
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	37578	38569	38839	39145	39452	39129	38690
	मिलियन अमरीकी डॉलर	5145	5162	5180	5170	5179	5207	5207

\* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से हैं।

## सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2020-21	2020	2021		2020-21	2021-22
		नव.	अक्टू.	नव.	अप्रै.-नव.	अप्रै.-नव.
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	141,895	139,264	141,305	140,734	7,012	2,592
1.1 एफसीएनआर (बी)	20,473	21,925	18,802	18,668	-2,319	-1,805
1.2 एनआर (ई) आरए	102,579	100,070	102,485	101,794	8,272	2,375
1.3 एनआरओ	18,842	17,268	20,018	20,273	1,059	2,022

## सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2020-21	2020-21	2021-22	2020	2021	
		अप्रै.-नव.	अप्रै.-नव.	नव.	अक्टू.	नव.
	1	2	3	4	5	6
<b>1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)</b>	<b>43955</b>	<b>35037</b>	<b>24714</b>	<b>7170</b>	<b>1914</b>	<b>1641</b>
<b>1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)</b>	<b>54927</b>	<b>42047</b>	<b>35961</b>	<b>8024</b>	<b>3240</b>	<b>2706</b>
<b>1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश</b>	<b>81973</b>	<b>58853</b>	<b>54104</b>	<b>10335</b>	<b>5566</b>	<b>6138</b>
1.1.1.1.1 इक्विटी	61088	44788	40202	8640	3845	4515
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	948	265	1549	48	1105	112
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	51597	38599	27602	7355	2076	3894
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7091	4985	10111	1112	539	384
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	1452	939	939	126	126	126
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	16935	10953	11665	1464	1464	1464
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3950	3113	2237	230	257	159
<b>1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश</b>	<b>27046</b>	<b>16807</b>	<b>18143</b>	<b>2311</b>	<b>2326</b>	<b>3432</b>
1.1.1.2.1 इक्विटी	26983	16782	17689	2306	2286	3326
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	63	24	454	4	40	106
<b>1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)</b>	<b>10972</b>	<b>7010</b>	<b>11248</b>	<b>854</b>	<b>1326</b>	<b>1065</b>
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	5583	3744	5786	689	523	771
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3013	2009	2065	251	251	251
1.1.2.3 अन्य पूंजी	6688	3362	5510	407	803	196
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	4313	2105	2113	493	251	153
<b>1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)</b>	<b>36137</b>	<b>20305</b>	<b>1574</b>	<b>10929</b>	<b>-2663</b>	<b>-42</b>
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	38725	21823	2538	11091	-2128	-255
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	2589	1518	964	162	535	-213
<b>1 विदेशी निवेश अंतर्वाह</b>	<b>80092</b>	<b>55343</b>	<b>26288</b>	<b>18099</b>	<b>-749</b>	<b>1599</b>

## सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2020-21	2020	2021		
		नव.	सित.	अक्टू.	नव.
	1	2	3	4	5
<b>1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण</b>	<b>12684.40</b>	<b>942.44</b>	<b>1970.01</b>	<b>1564.90</b>	<b>1547.41</b>
1.1 जमाराशियां	680.37	23.32	60.09	46.58	50.40
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	62.75	3.53	9.36	7.43	11.01
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	471.80	25.39	73.55	55.20	57.68
1.4 उपहार	1586.24	110.55	210.23	172.06	206.21
1.5 दान	12.59	0.65	0.85	0.83	0.94
1.6 यात्रा	3239.67	253.26	580.35	464.59	456.31
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2680.10	160.81	295.25	221.56	267.22
1.8 चिकित्सा उपचार	29.75	2.92	3.32	3.11	3.30
1.9 विदेश में शिक्षा	3836.12	355.77	718.32	579.84	482.35
1.10 अन्य	85.03	6.24	18.71	13.71	11.99



सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और  
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2019-20	2020-21	2020	2021	
			दिसंबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
<b>40- मुद्रा बास्केट (आधार: 2015-16=100)</b>					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	98.00	93.92	92.96	94.04	93.50
1.2 रीर	103.20	103.46	103.34	105.91	104.38
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	97.38	93.59	92.80	93.97	93.70
2.2 रीर	102.88	102.96	103.13	105.37	104.15
<b>6- मुद्रा बास्केट (व्यापार-भारित)</b>					
1 आधार : 2015-16=100					
1.1 नीर	94.92	88.47	87.13	87.60	86.64
1.2 रीर	103.62	101.88	101.66	104.31	102.68
2 आधार : 2018-19 =100					
2.1 नीर	100.78	93.93	92.50	93.00	91.98
2.2 रीर	103.32	101.59	101.37	104.01	102.38

## सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमरीकी मिलियन डॉलर में)

मद	2020-21	2020	2021	2021
		नव.-20	अक्टू.-21	नव.-21
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1063	87	76	90
1.2 राशि	26799	2045	1339	1694
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	13	0	0	3
2.2 राशि	8456	0	0	705
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1076	87	76	93
3.2 राशि	35255	2045	1339	2399
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.03	5.48	5.04	4.37
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारित औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.93	1.87	1.14	2.79
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-13.00	0.00-10.30	0.00-11.00	0.00-10.60
<b>उधारकर्ता श्रेणियाँ</b>				
I. कॉर्पोरेट विनिर्माण	12827	466	231	401
II. कॉर्पोरेट -बुनियादी संरचना	9985	900	1065	1110
ए) परिवहन	636	0	0	0
बी) ऊर्जा	2713	194	166	1106
सी) पानी और सफाई व्यवस्था	151	0	0	0
डी) संचार	757	0	0	1
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	1761	1	0	0
एफ)अन्वेषण खनन और रिफाइनरी	1346	706	850	0
जी) अन्य उप-क्षेत्र	2622	0	48	3
III. कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्र	1894	583	16	48
IV. अन्य संस्थाएं	1026	5	0	100
ए) एसई जेड में इकाई	26	5	0	0
बी) सिडबी	0			
सी) एकिजम बैंक	1000	0	0	100
V. बैंक	0	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबी एफ सी के अलावा)	2110	0	0	4
VII. एनबीएफसी	6934	45	5	724
ए) एनबीएफसी -आई एफ सी/ए एफ सी	6024	27	0	550
बी) एनबी एफ सी -एमएफआई	84	18	0	1
सी) एनबीएफसी - अन्य	827	0	5	173
VIII. गैर-सरकारी संगठन	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था	8	0	0	0
X. अन्य	470	45	22	12

## सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	जुला.-सितं. 2020			जुला.-सितं. 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	296176	264608	31568	404597	373408	31189
1 चालू खाता (1.1+1.2)	150791	135541	15250	194275	203886	-9611
1.1 पण्य	75591	90407	-14816	104842	149265	-44423
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	75200	45134	30066	89434	54621	34813
1.2.1 सेवाएं	49793	28707	21086	61421	35836	25585
1.2.1.1 यात्रा	2138	2764	-626	2147	3919	-1772
1.2.1.2 परिवहन	5368	4759	609	7584	8181	-597
1.2.1.3 बीमा	590	537	53	796	575	220
1.2.1.4 जीएनआईई	144	190	-46	217	198	19
1.2.1.5 विविध	41554	20458	21096	50678	22962	27716
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	24791	2769	22021	29965	3184	26781
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	11624	12354	-730	13858	12457	1401
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1003	1107	-104	1303	1463	-160
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	661	355	306	766	275	491
1.2.2 अंतरण	20421	2035	18386	21154	2239	18915
1.2.2.1 आधिकारिक	36	270	-233	18	315	-297
1.2.2.2 निजी	20385	1766	18619	21135	1924	19212
1.2.3 आय	4986	14391	-9405	6859	16546	-9688
1.2.3.1 निवेश आय	3541	13695	-10154	5362	15792	-10430
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1445	696	749	1497	754	743
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	145010	129067	15943	209579	169522	40057
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	97296	65874	31422	132378	119040	13338
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	30502	6077	24424	20447	10987	9461
2.1.1.1 भारत में	29527	2450	27078	19281	6475	12806
2.1.1.1.1 इक्विटी	23794	2445	21350	13940	6259	7681
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	4117		4117	4482	0	4482
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1617	5	1611	859	216	643
2.1.1.2 विदेश में	974	3627	-2653	1167	4512	-3345
2.1.1.2.1 इक्विटी	974	1202	-228	1167	2060	-894
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	753	-753	0	781	-781
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1672	-1672	0	1670	-1670
2.1.2 संविभाग निवेश	66794	59796	6998	111931	108054	3877
2.1.2.1 भारत में	66420	58684	7736	110448	105904	4544
2.1.2.1.1 एफआईआई	66420	58684	7736	110448	105904	4544
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	55007	48183	6824	95335	94718	618
2.1.2.1.1.2 ऋण	11413	10501	912	15112	11186	3926
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	375	1113	-738	1483	2150	-666
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	20645	24532	-3887	25555	17965	7590
2.2.1 बाह्य सहायता	3209	1323	1886	2420	1303	1117
2.2.1.1 भारत द्वारा	10	21	-11	14	30	-15
2.2.1.2 भारत को	3199	1302	1897	2406	1273	1132
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	8775	12731	-3956	9114	5004	4110
2.2.2.1 भारत द्वारा	769	1005	-235	282	249	33
2.2.2.2 भारत को	8005	11726	-3721	8832	4755	4077
2.2.3 भारत को अल्पावधि	8662	10479	-1817	14021	11658	2364
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	8662	9770	-1108	9615	11658	-2043
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	709	-709	4407	0	4407
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	18762	30025	-11263	20817	20457	360
2.3.1 वाणिज्य बैंक	18749	30025	-11276	20473	20457	17
2.3.1.1 आस्तियां	7207	16747	-9539	10097	9858	239
2.3.1.2 देयताएं	11541	13279	-1737	10376	10598	-222
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	10311	8377	1934	8574	9357	-783
2.3.2 अन्य	13	0	13	344	0	344
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	2	-2	0	2	-2
2.5 अन्य पूंजी	8307	8633	-327	30829	12059	18770
3 भूल-चूक	375		375	742	0	742
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	31568	-31568	0	31189	-31189
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)		31568	-31568	0	31189	-31189

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

## सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	जुला.-सितं. 2020			जुला.-सितं. 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	2203029	1968215	234814	2997726	2766643	231083
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1121622	1008187	113435	1439417	1510625	-71208
1.1 पण्य	562264	672468	-110205	776788	1105928	-329140
1.2 अदृश्य मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	559358	335719	223639	662629	404696	257932
1.2.1 सेवाएं	370373	213533	156840	455079	265514	189566
1.2.1.1 यात्रा	15903	20559	-4657	15905	29037	-13132
1.2.1.2 परिवहन	39926	35397	4528	56188	60613	-4425
1.2.1.3 बीमा	4385	3994	391	5896	4263	1633
1.2.1.4 जीएनआईई	1074	1414	-339	1607	1467	141
1.2.1.5 विविध	309085	152168	156917	375483	170133	205350
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	184399	20598	163801	222016	23589	198426
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	86464	91890	-5426	102675	92295	10380
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	7462	8233	-771	9652	10836	-1184
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	4914	2638	2275	5676	2035	3641
1.2.2 अंतरण	151896	15140	136756	156732	16588	140144
1.2.2.1 आधिकारिक	269	2006	-1737	137	2334	-2198
1.2.2.2 निजी	151627	13134	138492	156596	14254	142342
1.2.3 आय	37089	107046	-69956	50817	122594	-71777
1.2.3.1 निवेश आय	26339	101868	-75528	39725	117005	-77280
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	10750	5178	5572	11092	5589	5503
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1078616	960028	118588	1552809	1256019	296790
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	723708	489983	233725	980814	881990	98824
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	226877	45202	181675	151499	81403	70095
2.1.1.1 भारत में	219632	18223	201410	142854	47973	94880
2.1.1.1.1 इक्विटी	176987	18184	158803	103281	46371	56909
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	30620	0	30620	33210	0	33210
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	12025	39	11987	6364	1602	4761
2.1.1.2 विदेश में	7245	26980	-19735	8645	33430	-24785
2.1.1.2.1 इक्विटी	7245	8940	-1695	8645	15265	-6620
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5603	-5603	0	5789	-5789
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	12437	-12437	0	12375	-12375
2.1.2 संविभाग निवेश	496831	444780	52050	829315	800587	28729
2.1.2.1 भारत में	494044	436504	57540	818325	784660	33664
2.1.2.1.1 एफआईआई	494044	436504	57540	818325	784660	33664
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	409153	358396	50757	706356	701779	4577
2.1.2.1.1.2 ऋण	84891	78108	6783	111968	82881	29087
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	2786	8276	-5490	10991	15927	-4936
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	153564	182478	-28914	189343	133104	56239
2.2.1 बाह्य सहायता	23866	9840	14026	17930	9654	8276
2.2.1.1 भारत द्वारा	71	153	-82	106	220	-114
2.2.1.2 भारत को	23795	9687	14108	17824	9434	8390
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	65268	94694	-29426	67525	37075	30451
2.2.2.1 भारत द्वारा	5722	7473	-1751	2087	1844	242
2.2.2.2 भारत को	59545	87221	-27675	65439	35231	30208
2.2.3 भारत को अल्पावधि	64430	77945	-13515	103887	86375	17512
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	64430	72671	-8241	71239	86375	-15136
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	5273	-5273	32649	0	32649
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	139558	223336	-83778	154236	151566	2670
2.3.1 वाणिज्य बैंक	139459	223336	-83877	151690	151566	124
2.3.1.1 आस्तियां	53611	124564	-70953	74810	73041	1769
2.3.1.2 देयताएं	85848	98771	-12923	76881	78525	-1645
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	76699	62311	14387	63530	69328	-5798
2.3.2 अन्य	99	0	99	2545	0	2545
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	15	-15	0	15	-15
2.5 अन्य पूंजी	61787	64217	-2430	228416	89344	139073
3 भूल-चूक	2791	0	2791	5500	0	5500
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	234814	-234814	0	231083	-231083
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	234814	-234814	0	231083	-231083

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

## सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	जुला.-सित्त. 2020			जुला.-सित्त. 2021 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
<b>1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)</b>	<b>150790</b>	<b>135515</b>	<b>15275</b>	<b>194275</b>	<b>203856</b>	<b>-9581</b>
<b>1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)</b>	<b>125384</b>	<b>119114</b>	<b>6270</b>	<b>166263</b>	<b>185101</b>	<b>-18838</b>
<b>1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)</b>	<b>75591</b>	<b>90407</b>	<b>-14816</b>	<b>104842</b>	<b>149265</b>	<b>-44423</b>
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	75243	84319	-9076	104327	133243	-28916
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	348	0	348	515	0	515
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		6088	-6088		16022	-16022
<b>1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)</b>	<b>49793</b>	<b>28707</b>	<b>21086</b>	<b>61421</b>	<b>35836</b>	<b>25585</b>
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	68	11	56	75	16	59
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	35	204	-169	74	418	-345
1.अ.ख.3 परिवहन	5368	4759	609	7584	8181	-597
1.अ.ख.4 यात्रा	2138	2764	-626	2147	3919	-1772
1.अ.ख.5 निर्माण	589	563	26	716	715	0
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	590	537	53	796	575	220
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1003	1107	-104	1303	1463	-160
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	313	1456	-1143	202	2189	-1987
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	25515	3290	22225	30823	3651	27172
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	11624	12354	-730	13858	12457	1401
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	530	817	-287	713	1243	-530
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	144	190	-46	217	198	19
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	1875	655	1220	2915	811	2105
<b>1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)</b>	<b>4986</b>	<b>14391</b>	<b>-9405</b>	<b>6859</b>	<b>16546</b>	<b>-9688</b>
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1445	696	749	1497	754	743
1.आ.2 निवेश आय	2753	13394	-10641	4349	15572	-11223
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1272	8131	-6859	1983	9630	-7647
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	49	2126	-2076	111	2859	-2748
1.आ.2.3 अन्य निवेश	78	3137	-3059	62	3082	-3020
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1354	1	1353	2193	1	2193
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	788	301	487	1012	220	792
<b>1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)</b>	<b>20419</b>	<b>2009</b>	<b>18410</b>	<b>21153</b>	<b>2209</b>	<b>18944</b>
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	20385	1766	18619	21135	1924	19212
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	19711	1287	18424	20237	1356	18881
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	674	479	195	899	568	331
1.इ.2 सामान्य सरकार	35	243	-209	18	285	-267
<b>2. पूँजी खाता (2.1+2.2)</b>	<b>109</b>	<b>198</b>	<b>-88</b>	<b>189</b>	<b>210</b>	<b>-20</b>
2.1 अनुत्पादित वित्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निरुत्तरण (जमा)	8	100	-92	62	132	-71
2.2 पूँजी अंतरण	101	97	4	128	77	50
<b>3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)</b>	<b>144902</b>	<b>160464</b>	<b>-15562</b>	<b>209391</b>	<b>200531</b>	<b>8859</b>
<b>3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1.अ+3.1.आ)</b>	<b>30502</b>	<b>6077</b>	<b>24424</b>	<b>20447</b>	<b>10987</b>	<b>9461</b>
3.1.अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	29527	2450	27078	19281	6475	12806
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	27911	2445	25466	18422	6259	12163
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	23794	2445	21350	13940	6259	7681
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	4117		4117	4482		4482
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1617	5	1611	859	216	643
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1617	5	1611	859	216	643
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	974	3627	-2653	1167	4512	-3345
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	974	1955	-981	1167	2842	-1675
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	974	1202	-228	1167	2060	-894
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		753	-753		781	-781
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1672	-1672		1670	-1670
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1672	-1672		1670	-1670
<b>3.2 संविभाग निवेश</b>	<b>66794</b>	<b>59796</b>	<b>6998</b>	<b>111931</b>	<b>108054</b>	<b>3877</b>
3.2.अ भारत में संविभाग निवेश	66420	58684	7736	110448	105904	4544
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	55007	48183	6824	95335	94718	618
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	11413	10501	912	15112	11186	3926
3.2.आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	375	1113	-738	1483	2150	-666
<b>3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन</b>	<b>2858</b>	<b>3936</b>	<b>-1078</b>	<b>5367</b>	<b>5806</b>	<b>-439</b>
<b>3.4 अन्य निवेश</b>	<b>44749</b>	<b>59086</b>	<b>-14337</b>	<b>71646</b>	<b>44496</b>	<b>27150</b>
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	0	0	0	0	0	0
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	10325	8377	1948	8918	9357	-439
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	13	0	13	344	0	344
3.4.2.3 सामान्य सरकार	10311	8377	1934	8574	9357	-783
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0			
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)						
3.4.3.अ भारत को ऋण	20421	35702	-15281	23433	17406	6026
3.4.3.आ भारत द्वारा ऋण	19642	34677	-15035	23137	17128	6009
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	779	1025	-246	296	279	17
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	78	62	16	55	13	42
3.4.6 अन्य खाते प्राप्ति/देय-अन्य	8662	10479	-1817	14021	11658	2364
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	5263	4466	797	7356	6062	1295
<b>3.5 आरक्षित आस्तियां</b>	<b>0</b>	<b>31568</b>	<b>-31568</b>	<b>0</b>	<b>31189</b>	<b>-31189</b>
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण						
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए						
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए					17862	-17862
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)						
<b>4. कुल आस्तियां / देयताएं</b>	<b>0</b>	<b>31568</b>	<b>-31568</b>	<b>0</b>	<b>13326</b>	<b>-13326</b>
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	<b>144902</b>	<b>160464</b>	<b>-15562</b>	<b>209391</b>	<b>200531</b>	<b>8859</b>
4.2 ऋण लिखत	87202	57694	29508	121829	111787	10042
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	52437	66736	-14299	62343	51494	10849
<b>5. निवल भूल-चूक</b>	<b>5263</b>	<b>36034</b>	<b>-30771</b>	<b>25219</b>	<b>37251</b>	<b>-12032</b>
<b>टिप्पणी: पॉ: प्रारंभिक</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>742</b>	<b>742</b>	<b>742</b>

Note : P : Preliminary

## सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(कोड़ ₹)

मद	जुला.-सितं. 2020			जुला.-सितं. 2021 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
<b>1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)</b>	<b>1121609</b>	<b>1007991</b>	<b>113618</b>	<b>1439413</b>	<b>1510403</b>	<b>-70990</b>
<b>1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)</b>	<b>932637</b>	<b>886001</b>	<b>46635</b>	<b>1231868</b>	<b>1371442</b>	<b>-139574</b>
<b>1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)</b>	<b>562264</b>	<b>672468</b>	<b>-110205</b>	<b>776788</b>	<b>1105928</b>	<b>-329140</b>
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	559675	627181	-67506	772976	987218	-214242
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	2588	0	2588	3812	0	3812
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	45287	-45287	0	118711	-118711
<b>1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)</b>	<b>370373</b>	<b>213533</b>	<b>156840</b>	<b>455079</b>	<b>265514</b>	<b>189566</b>
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	505	85	420	558	118	440
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	263	1519	-1256	546	3100	-2554
1.अ.ख.3 परिवहन	39926	35397	4528	56188	60613	-4425
1.अ.ख.4 यात्रा	15903	20559	-4657	15905	29037	-13132
1.अ.ख.5 निर्माण	4383	4186	197	5302	5299	3
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4385	3994	391	5896	4263	1633
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	7462	8233	-771	9652	10836	-1184
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	2330	10833	-8503	1499	16220	-14721
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	189787	24472	165315	228370	27051	201318
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	86464	91890	-5426	102675	92295	10380
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3944	6078	-2135	5279	9207	-3928
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1074	1414	-339	1607	1467	141
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	13948	4871	9077	21601	6006	15595
<b>1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)</b>	<b>37089</b>	<b>107046</b>	<b>-69956</b>	<b>50817</b>	<b>122594</b>	<b>-71777</b>
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	10750	5178	5572	11092	5589	5503
1.आ.2 निवेश आय	20478	99630	-79152	32225	115376	-83151
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	9463	60481	-51018	14692	71350	-56658
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	366	15810	-15445	820	21184	-20364
1.आ.2.3 अन्य निवेश	579	23331	-22752	461	22836	-22375
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	10070	7	10063	16251	5	16246
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	5861	2238	3623	7500	1629	5871
<b>1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)</b>	<b>151883</b>	<b>14944</b>	<b>136939</b>	<b>156729</b>	<b>16367</b>	<b>140361</b>
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्ततर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	151627	13134	138492	156596	14254	142342
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और/अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	146616	9573	137043	149936	10045	139891
1.इ.2 सामान्य सरकार	5011	3561	1450	6659	4209	2451
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	257	1810	-1553	133	2113	-1980
2.1 अनुत्पादित वित्ततर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नाम) / निस्तारण (जमा)	813	1471	-658	1402	1553	-151
2.2 पूँजी अंतरण	62	747	-685	457	981	-524
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	751	725	27	946	572	374
<b>3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)</b>	<b>1077815</b>	<b>1193566</b>	<b>-115751</b>	<b>1551410</b>	<b>1485770</b>	<b>65641</b>
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	226877	45202	181675	151499	81403	70095
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	219632	18223	201410	142854	47973	94880
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	207607	18184	189423	136490	46371	90119
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	176987	18184	158803	103281	46371	56909
3.1.अ.2 ऋण लिखत	30620	0	30620	33210	0	33210
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	12025	39	11987	6364	1602	4761
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	12025	39	11987	6364	1602	4761
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	7245	26980	-19735	8645	33430	-24785
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	7245	14543	-7298	8645	21055	-12410
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	7245	8940	-1695	8645	15265	-6620
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	5603	-5603	0	5789	-5789
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	12437	-12437	0	12375	-12375
3.1.आ.2.2 ऋण लिखत	0	12437	-12437	0	12375	-12375
3.2 संविभाग निवेश	0	12437	-12437	0	12375	-12375
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	496831	444780	52050	829315	800587	28729
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	494044	436504	57540	818325	784660	33664
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	409153	358396	50757	706356	701779	4577
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	84891	78108	6783	111968	82881	29087
<b>3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन</b>	<b>2786</b>	<b>8276</b>	<b>-5490</b>	<b>10991</b>	<b>15927</b>	<b>-4936</b>
<b>3.4 अन्य निवेश</b>	<b>21257</b>	<b>29276</b>	<b>-8019</b>	<b>39762</b>	<b>43017</b>	<b>-3256</b>
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	332850	439493	-106643	530835	329679	201155
3.4.2 मुद्रा और जमाराशिया	0	0	0	0	0	0
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट, एनआरजी)	76798	62311	14486	66075	69328	-3253
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	99	0	99	2545	0	2545
3.4.2.3 सामान्य सरकार	76699	62311	14387	63530	69328	-5798
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईपीबी और बैंकिंग पूँजी)	0	0	0	0	0	0
3.4.3अ भारत को ऋण	151894	265558	-113664	173616	128967	44649
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	146100	257932	-111832	171423	126903	44520
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	5793	7626	-1833	2193	2064	128
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	580	462	117	405	97	308
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	64430	77945	-13515	103887	86375	17512
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	39149	33218	5932	54505	44912	9592
<b>3.5 आरक्षित आस्तियां</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132346</b>	<b>0</b>	<b>132346</b>
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	234814	-234814	0	231083	-231083
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	132346	-132346
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	0	0	0	0	0
<b>4. कुल आस्तियां / देयताएं</b>	<b>0</b>	<b>234814</b>	<b>-234814</b>	<b>0</b>	<b>98737</b>	<b>-98737</b>
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	1077815	1193566	-115751	1551410	1485770	65641
4.2 ऋण लिखत	648628	429138	219490	902649	828246	74403
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	390038	496397	-106359	461910	381529	80382
<b>5. निवल भूल-चूक</b>	<b>39149</b>	<b>268031</b>	<b>-228882</b>	<b>186851</b>	<b>275995</b>	<b>-89145</b>
<b>Net errors and omissions</b>	<b>2791</b>	<b>0</b>	<b>2791</b>	<b>5500</b>	<b>0</b>	<b>5500</b>

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

Note: P: Preliminary

## सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2020-21		2020		2021			
			सितं.		जून		सितं.	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	193929	482226	188243	455981	199440	493763	202785	506723
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	122726	456947	121267	430714	125397	467990	127072	480697
1.2 अन्य पूंजी	71203	25278	66976	25267	74043	25773	75713	26026
2 संविभाग निवेश	7936	274104	5041	244308	7912	272859	8578	276375
2.1 इक्विटी	2340	177278	1906	149095	3146	176203	4590	177034
2.2 ऋण	5596	96826	3136	95213	4766	96657	3988	99341
3 अन्य निवेश	80606	454253	64785	440252	76828	455000	80317	475775
3.1 व्यापार ऋण	5644	100337	2792	102187	7875	102117	11879	100267
3.2 ऋण	13335	197773	9038	189705	13622	197443	10131	201213
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	42436	143760	34864	138822	35904	143096	41102	142904
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	19191	12384	18092	9538	19427	12344	17205	31391
4 रिज़र्व्स	576984		544687		611075		635363	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	859454	1210583	802757	1140541	895254	1221622	927043	1258873
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-351129		-337784		-326368		-331830

# भुगतान और निपटान प्रणाली

## सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक - भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)					
	वि. व 2020-21	2020		2021		वि. व 2020-21	2020		2021	
		नव.	अक्टू.	नव.	अक्टू.		नव.	अक्टू.	नव.	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>ए. निपटान प्रणाली</b>										
<b>वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)</b>										
<b>1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)</b>	27.97	2.45	2.85	2.56	161943141	10692192	16600978	17364381		
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	11.55	0.79	1.04	0.97	110634315	6942678	11415739	12229072		
1.1.1 आउटराइट	6.28	0.48	0.55	0.46	10032187	727023	745937	617831		
1.1.2 रेपो	2.84	0.12	0.25	0.26	43751173	1762647	3822009	4273958		
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	2.43	0.19	0.23	0.25	56850956	4453008	6847793	7337283		
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	16.04	1.64	1.73	1.53	48903961	3625849	4736040	4816873		
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	0.38	0.02	0.08	0.06	2404865	123665	449200	318437		
<b>बी. भुगतान प्रणाली</b>										
<b>I वित्तीय बाजार आधार-संरचना (एफएमआई)</b>										
<b>1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)</b>	1591.92	137.80	184.11	172.14	105599849	7987655	10134368	10981778		
1.1 ग्राहक लेनदेन	1573.47	136.13	182.90	170.95	91008367	6802206	8956918	9589985		
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	18.45	1.67	1.22	1.19	14591482	1185449	1177450	1391793		
<b>II खुदरा</b>										
<b>2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)</b>	317867.59	30269.97	52919.52	51855.52	33504168	2986234	3748602	3552986		
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	11.31	0.93	0.86	0.62	623	54	49	35		
2.2 एपीबीएस \$	14372.99	927.29	1192.91	1119.16	111001	4400	7519	9750		
2.3 आईएमपीएस	32783.47	3391.14	4306.71	4120.29	2941500	276459	370712	364672		
2.4 एनएसीएच जमा \$	16465.29	1114.23	1660.26	1356.65	1216477	96069	122519	95602		
2.5 एनईएफटी	30927.89	2734.10	3574.46	3394.00	25130910	2218252	2476397	2314490		
2.6 यूपीआई @	223306.64	22102.28	42184.32	41864.80	4103658	390999	771407	768436		
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	10.45	0.91	1.11	1.00	172	15	16	15		
<b>3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)</b>	10456.54	944.24	979.36	1031.91	865520	78709	85776	87212		
3.1 भीम आधार पे @	160.84	9.39	21.49	19.78	2580	181	560	536		
3.2 एनएसीएच नामे \$	9645.75	869.63	865.69	900.10	862027	78433	85103	86517		
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	649.96	65.22	92.18	112.03	913	96	114	158		
<b>4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)</b>	57786.60	5428.32	6008.76	5418.21	1291799	130239	177413	156325		
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	17641.06	1662.58	2155.81	2011.16	630414	62350	100943	89217		
4.1.1 पीओएस आधारित \$	8688.81	874.82	1075.23	1068.93	280769	30495	38442	37499		
4.1.2 अन्य \$	8952.25	787.76	1080.58	942.23	349645	31855	62500	51718		
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.2)	40145.54	3765.75	3852.95	3407.05	661385	67889	76471	67109		
4.2.1 पीओएस आधारित \$	20773.50	2112.56	2302.56	2111.98	377630	42289	47226	43750		
4.2.2 अन्य \$	19372.04	1653.18	1550.39	1295.07	283755	25600	29245	23358		
<b>5 प्रीपेड भुगतान साधन (5.1 से 5.2)</b>	49742.55	4226.72	6131.06	6107.21	197696	16712	26372	25583		
5.1 वालेट	39987.01	3421.15	4888.97	4871.05	152065	12724	21702	21057		
<b>5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)</b>	9755.54	805.58	1242.09	1236.16	45631	3987	4670	4526		
5.2.1 पीओएस आधारित \$	607.15	53.62	64.58	74.48	10690	1111	998	1287		
5.2.2 अन्य \$	9148.39	751.96	1177.51	1161.68	34941	2877	3672	3240		
<b>6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)</b>	6703.70	596.35	635.20	577.00	5627190	494383	582604	533223		
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6702.54	596.35	635.20	577.00	5625941	494383	582604	533223		
6.2 अन्य	1.17	-	-	-	1249	-	-	-		
<b>कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	442557.14	41465.61	66673.91	64989.85	41486430	3706276	4620768	4355329		
<b>कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	444149.06	41603.41	66858.02	65161.98	147086278	11693931	14755136	15337107		
<b>कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	437445.36	41007.06	66222.82	64584.98	141459089	11199549	14172532	14803884		



## भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2020-21	2020	2021		वि. व. 2020-21	2020	2021	
		नव.	अक्टू.	नव.		नव.	अक्टू.	नव.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ए. अन्य भुगतान चैनल</b>								
<b>1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)</b>	258033.70	24288.77	45884.23	45045.78	9201212	822100	1353833	1306948
1.1 इंटर-बैंक \$	25220.71	2191.98	3761.38	3230.26	1871390	165155	243728	222891
1.2 इंटर-बैंक \$	232812.99	22096.79	42122.85	41815.52	7329822	656945	1110105	1084057
<b>2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)</b>	32493.63	2814.17	3233.71	2860.67	41581497	3419474	3960872	3937877
2.1 इंटर-बैंक @	6886.15	585.09	631.51	570.26	20601554	1653359	1723311	1788978
2.2 इंटर-बैंक @	25607.48	2229.09	2602.20	2290.41	20979943	1766114	2237561	2148899
<b>बी. एटीएम</b>								
<b>3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)</b>	60905.81	5887.86	6037.14	5690.35	2889826	277940	289888	271685
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	51.41	4.64	5.64	5.45	2560	231	286	276
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	60602.23	5857.58	6002.43	5656.45	2878025	276797	288605	270470
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	252.17	25.63	29.07	28.44	9240	912	997	939
<b>4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)</b>	394.77	37.91	5.34	4.82	1533	143	64	63
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	353.50	32.33	4.44	4.14	1484	137	39	39
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	41.27	5.58	0.90	0.68	49	6	25	24
<b>5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @</b>	9460.43	684.78	946.33	925.63	225420	18820	24799	25112
5.1 एईपीएस @	9460.43	684.78	946.33	925.63	225420	18820	24799	25112

## भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2021	2020	2021	
	तक	नव.	अक्टू.	नव.
	1	2	3	4
<b>भुगतान प्रणाली अवसंरचना</b>				
<b>1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)</b>	9602.51	9528.15	9991.94	10015.90
1.1 क्रेडिट कार्ड	620.49	601.13	663.61	675.83
1.2 डेबिट कार्ड	8982.02	8927.02	9328.34	9340.07
<b>2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)</b>	21952.60	20443.15	25307.71	25421.67
2.1 वॉलेट @	20052.10	18857.67	22886.70	22911.53
2.2 कार्ड @	1900.51	1585.48	2421.01	2510.13
<b>3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)</b>	2.39	2.34	2.41	2.42
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.14	2.09	2.13	2.13
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.25	0.25	0.28	0.29
<b>4 माइक्रो एटीएम की संख्या @</b>	4.04	3.57	5.34	5.57
<b>5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या</b>	47.20	45.77	51.55	52.92
<b>6 भारत क्यूआर @</b>	35.70	30.46	44.35	45.41
<b>7 यूपीआई क्यूआर *</b>	925.22	697.82	1285.05	1373.33

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।

\* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिल दिया गया है।

3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

# अवसरिक श्रृंखला

## सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2019-20	2020		2021	
			फर.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5
<b>1. लघु बचत</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>159573</b>	<b>16911</b>	<b>16781</b>	<b>14261</b>	<b>14405</b>
	<b>बकाया</b>	<b>1078535</b>	<b>1046766</b>	<b>1196084</b>	<b>1210379</b>	<b>1224772</b>
<b>1.1 कुल जमाराशियां</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>116389</b>	<b>11460</b>	<b>12407</b>	<b>9820</b>	<b>10143</b>
	<b>बकाया</b>	<b>734807</b>	<b>716363</b>	<b>827156</b>	<b>836976</b>	<b>847119</b>
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	25893	2690	3307	2049	2252
	बकाया	166140	156258	190437	192486	194738
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	36	-20	-21	-26	-23
	बकाया	3143	2939	3086	3060	3037
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	-1	-3	-3	0	57
	बकाया	9	-23	-17	-17	40
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	16510	1887	1053	1162	1135
	बकाया	209168	207059	217980	219142	220277
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	20334	2131	2014	1886	1950
	बकाया	76042	73728	90914	92800	94750
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	41795	4494	4330	3952	3798
	बकाया	166087	161115	195847	199799	203597
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	92618	90327	104601	105928	107099
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7097	6970	7324	7375	7418
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7536	7464	7330	7285	7267
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	58836	56354	76592	79211	81813
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	11821	281	1727	797	974
	बकाया	114222	115291	128912	129709	130683
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	1	0	0	0	0
	बकाया	-25	-25	-24	-24	-24
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
<b>1.2 बचत प्रमाणपत्र</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>30170</b>	<b>3937</b>	<b>3941</b>	<b>3909</b>	<b>3647</b>
	<b>बकाया</b>	<b>252190</b>	<b>248022</b>	<b>274905</b>	<b>278848</b>	<b>282483</b>
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	19495	2619	1923	1903	1843
	बकाया	117987	115127	129270	131173	133016
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	-101	1	-1	-1	0
	बकाया	162	-288	158	157	157
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-18168	-1120	-669	-603	-470
	बकाया	1135	3949	-5121	-5724	-6194
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	28972	2452	2677	2610	2274
	बकाया	122602	118507	140538	143148	145422
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	-4	0	8	0	0
	बकाया	-155	-180	-147	-147	-147
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-24	-15	3	0	0
	बकाया	-106	-99	-103	-103	-103
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	10565	11006	10310	10344	10332
<b>1.3 लोक भविष्य निधि</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>13014</b>	<b>1514</b>	<b>433</b>	<b>532</b>	<b>615</b>
	<b>बकाया</b>	<b>91538</b>	<b>82381</b>	<b>94023</b>	<b>94555</b>	<b>95170</b>

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियों हैं। अर्थात् सकल प्राप्तियों माइनस सकल भुगतान

## सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

श्रेणी	केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां				
	2020		2021		
	सित्त.	दिसं.	मार्च	जन.	सित्त.
	1	2	3	4	5
<b>(क) कुल (₹ करोड़ में)</b>	<b>7137069</b>	<b>7357111</b>	<b>7635902</b>	<b>7882533</b>	<b>8235318</b>
1. वाणिज्य बैंक	38.55	37.81	37.77	35.99	37.82
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.34	0.25	0.27	0.34	0.35
3. बीमाकृत कंपनियां	25.33	25.64	25.30	25.83	24.18
4. म्यूच्युअल फंड	2.42	2.62	2.94	2.82	2.91
5. सहकारी बैंक	1.86	1.83	1.82	1.82	1.50
6. वित्तीय संस्थाएं	1.42	1.00	1.00	1.43	1.17
7. कॉरपोरेट	0.94	1.05	1.06	1.39	0.72
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	2.05	2.10	1.87	1.79	1.81
9. भविष्य निधियां	4.77	4.61	4.44	4.04	3.77
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	15.00	15.71	16.20	17.11	16.98
11. अन्य	7.32	7.37	7.33	7.43	8.79
11.1 राज्य सरकार	1.86	1.76	1.69	1.67	1.67

श्रेणी	राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां				
	2020		2021		
	सित्त.	दिसं.	मार्च	जन.	सित्त.
	1	2	3	4	5
<b>(ख) कुल (₹ करोड़ में)</b>	<b>3564979</b>	<b>3721573</b>	<b>3879982</b>	<b>4028849</b>	<b>4153508</b>
1. वाणिज्य बैंक	34.60	34.19	33.69	33.75	35.94
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.54	0.36	0.48	0.39	0.44
3. बीमाकृत कंपनियां	30.26	30.25	30.04	29.67	27.50
4. म्यूच्युअल फंड	1.96	1.92	1.82	1.74	1.97
5. सहकारी बैंक	4.19	4.11	4.05	4.12	3.60
6. वित्तीय संस्थाएं	1.92	1.88	1.86	1.79	1.72
7. कॉरपोरेट	0.39	0.45	0.49	1.45	1.32
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
9. भविष्य निधियां	21.31	21.20	22.00	21.09	18.27
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.81	0.77	0.88	0.85
11. अन्य	4.80	4.82	4.77	5.10	8.38
11.1 राज्य सरकार	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18

श्रेणी	खजाना बिल				
	2020		2021		
	सित्त.	दिसं.	मार्च	जन.	सित्त.
	1	2	3	4	5
<b>(ग) कुल (₹ करोड़ में)</b>	<b>982286</b>	<b>839729</b>	<b>690646</b>	<b>901327</b>	<b>763582</b>
1. वाणिज्य बैंक	53.50	54.75	55.54	52.25	50.22
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	2.16	1.65	2.82	1.82	1.33
3. बीमाकृत कंपनियां	4.06	4.50	5.61	4.75	4.12
4. म्यूच्युअल फंड	19.90	18.98	17.80	19.93	17.72
5. सहकारी बैंक	1.63	1.61	2.43	1.60	1.32
6. वित्तीय संस्थाएं	1.34	1.11	1.24	2.56	2.12
7. कॉरपोरेट	1.63	2.01	3.16	3.00	2.40
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
9. भविष्य निधियां	0.00	0.09	0.22	0.10	0.37
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	4.80	0.68	0.49	2.58	2.63
11. अन्य	10.99	14.63	10.70	11.42	17.62
11.1 राज्य सरकार	7.76	13.27	5.98	7.97	12.64

## सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (सं.अ.)	2021-22 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
<b>1. कुल वितरण</b>	<b>4265969</b>	<b>4515946</b>	<b>5040747</b>	<b>5410887</b>	<b>6523916</b>	<b>7160694</b>
1.1 गतिविधियां	2537905	2635110	2882758	3074492	3906147	4254004
1.1.1 राजस्व	1878417	2029044	2224367	2446605	3259401	3242247
1.1.2 पूंजी	501213	519356	596774	588233	636062	922982
1.1.3 ऋण	158275	86710	61617	39654	10684	88775
1.2 गैर गतिविधियां	1672646	1812455	2078276	2253027	2526514	2810847
1.2.1 राजस्व	1555239	1741432	1965907	2109629	2334608	2602289
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	724448	814757	894520	955801	1082302	1244457
1.2.2 पूंजी	115775	69370	111029	141457	189487	177328
1.2.3 ऋण	1632	1654	1340	1941	2419	31230
1.3 अन्य	55417	68381	79713	83368	91255	95843
<b>2. कुल प्राप्तियां</b>	<b>4288432</b>	<b>4528422</b>	<b>5023352</b>	<b>5734166</b>	<b>6489736</b>	<b>7039032</b>
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3132201	3376416	3797731	3851563	3834126	4682025
2.1.1 कर प्राप्तियां	2622145	2978134	3278947	3231582	3175594	3829889
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1652377	1853859	2030050	2012578	2100982	2514708
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	965622	1121189	1246083	1216203	1071552	1311449
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	4146	3086	2814	2800	3060	3732
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	510056	398282	518783	619981	658532	852135
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	33220	34224	36273	31137	39830	33198
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	69063	142433	140287	110094	54861	201138
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	20942	42213	44667	59515	21151	19581
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	48122	100219	95621	50578	33710	181557
<b>3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]</b>	<b>1064704</b>	<b>997097</b>	<b>1102729</b>	<b>1449230</b>	<b>2634928</b>	<b>2277532</b>
<b>3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार</b>						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	1046708	989167	1097210	1440548	2580406	2276017
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	617123	144792	387091	571872	890012	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	195816	-144847	325987	190241	107494	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	429585	844375	710119	868676	1690394	-----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	17997	7931	5519	8682	54522	1514
<b>3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार</b>						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	1046708	989167	1097210	1440548	2580406	2276017
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	689821	794856	795845	971378	1778062	1620936
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	35038	71222	88961	209232	455724	367863
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	45688	42351	51004	38280	47300	45504
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-6436	18423	-18298	10411	-3450	5051
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	17792	25138	66289	-14227	29050	28868
3ख.1.6 नकद शेष	-22463	-12476	17395	-323279	34179	121663
3ख.1.7 अन्य	287268	49653	96014	548753	239540	86132
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	17997	7931	5519	8682	54522	1514
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	27.7	26.4	26.7	26.6	33.0	32.1
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	27.9	26.5	26.6	28.2	32.9	31.6
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	20.3	19.8	20.1	18.9	19.4	21.0
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	17.0	17.4	17.4	15.9	16.1	17.2
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.9	5.8	5.8	7.1	13.3	10.2

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

## सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	नवंबर 2021 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	587	21	2151	18	1663	3
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	65	5	-	-	-	-
6	गोवा	11	2	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	1037	26	899	11
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	-	-	-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	-	-	303	29	269	20
17	मेघालय	89	12	86	6	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	155	18	6	3
19	नगालैंड	78	21	295	7	76	6
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	-	-	-	-	-	-
23	राजस्थान	2343	21	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	645	21	1345	19	682	9
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

## सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	नवंबर 2021 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	9054	892	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1920	3	--	-
3	असम	3853	60	--	-
4	बिहार	6102	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	5264	--	1	4550
6	गोवा	670	338	--	-
7	गुजरात	5330	524	--	-
8	हरियाणा	842	1330	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	2500
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	490	--	--	-
12	कर्नाटक	6292	--	--	30500
13	केरल	2338	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	1003	--	-
15	महाराष्ट्र	48418	686	--	25000
16	मणिपुर	168	110	--	-
17	मेघालय	791	45	9	-
18	मिज़ोरम	383	49	--	-
19	नगालैंड	1794	36	--	-
20	उड़ीसा	12233	1595	92	30783
21	पुदुचेरी	336	--	--	1280
22	पंजाब	1987	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	5200
24	तमिलनाडु	7258	--	40	14023
25	तेलंगाना	6193	1350	--	-
26	त्रिपुरा	565	10	--	700
27	उत्तराखंड	1009	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3566	139	--	-
29	पश्चिम बंगाल	9715	633	214	-
	<b>कुल</b>	<b>136567</b>	<b>8803</b>	<b>672</b>	<b>114536</b>

**टिप्पणी :** 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं

## सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22						2021-22 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सितंबर		अक्टूबर		नवंबर		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	42415	33444	50896	41915	6000	4840	5000	3840	2000	840	32750	24739
2	अरुणाचल प्रदेश	1366	1287	767	767	-	-	-	-	-	-	400	400
3	असम	12906	10996	15030	14230	1700	1700	1600	1600	1000	500	6500	6000
4	बिहार	25601	22601	27285	24685	2000	2000	4000	3000	4000	4000	20000	19000
5	छत्तीसगढ़	11680	10980	13000	10500	1000	1000	2000	1500	-	-1000	4000	2500
6	गोवा	2600	2000	3354	3054	400	200	100	100	100	-100	1300	900
7	गुजरात	38900	28600	44780	33280	3000	1000	5554	3554	-	-1000	17554	7554
8	हरियाणा	24677	20677	30000	25550	1000	1000	3000	2500	-	-500	16500	12200
9	हिमाचल प्रदेश	6580	4460	6000	3755	1000	1000	-	-100	2000	1795	3000	2695
10	जम्मू और कश्मीर	7869	6760	9328	6020	1100	1100	-	-	400	225	4600	3725
11	झारखंड	7500	5656	9400	8900	500	500	1000	500	-	-	1500	500
12	कर्नाटक	48500	42500	69000	61900	-	-	6000	6000	4000	2500	10000	8500
13	केरल	18073	12617	28566	23066	5500	4500	2000	1000	-	-	19000	16000
14	मध्य प्रदेश	22371	16550	45573	38773	6000	6000	2000	-1000	4000	4000	14000	11000
15	महाराष्ट्र	48498	32998	69000	50022	8500	7000	2500	-1000	3000	3000	51750	41750
16	मणिपुर	1757	1254	1302	1044	147	47	140	90	200	200	1087	937
17	मेघालय	1344	1070	1777	1587	400	400	200	140	-	-50	1000	790
18	मिज़ोरम	900	745	944	677	80	80	104	104	-	-	434	184
19	नगालैंड	1000	423	1721	1366	150	150	89	89	-	-	989	889
20	उड़ीसा	7500	6500	3000	500	-	-	-	-1000	-	-500	-	-3500
21	पुदुचेरी	970	470	1390	790	124	124	-	-	125	125	249	249
22	पंजाब	27355	18470	32995	23467	5170	3770	1162	862	-	-500	12282	2532
23	राजस्थान	39092	24686	57359	44273	6000	5500	5000	3730	1500	617	32100	25635
24	सिक्किम	809	481	1292	1292	251	251	-	-	-	-	751	751
25	तमिलनाडु	62425	49826	87977	76796	1000	1000	4000	2740	4000	2260	47000	40000
26	तेलंगाना	37109	30697	43784	37365	3500	2660	1500	660	3000	2160	28000	22211
27	त्रिपुरा	2928	2578	1916	1631	300	300	-	-	-	-	300	150
28	उत्तराखंड	69703	52744	75500	59185	7500	6500	7500	5524	5000	2513	40000	26791
29	उत्तरप्रदेश	5100	4500	6200	5208	-	-150	-	-	-	-	1200	350
30	पश्चिम बंगाल	56992	40882	59680	50180	8500	7000	5000	3500	3500	2500	38000	21827
	<b>कुल</b>	<b>634521</b>	<b>487454</b>	<b>798816</b>	<b>651777</b>	<b>70822</b>	<b>59472</b>	<b>59449</b>	<b>37934</b>	<b>37825</b>	<b>23585</b>	<b>406246</b>	<b>297259</b>

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

## वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

### सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।  
3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।  
4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।  
4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।  
4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।  
4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।  
7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

### सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।  
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

### सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टेम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

### सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्जिम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

### सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।  
2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

### सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

### सारणी सं. 8

एनएम<sub>2</sub> और एनएम<sub>3</sub> में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।  
2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।  
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

### सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।  
एल<sub>1</sub> और एल<sub>2</sub> मासिक आधार पर और एल<sub>3</sub> तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।  
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

### सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाए गए आंकड़ें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।



**सारणी सं. 14**

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

**सारणी सं. 17**

- 2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।  
 2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।  
 4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

**सारणी सं. 24**

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

**सारणी सं. 30**

- प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।  
 1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।  
 2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

**सारणी सं. 32**

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

**सारणी सं. 34**

- 1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान  
 1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान  
 'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।  
 हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

**सारणी सं. 35**

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

**सारणी सं. 36**

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का सकेंतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2018-19 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में दिया गया है।

**सारणी सं. 37**

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

### सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

### सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -

o बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल हैं।

o जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए हैं, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

### सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खजाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

**सारणी सं. 46**

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 29 मई 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बजट 2020-21 से लिया गया है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों सहित।

**सारणी सं. 47**

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

:- नगण्य

**सारणी सं. 48**

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

'वर्तमान सांख्यिकी' का टाइम सीरिज डाटा <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

### भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2022	₹350 एक प्रति (काउंटर पर) ₹400 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,800 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,600 (एक वर्ष रियायती दर*) ₹3,840 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित <sup>@</sup> ) ₹2,880 (एक वर्ष रियायती दर <sup>@</sup> )	15 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंडबुक 2020-21	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक 2020-21	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2020-21 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 2, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 1, 2020	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 2, 2020	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

#### टिप्पणियां:

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट ([www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)) पर उपलब्ध हैं।
  - टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- \* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

**सामान्य अनुदेश:**

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमि क और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं हैं।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 में किया जाएगा। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: [spsdepr@rbi.org.in](mailto:spsdepr@rbi.org.in) है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001।

एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' **2 महीने के अंदर भेजी जाए।**
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी [spsdepr@rbi.org.in](mailto:spsdepr@rbi.org.in) पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।

